

भारतीय रिज़र्व बैंक
बुलेटिन



जून 2020

खंड 74 अंक 6

संपादन समिति
राजीव रंजन
डी. पी. रथ
सितीकांत पट्टनाईक
जी. पी. सामंता
एस. गंगाधरन
पल्लवी चव्हाण
स्नेहल हेरवाडकर

संपादक
शशीधर एम. लोकरे

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन संपादकीय समिति के निर्देशन में आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग द्वारा मासिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। इसमें व्यक्त व्याख्याओं और विचारों के लिए बैंक का केंद्रीय निदेशक मंडल उत्तरदायी नहीं है। हस्ताक्षरित लेखों में व्यक्त विचारों के लिए लेखक स्वयं उत्तरदायी हैं।

© भारतीय रिज़र्व बैंक 2020

सर्वाधिकार सुरक्षित।
सामग्री के पुनः प्रयोग की अनुमति है,
बशर्ते स्रोत का उल्लेख किया जाए।

बुलेटिन के सदस्यता शुल्क के लिए कृपया “भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के महत्वपूर्ण प्रकाशन” खंड देखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन को इंटरनेट के माध्यम से
<http://www.bulletin.rbi.org.in> पर भी देखा जा सकता है।

विषय-वस्तु

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य 1

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 7

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य 11

लेख

हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के तिमाही अनुमान 15

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े मुद्दे 25

एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति:
मुद्दे और नीति विकल्प 35

केंद्र सरकार के वित्त 2019-20 का अनंतिम लेखा: एक आकलन 43

वर्तमान सांख्यिकी 55

हाल के प्रकाशन 101

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य

गवर्नर का वक्तव्य*

शक्तिकांत दास

“जब क्षितिज तमोमय हो जाता है और

तर्क शक्ति धराशायी हो जाती है

तब विश्वास की चमकती किरण हमें बचा लेती है”¹

हमें एक राष्ट्र के रूप में सभी बाधाओं से बचा लेने के भारत के लचीलेपन और क्षमता पर हमें विश्वास होना चाहिए। COVID-19, 0.12 माइक्रोन आकार के एक वायरस ने 300,000 से अधिक मृत्युओं से और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधि को ठप कर के वैश्विक अर्थव्यवस्था को पंगु बना दिया है। एक बार फिर केंद्रीय बैंकों को अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए अग्रिम पंक्ति में आकर इस समस्या का मुकाबला करना पड़ेगा।

वृहद आर्थिक आंकड़ों की हालिया प्रकाशनी से पहली बार COVID-19 द्वारा गढ़े गए नुकसान का संज्ञान हुआ है जिससे मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की 3 से 5 जून, 2020 के दौरान निर्धारित बैठक को समय से पूर्व आयोजित करने की आवश्यकता महसूस की गई। पिछले तीन दिनों में यानी 20, 21 और 22 मई 2020 को एमपीसी ने संभावनाओं का पता करने के लिये घरेलू और वैश्विक घटनाक्रमों और उनके निहितार्थों की समीक्षा की। यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए सर्वसम्मति से मतदान किया। कटौती की मात्रा पर एमपीसी ने 5-1 बहुमत के साथ मतदान कर नीतिगत दर को 4.4 प्रतिशत से 40 आधार अंकों से घटाकर 4.0 प्रतिशत कर दिया। नतीजतन, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65% से घटकर 4.25% हो गई है। रिवर्स रेपो रेट 3.75% से घटकर 3.35% हो गई है।

इससे पहले कि मैं एमपीसी के निर्णय की पृष्ठभूमि, औचित्य और अपेक्षित परिणाम पर बात करूं, मैं समिति के सदस्यों को

आज लिए गए मौद्रिक नीति निर्णय में समिति के कार्य में बहुमूल्य योगदान देने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं भारतीय रिजर्व बैंक में अपने सहयोगियों को भी धन्यवाद देना चाहूंगा जो COVID-19 के खिलाफ हमारी लड़ाई में अथक परिश्रम कर रहे हैं। मेरी कृतज्ञता हमारी टीमों के प्रति भी व्यक्त करता हूं जो हमें बौद्धिक समर्थन, विश्लेषणात्मक काम और लोजिस्टिकल व्यवस्था में सहायता करते हैं। मैं 200 से अधिक उन अधिकारियों, कर्मचारियों और सेवा प्रदाताओं की हमारी टीम की विशेष प्रशंसा करना चाहता हूं जो भारतीय रिजर्व बैंक की आवश्यक सेवाओं को राष्ट्र के लिए उपलब्ध रखने के लिए अलगाव में 24X7 काम कर रहे हैं। मैं डॉक्टरों, स्वास्थ्य देखभाल और चिकित्सा कर्मचारियों, पुलिस और कानून प्रवर्तन एजेंसियों, सरकारी कार्यकर्ताओं और कर्मियों, निजी क्षेत्र, बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त करना चाहता हूं, जो सभी आवश्यक सेवाओं के प्रावधान में निरंतरता सुनिश्चित करते हुए महामारी के बीच दिन-प्रतिदिन ड्यूटी के आह्वान को पूर्ण करने के लिये बढ़कर आगे आ गए हैं। उनके परिवारों के प्रति भी हमारी गहरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं।

I. आकलन

सभी मामलों में वृहद आर्थिक और वित्तीय स्थितियां दबावग्रस्त हैं। वैश्विक अर्थव्यवस्था बुरी तरह से मंदी की ओर बढ़ रही है। वैश्विक विनिर्माण क्रय प्रबंधक सूचकांक (पीएमआई) अप्रैल 2020 में 11 साल के निचले स्तर तक संकुचित हुआ है। वैश्विक सेवाएं पीएमआई ने सूचकांक के इतिहास में अपनी सबसे तेज गिरावट दर्ज की है। 2020 की पहली तिमाही के लिए सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़े जारी करने वाली उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (एईएस) में संकुचन 3.4 प्रतिशत से 14.2 प्रतिशत (तिमाही-दर-तिमाही, वार्षिकीकृत) की सीमा में रहे हैं; उभरती बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमएस) के लिए विकास दर 2.9 प्रतिशत और (-) 6.8 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष आधार पर) के बीच रही है। अशांत वित्तीय बाजारों के झटकों से प्रभावित ईएमईज़ को पूंजी बहिर्वाह और परिसंपत्ति मूल्य अस्थिरता के रूप में अतिरिक्त दबावों का सामना करना पड़ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से तेल निर्यातकों के लिए बजटीय राजस्व सूख गया है; दूसरी ओर, महामारी द्वारा कुचल दी गई मांग ने तेल आयातकों

* गवर्नर का वक्तव्य - 22 मई 2020

¹ महात्मा गांधी, यंग इंडिया, 21 मार्च 1929

को व्यापारिक लाभ से वंचित कर दिया है। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन (यूएनसीसीएडी) के अनुसार, वैश्विक व्यापार का मूल्य 2020 की पहली तिमाही में 3.0 प्रतिशत तक संकुचित हो गया है। विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अनुमान के अनुसार विश्व व्यापार की मात्रा 2020 में 13-32 प्रतिशत तक सिकुड़ सकती है। यात्री हवाई यात्रा, कंटेनर शिपिंग, वित्तीय और आईसीटी सेवाओं में व्यापक गतिहीनता के कारण 2020 की पहली तिमाही में विश्व सेवा व्यापार की हानि हुई है। व्यापक लॉकडाउन के बीच कमोडिटी की कीमतों में बड़े मांग झटके से हालांकि नरमी आई, लेकिन आपूर्ति अवरोधों के कारण मुद्रास्फीति प्रिंट में खाद्य मूल्य का दबाव दिखाई दे रहा है, विशेष रूप से उन देशों में जहां परिवारों के उपभोग व्यय का एक प्रमुख मद खाद्य पदार्थ है। वैश्विक वित्तीय बाजार मार्च में एक अशांत अवधि के बाद शांत हो गए हैं और अस्थिरता कम हो गई है लेकिन बाजार आम तौर पर वास्तविक अर्थव्यवस्था के विकास से नहीं जुड़े हैं।

केंद्रीय बैंकों और सरकारों द्वारा अभूतपूर्व वैश्विक नीति प्रतिक्रिया अपेक्षाकृत गुमनाम रही है।

अब मैं घरेलू विकास की ओर मुड़ता हूं। घरेलू आर्थिक गतिविधि 2 महीने के लॉकडाउन से गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। करीब 60 प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन देने वाले शीर्ष 6 औद्योगिक राज्य काफी हद तक लाल या नारंगी क्षेत्रों में हैं। मार्च 2020 की शुरुआत में उच्च आवृत्ति संकेतक शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग में गिरावट की ओर इशारा करते हैं। बिजली और पेट्रोलियम उत्पादों की खपत - दिन-प्रतिदिन की मांग के संकेतक - भारी गिरावट में डूब गए हैं। मांग और उत्पादन दोनों के नुकसान के मामले में दोहरी मार ने राजकोषीय राजस्व में गिरावट आई है। मार्च में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में 36 प्रतिशत की गिरावट ने निवेश की मांग पर लगभग रोक लगा दी है, संयोग से मार्च में पूंजीगत वस्तुओं के आयात में 27 प्रतिशत और अप्रैल में 57.5 प्रतिशत संकुचन भी हुआ है। यह अप्रैल में तैयार इस्पात खपत में 91 प्रतिशत की गिरावट और मार्च में सीमेंट उत्पादन में 25 प्रतिशत सिकुड़न में भी परिलक्षित हो रहा है। COVID-19 से सबसे बड़ा झटका निजी खपत को लगा है, जो घरेलू मांग के करीब 60 फीसदी है। उपभोक्ता टिकाऊ

वस्तुओं का उत्पादन मार्च 2020 में 33 फीसदी गिर गया, साथ ही गैर-उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में 16 फीसदी की गिरावट आई। इसी तरह के संकेत तेजी से बढ़ती उपभोक्ता वस्तुओं के सर्वेक्षणों में परिलक्षित हुए हैं।

उत्पादन क्षेत्रों में, औद्योगिक उत्पादन मार्च 2020 में करीब 17 प्रतिशत तक सिकुड़ गया, विनिर्माण गतिविधियों में 21 प्रतिशत की गिरावट आई। कोर उद्योग जिनका कुल औद्योगिक उत्पादन में लगभग 40 प्रतिशत हिस्सा होता है, उनका उत्पादन 6.5 प्रतिशत तक संकुचित हुआ। अप्रैल के लिए विनिर्माण पीएमआई ने 27.4 की अपनी सबसे तेज गिरावट दर्ज की जो सभी क्षेत्रों में फैल गई। अप्रैल 2020 में सेवा पीएमआई में 5.4 के सर्वकालिक निचले स्तर तक की गिरावट हुई।

इस घोर निराशा के बीच, कृषि और संबद्ध गतिविधियों ने खाद्यान्न उत्पादन में 3.7 प्रतिशत की वृद्धि के एक नए रिकॉर्ड (15 मई 2020 को जारी कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमानों के अनुसार) ने आशा की किरण प्रदान की है। भारतीय मौसम विभाग (आईएमडी) के 2020 में सामान्य दक्षिण पश्चिम मानसून के पूर्वानुमान में भी उम्मीद की एक किरण नजर आ रही है। 10 मई 2020 की उपलब्ध नवीनतम जानकारी के अनुसार खरीफ की बुवाई पिछले साल के एकड़ों की तुलना में 44 प्रतिशत अधिक थी। तिलहन, दलहन और गेहूं के संबंध में रबी की खरीद प्रक्रिया जारी है, जिससे बंपर फसल लाभान्वित हो रही है। इन घटनाक्रमों से कृषि आय में सहायता मिलेगी, कृषि क्षेत्र के सम्मुख व्यापारिक शर्तों में सुधार होगा और देश की खाद्य सुरक्षा मजबूत होगी। आगे, खाद्य मूल्य के दबाव पर भी इनका हितकारी प्रभाव पड़ेगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) द्वारा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) के बारे में आंशिक जानकारी जारी करने से मुद्रास्फीति का संभावनाएं जटिल हो गई है, क्योंकि इससे मूल्य की स्थिति का व्यापक और स्पष्ट आकलन प्राप्त नहीं हो रहा है। जो अधूरे आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं, खाद्य मुद्रास्फीति, जो मार्च में लगातार दूसरे महीने के लिए अपने जनवरी 2020 शिखर से कम हो गई थी, अचानक पलट कर अप्रैल में 8.6 प्रतिशत तक बढ़ी क्योंकि आपूर्ति अवरोधों ने अपना टोल और जारी मांग संकुचन ने अपनी प्रतिरक्षा की

वसूली की। सब्जियों, दालों, खाद्य तेलों, दूध और अनाज के दाम दबाव बिंदू के रूप में उभरे।²

बाहरी क्षेत्र में, भारत के निर्यात और आयात माल में पिछले 30 वर्षों में सबसे ज्यादा मंदी आई क्योंकि COVID-19 ने विश्व उत्पादन और मांग को पंगु बना दिया। अप्रैल 2020 में भारत का माल निर्यात 60.3 प्रतिशत गिर गया जबकि आयात में 58.6 प्रतिशत का संकूचन हुआ। अप्रैल 2020 में व्यापार घाटा, जून 2016 के बाद सबसे कम 6.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक कम हुआ। वित्तपोषण के मामले में, निवल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह मार्च 2020 में 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़े। 2020-21 में अब तक (18 मई तक) इक्विटी में निवल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) भी एक साल पहले 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है। हालांकि, ऋण खंड में, इसी अवधि के दौरान पोर्टफोलियो बहिर्वाह एक साल पहले 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्गमन के मुकाबले 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। इसके विपरीत, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के तहत निवल निवेश में इसी अवधि के दौरान 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में अब तक (15 मई तक) 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर बढ़कर 487.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है- जो एक साल के आयात के बराबर है।

II. संभावना

इस पृष्ठभूमि के खिलाफ, एमपीसी ने मूल्यांकन किया कि मुद्रास्फीति संभावनाएं अत्यधिक अनिश्चित हैं। अप्रैल में खाद्य कीमतों में आपूर्ति आघात की स्थिति अगले कुछ महीनों तक बनी रह सकती है, जो लॉकडाउन की स्थिति और उसके बाद आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में लगने वाले समय पर निर्भर करती है। दबाव बिंदुओं में से, दाल की मुद्रास्फीति का उंचा स्तर चिंताजनक है, और समय पर और तेजी से आपूर्ति प्रबंधन हस्तक्षेपों की आवश्यकता है, जिसमें आयात शुल्कों का पुनः मूल्यांकन शामिल है। अतिरिक्त स्टॉक के कुछ भाग के भारी मात्रा में बिक्री के लिए एफसीआई द्वारा खुले बाजार में बिक्री /

पीडीएस-ऑफटेक के तत्काल उपाय से अनाज की कीमतें कम हो सकती हैं और रबी खरीद के लिए जगह भी बन सकती है। वर्तमान वैश्विक मांग-आपूर्ति संतुलन को देखते हुए, अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतें, धातुओं और औद्योगिक कच्चे माल की कीमतें सौम्य बने रहने की संभावना है। इससे घरेलू कंपनियों के लिए लागत मूल्यों को कम करेगी। न्यून मांग मुख्य मुद्रास्फीति पर दबाव डाल सकता है, हालांकि आपूर्ति की लगातार अव्यवस्था के कारण निकट अवधि की संभावनाओं के लिए अनिश्चितता पैदा होती है। बहुत कुछ COVID के बाद रिकवरी के आकार पर निर्भर करेगा। तदनुसार, एमपीसी का मानना है कि हेडलाइन मुद्रास्फीति 2020-21 की पहली छमाही में स्थिर रह सकती है, लेकिन अनुकूल आधार प्रभावों के कारण दूसरी छमाही में भी इसमें आसानी होनी चाहिए। वित्तीय वर्ष 20-21 के तीसरी और चौथी तिमाही तक, यह लक्ष्य से नीचे गिरने की उम्मीद है। इस प्रकार, मुद्रास्फीति के संबंध में एमपीसी का आगे के दिशानिर्देश स्तरों के संदर्भ में न होकर निदेशात्मक है। आगे, जब और अधिक आंकड़े उपलब्ध होंगे, तब अधिक निश्चितता के साथ मुद्रास्फीति के मार्ग का अनुमान लगाना संभव होना चाहिए।

यह संवृद्धि संभावना में है कि एमपीसी ने जोखिम को सबसे गंभीर माना। मांग संपीड़न और आपूर्ति में व्यवधान का संयुक्त प्रभाव वर्ष की पहली छमाही में आर्थिक गतिविधि को प्रभावित करेगा। यह मानते हुए कि आर्थिक गतिविधि चरणबद्ध तरीके से बहाल होगी, विशेष रूप से इस वर्ष की दूसरी छमाही में, और अनुकूल आधार प्रभावों को ध्यान में रखते हुए यह उम्मीद की जाती है कि वर्तमान में किए जा रहे राजकोषीय, मौद्रिक और प्रशासनिक उपायों के संयोजन से 2020-21 की दूसरी छमाही में गतिविधि में क्रमिक पुनरुद्धार के लिए शर्तें पैदा करेंगी। बहरहाल, इस मूल्यांकन के लिए नकारात्मक जोखिम महत्वपूर्ण हैं और सामाजिक अलगाव / लॉकडाउन द्वारा महामारी और त्वरित चरणबद्धता पर नियंत्रण के लिए आकस्मिक हैं। इन सभी अनिश्चितताओं को देखते हुए, 2020-21 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि 2020-21 की दूसरी छमाही के बाद से संवृद्धि आवेगों में कुछ संवृद्धि के साथ नकारात्मक क्षेत्र में रहने का अनुमान है। राष्ट्रीय आय पर एनएसओ के मई 2020 के विमोचन से अधिक स्पष्टता मिलनी चाहिए, जिससे जीडीपी वृद्धि के अधिक विशिष्ट अनुमानों को परिमाण और दिशा दोनों के संदर्भ में सक्षम बनाया जा सके। बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि COVID वक्र

² लॉकडाउन के कारण गैर-खाद्य पदार्थों में सीमित लेनदेन को देखते हुए अखिल भारतीय हेडलाइन सीपीआई को अप्रैल 2020 के लिए जारी नहीं किया गया था; आंकड़े केवल खाद्य और आवास समूहों के लिए जारी किए गए थे।

कितनी जल्दी समतल और धीमा होना शुरू होता है। जैसे ही राष्ट्र इस भविष्य के लिए तैयार होता है, महात्मा गांधी के शब्दों से हमें लड़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए: "हम ठोकर खा सकते हैं और गिर सकते हैं, लेकिन फिर से उठेंगे"³

एमपीसी का विचार है कि महामारी का समष्टि आर्थिक प्रभाव पहले से प्रत्याशित रूप से अधिक गंभीर हो रहा है। आर्थिक और वित्तीय गतिविधियों के विनाश से परे, आजीविका और स्वास्थ्य बुरी तरह प्रभावित हुआ है। यह देखते हुए कि वृद्धि के जोखिम तीव्र हैं, जबकि मुद्रास्फीति के जोखिम अल्पकालिक होने की संभावना है, एमपीसी का मानना है कि अब आत्मविश्वास पैदा करना आवश्यक है और वित्तीय स्थिति में और सुधार किया जाए। इससे किफ़ायती दरों पर धन के प्रवाह में मदद मिलेगी और निवेश आवेगों को फिर से बढ़ावा मिलेगा। यह इस संदर्भ में है कि एमपीसी ने पॉलिसी रेपो दर को 40 आधार अंकों से घटाकर 4.4 प्रतिशत से 4.0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया। यदि मुद्रास्फीति ट्राजेक्टरी अपेक्षित रूप से विकसित होता है, तो वृद्धि के जोखिमों को निपटने के लिए काफी स्पेस मिलेगा।

III. विनियामक और विकासात्मक उपाय

मैं अब एमपीसी द्वारा तय की गई नीति दर में कमी को पूरक और बढ़ाने के लिए विभिन्न विनियामक और विकासात्मक उपायों की घोषणा करता हूँ। ऐसा करते समय, मैं आरबीआई द्वारा पहले से तय की गई नीतिगत कार्रवाइयों, उनके औचित्य और उनके संभावित प्रभाव पर थोड़ा समय बिताऊंगा। फरवरी 2020 में एमपीसी की बैठक के समय अपने बयान में, मैंने कोरोनावायरस के प्रकोप के संदर्भ में वैश्विक विकास के लिए बढ़ते नकारात्मक जोखिमों को इंगित किया था, जिसके पूर्ण प्रभाव अनिश्चित और अप्रत्यक्ष थे। तब से, अपने पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के उपायों की श्रेणी का विस्तार करते हुए अग्र-सक्रिय चलनिधि प्रबंधन स्थिति में बना रहा, ताकि रुपया और विदेशी मुद्रा दोनों में प्रणाली स्तरीय चलनिधि को बढ़ाया जा सके और साथ ही वित्तपोषण की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को भी चलनिधि उपलब्ध करवा सके। इन तरलता उपायों का उद्देश्य इन परिस्थितियों में वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजारों को सामान्य रूप से कार्य कराना है

³ महात्मा गांधी, "अवर एम", नवजीवन, 7 सितंबर 2019, कलेक्टेड वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी (सी डब्ल्यू एम जी), खंड XVI, पृष्ठ.93

ताकि वित्तीय स्थितियां फ्रीज़ न हों।

इस बीच, बैंकों की उधार दरों में मौद्रिक नीति संचरण में सुधार जारी रहा है। निधि आधारित उधार दर (एमसीएलआर) की 1 वर्ष की औसत सीमांत लागत 90 बीपीएस (फरवरी 2019- 15 मई 2020) तक घट गई। फरवरी 2019 से नए रुपये के ऋणों पर भारत औसत उधार दर (डब्ल्यूएलआर) में संचयी रूप से 114 बीपीएस की गिरावट आई है, जिसमें से 43 बीपीएस की गिरावट अकेले मार्च 2020 में आई है। अक्टूबर 2019-मार्च 2020 के दौरान बकाया रुपये के ऋणों पर डब्ल्यूएलआर में 29 बीपीएस की गिरावट दर्ज की गई। घरेलू वित्तीय स्थितियों में भी कमी आई है जैसा कि विभिन्न बाजार खंडों में चलनिधि प्रीमिया की संकीर्णता में परिलक्षित है। 17 अप्रैल के बाद जब मैंने आपसे आखिरी बार बात की थी, 3-महीने के सीपी, 3-महीने की सीडी, 5-वर्षीय एए कॉरपोरेट बॉन्ड, 91-दिवसीय खजाना बिल, 5-वर्षीय और बेंचमार्क 10-वर्षीय सरकारी कागज पर ब्याज दरें 15 मई, 2020 तक क्रमशः 220 बीपीएस, 108 बीपीएस, 48 बीपीएस, 71 बीपीएस, 59 बीपीएस और 66 बीपीएस कम हो गई है।

नीतिगत रेपो दर को कम करने और मौद्रिक नीति के निभावकारी रुख को बनाए रखने का एमपीसी का निर्णय रिज़र्व बैंक को आर्थिक गतिविधि के लिए बिगड़ते संभावनाओं की पृष्ठभूमि के एवज में कुछ अतिरिक्त उपायों की घोषणा करने का अवसर प्रदान करता है। ये नीतिगत कार्य इरादे और पहुंच में एक दूसरे को पूरक और मजबूत करती हैं। आज घोषित किए जा रहे उपायों को मोटे तौर पर चार श्रेणियों के तहत निरूपित किया जा सकता है:

- (क) बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार के उपाय;
- (ख) निर्यात और आयात का समर्थन करने के उपाय;
- (ग) ऋण सेवा पर राहत और कार्यशील पूंजी के एक्सेस में सुधार करके COVID-19 व्यवधानों के कारण उत्पन्न वित्तीय तनाव को और कम करने के लिए किए गए प्रयास; तथा
- (घ) राज्य सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के लिए कदम।

(क) बाजारों के कार्य में सुधार के लिए उपाय**भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए पुनर्वित्त सुविधा**

भारतीय रिज़र्व बैंक ने पहले सिडबी के लिए रिज़र्व बैंक की पॉलिसी रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए उधार / पुनर्वित्त हेतु ₹15,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की थी। सिडबी को अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, 90 वें दिन के अंत में 90 दिनों की दूसरी अवधि के लिए रोल ओवर सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

स्वैच्छक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

इसके आरंभ होने के बाद से, वीआरआर योजना ने योजना के तहत आवंटित सीमा की 90 प्रतिशत से अधिक निवेश के साथ मजबूत निवेशक भागीदारी को विकसित किया है। COVID-19 से संबंधित व्यवधानों के कारण एफपीआई और उनके संरक्षकों द्वारा तीन महीने के भीतर आवंटित सीमाओं का कम से कम 75 प्रतिशत निवेश किए जाने की शर्त का पालन करने में हो रही कठिनाई के मद्देनजर, यह निर्णय लिया गया है कि इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए एफपीआई को अतिरिक्त तीन महीने की अनुमति दी जाएगी।

(ख) निर्यात और आयात का समर्थन करने के उपाय

COVID-19 के तेजी से प्रसार के कारण वैश्विक गतिविधि और व्यापार में संकुचन की गहनता से बाहरी मांग में कमी आई है। बदले में, इसने भारत के निर्यात और आयात को प्रभावित किया है, दोनों ही हाल के महीनों में तेजी से संकुचित हुए हैं। अर्थव्यवस्था में निर्यात और आयात के महत्व को देखते हुए विदेशी व्यापार क्षेत्र को समर्थन देने के लिए कुछ उपाय किए जा रहे हैं।

निर्यात ऋण

अपने उत्पादन और वसूली चक्रों में निर्यातकों द्वारा सामना की जा रही वास्तविक कठिनाइयों को कम करने के लिए, 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण हेतु बैंकों द्वारा मंजूर पोतलदान-पूर्व और पोतलदान-पश्चात निर्यात ऋण

की अधिकतम अनुमेय अवधि को वर्तमान एक वर्ष से 15 महीनों के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

भारतीय आयात-निर्यात बैंक के लिए चलनिधि की सुविधा

एकजम बैंक द्वारा अपनी विदेशी मुद्रा संसाधन आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से, यह निर्णय किया गया है कि एकजम बैंक को 90 दिनों की अवधि के लिए (एक वर्ष के रोलओवर के साथ) ₹.15,000 करोड़ की ऋण सुविधा प्रदान की जाए, ताकि वह अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके।

आयात के भुगतान के लिए समय-सीमा में विस्तार

COVID-19 के माहौल में आयातकों को उनके परिचालन चक्रों को प्रबंधित करने में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, यह निर्णय किया गया कि, भारत में सामान्य आयात (सोने/हीरे और बहुमूल्य पत्थरों/आभूषणों के आयात को छोड़कर) के लिए बाह्य विप्रेषण की समयावधि को, 31 जुलाई 2020 तक या उससे पहले किए गए इस तरह के आयात के लिए शिपमेंट की तारीख से छह महीने से बारह महीने तक बढ़ाया जाए।

(ग) वित्तीय दबाव को कम करने के उपाय

रिज़र्व बैंक ने पहले भी दो अलग-अलग अवसरों पर (27 मार्च और 17 अप्रैल 2020) (क) सावधि ऋण की किस्तों पर 3 महीने की ऋणस्थगन देने; (ख) कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर 3 महीने के लिए ब्याज का आस्थगन; (ग) कार्यशील पूंजीगत चक्र के पुनर्मूल्यांकन या मार्जिन को कम कर कार्यशील पूंजीगत वित्तपोषण जरूरतों को सुगम बनाने; (घ) पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और क्रेडिट सूचना कंपनियों की रिपोर्टिंग में 'चूककर्ता' के रूप में वर्गीकृत होने से छूट देने; (ड.) दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान हेतु समयसीमा में विस्तार; तथा (च) ऋण प्रदान करने वाली संस्थानों द्वारा 3 महीने की ऋणस्थगन अवधि इत्यादि को छोड़कर आस्तित्व वर्गीकरण स्टैंड स्टिल से संबंधित कुछ नियामक उपायों की घोषणा की थी।

COVID-19 के कारण लॉकडाउन के विस्तार और निरंतर अवरोधों के मद्देनजर, उपरोक्त उपायों को 1 जून 2020 से

31 अगस्त 2020 तक और तीन महीनों तक बढ़ाया जा रहा है, इस प्रकार उपायों की प्रयोज्यता की कुल अवधि छह महीने तक (अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक) हो गई है। ऋण देने वाली संस्थानों को 31 मार्च 2021 तक कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन को उनके मूल स्तरों पर बहाल करने की अनुमति दी जा रही है। इसी प्रकार, कार्यशील पूंजी चक्र के पुनः निर्धारण से संबंधित उपायों को 31 मार्च 2021 तक बढ़ाया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, यह निर्णय किया गया है कि उधार देने वाले संस्थानों को 6 महीने (अर्थात् 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक) की कुल आस्थगन अवधि के लिए कार्यशील पूंजीगत सुविधाओं पर संचित ब्याज को एक वित्तपोषित ब्याज अवधि ऋण में बदलने की अनुमति दी जाए, जिसे 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान पूरी तरह से चुकाया जाएगा।

पूंजीगत बाजारों से संसाधन जुटाने में मौजूदा कठिनाई को देखते हुए, कॉर्पोरेट्स को बैंकों से उनकी वित्त पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए, बैंकों की समूह एक्सपोजर सीमा को पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा रहा है। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

(घ) राज्य सरकारों द्वारा सामना की जाने वाली वित्तीय बाधाओं को कम करने के उपाय

राज्य सरकारों के समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) - दिशानिर्देशों में ढील

राज्यों पर बांड मोचन दबाव को कम करने के लिए, यह निर्णय किया गया है कि सीएसएफ से आहरण नियंत्रित

करने वाले नियमों में ढील दी जाए, जबकि उसी समय यह सुनिश्चित करना होगा कि निधि शेष की कमी विवेकपूर्ण तरीके से की जा रही है। सामान्य अनुमत आहरण के साथ, यह उपाय राज्यों को 2020-21 में देय उनके बाजार उधार के लगभग 45 प्रतिशत मोचन को पूरा करने में सक्षम करेगा। आहरण मानदंडों में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगा।

उपरोक्त सभी घोषणाओं के लिए विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जाएंगे।

समापन टिप्पणी

केंद्रीय बैंकों को आमतौर पर रुढ़िवादी संस्थानों के रूप में देखा जाता है। फिर भी, जब हवा का रुख बदलता है और परिस्थितियाँ विपरित हो तब सहायता के लिए उनकी ओर ही देखता है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, अज्ञात भविष्य की गतिशीलता को संबोधित करने के लिए रिजर्व बैंक सतर्क रहना जारी रखेगा और, इस युद्ध में अपने सभी साधनों और यहां तक कि नए वाले का उपयोग करने में तत्पर होगा, जैसा कि हाल के अनुभव में दर्शाया गया है। जैसा कि मैंने पहले बताया हमारे लक्ष्य हैं, (i) वित्तीय प्रणाली और वित्तीय बाजारों को मजबूत, तरल, और सुचारू रूप से कार्य करने लायक बनाना; (ii) सभी तक वित्त की पहुंच सुनिश्चित करना, विशेष रूप से वित्तीय बाजारों से बाहर हुए लोगों के लिए; और (iii) वित्तीय स्थिरता को बनाए रखना। यह हमारा प्रयास होगा कि रिजर्व बैंक के कार्य और रुख, बेहतर कल की नींव रखने में योगदान कर सकें। आज की परीक्षा दर्दनाक हो सकती हैं, लेकिन साथ में हम जीतेंगे। धन्यवाद।

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21

मौद्रिक नीति वक्तव्य, 2020-21 मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी), भारतीय रिज़र्व बैंक का संकल्प*

मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने आज (22 मई 2020) अपनी बैठक में वर्तमान और उभरती समष्टिगत आर्थिक परिस्थिति के आकलन के आधार पर यह निर्णय लिया है कि:

- चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत नीतिगत रेपो दर को 4.40 प्रतिशत से 4.0 आधार अंक कम करके तत्काल प्रभाव से 4.0 प्रतिशत कर दिया जाए;
- तदनुसार, सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर और बैंक दर 4.65 प्रतिशत से घटकर 4.25 प्रतिशत हो गई; और
- एलएएफ के तहत प्रतिवर्ती रेपो दर 3.75 प्रतिशत से घटकर 3.35 प्रतिशत हो गई।
- यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, एमपीसी ने विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने का निर्णय लिया।

ये निर्णय वृद्धि को सहारा प्रदान करते हुए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) आधारित मुद्रास्फीति के 4 प्रतिशत के मध्यावधिक लक्ष्य को +/-2 प्रतिशत के दायरे में हासिल करने के उद्देश्य से भी है।

इस निर्णय के समर्थन में प्रमुख विवेचनों को नीचे दिए गए विवरण में वर्णित किया गया है।

आकलन

वैश्विक अर्थव्यवस्था

2. मार्च 2020 में एमपीसी की बैठक के बाद से वैश्विक आर्थिक गतिविधि में COVID-19 संबंधित लॉकडाउन और सामाजिक अलगाव की वजह से ठहराव की स्थिति बनी हुई है। 2020 की

पहली तिमाही में प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (ईई) में यूएस, यूरो क्षेत्र, जापान और यूके में आर्थिक गतिविधि संकुचित हो गयी। उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं (ईएमई) के बीच चीनी अर्थव्यवस्था में स्पष्ट गिरावट देखी गई और उच्च आवृत्ति संकेतकों के आंकड़ों से ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे ईएमई में भी गतिविधि संकुचित हो जाने की संभावनाओं का संकेत मिलता है।

3. वैश्विक वित्तीय बाजारों में मार्च में एक अशांत अवधि के बाद शांती छाई हुई है और अस्थिरता में कमी आ गयी क्योंकि तेज और बृहद राजकोषीय और मौद्रिक नीति प्रतिक्रियाओं से मनोभावों को शांत करने में मदद मिली। इक्विटी बाजारों में कुछ हानियों को पुनः वसूल कर लिया गया, जबकि सरकारी बॉन्ड प्रतिफल सीमाबद्ध रहें हालांकि देश-विशिष्ट कारकों के कारण कतिपय ईएमई में कुछ वृद्धि हुई। ईएमई में पोर्टफोलियो प्रवाह अप्रैल में पुनर्जीवित हो गए और उन्हें सुरक्षित पनाहगाह तक पहुंचने में आसानी हुई। अमेरिकी डॉलर कमजोर होने के साथ, प्रमुख ईएमई मुद्राएं, जो लगातार नीचे की ओर दबाव का अनुभव करती थीं, ने एक विकासोन्मुख दृष्टिकोण के साथ कारोबार किया। कच्चे तेल की कीमतों में मामूली वृद्धि हुई क्योंकि तेल उत्पादक देशों (ओपेक प्लस) ने उत्पादन में कटौती करने के लिए सहमति व्यक्त की और लॉकडाउन के आसन्न सहजता की उम्मीदों ने मांग में पुनरुद्धार की संभावनाओं में सुधार हुआ। सोने की कीमतें हेजिंग मांग के कारण बढ़ गई। मुख्य रूप से तेल की कीमतों में गिरावट और लॉकडाउन के बीच मांग में कमी के कारण सीपीआई मुद्रास्फीति मुख्य ईई और ईएमई में मंद रही, जबकि आपूर्ति की गड़बड़ी के कारण खाद्य मुद्रास्फीति में तेजी आई।

घरेलू अर्थव्यवस्था

4. पिछले दो महीनों में हुए लॉकडाउन से घरेलू आर्थिक गतिविधि बुरी तरह प्रभावित हुई है। उच्च आवृत्ति संकेतक मार्च 2020 से शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में मांग में गिरावट की ओर संकेत करते हैं। बिजली की खपत कम हो गई है, जबकि निवेश की गतिविधि और निजी खपत दोनों में तेज गिरावट का सामना करना पड़ा, जैसा कि मार्च में पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में गिरावट और उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं के उत्पादन में बड़ी छंटनी के रूप में दिखाई दिया। यात्री और वाणिज्यिक वाहन बिक्री, घरेलू हवाई यात्री यातायात और विदेशी पर्यटकों के

* 22 मई 2020 को जारी किया गया।

आगमन जैसे सेवा क्षेत्र की गतिविधि के उच्च आवृत्ति संकेतकों में भी मार्च में भारी संकुचन देखा गया। देश में चावल, दलहन और तिलहन की ग्रीष्म बुवाई से ही कृषि द्वारा एकमात्र उम्मीद की किरण देखी गयी, जिसमें खरीफ ऋतु के तहत बोए गए कुल क्षेत्रफल में 43.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई और रबी की फसल भरपूर होने का अंदाज रिकॉर्ड खरीद में परिलक्षित हो रहा है।

5. उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा मापी गई खुदरा मुद्रास्फीति में जनवरी में बढ़ोत्तरी के बाद मार्च 2020 में लगातार दूसरे महीने 5.8 प्रतिशत तक सुधार हुआ। यह मुख्य रूप से दिसंबर 2019 - जनवरी 2020 में खाद्य मुद्रास्फीति के दोहरे अंक से कम हो जाने के कारण था। हालांकि, अप्रैल में आपूर्ति में व्यवधानों ने राहत दी और खाद्य मुद्रास्फीति में सौम्यता को पलट दिया, जो मार्च में 7.8 प्रतिशत से बढ़कर 8.6 प्रतिशत हो गई। सब्जियां, अनाज, दूध, दाल और खाद्य तेलों और चीनी की कीमतें दबाव बिंदुओं के रूप में उभरीं¹।

6. रिजर्व बैंक अपने पारंपरिक और अपरंपरागत दोनों तरह के उपायों की श्रेणी का विस्तार करते हुए अग्र-सक्रिय चलनिधि प्रबंधन मोड में बना रहा, ताकि प्रणाली स्तरीय चलनिधि को बढ़ाया जा सके साथ ही वित्तपोषण की कमी का सामना करने वाले विशिष्ट क्षेत्रों को भी चलनिधि उपलब्ध करवाया जा सके। चलनिधि समायोजन सुविधा (एलएएफ) के तहत औसत दैनिक निवल अवशोषण के साथ प्रणालीगत चलनिधि में बहुतायत बनी रही, जो अप्रैल में ₹4.75 लाख करोड़ से बढ़कर मई 2020 (20 मई तक) में ₹5.66 लाख करोड़ हो गई। 2020-21 (20 मई तक) के दौरान, खुला बाजार परिचालन (ओएमओ) खरीद के माध्यम से ₹1,20,474 करोड़ और तीन लक्षित दीर्घवधि रेपो परिचालन (टीएलटीआरओ) नीलामी और एक टीएलटीआरओ 2.0 नीलामी के माध्यम से ₹87,891 करोड़ उपलब्ध करवाए गए। प्रतिफल वक्र में समान रूप से अधिक चलनिधि वितरित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने 'ऑपरेशन ट्विस्ट' नीलामी आयोजित की जिसमें एक साथ ही 27 अप्रैल 2020 को प्रत्येक के लिए ₹10,000 करोड़ की सरकारी प्रतिभूतियों की बिक्री और खरीद शामिल थे। इसके अलावा, रिजर्व बैंक ने राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) और

राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) के पुनर्वित्त के रूप में अब तक (21 मई 2020 तक) ₹22,334 करोड़ रुपये और तरलता की कमी को दूर करने तथा वित्तीय बाजारों को दबावरहित बनाने के लिए विशेष चलनिधि सुविधा (एसएलएफ) के माध्यम से म्यूचुअल फंड में ₹2,430 करोड़ उपलब्ध करवाए। 6 फरवरी 2020 के बाद रिजर्व बैंक ने ₹9.42 लाख करोड़ (जीडीपी का 4.6 प्रतिशत) की चलनिधि बढ़ाने के उपायों की घोषणा की है।

7. विभिन्न तरलता प्रबंधन उपायों को प्रतिबिम्बित करते हुए, घरेलू वित्तीय स्थितियों ने विभिन्न बाजार खंडों में तरलता प्रीमिया को कम करते हुए सराहनीय रूप से आसानी को प्रतिबिम्बित किया है। सरकारी प्रतिभूतियों, वाणिज्यिक पत्रों (सीपी), 91 दिन के ट्रेजरी बिल, जमा के प्रमाण पत्र (सीडी) और कॉर्पोरेट बांड पर प्रतिफल में नरमी आई है। वाणिज्यिक बैंकों के नए रुपये ऋणों पर भारित औसत ऋण दरों में अकेले मार्च 2020 में 43 बीपीएस की गिरावट आई। हालांकि क्रेडिट ग्रोथ मौन बनी हुई है, इस साल अब तक (8 मई तक) वाणिज्यिक पत्रों, बांड, डिबेंचर और कॉर्पोरेट निकायों के शेयरों में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के निवेश में 66,757 करोड़ रुपये की तेजी से वृद्धि हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 8,822 करोड़ रुपये की गिरावट आई थी। मार्च में बड़े बहिर्गमन के विपरीत अप्रैल में म्यूचुअल फंड की विभिन्न योजनाओं में शुद्ध अंतर्प्रवाह भी दर्ज किये गये हैं।

8. बाहरी क्षेत्र में, अप्रैल 2020 में भारत के वस्तु व्यापार में गिरावट आई, निर्यात और आयात में क्रमशः 60.3 प्रतिशत और 58.6 प्रतिशत (वर्ष-दर-वर्ष) की गिरावट आई। जबकि अप्रैल में आयात में सभी 30 कमोडिटी समूहों संकुचन हो गया, निर्यात में 30 समूहों में से 28 में संकुचन हुआ। अप्रैल 2020 में व्यापार घाटा क्रमिक रूप से और साल-दर-साल आधार पर - 47 महीनों में अपने निम्नतम स्तर तक - संकुचित हो गया। वित्तपोषण के पक्ष में, शुद्ध प्रत्यक्ष विदेशी निवेश अंतर्वाह मार्च 2020 में एक वर्ष पहले के 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 2.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक बढ़े। 2020-21 में अब तक (18 मई तक) इक्विटी में शुद्ध विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (एफपीआई) एक साल पहले के 0.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर 1.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया। हालांकि, ऋण खंड में, एक साल पहले के 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर के बहिर्गमन की तुलना में इसी अवधि

¹ अखिल भारतीय हेडलाइन सीपीआई को लॉकडाउन के कारण गैर-खाद्य पदार्थों में सीमित लेनदेन के मद्देनजर अप्रैल 2020 के लिए जारी नहीं किया गया था; आंकड़े केवल खाद्य और आवास समूहों के लिए जारी किए गए थे।

के दौरान 3.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर का पोर्टफोलियो बहिर्गमन हुआ। इसके विपरीत, स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग के तहत शुद्ध निवेश में इसी अवधि के दौरान 0.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हुई। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 2020-21 में अब तक 9.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर (15 मई तक) बढ़कर- 12 महीने के आयात के बराबर 487.0 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया है।

संभावनाएं

9. मुद्रास्फीति का दृष्टिकोण अत्यधिक अनिश्चित है, क्योंकि आने वाले महीनों में लॉकडाउन में क्रमिक छूट के साथ आपूर्ति व्यवस्थाओं की बहाली के साथ, अप्रैल में खाद्य मुद्रास्फीति में असामान्य उछाल में नरमी आने की उम्मीद है। सामान्य मानसून का पूर्वानुमान खाद्य मुद्रास्फीति के लिए भी अच्छा पूर्वसूचक सिद्ध हो सकता है। वर्तमान वैश्विक मांग-आपूर्ति संतुलन को देखते हुए, अंतरराष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमतों के कम रहने की संभावना है, हालांकि वे हाल ही के दबावग्रस्त स्तर से मजबूत भी हो सकती हैं। धातुओं और अन्य औद्योगिक कच्चे माल की नरम वैश्विक कीमतों से घरेलू फर्मों के लिए इनपुट लागत कम रहने की संभावना है। मांग में कमी कोर मुद्रास्फीति (खाद्य और ईंधन को छोड़कर) पर नीचे की ओर का दबाव डाल सकती है, हालांकि आपूर्ति अव्यवस्था का बने रहना निकट अवधि के दृष्टिकोण के लिए अनिश्चितता प्रदान करता है। हालांकि वित्तीय बाजारों में उतार-चढ़ाव का असर महंगाई पर पड़ सकता है। अनुकूल आधार प्रभावों के साथ संयुक्त होकर इन कारकों के प्रभावी होने से हेडलाइन मुद्रास्फीति को 2020-21 की तीसरी और चौथी तिमाही में लक्ष्य से नीचे लाने की उम्मीद है।

10. विकास के दृष्टिकोण की ओर मुड़ते हुए, विस्तारित लॉकडाउन को देखते हुए 2020-21 की पहली तिमाही में कृषि के अलावा अन्य आर्थिक गतिविधियों के दबावग्रस्त रहने की संभावना है। हालांकि लॉकडाउन को कुछ प्रतिबंधों के साथ मई के अंत तक हटाया जा सकता है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग उपायों और श्रम की अस्थायी कमी के कारण दूसरी तिमाही में भी आर्थिक गतिविधि नियंत्रित रह सकती है। आर्थिक गतिविधियों में तीसरी तिमाही में सुधार शुरू होने और चौथी तिमाही में उसके गति हासिल करने की उम्मीद है क्योंकि धीरे-धीरे आपूर्ति व्यवस्थाओं में सामान्य स्थितियां बहाल हो जाती हैं और मांग धीरे-धीरे पुनर्जीवित होती है। एक पूरे वर्ष के रूप में अभी भी

महामारी की अवधि और कब तक सोशल डिस्टेंसिंग उपायों के बने रहने की संभावना है उसके बारे में अनिश्चितता बढ़ रही है और फलस्वरूप घरेलू विकास के लिए नकारात्मक जोखिम महत्वपूर्ण बनी हुई है। दूसरी ओर, अगर महामारी को नियंत्रित किया जाता है और सोशल डिस्टेंसिंग उपायों को तेजी से चरणबद्ध तरीके से समाप्त किया जाता है तो उपरी दिशा में संवेगों को फैलाया जा सकता है।

11. एमपीसी का मानना है कि महामारी का व्यापक आर्थिक प्रभाव शुरू में प्रत्याशित से अधिक गंभीर हो रहा है और अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में तीव्र तनाव का सामना करना पड़ रहा है। आपूर्ति अवरोधों के साथ-साथ मांग के संकुचित हो जाने से आपत्ति का प्रभाव और बढ़ गया है। आर्थिक और वित्तीय गतिविधि की हानि से परे, आजीविका और स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा शुरू किए गए विभिन्न उपाय अर्थव्यवस्था पर महामारी के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए काम कर रहे हैं, वित्तीय स्थितियों को और सुविधायुक्त बनाने की आवश्यकता है। इससे सस्ती दरों पर धन के प्रवाह में आसानी होगी और जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकेगा। मुद्रास्फीति संभावनाओं के सौम्य बने रहने के साथ चूंकि लॉकडाउन से संबंधित आपूर्ति अवरोधों में सुधार हो रहा है, विकास की चिंताओं को संबोधित करने के लिए नीति अवसरों के अभी इस्तेमाल किये जाने की जरूरत है बजाय इसके कि बाद में जब गतिविधि पुनर्जीवित हो जायेगी तब हेडरूम को बनाए रखने के लिए अर्थव्यवस्था का समर्थन करने के लिए इनका प्रयोग किया जाए।

12. यह सुनिश्चित करते हुए कि मुद्रास्फीति लक्ष्य के भीतर बनी रहे, सभी सदस्यों ने नीतिगत रेपो दर में कमी और विकास को पुनर्जीवित करने और अर्थव्यवस्था पर COVID -19 के प्रभाव को कम करने के लिए जब तक आवश्यक हो निभावकारी रुख बनाए रखने के लिए वोट किया।

13. डॉ. पामी दुआ, डॉ. रविन्द्र एच. ढोलाकिया, डॉ. जनक राज, डॉ. माइकल देबब्रत पात्र और श्री शक्तिकांत दास ने नीतिगत रेपो दर में 40 बीपीएस की कमी के लिए मतदान किया, जबकि डॉ. चेतन घाटे ने 25 बीपीएस की कमी के लिए मतदान किया।

एमपीसी की बैठक के कार्यवृत्त 5 जून 2020 तक प्रकाशित किए जाएंगे।

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

विकासात्मक और विनियामकीय नीतियों से संबंधित वक्तव्य

यह वक्तव्य बाजारों और बाजार सहभागियों के कामकाज में सुधार; निर्यात और आयात को बढ़ावा देने के उपाय; COVID-19 व्यवधानों के कारण वित्तीय दबाव को कम करने के लिए ऋण सेवा पर राहत प्रदान करने और कार्यशील पूंजी तक पहुंच में सुधार; और राज्य सरकारों को हो रही वित्तीय कठिनाइयों को कम करने हेतु विभिन्न विकासात्मक और विनियामक नीति उपायों को निर्धारित करता है।

I. बाजार की कार्यप्रणाली में सुधार के उपाय

इन उपायों का उद्देश्य बाजार सहभागियों की बाधाओं को कम करने और COVID-19 संबंधी अव्यवस्थाओं से प्रभावित अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में चलनिधि प्रवाहित करना है।

1. भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) के लिए पुनर्वित्त सुविधा

भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), लघु उद्योगों की दीर्घकालिक वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। COVID-19 महामारी के कारण वित्तीय स्थिति के दबाव और बाजार से संसाधन जुटाने में कठिनाइयों के मद्देनजर, रिज़र्व बैंक ने सिडबी को उधारी/ पुनर्वित्तीकरण के लिए ₹15,000 करोड़ की विशेष पुनर्वित्त सुविधा की घोषणा की थी। इस सुविधा के अंतर्गत रिज़र्व बैंक की पॉलिसी रेपो दर पर 90 दिनों की अवधि के लिए अग्रिम उपलब्ध कराए गए थे। सिडबी को अपने परिचालन में अधिक लचीलापन प्रदान करने के लिए, इस सुविधा को 90 वें दिन के अंत से अतिरिक्त 90 दिनों की दूसरी अवधि के लिए प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

2. स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर) के तहत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) द्वारा निवेश

ऋण में एफपीआई निवेश के लिए विनियामक ढांचा पिछले कुछ वर्षों में विकसित हुआ है, जो प्रचलित समष्टि-विवेकपूर्ण ढांचे के भीतर ऐसे प्रवाह को प्रोत्साहित करने के नीतिगत उद्देश्य के अनुरूप है। मार्च 2019 में शुरू किया गया स्वैच्छिक प्रतिधारण मार्ग (वीआरआर), ऋण में दीर्घकालिक और स्थिर एफपीआई

निवेश की सुविधा देता है और लिखत चयनों के मामलों में परिचालनगत लचीलापन और कतिपय विनियामक अपेक्षाओं से छूट प्रदान करता है। इसकी शुरुआत के बाद से, वीआरआर योजना ने मजबूत निवेशक भागीदारी को विकसित किया है और इसका निवेश, योजना के तहत आवंटित सीमा से 90 प्रतिशत अधिक है। COVID-19 से संबंधित व्यवधानों के कारण एफपीआई और उनके संरक्षकों द्वारा आवंटित सीमा का कम से कम 75 प्रतिशत निवेश तीन महीने के भीतर किया जाना चाहिए, इस शर्त का पालन करने में व्यक्त की गई कठिनाइयों को देखते हुए, यह निर्णय किया गया है कि एफपीआई को इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए तीन महीने का अतिरिक्त समय दिया जाए। विस्तृत दिशानिर्देश अलग से जारी किए जा रहे हैं।

II. निर्यात और आयात को बढ़ाने के उपाय

COVID-19 के प्रकोप और इसके तेजी से फैलने के कारण वैश्विक गतिविधि और व्यापार में संकुचन गहराई से बढ़ा है, जिसने बाहरी मांग को समाप्त कर दिया है। फलस्वरूप, भारत के निर्यात और आयात दोनों प्रभावित हुए और हाल के महीनों में दोनों में तेजी से संकुचन हुआ है। विदेशी मुद्रा अर्जित करने तथा आय और रोजगार प्रदान करने में निर्यात; और कच्चे माल, मध्यवर्ती, तैयार माल और प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं को पूरा करने में आयात के महत्व को देखते हुए, विदेशी व्यापार क्षेत्र को बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

3. निर्यात ऋण

निर्यातकों को वास्तविक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसे कि ऑर्डर का विलंब / स्थगित होना और बिलों के वसूली में देरी, जिससे उनके उत्पादन और वसूली चक्रों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसी संदर्भ में रिज़र्व बैंक ने 31 जुलाई 2020 तक या उससे पहले किए गए निर्यात के संबंध में निर्यात की तारीख से नौ महीने से 15 महीने तक भारत में निर्यात आय की वसूली और प्रत्यावर्तन की अवधि में वृद्धि की अनुमति दी। अब 31 जुलाई 2020 तक किए गए संवितरण के लिए, बैंकों द्वारा स्वीकृत प्री-शिपमेंट और पोस्ट-शिपमेंट निर्यात ऋण की अधिकतम अनुमत अवधि को वर्तमान एक वर्ष से 15 माह तक बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

4. भारतीय आयात-निर्यात बैंक के लिए चलनिधि की सुविधा

भारतीय आयात-निर्यात बैंक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से निर्यातकों और आयातकों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। COVID-19 महामारी के कारण, हालांकि, वैश्विक व्यापार में तेजी से संकुचन हुआ है और वैश्विक वित्तीय बाजारों को अत्यधिक अस्थिरता और जोखिम का सामना करना पड़ा है, विशेषकर ईएमई को। चूंकि एक्विजम बैंक अपने परिचालनों के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजारों से उठाए गए विदेशी मुद्रा संसाधनों पर मुख्य रूप से निर्भर करता है, यह अंतर्राष्ट्रीय ऋण पूंजी बाजार में धन जुटाने के लिए चुनौतियों का सामना कर रहा है। तदनुसार, यह निर्णय किया गया कि एक्विजम बैंक को सुविधा का लाभ उठाने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के लिए एक वर्ष के अधिकतम रोलओवर के साथ रु.15,000 करोड़ रुपये की क्रेडिट लाइन प्रदान की जाए, ताकि वह अपनी विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अमेरिकी डॉलर स्वैप सुविधा का लाभ उठा सके।

5. आयात के भुगतान के लिए समय-सीमा में विस्तार

सीमा पार व्यापार को COVID-19 संबंधी व्यवधानों से विनिर्माण / तैयार उत्पादों की बिक्री में मंदी आ गई, और घरेलू और विदेशी दोनों तरह की बिक्री आय की वसूली में विलंब हुआ। इसके परिणामस्वरूप, कारोबारी संस्थाओं के लिए परिचालन चक्र को लंबा कर दिया है। इस स्थिति में, यूनितों को विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत निर्धारित समय के भीतर अपने आयात के लिए भुगतान करना मुश्किल लग रहा है। वर्तमान में, भारत में सामान्य आयात के लिए प्रेषण (सोने/ हीरे और बहुमूल्य पत्थरों/आभूषणों के आयात को छोड़कर) को विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा शिपमेंट की तारीख से छह महीने की अवधि के भीतर पूरा करने की आवश्यकता होती है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोक दी जाती है। भारत में सामान्य आयात के लिए प्रेषण की समय सीमा (उन मामलों को छोड़कर जहां कार्यनिष्पादन की गारंटी के लिए राशि रोक दी जाती है) 31 जुलाई 2020 तक या उससे पहले किए गए इस तरह के आयात के लिए शिपमेंट की तारीख से छह महीने से बारह महीने तक बढ़ाने का निर्णय किया

गया है। COVID-19 के माहौल में यह उपाय आयातकों को उनके परिचालन चक्रों का प्रबंधन करने के लिए अधिक लचीलापन प्रदान करेगा।

III. वित्तीय दबाव कम करने के उपाय

COVID-19 व्यवधानों की तीव्रता ने पुनर्भुगतान के दबाव को कम करने और ऋण सेवा के बोझ को कम करके कार्यशील पूंजी तक पहुंच सुधारने, वास्तविक अर्थव्यवस्था में वित्तीय दबाव के प्रसारण को रोकने, और व्यवहार्य कारोबारों और परिवारों की निरंतरता सुनिश्चित करने को प्राथमिकता दी है।

6. सावधि ऋण किस्तों पर अधिस्थगन

27 मार्च 2020 को, रिजर्व बैंक ने सभी वाणिज्यिक बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, लघु वित्त बैंकों और स्थानीय क्षेत्र बैंकों सहित), सहकारी बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों और एनबीएफसी (आवास वित्त कंपनियों और सूक्ष्म-वित्त संस्थानों सहित) (जिसे इसके बाद “उधार ऋण देने वाली संस्थाओं” के रूप में संदर्भित किया गया है) को 1 मार्च 2020 तक बकाया सभी मीयादी ऋणों के संबंध में किस्तों के भुगतान पर तीन महीने का अधिस्थगन प्रदान करने की अनुमति दी। COVID-19 के कारण निरंतर व्यवधानों और लॉकडाउन बढ़ने के मद्देनजर, उधार देने वाली संस्थाओं को मीयादी ऋण किस्तों पर अधिस्थगन अवधि को तीन महीने अर्थात् 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक बढ़ाने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है। तदनुसार, पुनर्भुगतान अनुसूची और बाद की सभी देय तारीखें, इस तरह के ऋणों के लिए अवधि के साथ अगले तीन महीने तक बढ़ाई जा सकती हैं।

7. कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का आस्थगन

नकद ऋण / ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को 1 जून 2020 से 31 अगस्त 2020 तक, और तीन महीनों के लिए आस्थगन देने की अनुमति दी जा रही है। यह 1 मार्च 2020 तक बकाया ऐसी सभी सुविधाओं के संबंध में ब्याज के भुगतान पर 27 मार्च 2020 को तीन महीने की दी गई अनुमति के अलावा है।

8. आस्थगन अवधि के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर ब्याज का भुगतान

कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर आस्थगित अवधि के लिए संचित ब्याज को एकबारगी चुकाने में उधारकर्ताओं को होने वाली कठिनाइयों को सुधारने के लिए, उधार देने वाली संस्थाओं को आस्थगन अवधि (31 अगस्त 2020 तक) के लिए कार्यशील पूंजी सुविधाओं पर जमा ब्याज को एक वित्तपोषित ब्याज मीयादी ऋण में परिवर्तित करने की अनुमति प्रदान की गई है जिसे चालू वित्त वर्ष (अर्थात 31 मार्च 2021) के अंत से पहले चुकाना होगा।

तदनुसार, उधार देने वाली संस्थाएं पैरा 6, 7, 8 में घोषित उपायों को लागू करने के लिए एक बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को लागू कर सकते हैं।

9. आस्ति वर्गीकरण

- (i) चूंकि COVID-19 व्यवधानों से उधारकर्ताओं को उबारने के लिए विशेष रूप से ऋणस्थगन/अधिस्थगन प्रदान किया जा रहा है, इसलिए इसे उधारकर्ताओं की वित्तीय कठिनाई के कारण ऋण करारों के नियमों और शर्तों में परिवर्तन के रूप में नहीं माना जाएगा और, परिणामस्वरूप, इससे आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं होगी।
- (ii) पहले की तरह, ऋणस्थगन/अधिस्थगन के कारण भुगतानों का पुनर्निर्धारण, पर्यवेक्षी रिपोर्टिंग और उधार देने वाली संस्थानों द्वारा क्रेडिट सूचना कंपनियों (सीआईसी) को रिपोर्टिंग के प्रयोजनों के लिए एक डिफॉल्ट के रूप में अर्हता प्राप्त नहीं करेगा। सीआईसी यह सुनिश्चित करेगी कि आज की गई घोषणाओं के अनुसरण में ऋण संस्थानों द्वारा की गई कार्रवाई से उधारकर्ताओं के क्रेडिट इतिहास पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े।
- (iii) उन सभी खातों के संबंध में, जिनके लिए उधार देने वाली संस्थाएं ऋणस्थगन/अधिस्थगन देने का निर्णय करती हैं, और जो 1 मार्च 2020 तक मानक थे, उन पर 90-दिवसीय एनपीए मानदंड के अनुसार विस्तारित ऋणस्थगन/अधिस्थगन नहीं होगा। परिणामस्वरूप, 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक ऋणस्थगन/अधिस्थगन अवधि के दौरान

ऐसे सभी खातों के लिए एक परिसंपत्ति वर्गीकरण ठहराव होगा। इसके बाद, सामान्य मानदंड लागू होंगे।

- (iv) एनबीएफसी, जिन्हें भारतीय लेखा मानकों (IndAS) का अनुपालन करना आवश्यक है, वे अपने बोर्डों द्वारा अनुमोदित दिशानिर्देशों तथा कमियों को पहचानने में भारतीय सनदी लेखकार संस्थान (आईसीएआई) के परामर्शों का पालन कर सकते हैं। इस प्रकार, एनबीएफसी के पास अपने उधारकर्ताओं को इस तरह की राहत देने के लिए निर्धारित लेखांकन मानकों के तहत लचीलापन है।

10. कार्यशील पूंजी वित्तपोषण को सुगम बनाना

- (i) नकद ऋण/ओवरड्राफ्ट के रूप में स्वीकृत कार्यशील पूंजी सुविधाओं के संबंध में, उधार देने वाली संस्थाओं को विस्तारित अवधि अर्थात, 31 अगस्त, 2020 तक मार्जिन को कम करके 'ड्राइंग पावर' की पुनः गणना करने की अनुमति है। उधारकर्ताओं के लिए प्रभाव को सुचारू करने के लिए, उधार देने वाले संस्थानों को 31 मार्च 2021 तक मूल स्तर तक मार्जिन को बहाल करने की अनुमति है।
- (ii) इसके अलावा, उधार देने वाली संस्थाओं को 31 मार्च, 2021 तक एक विस्तारित अवधि तक एक उधार लेने वाली इकाई के कार्यशील पूंजी चक्र को पुनः निर्धारित करने की अनुमति है। यह ऋणदाताओं को संबंधित इकाई पर महामारी के प्रभाव के बारे में सूचित मूल्यांकन करने के लिए आवश्यक मार्ग प्रदान करेगा।
- (iii) दिनांक 7 जून 2019 के भारतीय रिजर्व बैंक (दबावग्रस्त आस्तियों के संकल्प हेतु विवेकपूर्ण ढांचा) निदेश, 2019 ('विवेकपूर्ण ढांचा') के अनुबंध के पैराग्राफ 2 के अंतर्गत उधारकर्ताओं को विशेष रूप से COVID-19 के नतीजों से उबरने के लिए ऋण शर्तों में किए गए ऐसे बदलाव को, उधारकर्ता की वित्तीय कठिनाई के कारण दी गई रियायतों के रूप में नहीं माना जाएगा, और इसके परिणामस्वरूप, आस्ति वर्गीकरण में गिरावट नहीं आएगी।

11. संकल्प समय में विस्तार

विवेकपूर्ण ढांचे के अंतर्गत, उधारदाता संस्थानों को चूक (डिफॉल्ट) के तहत बड़े खातों के मामले में 20 प्रतिशत का

अतिरिक्त प्रावधान रखने की आवश्यकता होती है, यदि इस तरह की चूक की तारीख से 210 दिनों के भीतर एक संकल्प योजना लागू नहीं की गई हो। दबावग्रस्त आस्तियों के समाधान के लिए निरंतर चुनौतियों को देखते हुए, यदि 1 मार्च 2020 तक समीक्षा / संकल्प अवधि समाप्त नहीं हुई हो तो, ऋण संस्थानों को 1 मार्च 2020 से 31 अगस्त 2020 तक की 30 दिनों की समीक्षा अवधि या 180-दिवसीय संकल्प अवधि की गणना से संपूर्ण ऋणस्थगन/अधिस्थगन अवधि को निकाल देने की अनुमति है।

12. बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के तहत गुप एक्सपोजर पर सीमा

बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क पर मौजूदा दिशा-निर्देशों के तहत, जुड़े हुए समकक्षों के समूह की तुलना में बैंक का एक्सपोजर हर समय बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। COVID-19 महामारी के कारण, ऋण बाजार और अन्य पूंजी बाजार खंडों में अनिश्चितता देखी जा रही है। परिणामस्वरूप, कई कॉरपोरेट्स को पूंजी बाजार से धन जुटाने में कठिनाई हो रही है और वे मुख्य रूप से बैंकों से वित्त पोषण पर निर्भर हैं। कॉरपोरेट्स को संसाधनों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से, एकबारगी उपाय के रूप में यह निर्णय लिया गया है कि जुड़े हुए समकक्षों के समूह की तुलना में बैंक के एक्सपोजर को बैंक के पात्र पूंजी आधार के 25 प्रतिशत से 30 प्रतिशत तक बढ़ाया जाए। बढ़ी हुई सीमा 30 जून 2021 तक लागू रहेगी।

IV. ऋण प्रबंधन

13. राज्य सरकारों की समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) - दिशानिर्देशों में छूट

राज्य सरकारें अपनी देयताओं को चुकाने के लिए एक बफर के रूप में रिजर्व बैंक के साथ एक समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ) को बनाए रखती हैं। Covid-19 महामारी और राज्य सरकार के वित्त पर परिणामी तनाव के मद्देनजर, आरबीआई ने इस योजना की समीक्षा की है और सीएसएफ से आहरण नियंत्रित करने वाले नियमों को शिथिल करने का निर्णय लिया है, साथ ही यह सुनिश्चित करते हुए कि निधि शेष की कमी को विवेकपूर्ण तरीके से पूरा किया जा रहा है। यह राज्यों को सीएसएफ से चालू वित्त वर्ष में देय होने वाले उनके बाजार ऋणों के मोचन के एक बड़े हिस्से को पूरा करने में सक्षम करेगा। राज्यों को दी जानेवाली ऐसी छूट के लिए लगभग रु. 13,300 करोड़ की अतिरिक्त राशि जारी की जाएगी। सामान्य रूप से अनुमत आहरण को मिलाकर, यह उपाय राज्यों को सीएसएफ से आहरण के माध्यम से 2020-21 में उनके देय मोचन का लगभग 45 प्रतिशत पूरा करने में सक्षम करेगा। आहरण मानदंडों में यह बदलाव तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 31 मार्च 2021 तक मान्य रहेगा।

COVID-19 के जवाब में, राजकोषीय संसाधनों की आवश्यकता, बाजार की स्थितियों के आगे बढ़ने के संभावित प्रभाव से बढ़ी है। रिजर्व बैंक सतर्क रहेगा और न्यूनतम विघटनकारी तरीके से केंद्र और राज्यों के उधार कार्यक्रम को सुगमता से पूरा करने में सहयोग करेगा।

लेख

हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के तिमाही अनुमान

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े मुद्दे

एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति:
मुद्दे और नीति विकल्प

केंद्र सरकार के वित्त 2019-20 का अनंतिम लेखा: एक आकलन

हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और देयताओं के तिमाही अनुमान *

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों को वित्तीय संसाधनों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता हाउसहोल्ड्स होते हैं। इसीलिए, वित्तीय आस्तियों और हाउसहोल्ड्स की देनदारियों में उतार-चढ़ाव के अध्ययन से भारतीय अर्थव्यवस्था में विकास की गति को समझा जा सकता है। यह लेख इस दिशा में मार्च 2018 में किए गए शुरुआती प्रयास को अद्यतन करता है और मार्च 2020 से पहले की सभी बारह तिमाहियों के लिए हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के बारे में उपलब्ध जानकारी को समेकित करता है। दोनों हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियाँ और देनदारियाँ मुख्यतः बैंक केंद्रित रही हैं, परंतु हाल की तिमाहियों में म्यूचुअल फंड और बीमा की ओर भी कुछ रुझान देखा गया है।

परिचय

भारत में, हाउसहोल्ड्स क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल बचत का लगभग 60 प्रतिशत योगदान देता है, और इस प्रकार सकल निवेश के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रमुख आपूर्तिकर्ता बना हुआ है।

हाउसहोल्ड्स बचत के वार्षिक आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय (एनएसओ) द्वारा प्रकाशित किए जाते हैं और 31 जनवरी, 2020¹ को जारी किए गए नवीनतम वार्षिक अनुमान यह दर्शाता है कि हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की वित्तीय बचत 2016-17 में जीडीपी के 7.4 प्रतिशत और 2017-18 के 7.7 प्रतिशत से घटकर 2018-19 में 6.5 प्रतिशत रह गयी। वर्ष 2019-20 के लिए डेटा 29 जनवरी 2021 को उपलब्ध होगा।

हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के बारे में वार्षिक जानकारी आरबीआई बुलेटिन² के जुलाई 2019 के अंक में प्रकाशित की गई थी, जो लिखतवार 'किससे किसको' आधार पर तैयार की गयी थी। इस आलेख में पहली बार, मार्च 2020 तक के तिमाही आंकड़े उपलब्ध कराए गए हैं जिससे

* आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक के राष्ट्रीय लेखा विश्लेषण प्रभाग के अनुपम प्रकाश, आनंद प्रकाश एक्का, कुणाल प्रियदर्शी, चैताली भौमिक और ईशु ठाकुर। आंकड़े जुटाने में शालिनी जैन द्वारा भी सहायता प्रदान की गयी। लेख में व्यक्त विचार लेखकों के निजी विचार हैं और वे रिजर्व बैंक के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व नहीं करते।

¹ राष्ट्रीय आय, उपभोग व्यय, बचत और पूंजी निर्माण का पहला संशोधित अनुमान (एफआरई)।

² भारतीय अर्थव्यवस्था का वित्तीय स्टॉक और फ्लो लेखा: 2011-12 से 2017-18।

हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की वित्तीय बचत के आधिकारिक वार्षिक अनुमानों की उपलब्धता में मौजूद 10 महीनों के अंतराल को भरा जा सका है। अतिव्यापन (ओवरलैप) की अवधि - 2017-18 की पहली और दूसरी तिमाही - से संबंधित डाटा नवीनतम उपलब्ध जानकारी को शामिल करते हुए संशोधित किया गया है। इसे जारी करते हुए, भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जो तिमाही आधार पर हाउसहोल्ड्स बचत को प्रकाशित करते हैं।

शेष आलेख को तीन भागों में विभाजित किया गया है। भाग II में समग्र स्तर पर हाउसहोल्ड्स क्षेत्र की तिमाही वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के अनुमानों पर चर्चा की गई है। भाग III वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के लिखतवार संघटन की जांच करता है। भाग IV में निष्कर्षात्मक टिप्पणियाँ की गयी हैं। अनुलग्नक में इसकी कार्यप्रणाली, डेटा के स्रोत / सीमाएँ और हाउसहोल्ड्स वित्तीय आस्तियों और देनदारियों के लिखतवार अनुमानों को सारणीबद्ध रूप में दिया गया है।

II. हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ

2018-19⁴ में भारतीय हाउसहोल्ड्स की शुद्ध वित्तीय आस्तियाँ थोड़ी कम हुईं जिससे यह संकेत मिलता है कि हाउसहोल्ड्स ने उपभोग पर अधिक खर्च किया है। हालांकि, 2019-20 में, आस्तियों में तेजी से वृद्धि होने लगी है और उन्होंने 2017-18 में प्राप्त स्तर, अर्थात् जीडीपी का 7.7 प्रतिशत, तक पहुंचने लगी हैं (सारणी 1)। यह सुधार इसलिए हो सका क्योंकि हाउसहोल्ड्स की बैंक जमाओं की तुलना में बैंक उधारी में आयी गिरावट की गति तेज रही है यद्यपि कोविड-19 के कारण आर्थिक व्यवधानों के चलते 2019-20 की चौथी तिमाही में ऐसा नहीं हो सका।

तिमाही आंकड़े इस क्षेत्र से संसाधनों के प्रवाह में बड़े उतार-चढ़ाव को भी प्रकट करते हैं जो कि वार्षिक आंकड़ों में देखने को नहीं मिलता (चार्ट 1)।

हाउसहोल्ड्स की सकल वित्तीय देनदारियाँ 2019-20 की पहली तिमाही में ऋणात्मक स्तर पर पहुंच गयीं जिसका प्रमुख कारण था वाणिज्यिक बैंकों से उधारियों में आयी कमी; परंतु उसके बाद इसमें तेजी आयी और 2019-20 की चौथी तिमाही में

³ ओईसीडी स्टैट केवल 19 देशों के लिए हाउसहोल्ड वित्तीय बचत डेटा रिपोर्ट करता है।

⁴ एनएसओ द्वारा वर्ष 2018-19 के लिए हाउसहोल्ड वित्तीय बचत जीडीपी का 6.5% दर्शायी गयी थी जो अब भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) द्वारा प्रकाशित जीवन बीमा पॉलिसियों के अद्यतन डाटा तथा केंद्रीय बजट 2020-21 में प्रकाशित लघु बचत आंकड़ों के आधार पर जीडीपी का 7.2% प्रतिशत उठरती है।

सारणी1: हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियाँ और देयताएँ

(राशि ₹ लाख करोड़ में)

मद	2017-18					2018-19					2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
निवल वित्तीय आस्तियाँ (ए-बी)	2.78 (6.9)	3.59 (8.6)	2.48 (5.7)	4.45 (9.7)	13.29 (7.7)	2.76 (6.1)	2.29 (4.9)	2.13 (4.4)	6.56 (13.2)	13.73 (7.2)	3.48 (7.1)	3.68 (7.5)	3.36 (6.5)	5.09 (9.6)	15.62 (7.7)
ए: सकल वित्तीय आस्तियाँ	3.85 (9.6)	5.77 (13.8)	3.42 (7.9)	7.56 (16.5)	20.60 (12.0)	3.58 (7.9)	4.82 (10.4)	3.52 (7.3)	9.31 (18.8)	21.23 (11.1)	3.31 (6.7)	5.06 (10.3)	5.52 (10.7)	7.73 (14.5)	21.63 (10.6)
बी: वित्तीय देयताएँ	1.08 (2.7)	2.18 (5.2)	0.94 (2.2)	3.11 (6.8)	7.31 (4.2)	0.83 (1.8)	2.53 (5.5)	1.38 (2.9)	2.75 (5.6)	7.50 (3.9)	-0.18 (-0.4)	1.38 (2.8)	2.16 (4.2)	2.64 (5.0)	6.01 (2.9)

टिप्पणी: (i) कोष्ठक में आंकड़ों को जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया गया है।

(ii) मार्च 2018 के आरबीआई बुलेटिन में वर्ष 2017-18 की पहली और दूसरी तिमाही के लिए प्रकाशित आंकड़ों को संशोधित किया गया है।

स्रोत: स्टाफ द्वारा की गयी गणना।

ये अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गयीं जिससे मौसमी उछाल के साथ-साथ कोविड-19 जनित कठिनाइयों के कारण अपेक्षाकृत अधिक उधारियों का संकेत मिलता है। कई अध्ययन यह दर्शाते हैं कि जब भी आर्थिक मंदी होती है और आय की अनिश्चितता बढ़ जाती है, तब हाउसहोल्ड्स की बचत करने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है [मूडी और अन्य, 2012; चक्रवर्ती और अन्य, 2011; नामियस, 2010; लेवानोन एण्ड फ्रेंको, 2011]।

III. हाउसहोल्ड्स की वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का लिखतवार संविभाग

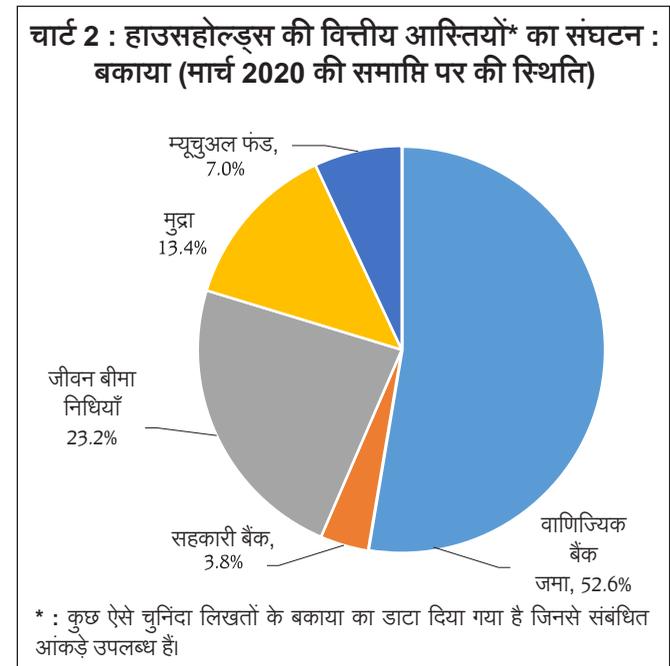
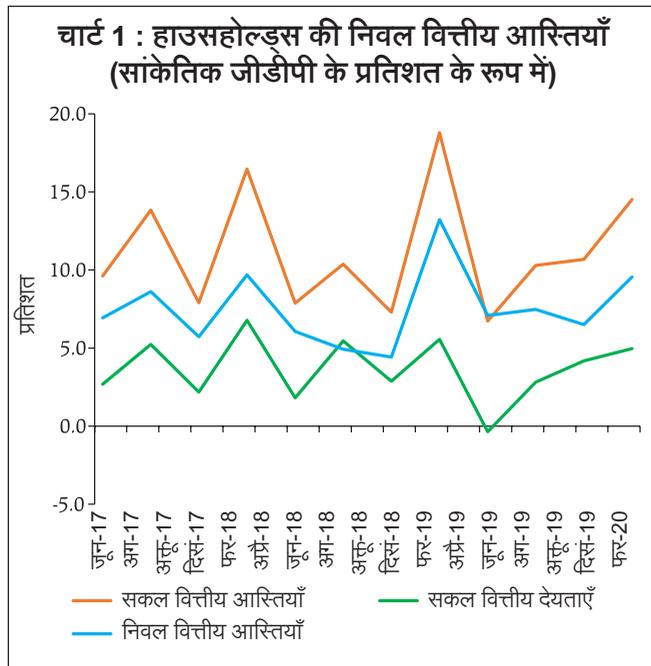
हाउसहोल्ड्स अपनी वित्तीय आस्तियों और देनदारियों का आबंटन भिन्न-भिन्न स्तर की तरलता और जोखिमों वाले विभिन्न लिखतों में करते हैं। वित्तीय आस्तियाँ मुद्रा, बैंक जमा,

कर्ज प्रतिभूतियों, म्यूचुअल फंडों, बीमा, पेंशन फंडों और छोटी बचतों के रूप में धारित की जाती हैं। वित्तीय देनदारियाँ मुख्यतया बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) से लिए गए ऋण और उधारियों के रूप में होती हैं।

III.1 हाउसहोल्ड आस्तियाँ

अधिकांश वित्तीय आस्तियाँ (66 प्रतिशत) बैंकों के पास मौजूद मुद्रा और जमा के रूप में होती हैं और इनके बाद बीमा निधियों और म्यूचुअल फंड का स्थान आता है (चार्ट 2)।

मुद्रा, वाणिज्यिक बैंक जमा, सहकारी बैंक जमा, जीवन बीमा निधि और म्यूचुअल फंड जैसे कुछ चुनिंदा लिखतों के संदर्भ में



हाउसहोल्ड्स की बकाया वित्तीय आस्तियों के संघटन की प्रवृत्ति से हमें कुछ दिलचस्प जानकारी प्राप्त होती है (अनुलग्नक II; सारणी 3)। बैंकों के पास जमा, जिसमें 2016-17 की तीसरी तिमाही से लगातार गिरावट आ रही थी, उसमें 2018-19 की चौथी तिमाही से वृद्धि दर्ज की गयी क्योंकि बैंकों, विशेष रूप से निजी बैंकों में संसाधन जुटाने के लिए तीव्र प्रतिस्पर्धा होने लगी (आरबीआई, 2019 ए)। बीमा और म्यूचुअल फंड उत्पादों में लगातार हो रही वृद्धि से वैकल्पिक वित्तीय साधनों की बढ़ती खपत का संकेत मिला। कुल बकाया आस्तियों में मुद्रा की हिस्सेदारी मोटे तौर पर स्थिर बनी हुई है।

कम से कम दो वित्तीय आस्तियों यथा बैंक जमा और मुद्रा में स्पष्ट मौसमी पैटर्न देखा जा सकता है (चार्ट 3)। पहली तिमाही में बैंकिंग प्रणाली में जमा में आम तौर पर कमी आती है और वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में यह बढ़ जाता है जबकि हाउसहोल्ड्स की मुद्रा धारिता पहली तिमाही में चरम पर होती है और दूसरी तिमाही में इसमें कमी आती है। वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में बैंक प्रायः अपनी ऋण सुपुर्दगी और जमा संग्रहण बढ़ा देते हैं अर्थात् वे वर्षांत के लक्ष्यों⁶ को प्राप्त करने और अपने आस्ति

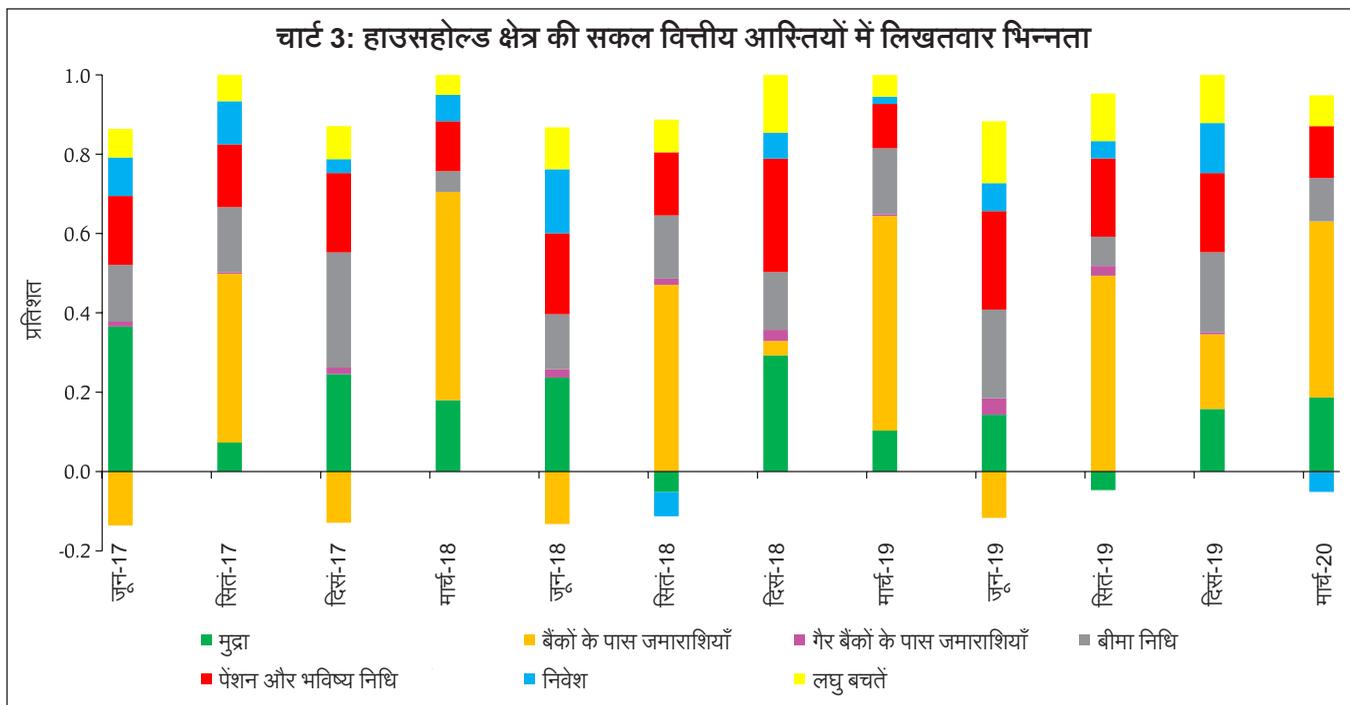
गुणवत्ता संकेतकों में सुधार लाने के लिए कुछ विंडो ड्रेसिंग⁵ भी करते हैं (आरबीआई, 2013 बी; राजपाठक, 2019)।

मुद्रा पैटर्न त्योहारों, रबी की खरीद और खरीफ की बुआई और पर्यटन संबंधी मांग से जुड़े हैं (आरबीआई, 2019 सी)। बीमा उत्पादों में भी मध्यम दर्जे का मौसमी रुझान देखा जाता है - आय में कटौती प्राप्त करने के लिए चौथी तिमाही में मांग सबसे अधिक हो जाती है।

III.2 हाउसहोल्ड्स की देनदारियाँ

हाउसहोल्ड्स की वित्तीय देनदारियों में सबसे अधिक हिस्सेदारी वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए उधार की है। 2019-20 की चौथी तिमाही के अंत में, हाउसहोल्ड्स की कुल वित्तीय देनदारियों का अधिकांश (75.9 प्रतिशत) भाग उनके द्वारा वाणिज्यिक बैंकों से लिए गए बकाया ऋणों का था और उनके बाद क्रमशः एचएफसी, एनबीएफसी, सहकारी बैंकों और क्रेडिट सोसाइटियों का हिस्सा था (चार्ट 4)।

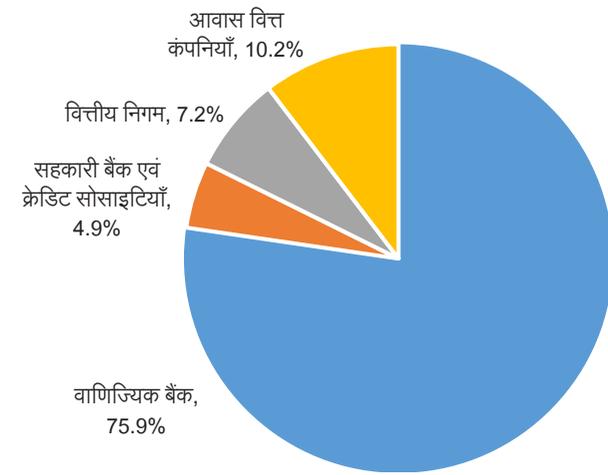
वित्तीय देनदारियों का अधिग्रहण भी एक मौसमी पैटर्न को प्रकट करता है; वे आम तौर पर चौथी तिमाही के दौरान चरम पर होते हैं और फिर पहली तिमाही में कम हो जाते हैं जो कि



⁵ भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा 18 नवंबर 2019 के आदेश के माध्यम से इंडियन बैंक पर ₹1 करोड़ का मौद्रिक जुर्माना लगाया क्योंकि उन्होंने आरबीआई द्वारा बैलेंस शीट की विंडो-ड्रेसिंग और वर्गीकरण तथा धोखाधड़ी के रिपोर्टिंग पर जारी दिशानिर्देशों (आरबीआई, 2019 डी) का अनुपालन नहीं किया था।

⁶ हालांकि एससीबी के लिए कोई क्रेडिट लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं, बहुत से बैंक अपनी वार्षिक रिपोर्टों में अपने आंतरिक क्रेडिट वृद्धि लक्ष्य का उल्लेख करते हैं।

चार्ट 4: हाउसहोल्ड्स की वित्तीय देनदारियों* का संघटन: बकाया (मार्च 2020 की समाप्ति पर की स्थिति)



*: डाटा की अनुपलब्धता के कारण बकाया के आंकड़े केवल चुनिंदा क्षेत्रों के लिए दिए गए हैं।

मोटे तौर पर बैंकिंग क्षेत्र द्वारा ऋणों के संवितरण में मौजूद मौसमी प्रभाव का ही परिणाम होता है जैसा कि पिछले भाग में बताया गया है।

हाउसहोल्ड्स द्वारा एनबीएफसी से लिए गए उधार, जिसमें इन्फ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (IL & FS) के संकट के कारण उत्पन्न चलनिधि के दबाव के कारण

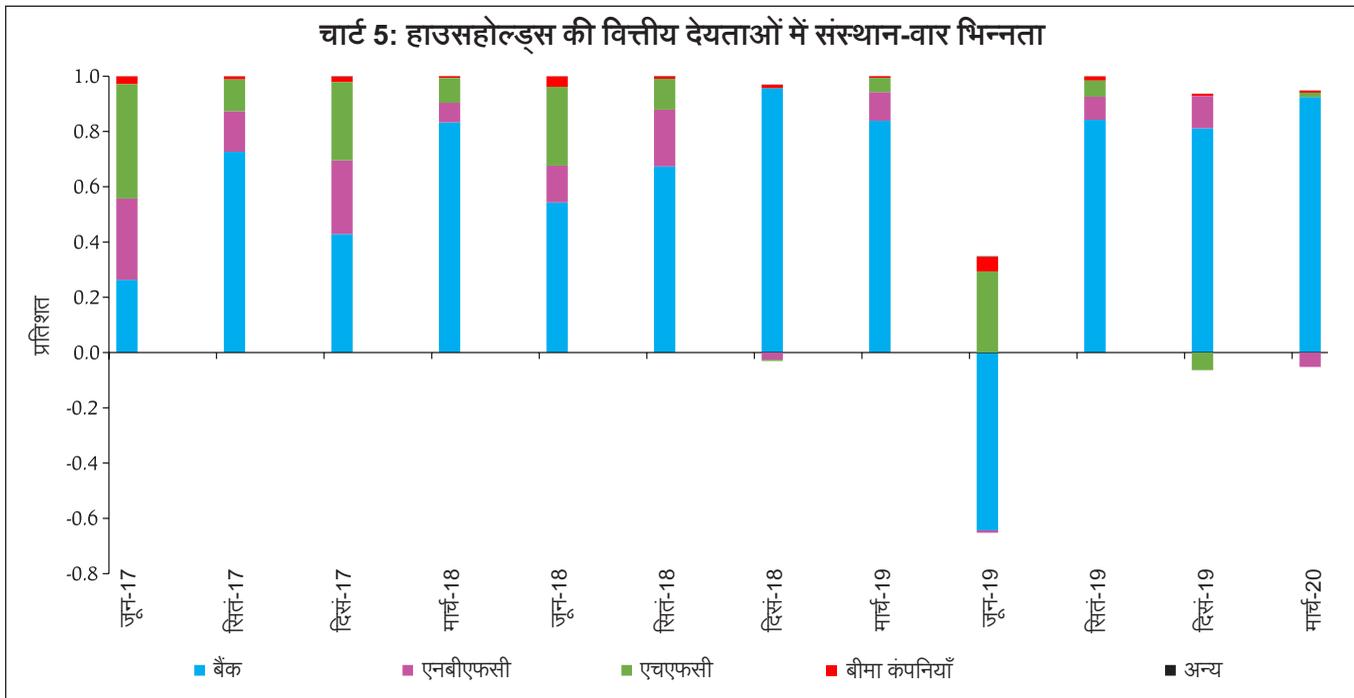
2018-19 की तीसरी तिमाही के दौरान गिरावट आ गयी थी, उसमें बाद की तिमाहियों में बहाली आयी (चार्ट 5)। एचएफसी से लिए जाने वाले ऋणों में 2019-20 की तीसरी तिमाही के दौरान आयी कमी से रीयल एस्टेट में घटती मांग का संकेत मिलता है, जो रीयल एस्टेट की बिक्री में आयी कमी से भी स्पष्ट है।

बैंक क्रेडिट के रूप में देनदारियों का अधिग्रहण 2019-20 की पहली तिमाही में कम होकर जीडीपी के 1.5 प्रतिशत तक रह गया हालांकि इस वर्ष की बाद की तिमाहियों में इसमें तेजी आयी। ऐसा प्रतीत होता है कि अर्थव्यवस्था में आ रही मंदी के माहौल में आय में वृद्धि से जुड़ी भावी अनिश्चितताओं तथा बैंकों में आस्ति-गुणवत्ता बनाए रखने की चिंता से उपजी जोखिम विमुखता की प्रवृत्ति के कारण 2019-20 की पहली तिमाही में हाउसहोल्ड्स द्वारा बैंकिंग क्षेत्र से लिए गए उधार में मौसमी कारकों की वजह से आ रहा संकुचन और तीव्र हो गया है।

IV. निष्कर्ष

हाउसहोल्ड्स क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था के वित्तपोषण का सबसे स्थायी और आत्मनिर्भर स्रोत है। भारतीय अर्थव्यवस्था को मंदी की चपेट में आने से रोकने और हाल ही में जानलेवा कोविड-19 महामारी की चपेट में आयी भारतीय अर्थव्यवस्था को उबारने की दिशा में किए जा रहे नीतिगत प्रयासों के संदर्भ में इसकी भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाने की संभावना है।

चार्ट 5: हाउसहोल्ड्स की वित्तीय देयताओं में संस्थान-वार भिन्नता



हाउसहोल्ड्स अभी भी ऋणों के लिए तथा अपने अधिशेष के निवेश हेतु ज्यादातर बैंकिंग क्षेत्र पर ही निर्भर करते हैं, हालांकि उनकी वित्तीय आस्तियों में बैंक जमा की हिस्सेदारी में एकसमान गिरावट आयी है। हालिया बदलाव यह हुआ है कि म्यूचुअल फंड और बीमा में उनकी आस्तियाँ बढ़ने लगी हैं। देनदारियों की बात करें तो, 2019-20 के दौरान कुल देनदारियों में बैंकिंग क्षेत्र से लिए गए उधार की हिस्सेदारी में उल्लेखनीय गिरावट से अर्थव्यवस्था में चल रही मंदी और बैंकों की जोखिम विमुखता का संकेत मिला। कोविड -19 के कारण उत्पन्न अनिश्चितताओं के परिणामस्वरूप, म्यूचुअल फंडों से बहिर्वाह और मुद्रा धारण में वृद्धि देखी गयी है।

भविष्य की बात करें तो, 2020-21 की पहली तिमाही में लॉकडाउन के कारण खपत में आयी तीव्र गिरावट के कारण हाउसहोल्ड्स की निवल वित्तीय आस्तियाँ तेजी से बढ़ने की संभावना है। आर्थिक गतिविधि के फिर से रफ्तार पकड़ने में होने वाले विलंब के कारण हाउसहोल्ड्स का वित्तीय अधिशेष बाद की तिमाहियों में कम हो सकता है। निर्माण गतिविधियाँ थम जाने के कारण यह संभावना जतायी जा रही है कि हाउसहोल्ड्स अपनी भौतिक आस्तियों को वित्तीय आस्तियों में बदलेंगे।

संदर्भ:

Chakrabarti, Rajashri, Donghoon Lee, Wilbert van der Klaauw, and Basit Zafar (2011), "Household Debt and Saving During The 2007 Recession", *NBER Working Paper Series*, National Bureau of Economic Research, April 2011.

Das, M. R. (2012), "Window-dressing of Deposits By Banks: Some Truths", *Business Standard*, September 13, 2012. <https://www.thehindubusinessline.com/money-and-banking/Window-dressing-of-deposits-by-banks-Some-truths/article20505189.ece>

FSB (2018), "Financial Crisis and Information Gaps, Second Phase of the G20 Data Gaps Initiative (DGI-2) Third Progress Report" International Monetary Fund and Financial Stability Board.

Government of India (2018), "Report of the Committee on Financial Sector Statistics", Central Statistical Organisation, Ministry of Statistics & Programme and Implementation, Government of India.

Levanon, Gad and Lynn Franco (2011), "The Great Recession and Household Savings", The Conference Board, February 2011.

Mody, Ashoka, Franziska Ohnsorge and Damiano Sandri (2012), "Precautionary Savings in the Great Recession", *IMF Working Paper*, WP/12/42, February 2012.

Nahmias, Laurent (2010), "The Financial Crisis and Household Savings Behaviour in France", *Economic Research – BNP PARIBAS*, France.

OECD (2017), "Understanding Financial Accounts", Edited by Peter Van De Ven and Daniele Fano, OECD Publishing, Paris.

Prakash, Anupam, Avdhesh Kumar Shukla, Anand Prakash Ekka and Kunal Priyadarshi (2018), "Quarterly Estimates of Households' Financial Assets and Liabilities", *RBI Bulletin*, March 2018.

Prakash, Anupam, Avdhesh Kumar Shukla, Anand Prakash Ekka, Kunal Priyadarshi and Chaitali Bhowmick (2019), "Financial Stocks and Flows of the Indian Economy 2011-12 to 2017-18", *RBI Bulletin*, July 2019.

Rajpathak, Rajashree, Sanjay Singh and Srijashree Sardar (2019), "Seasonality in India's Key Economic Indicators", *RBI Bulletin*, March 2019.

Rangarajan, C. (2009), "Report of the High Level Committee on Estimation of Savings and Investment", Reserve Bank of India.

RBI (2019a), "Report on Trend and Progress of Banking in India 2018-19", Reserve Bank of India.

___ (2013b), "*Financial Stability Report*", Reserve Bank of India, June, 2013

___ (2019c), "*Annual Report 2018-19*", Reserve Bank of India.

___ (2019d), "Reserve Bank of India Imposes Monetary Penalty on Indian Bank", Press Release, Reserve Bank of India, November 20, 2019.

Rebello, Joel (2019), "In Deposit War, Private Sector Banks Win Hands Down", The Economic Time, February 27, 2019, <https://economictimes.indiatimes.com/industry/banking/finance/banking/in-deposit-war-private-banks-win-hands-down/articleshow/68177391.cms?from=mdr>

अनुलग्नक I आंकड़ों के स्रोत और प्रयुक्त प्रविधि

सांख्यिकीय दृष्टिकोण से, हाउसहोल्ड्स से संबंधित आंकड़े एक क्षेत्रीय संतुलन प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं (ओईसीडी 2017)। इस प्रक्रिया में हाउसहोल्ड्स संबंधी आंकड़े संबद्ध क्षेत्रों में उपलब्ध जानकारी पर आधारित होते हैं। उदाहरण के लिए, हाउसहोल्ड्स की ऋण देयताओं से संबंधित आंकड़े वाणिज्यिक बैंकों, एनबीएफसी, बीमा कंपनियों, सामान्य सरकारी क्षेत्र और गैर वित्तीय निकायों जैसे क्षेत्रों के तुलन-पत्रों में उपलब्ध जानकारी से प्राप्त किए जाते हैं (सारणी ए)।

हाउसहोल्ड क्षेत्र के सर्वेक्षणों से नियमित अंतराल पर आवश्यक आंकड़े उपलब्ध न हो पाने के कारण और पर्याप्त कवरेज के अभाव में सामान्य रूप से यही प्रक्रिया सभी देशों द्वारा अपनायी जाती है। जैसा कि ओईसीडी ने बताया है, “सर्वेक्षणों द्वारा हाउसहोल्ड्स के वित्तीय और गैर वित्तीय व्यवहार के संबंध में निकाले जाने वाले निष्कर्ष सटीक नहीं होते, जबकि संबंधित पार्टियों से प्राप्त जानकारी प्रायः सुपरिभाषित और सही पायी गयी है” (ओईसीडी 2017)।

सारणी ए: वित्तीय आस्तियों और देयताओं के लिए डाटा स्रोतों का सारांश

वित्तीय आस्तियाँ		
लिखत	परिभाषा	आस्तियाँ
मुद्रा	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मुद्रा	रंगराजन (2009) के बाद से अनुमानित अवशिष्ट मर्दे
जमाराशियाँ	चालू, बचत और मीयादी जमाराशियाँ चाहे उनकी परिपक्वता अवधि कुछ भी हो	वाणिज्य बैंकों, सहकारी बैंकों, गैर बैंक वित्तीय संस्थाएं, एचएफसीएस आदि से प्राप्त प्रतिरूप डाटा
कर्ज प्रतिभूतियाँ, सूचीबद्ध शेयर, म्यूचुअल फंड यूनिट	कर्ज प्रतिभूतियों में शामिल हैं- वाणिज्यिक पत्र, खजाना प्रतिभूतियाँ, सरकारी बॉण्ड, वित्तीय और गैर वित्तीय निगमों द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए डिबेंचर, वित्तीय और गैर-वित्तीय निगमों द्वारा पब्लिक इश्यू के माध्यम से जारी किए गए शेयर।	भारतीय रिज़र्व बैंक और सेबी की रिपोर्टें, विवरण पुस्तिकाएं और निर्गम से संबंधित दस्तावेज।
जीवन बीमा	व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसियों से संबंधित हकदारों के लिए बीमांकिक रिज़र्व और अन्य तकनीकी रिज़र्व।	बीमा कंपनियों और जनता के जानकारी हेतु जारी विवरणियों से प्राप्त डाटा।
पेंशन/भविष्य निधियाँ	सरकारी क्षेत्र और गैर सरकारी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति जमा निधि संबंधित लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता।	सरकारी बजट दस्तावेज, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ), पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण तथा अन्य पेंशन भविष्य निधि ट्रस्टों की रिपोर्टें।

देयताएँ

ऋण	वाणिज्य बैंकों, क्रेडिट सोसाइटियों, एनबीएफसी, एचएफसी जैसे वित्तीय संस्थानों से लिए गए आवास ऋण, उपभोक्ता ऋण, फसल ऋण और कारोबार ऋण।	संबंधित पक्षों के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक और राष्ट्रीय आवास बैंक की विभिन्न वार्षिक और तिमाही रिपोर्टों में दर्ज जानकारी।
व्यापार ऋण	निवल व्यापारिक देयराशियाँ	गैर वित्तीय निगम क्षेत्र की रिपोर्टें

टिप्पणियाँ:- उपर्युक्त लिखतों के अतिरिक्त, भारतीय हाउसहोल्ड्स के पास उनकी स्वयं की वित्तीय आस्तियाँ हो सकती हैं जैसे- वित्तीय व्युत्पन्नी, व्यापारिक संबंधियों को व्यापार ऋण; और वित्तीय देयताएँ, जैसे- गैर कार्पोरेट क्षेत्र से व्यापार ऋण। हमने डाटा के अभाव के कारण इन लिखतों पर चर्चा नहीं की है।

अनुलग्नक II

सारणी1: हाउसहोल्ड्स की सकल वित्तीय आस्तियाँ

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2017-18					2018-19					2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
सकल वित्तीय आस्तियाँ	9.6	13.8	7.9	16.5	12.0	7.9	10.4	7.3	18.8	11.1	6.7	10.3	10.7	14.5	10.6
जिनमें से :															
1. कुल जमाराशियाँ (ए) + (बी)	-1.6	5.9	-1.2	8.6	2.9	-1.2	6.5	0.5	10.2	4.0	-0.7	5.9	2.1	7.1	3.6
(ए) बैंक जमाराशियाँ	-1.8	5.9	-1.4	8.6	2.8	-1.4	6.3	0.3	10.2	3.8	-1.0	5.6	2.0	7.2	3.4
i. वाणिज्यिक बैंकों में जमाराशियाँ	-1.5	5.7	-1.5	8.6	2.8	-1.4	6.2	0.2	9.9	3.7	-1.1	5.5	1.2	7.1	3.2
ii. सहकारी बैंक	-0.3	0.2	0.1	0.1	0.0	-0.1	0.1	0.0	0.3	0.1	0.0	0.1	0.8	0.1	0.3
(ख) गैर बैंक जमाराशियाँ	0.2	0.1	0.2	0.0	0.1	0.2	0.2	0.2	0.1	0.2	0.4	0.3	0.1	0.0	0.2
2. जीवन बीमा निधियाँ	1.9	2.3	3.1	0.9	2.0	1.5	2.1	1.1	3.1	1.9	2.0	0.8	2.1	1.8	1.7
3. भविष्य निधि और पेंशन निधियाँ (पीपीएफ सहित)	2.3	2.2	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.2	2.2	2.1	2.1	2.2
4. मुद्रा	4.8	1.0	2.6	3.0	2.8	2.5	-0.7	2.1	1.9	1.5	1.3	-0.5	1.7	3.0	1.4
5. निवेश	1.3	1.5	0.4	1.1	1.1	1.7	-0.8	0.5	0.3	0.4	0.6	0.5	1.3	-0.8	0.4
जिनमें से :															
म्यूचुअल फंड	1.2	1.3	0.0	0.8	0.8	1.5	-1.0	0.4	0.2	0.3	0.2	0.4	1.3	-0.9	0.2
6. लघु बचतें (पीपीएफ को छोड़कर)	1.0	0.9	0.9	0.8	0.9	1.1	1.1	1.1	1.0	1.1	1.4	1.4	1.3	1.3	1.3

स्रोत: स्टाफ द्वारा की गयी गणना।

सारणी 2: हाउसहोल्ड्स की सकल वित्तीय देनदारियाँ

(जीडीपी के प्रतिशत के रूप में)

मद	2017-18					2018-19					2019-20				
	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक	ति1	ति2	ति3	ति4	वार्षिक
सकल वित्तीय देयताएँ	2.7	5.2	2.2	6.8	4.2	1.8	5.5	2.9	5.6	3.9	-0.4	2.8	4.2	5.0	2.9
ऋण (उधारराशियाँ); स्रोत															
ए. वित्तीय निगम (i+ii)	2.7	5.2	2.2	6.8	4.2	1.8	5.5	2.9	5.6	3.9	-0.4	2.8	4.2	5.0	2.9
(i) बैंकिंग क्षेत्र	0.7	3.8	0.9	5.7	2.8	1.0	3.7	2.9	4.7	3.1	-0.8	2.4	3.9	0.0	1.4
जिसमें से:															
वाणिज्यिक बैंक	0.7	3.8	0.9	5.5	2.7	0.9	3.7	2.9	4.5	3.0	-1.5	2.3	3.4	4.9	2.3
(ii) अन्य वित्तीय संस्थान	2.0	1.4	1.2	1.1	1.4	0.8	1.8	-0.1	0.9	0.9	0.4	0.4	0.3	-0.2	0.2
(ए) वित्तीय निगम	0.8	0.8	0.6	0.5	0.7	0.2	1.1	-0.1	0.6	0.5	0.0	0.2	0.6	-0.3	0.1
(बी) आवास वित्त	1.1	0.6	0.6	0.6	0.7	0.5	0.6	0.0	0.3	0.3	0.3	0.2	-0.3	0.1	0.1
कंपनियाँ															
(सी) बीमा कंपनियाँ	0.1	0.1	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.0
बी. गैर वित्तीय निगम (निजी	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
कॉर्पोरेट कारोबार)*															
सी. सामान्य सरकार *	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

*: नगण्य

स्रोत: स्टाफ द्वारा की गयी गणना।

सारणी 3: हाउसहोल्ड्स की आस्तियों और देयताओं में बकाया की स्थिति: चुनिंदा संकेतक

(₹ करोड़ में)

मद	2017-18				2018-19				2019-20			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
सकल वित्तीय आस्तियाँ												
जिनमें से:												
ए. बैंक जमाशायियाँ(i+ii)	74.06,499	76.51,681	75.92,300	79.88,459	79.23,991	82.16,181	82.28,953	87.32,543	86.82,099	89.57,299	90.61,181	94.43,347
i. वाणिज्यिक बैंकों में जमाशायियाँ	68.48,812	70.86,130	70.23,386	74.16,181	73.54,407	76.54,524	76.54,524	81.45,229	80.92,500	83.60,743	84.24,434	88.02,081
ii. सहकारी बैंक	5.57,687	5.65,552	5.68,914	5.72,278	5.69,584	5.72,291	5.74,428	5.87,315	5.89,540	5.96,556	6.36,747	6.41,266
बी. जीवन बीमा निधियाँ	29.44,884	30.38,077	31.70,213	32.07,898	32.70,270	33.64,359	34.10,441	35.59,920	36.50,999	36.86,887	37.92,633	38.81,446
सी. कर्सी निधियाँ	13.77,115	14.19,187	15.31,963	16.67,814	17.82,923	17.50,789	18.53,445	19.49,222	20.10,843	19.84,738	20.71,582	22.32,230
डी. म्यूचुअल फंड	9.46,249	10.18,110	10.61,206	10.65,882	11.93,501	11.50,709	11.93,246	12.42,184	12.65,871	12.79,311	13.85,427	11.62,078
कुल (ए+बी+सी+डी)	1,26,74,748	1,31,27,055	1,33,55,682	1,39,30,053	1,41,70,686	1,44,82,037	1,46,80,085	1,54,83,870	1,56,09,812	1,59,08,234	1,63,10,822	1,67,19,100

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

ए. बैंक जमाशायियाँ(i+ii)	46.2	45.9	43.9	43.5	43.5	44.2	42.7	44.1	44.1	45.5	43.8	44.3
i. वाणिज्यिक बैंकों में जमाशायियाँ	42.7	42.5	40.6	40.4	40.4	41.1	39.7	41.1	41.1	42.5	40.7	41.3
ii. सहकारी बैंक	3.5	3.4	3.3	3.1	3.1	3.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.1	3.0
बी. जीवन बीमा निधियाँ	18.4	18.2	18.3	17.5	18.0	18.1	17.7	18.0	18.6	18.7	18.3	18.2
सी. कर्सी निधियाँ	8.6	8.5	8.9	9.1	9.8	9.4	9.6	9.8	10.2	10.1	10.0	10.5
डी. म्यूचुअल फंड	5.9	6.1	6.1	5.8	6.6	6.2	6.2	6.3	6.4	6.5	6.7	5.5
कुल	79.1	78.7	77.2	75.8	77.8	77.9	76.2	78.1	79.3	80.8	78.8	78.5

सकल वित्तीय देयताएँ

ऋण (उधारशायियाँ); स्रोत	2017-18				2018-19				2019-20			
	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4	ति1	ति2	ति3	ति4
ए. वित्तीय कारपोरेशन (i+ii)	4615556	4833287	4927278	5238596	5321128	5574435	5712769	5988080	5970123	6108168	6323974	6587943
(i) बैंकिंग क्षेत्र	3725782	3884176	3924504	4183990	4228869	4399440	4540490	4771461	4733895	4850254	5050922	5323469
जिनमें से:												
वाणिज्यिक बैंक	3487301	3646121	3684863	3939323	3982324	4152097	4293543	4517329	4445666	4557895	4735661	4998267
सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी	238115	237677	239251	244265	246138	246931	246529	253708	287801	291925	314821	324762
(ii) अन्य वित्तीय संस्थान	889574	949111	1002774	1054606	1092259	1174995	1172278	1216619	1236228	1257914	1273053	1264474
जिनमें से:												
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	280643	312603	337693	359583	370545	422575	418860	447496	446982	458506	487403	472061
आवास वित्त कंपनियाँ	511319	536379	563004	591058	614618	642947	642160	656279	673312	681405	665695	670179

जीडीपी के प्रतिशत के रूप में

ए. वित्तीय कारपोरेशन (i+ii)	28.8	29.0	28.5	28.5	29.2	30.0	29.6	30.2	30.3	31.0	30.6	30.9
(i) बैंकिंग क्षेत्र	23.2	23.3	22.7	22.8	23.2	23.7	23.6	24.1	24.1	24.6	24.4	25.0
जिनमें से:												
वाणिज्यिक बैंक	21.8	21.8	21.3	21.4	21.9	22.3	22.3	22.8	22.6	23.2	22.9	23.5
सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसायटी	1.5	1.4	1.4	1.3	1.4	1.3	1.3	1.3	1.5	1.5	1.5	1.5
(ii) अन्य वित्तीय संस्थान	5.5	5.7	5.8	5.7	6.0	6.3	6.1	6.1	6.3	6.4	6.2	5.9
जिनमें से:												
गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	1.8	1.9	2.0	2.0	2.0	2.3	2.2	2.3	2.3	2.3	2.4	2.2
आवास वित्त कंपनियाँ	3.2	3.2	3.3	3.2	3.4	3.5	3.3	3.3	3.4	3.5	3.2	3.1

टिप्पणी: पेंशन और भविष्य निधि में हाउसहोल्ड्स के निवेश के बकाया को प्रकाशित नहीं किया जा रहा है क्योंकि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) द्वारा उपलब्ध कराया गया अद्यतन डाटा, 2016-17 से संबंधित है और यह इस संभाग का लगभग 70% हिस्सा होता है।

स्रोत: स्टाफ द्वारा की गयी गणना।

गैर-बैंक वित्तीय मध्यस्थता से जुड़े मुद्दे*

इस लेख में भारत में ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड में निहित कतिपय संरचनात्मक जोखिमों पर ध्यान दिया गया है, जो कोविड-19 के संदर्भ में सहसंबद्ध मोचन दबावों से उत्पन्न हुआ है। लेख में मौजूदा नीति ढांचे में कतिपय संशोधन करने पर विचार किया गया है ताकि डेट म्यूचुअल फंड सेक्टर से होने वाले जोखिमों को फैलने से रोकने में मदद हो सके।

परिचय

कोविड-19 के चलते विकसित और उभरती बाजार वाली अर्थव्यवस्था दोनों ही व्यापक तौर पर और एक-साथ ऋण जोखिम वाले निवेश से पीछे हटती हुईं नज़र आईं, नतीजतन अत्यधिक अस्थिरता के बीच कर्ज बाजारों में आस्ति की कीमतों में भारी गिरावट आई। चलनिधि और सुरक्षित आस्तियों के पीछे भागने के अपने इस प्रयास में आस्तियों को बाजार के भिन्न-भिन्न खंडों में कम दाम पर बेचा गया। इसने वित्तीय माध्यमों को खतरे में भी डाल दिया, परिणामतः इस तरह के खंडों में पारस्परिक क्रिया को आपसी सहारा मिला।

हाल में, म्यूचुअल फंड में संसाधनों के प्रवाह में अचानक वृद्धि हुई, जो दर्शाता है कि भारत में वित्तीय बचत इस्तेमाल के स्वरूप में विवेकपूर्ण बदलाव आया है। डेट/इनकम ओरियन्टेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स की शुद्ध प्रबंधनाधीन आस्तियां (एयूएम) मार्च 2015 के अंत में ₹6.94 ट्रिलियन से बढ़कर मार्च 2020 के अंत में ₹11.97 ट्रिलियन हो गईं, जो 5 साल की अवधि में लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि होती है।

इस परिवेश में, डेट पोर्टफोलियो प्रबंधक द्वारा आहरण को रोकने की हालिया वारदात ने संकट के समय ओपन-एंडेड म्यूचुअल फंड की कार्य-शैली को सहने को लेकर सुर्खियां बटोरी हैं। यह लेख डेट म्यूचुअल फंड में संस्थागत निवेशकों के प्रभुत्व, अकुशल विविधता और एक दृढ़ मूल्यांकन ढांचे की कमी पर

* यह लेख वित्तीय स्थिरता इकाई (एफएसयू), भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के यशवंत बित्रा, मनीष मीणा और अनुभव अग्रवाल द्वारा तैयार किया गया है। लेखक श्री इन्द्रनील चक्रवर्ती, श्री आर गुरुमूर्ति और श्री राजेश्वर राव की अंतर्दृष्टि एवं सहयोग के आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। सामान्य अस्वीकरण लागू हैं।

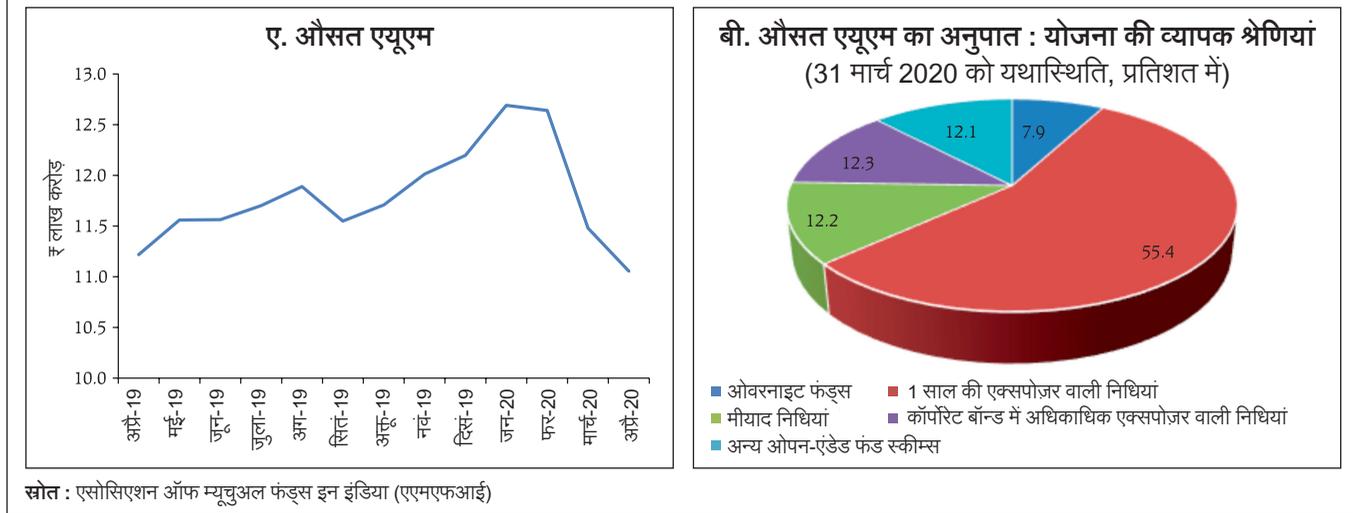
प्रकाश डालता है, क्योंकि ये ऐसे कारक हैं जो बदहाल स्थिति में इस तरह के फंड से आहरण पर जोर देने में अहम भूमिका अदा करते हैं। उथला (शैलो) गौण बॉन्ड बाजार में विश्वसनीय प्रतिपक्षकारों के अभाव में कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव होते हैं, जो जोखिम विमुखता पर जोर देते हैं। इसके अलावा, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी)/ आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) की देयताओं की काफी अल्पकालिक जमावट है, जो चुकौती संबंधी मोहलत देने के संदर्भ में इस तरह की देयताओं को चुकता करने को लेकर इन संस्थाओं की क्षमता के संबंध में चिंता जगाती है। वित्त प्रणाली में म्यूचुअल फंड की वजह से प्रतिकूल प्रतिक्रिया पनपने की संभावना के चलते, जिसके पोर्टफोलियो में उसकी आस्तियों का बड़ा हिस्सा है, संपूर्ण वित्तीय स्थिरता के लिए जोखिम बढ़ गया है।

इस लेख को पांच भागों में विभाजित किया जाता है। भाग II में विश्लेषण में उपयोग किए गए ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड का व्यापक वर्गीकरण प्रस्तुत है। भाग III डेट म्यूचुअल फंड में कतिपय हालिया अंतरराष्ट्रीय बदलावों को रेखांकित करता है। भाग IV में भारत में डेट म्यूचुअल फंड से जुड़े कतिपय मुद्दों पर चर्चा की गई है और भाग V में कतिपय नीतिगत सुझाव एवं निष्कर्षात्मक टिप्पणियां दी गई हैं।

II. ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड्स

म्यूचुअल फंड (एमएफ) योजनाओं के वर्गीकरण एवं उसे तर्कसंगत बनाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए म्यूचुअल फंड योजनाओं को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। केवल ओवरनाइट एक्सपोज़र की इजाजत देने वाली योजनाओं को ओवरनाइट फंड्स के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है। दूसरे, ऐसी योजनाएं भी हैं जो 1 साल तक की अवधि के लिखतों में निवेश करने की इजाजत देती हैं, जिसमें चलनिधि, अति लघु मीयाद निधि, कम मीयाद निधि और मुद्रा बाजार निधि आती हैं। तीसरे, मीयाद निधियां, जो मैकाले ड्यूरेशन पोर्टफोलियो (1 साल से अधिक) के आधार पर वर्गीकृत की जाती हैं, अर्थात्, लघु मीयाद निधियां, मध्यम से दीर्घ मीयाद निधियां तथा भिन्न-भिन्न मीयाद में निवेश करने की इजाजत प्राप्त निधियां। चौथे, वे निधियां जो प्रमुख रूप से कॉर्पोरेट बॉन्ड जैसे ऋण जोखिम निधि एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड निधियों में निवेश करती हैं (चार्ट 1)।

चार्ट 1: ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड का एयूएम



III. हालिया अंतरराष्ट्रीय बदलाव

बाजार-आधारित वित्त, वित्तीय एवं अन्य मध्यस्थ सेवाएं प्रदान करने में बैंकिंग प्रणाली का पूरक होता है और यह दुनिया भर में बढ़ रहा है। वित्त क्षेत्र की लगभग आधी आस्तियां, यूके और वैश्विक तौर पर (एफएसआर, बैंक ऑफ इंग्लैंड, 2019) गैर-बैंक वित्तीय प्रणाली की बढ़ती हैं।

विश्व-व्यापी तौर पर विनियमित ओपन-एंडेड फंड्स द्वारा संचालित कुल आस्तियां 2019 की चौथी तिमाही¹ में बढ़कर लगभग 59.2 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो गईं। पिछले कुछ वर्षों² में चलनिधि जोखिम प्रबंधन ने आस्तित्व प्रबंधन क्षेत्र में पर्याप्त ध्यान आकर्षित किया है। वैश्विक वित्तीय संकट के परिणामस्वरूप भिन्न-भिन्न अधिकार क्षेत्रों के विनियामकों ने इन मुद्दों से निपटने

के लिए मोचन द्वार⁴, उतार-चढ़ाव आधारित कीमत-निर्धारण⁵ अथवा दरकिनार करना⁶ पद्धतियों को अपनाया शुरू कर दिया है।

जून 2019 में एलएफ वुडफोर्ड इक्विटी फंड पर रोक लगने के परिणामस्वरूप विनियामकों की समझ बेहतर हो गई है। रोक लगने के बाद, क्षेत्र-विशिष्ट विनियामकों ने उपायों का ऐलान किया जैसे यूरोपीय प्रतिभूति और बाजार प्राधिकरण (ईएसएमए) ने निवेश निधियों के लिए चलनिधि दबाव परीक्षण को लेकर मार्गदर्शन प्रकाशित किया, जिसे इस जोखिम को कम करने के लिए एक साधन के रूप में उपयोग किया जाना है। भारत में, सेबी ने चल और ओवरनाइट निधियों के लिए जोखिम प्रबंधन ढांचा लागू किया है जिसके मुताबिक चल निधि अपनी शुद्ध आस्तियों का कम से कम 20 प्रतिशत चल आस्तियों में धारण करेगी। फिर भी, भारतीय बाजारों के विशिष्ट लक्षण ऐसे हैं जिससे ओपन-एंडेड डेट फंड को विशेष रूप से “धन निकासी दौड़ का जोखिम” उठाना पड़ सकता है।

¹ यूरोपीय फंड और एसेट मैनेजमेंट एसोसिएशन की 25 मार्च 2020 को प्रकाशित अंतरराष्ट्रीय सांख्यिकीय रिलीज़ का अवलोकन करें, जो <https://www.efama.org/Publications/Statistics/International/Quarterly%20International/20-03%20International%20Statistical%20Release%20Q4%202019.pdf> पर उपलब्ध है।

² अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (2015): वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट – “मौद्रिक नीति की चुनौतियों और जोखिम प्रबंधन का मार्गनिर्देशन”, अप्रैल; अंतरराष्ट्रीय निपटान बैंक (2015): 85वाँ वार्षिक रिपोर्ट; वित्तीय स्थिरता बोर्ड और अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन (2015): “गैर-बैंक गैर-बीमाकर्ता वैश्विक तौर पर प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय संस्थाओं की पहचान के लिए आकलन की कार्य-पद्धतियां।”

³ बैंक ऑफ इंग्लैंड (2019): ओपन-एंडेड फंड की कमजोरियों से निपटना: वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, संख्या 45; लिबर्टी स्ट्रीट इकोनॉमिक्स ब्लॉग (2016): “क्या आस्तित्व प्रबंधक ताबड़तोड़ बिक्री के प्रति संवेदनशील हैं”, फेडरल रिज़र्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क।

⁴ मोचन द्वार, निवेशकों द्वारा अपनी पूंजी के मोचन को लेकर उनकी क्षमता पर सामान्यतः यथानुपात आधार पर आंशिक प्रतिबंध लगाता है।

⁵ उतार-चढ़ाव आधारित कीमत-निर्धारण की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब फंड प्रदाता किसी फंड के शुद्ध आस्तित्व मूल्य (एनएवी) का समायोजन करने के उद्देश्य से उन लोगों पर ट्रेडिंग की लागत लादता है जो अपने-अपने खाते के भीतर क्रय-विक्रय करते हैं। इसकी रचना इस प्रकार की गई है कि यह उसी फंड के भीतर अन्य निवेशकों की लेनदेन क्रियाओं के चलते लंबे समय से टिके शेरधारकों के खातों के मूल्य को क्षय होने से बचाता है।

⁶ दरकिनार करना वह पद्धति है जो किसी पोर्टफोलियो में बढहाल, अतरल एवं असुलभ मूल्य वाली आस्तियों को अन्य अधिक तरल आस्तियों से अलग करती है। यह बढहाल आस्तियों को अधिक तरल व बेहतर प्रदर्शन कर रही आस्तियों से हुई आय को नुकसान पहुंचाने से रोकती है।

IV. भारत में डेट म्यूचुअल फंड के निवेशक का प्रोफाइल

वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट (एफएसआर) के दिसंबर 2018 संस्करण (आईएल और एफएस संकट के परिणामस्वरूप) ने डेट फंड में गैर-खुदरा निवेशक के प्रभुत्व की भूमिका पर प्रकाश डाला है (चार्ट 2)। कॉर्पोरेट और उच्च मालियत वाले व्यक्तियों (एचएनआई) के डेट फंड की कुल प्रबंधनाधीन आस्तियों (एयूएम) में 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा है, इसके विपरीत, इक्विटी फंड में उनकी हिस्सेदारी 48 प्रतिशत है।

एचएनआई और कॉर्पोरेट निवेशक आम तौर पर लागत को लेकर जागरूक रहते हैं। जहां विनियमों के माध्यम से व्यय अनुपात पर लगाम लगाई जाती है, वहीं बड़े फंड हाउस को यह फायदा होता है कि वे निर्धारित लागत को वृहद एयूएम में पाटने योग्य होते हैं और प्रतिस्पर्धी लागत बनाए रख पाते हैं। लिहाजा, निवेश को लेकर कॉर्पोरेट का प्रभुत्व निधि प्रबंधन में संकेन्द्रण की स्थिति पैदा कर सकता है क्योंकि छोटे फंड हाउस व्यय अनुपात के मोर्चे पर होड़ नहीं कर पाते। इसके अलावा, निवेशक की नज़र से देखें तो वृहद निधि आकार प्रोत्साहन अनुकूल भी होता है – इस तरह की निधियों का असर पूरी प्रणाली में फैल सकता है, जो संभवतः उबारने (बेल-आउट) की संभावनाओं को बेहतर बनाता है।⁷

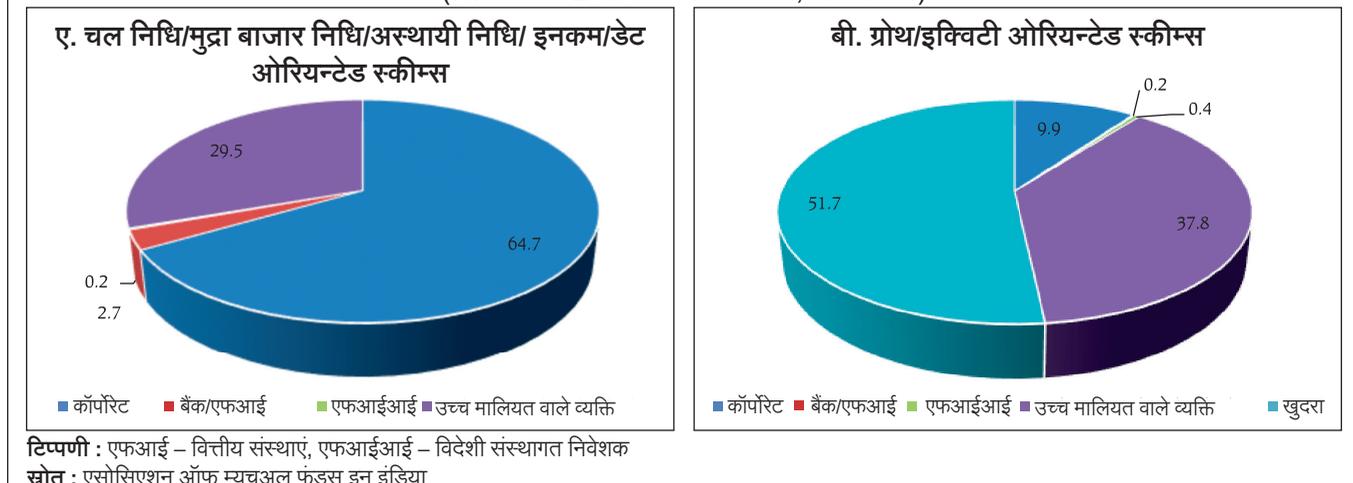
सैद्धांतिक तौर पर, आस्ति प्रबंधन कंपनी (एएमसी) की किसी योजना में किसी एकल निवेशक द्वारा अनुपातहीन हिस्सा न रखा जाना सुनिश्चित करने के जरिए कॉर्पोरेट समुदाय द्वारा इस तरह की योजना में पैर जमाने की वजह से होनेवाली भगदड़ के

खतरे को कम किया जा सकता है। मौजूदा विनियमों में निवेशक आधार में विविधता लाने के लिहाज से एकल निवेशक संकेन्द्रण मानदंड विनिर्दिष्ट किए गए हैं। फिर भी, जब निवेशक प्रोफाइल में जोखिम विमुख निवेशकों का बोलबाला होता है जैसा मुद्रा बाजार/ डेट म्यूचुअल फंड के मामले में है, इस बात की प्रबल संभावना है कि कुछ एक कॉर्पोरेट अपने अधिशेष को चार/पांच फंड हाउस में बांट लेंगे, लिहाजा बदहाली से निकलने की अभी भी कोशिश की जा सकती है।

पोर्टफोलियो का हालिया निष्पादन वृद्धिशील अंतर्वाहों में अनुपातहीन भूमिका अदा करता है, जो आम तौर पर अतरल प्रीमियम को बेशी आय का (कम समय के लिए) मुखौटा पहनाता है। एएमसी ने अतरलता को पोर्टफोलियो में नहीं समाया है (निधि की क्षणिकता के स्वरूप की बदौलत) जहां इस तरह की अतरलता से होने वाली बेशी आय अतिरिक्त कॉर्पोरेट प्रवाहों के संदर्भ में पोर्टफोलियो प्रबंधकों के लिए आने वाले समय में बड़े फायदे पहुंचा सकती है – वहीं जब ब्याज दर को लेकर अनुकूल विचार नहीं होते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड क्रय-विक्रय दरों के अंतर का जोखिम लादकर पर्याप्त प्रचक्रिय व्यवहार दर्शाते हैं और बैंक ऋण सहायता के जरिए पोर्टफोलियो की परिणामी अतरलता का हल (आंशिक तौर पर) ढूंढा जाता है। ऐसी व्यवस्थाओं में चलनिधि जोखिम कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार से अंतर-बैंक निधीयन बाजार में फैलने का खतरा अंतर्निहित होता है।

चार्ट 2: डेट और इक्विटी फंड का निवेशक प्रोफाइल

(31 दिसंबर 2019 को यथास्थिति, प्रतिशत में)



⁷ “बिग गेट्स बिगर: इन्वेस्टर्स फ्लाइंग टु सेफ्टी बूस्ट्स बिग-3 एएमसीज मार्केट शेयर”, 27 अप्रैल 2020 को <http://indianstructuredfinance.com/big-gets-bigger-investors-flight-to-safety-boosts-big-3-amcs-market-share/> में प्रकाशित।

मूल्यांकन रूपरेखा और निहिताथ

आईएल और एफएस घटना-प्रेरित जोखिम विमुखता की वजह से हुई अव्यवस्था एवं कॉर्पोरेट बॉन्ड को लेकर मूल्यांकन रूपरेखा पर पहले ही प्रकाश डाला जा चुका है (एफएसआर, आरबीआई-2018)। तथापि, एमएफ उद्योग में आम धारणा ऐसी प्रतीत होती है कि म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो⁸ के ऋण जोखिम को काबू में करने के लिए मूल्यांकन रूपरेखा में पर्याप्त बचाव व्यवस्था मौजूद है, भले ही ओपन एंडेड डेट फंड जितने तरल होने चाहिए उसकी अपेक्षा कम तरल हैं (उनके ओपन-एंडेड स्वरूप को देखते हुए) क्योंकि अंतर्निहित आस्तियां अपनेआप तब्दील होकर अधिक से अधिक अतरल हो जाती हैं। कर्ज प्रतिभूतियों के मूल्यांकन और जोखिम प्रबंधन रूपरेखा की कुछ कमियों का समाधान कर लिया गया है (सेबी, 2019)^{9, 10}। तथापि, अत्यधिक जोखिम विमुखता के बीच सहसंबद्ध आहरणों के तहत ऋण जोखिम स्पेक्ट्रम में प्रतिभूतियों का मूल्यांकन चुनौती बना हुआ है।

कोविड-19 व्यवधान और गौण बाजार चलनिधि

कॉर्पोरेट बॉन्ड में गौण बाजार चलनिधि के मुद्दे को लेकर वैश्विक तौर पर^{11, 12} हालिया कोविड-19 प्रेरित कर्ज बाजार व्यवधान के परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डाला गया है। संयुक्त राज्य में भी, जिसका बाजार सब में से अत्यधिक तरल है, कॉर्पोरेट बॉन्ड एक्सचेंज ट्रेडड फंड (ईटीएफ) एवं अंतर्निहित बॉन्ड मूल्य में काफी विचलन देखने मिला (कभी-कभी ईटीएफ में छूट कर्ज

⁸ "चूक जोखिम को निवेशकों पर लादने के विषय में आरबीआई द्वारा लगाई गई रोक को म्यूचुअल फंड द्वारा खारिज किया जाना", 3 जनवरी 2019 को <https://www.bloomberquint.com/business/mutual-funds-dismiss-rbis-red-flag-on-passing-on-default-risk-to-investors> में प्रकाशित।

⁹ सेबी (2019) "मुद्रा बाजार और कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन", 22 मार्च 2019 का परिपत्र संख्या SEBI/HO/IMD/DF4/CIR/P/2019/41.

¹⁰ सेबी (2019) "मुद्रा बाजार और कर्ज प्रतिभूतियों का मूल्यांकन", 24 सितंबर 2019 का परिपत्र संख्या SEBI/HO/IMD/DF4/CIR/P/2019/102.

¹¹ "यूरोपीय विनियामक द्वारा निवेश निधि चलनिधि की जांच को तीव्र करना", 19 अप्रैल 2020 को <https://www.ft.com/content/69e46be8-9513-4f15-ba10-0f9b70ca1c55> में प्रकाशित।

¹² "बॉन्ड ईटीएफ का अब विषाणु संकट में कठोर चलनिधि परीक्षा से गुजरना", 12 मार्च 2020 को <https://www.bloomberquint.com/markets/liquidity-reckoning-of-epic-proportions-is-brewing-in-bond-etfs> में प्रकाशित।

आधारित मूल्यांकन की तुलना में 5 प्रतिशत से अधिक हो जाती है)। भारतीय परिदृश्य में, यह मुद्दा और अधिक तीव्र हो जाता है क्योंकि इसके पहले चर्चा किए गए ढांचागत पहलू बदहाली के समय मोचन की वजह से पड़ने वाले प्रभाव पर अधिक जोर देते हुए प्रतीत होते हैं। भिन्न-भिन्न म्यूचुअल फंड में बड़े आहरणों के मामले में एमएफ कॉर्पोरेट बॉन्ड बिक्री के प्रतिपक्षकार निकट समय में प्रकट नहीं हो पाते। अस्थिरता के दौर में बैंक एवं अन्य संस्थागत निवेशक बाजार के क्रियाकलापों से आम तौर पर बाहर हो जाते हैं, जिसकी प्रमुख वजह जोखिम विमुखता है एवं/अथवा यह तथ्य है कि उनका अंतर्निहित बाध्यताधारी को लेकर पहले से ही पर्याप्त ऋण-संबंधी निवेश-जोखिम है तथा बाजार में अस्थिरता के दौरान विनियामक/जोखिम एक्सपोजर सीमाएं उनकी गतिविधियों में बाधा डालती हैं।

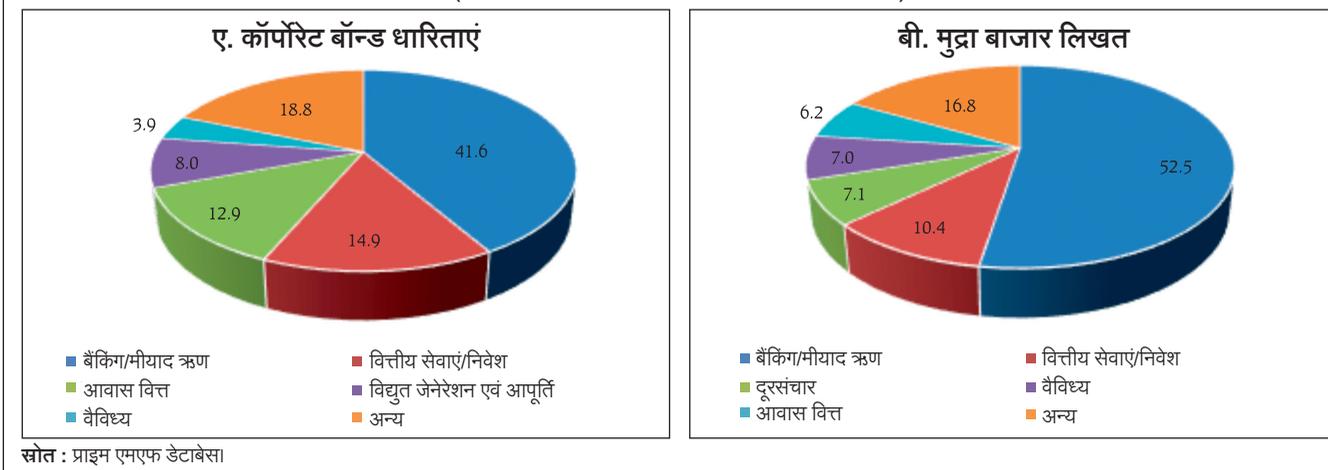
लिहाजा, एमएफ उद्योग सूक्ष्म ढांचे के दो डिजाइन फीचर निकलकर सामने आते हैं। पहला, डेट एमएफ का निवेशक प्रोफाइल उसे विशेष रूप से धन निकासी दौड़ में डाल सकता है। दूसरे, खास तौर पर बदहाली के दौरान बड़े सहसंबद्ध आहरणों के मामले में जब चलनिधि उपलब्ध कराने के लिए विश्वसनीय प्रतिपक्षकार नहीं होते हैं तो बाजार को, कीमतों में बड़े उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है जो जोखिम विमुखता पर जोर देता है।

प्रभाव का फैलना (स्पिलओवर्स)

वित्त क्षेत्र म्यूचुअल फंड के कर्ज धारिता स्वरूप की अगुआई करता है, जिसमें बैंकिंग/मीयाद ऋण, वित्तीय सेवाएं/निवेश और एचएफसी का कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड धारिताओं में 31 मार्च 2020 को यथास्थिति लगभग 69.3 प्रतिशत हिस्सेदारी है (चार्ट 3.ए.)। मुद्रा बाजार लिखतों के मामले में भी यह सही है (चार्ट 3.बी.)।

जनवरी 2020 के बाद ओपन-एंडेड डेट म्यूचुअल फंड (जिसमें कॉर्पोरेट और एचएनआई सबसे बड़े निवेशक होते हैं) के एयूएम में गिरावट से मोचन दबावों का साफ़-साफ़ पता चलता है। एनबीएफसी/एचएफसी द्वारा अपनी आस्तियों को लेकर मोहलत दिए जाने की वजह से ब्याज/परिपक्व हो रही देयताओं को चुकता करने की उनकी योग्यता को लेकर चिंता पैदा होती है जिसका प्रभाव म्यूचुअल फंड में फैलने की संभावना है।

चार्ट 3: उद्योग-वार म्यूचुअल फंड की धारिताएं
(31 मार्च 2020 को यथास्थिति, प्रतिशत में)

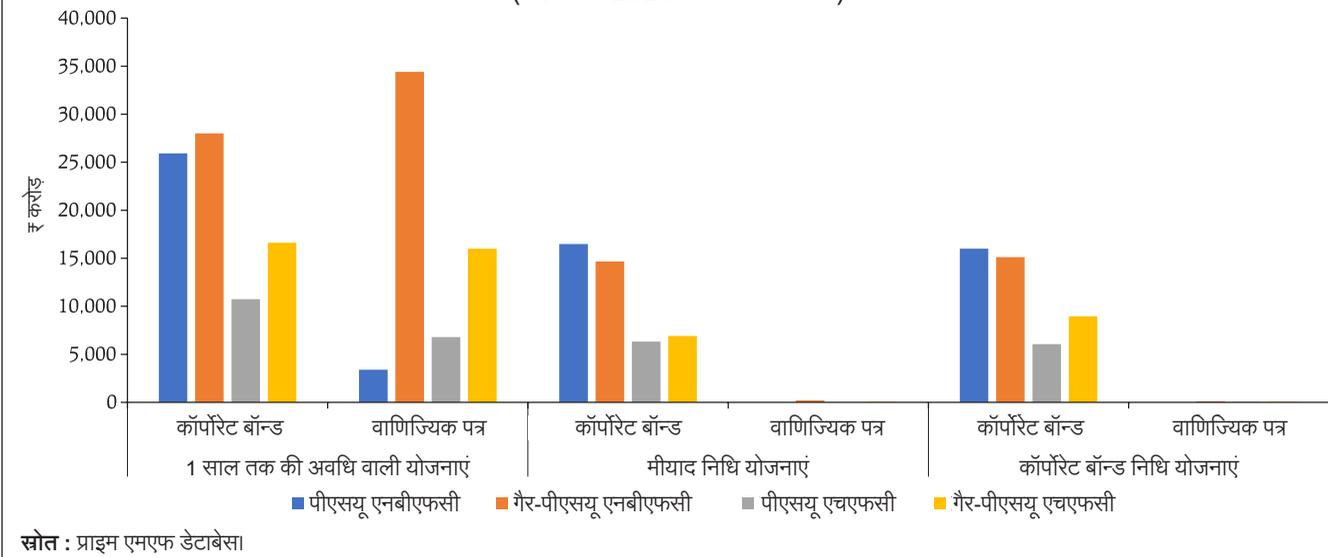


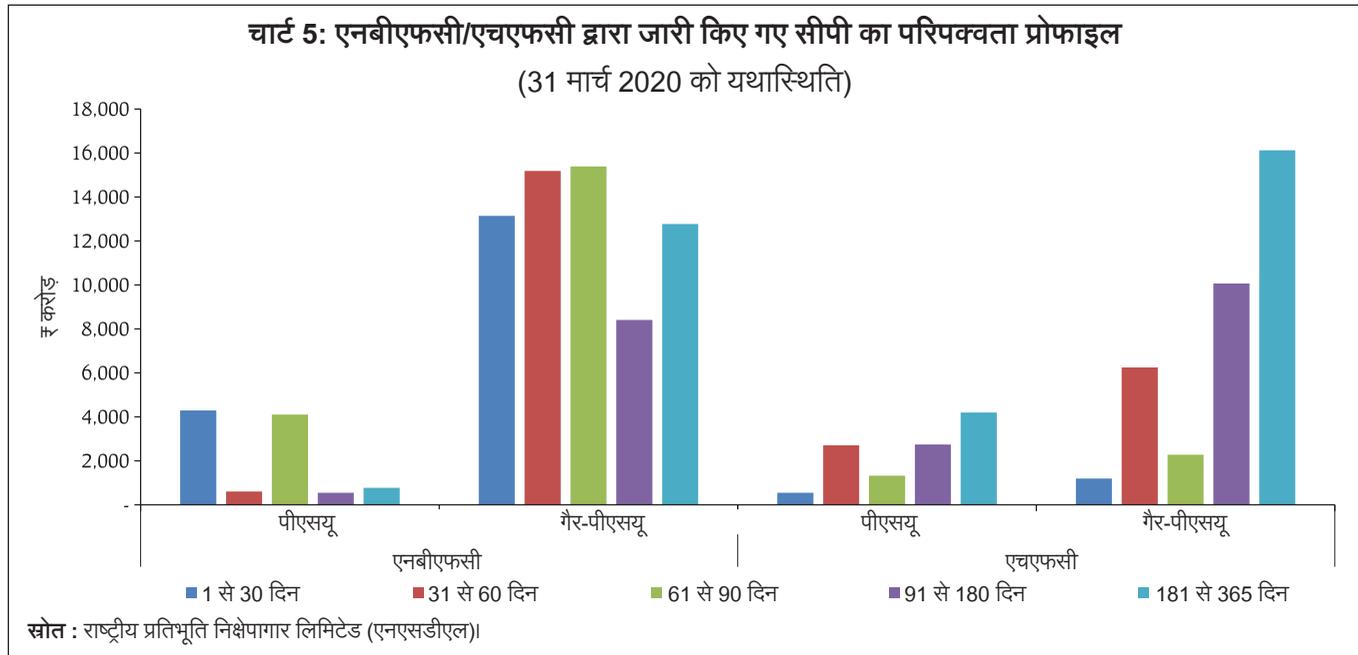
एमएफ डेट फंड की पोर्टफोलियो संरचना के अनुसार निजी संस्थाओं पर बल दिया जा रहा है, जो प्रमुख रूप से इस तथ्य के चलते कि निजी क्षेत्र (गैर-पीएसयू) वाली एनबीएफसी की तुलना में सरकारी क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) वाली एनबीएफसी/एचएफसी के वित्तीय लिखतों से आम तौर पर अधिक सुगमता से निधि जुटाई जाती है, भले ही अंतर्निहित रेटिंग कुछ भी हो (चार्ट 4)। इस संबंध में, एमएफ द्वारा गैर-पीएसयू वाली एनबीएफसी की वाणिज्यिक पत्र (सीपी) संबंधी देयताओं को

भारी मात्रा में धारण करना, निजी एनबीएफसी के वित्त संबंधी जरूरतों को लेकर एमएफ क्षेत्र की अहमियत पर रोशनी डालता है - जो संभवतः फैलने का एक जरिया है जिससे वित्त क्षेत्र के इस अमुक खंड में व्याप्त दबाव वास्तविक क्षेत्र के वित्तपोषण को प्रभावित कर सकता है।

निजी संस्थाओं के परिपक्वता प्रोफाइल में झांककर देखने से निजी एनबीएफसी के 90 दिन वाले सीपी की परिपक्वता की काफी जमावट होने का पता लगता है (चार्ट 5 और 6)।

चार्ट 4: डेट म्यूचुअल फंड की योजना-वार पोर्टफोलियो संरचना
(31 मार्च 2020 को यथास्थिति)

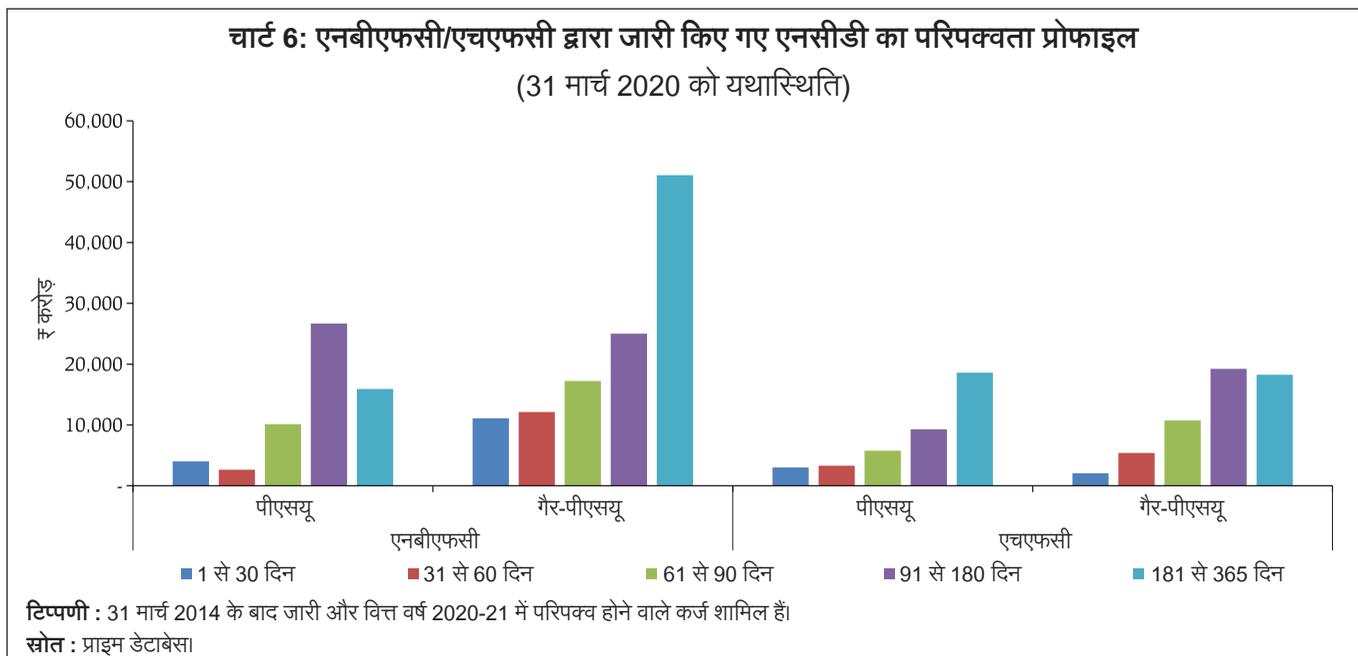


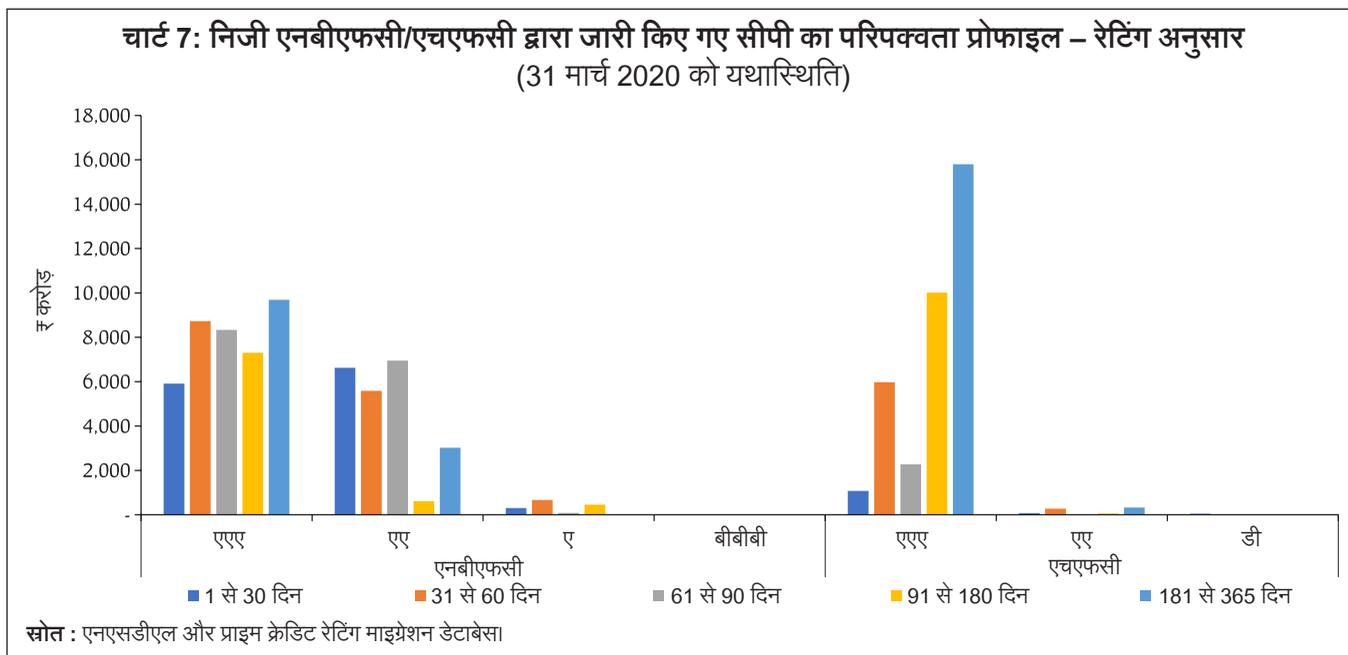


निजी एनबीएफसियों के मामलों में 90 दिन वाली परिपक्वता आय की जमावट शीर्ष दो रेटिंग का दर्जा पाने वालों में ज्यादा है। जहां तक निजी एनबीएफसी/एचएफसी के कॉर्पोरेट डेट का संबंध है 61-90 दिन वाली श्रेणी में इनकी कुछ जमावट देखने को मिलती है, यद्यपि परिपक्वता आय में 'एए' रेटेड एनबीएफसी/एचएफसी का आम तौर पर बोलबाला रहता है (चार्ट 7 से 9)।

कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की संरचना

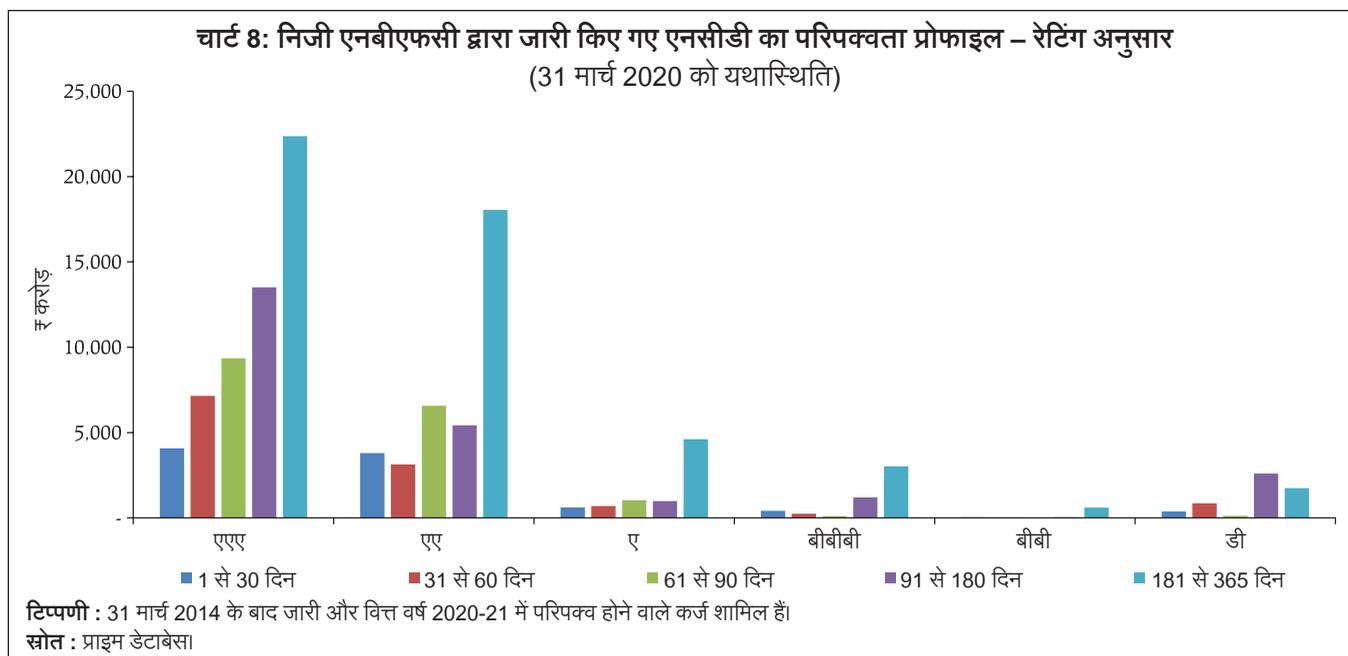
कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड की संरचना में भीतर तक झांककर देखने से कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड एवं क्रेडिट रिस्क फंड इन दो फंड श्रेणी के घटकों की बिल्कुल भिन्न संरचनाएं/विशेषताएं सामने आती हैं। 31 मार्च 2020 के आंकड़ों के आधार पर कॉर्पोरेट





बॉन्ड फंड की लगभग 97.3 प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड धारिताओं को 'एए' और उससे ऊपर की रेटिंग मिली हैं (चार्ट 10)। बड़े पीएसयू और विविधता वाले निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट के पास प्रमुख रूप से गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) कॉर्पस का एक बड़ा अनुपात होता है। इसके बिलकुल विपरीत, क्रेडिट रिस्क

फंड की लगभग 53.5 प्रतिशत कॉर्पोरेट बॉन्ड धारिताओं को 'एए' और उससे ऊपर की रेटिंग मिली हैं। इसके अलावा, क्रेडिट रिस्क फंड का चक्रिय आस्तियों जैसे पण्य कंपनियों या कोविड-19 महामारी से बुरी तरह प्रभावित ऑटोमोबाइल जैसे उद्योगों में अत्यधिक निवेश-जोखिम है। जहां संरचना में इस तरह की



मांग पर चुकौती योग्य म्यूचुअल फंड यूनिट्स की पेशकश, जिसमें शुद्ध आस्ति मूल्य (एनएवी) के प्रभाव को निवेशक पर लाद दिया जाता है, बैंक की उन जमाराशियों जैसी होती हैं जो मांग पर चुकाने योग्य होती हैं लेकिन उसमें उच्च गुणवत्ता वाली चलनिधि आस्तियों (एचक्यूएलए)/रिजर्व आवश्यकताओं/अंतिम सहारा की गुंजाइश नहीं रहती है, लिहाजा पर्याप्त विनियामक लाभ मिलता है। यह मुद्दा खास तौर पर उन अधिकार-क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है जहां निवेशक आधार छोटा/संकेद्रित है तथा गौण कर्ज बाजार अतरल होते हैं।

उबारने की प्रक्रियाओं के जरिए प्रोत्साहन अनुकूलता के मुद्दों एवं आकार के चलते होने वाले नैतिक खतरों से जुड़े मुद्दों को देखते हुए एयूएम में वृद्धि को संतुलित करने के साथ जोखिम को कम करने एवं उसके प्रभाव को फैलने से रोकने के लिए अतिरिक्त चलनिधि बफर की स्पष्ट जरूरत महसूस होती है। इससे निपटने का एक खास तरीका यह हो सकता है कि डेट स्कीम्स के आकार में इजाफा होने के साथ-साथ वृद्धिशील

धारिता में सरकारी प्रतिभूतियों के अनुपात में वृद्धि को लेकर नियम बनाए जाएं।

संदर्भ:

Financial Stability Board & IOSCO (2015), "Assessment Methodologies for Identifying Non-Bank Non-Insurer Globally Systemically Important Financial Institutions", *Financial Stability Board*.

Bank of England (2019), "Tackling vulnerabilities in open-ended funds", *Financial Stability Report*, No.45.

Nicola Cetorelli, Fernando M. Duarte, and Thomas M. Eisenbach (2016), "Are Asset Managers Vulnerable to Fire Sales", *Liberty Street Economics Blog, Federal Reserve Bank of New York*.

RBI (2018) *Financial Stability Report, June*, Mumbai.

RBI (2018) *Financial Stability Report, December*, Mumbai.

एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति: मुद्दे और नीति विकल्प*

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थितियां, हाल के दिनों में कोविड-19 से उत्पन्न व्यवधानों, और म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में हुए बदलावों के कारण बढ़े हुए जोखिम विमुखता और संस्थाओं के बीच उनके कथित जोखिम प्रोफाइल के आधार पर भेदभाव के माहौल में अधिक चुनौतीपूर्ण हो गई हैं। विशेष रूप से छोटे और मध्यम आकार के ऋण पात्रता वाली एनबीएफसी के लिए धन के प्रवाह को सुनिश्चित करने और प्रणालीगत जोखिमों को कम करने के लिए आगे नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता हो सकती है।

परिचय

ग्राहकों की विविध वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों देश में समावेशी विकास को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के गैर-शहरी भागों में बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष ऋण देने के लिए भारत में एनबीएफसी प्रतिस्थापित होती प्रतीत होती हैं (आचार्य और अन्य, 2013)। हाल के वर्षों में, एनबीएफसी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई) क्षेत्र के लिए ऋण का एक महत्वपूर्ण स्रोत रही है, जिसका भारत के जीडीपी¹ में लगभग 29 प्रतिशत हिस्सा है। इसके अलावा, विशेष एनबीएफसीयों ने भी इस क्षेत्र में दीर्घकालिक वित्तपोषण प्रदान करके बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

भारतीय वित्तीय परिदृश्य में एनबीएफसी का महत्व पिछले वर्षों के दौरान बढ़ गया है, मार्च 2014 के अंत में उनकी संयुक्त संपत्ति ₹14.5 लाख करोड़ थी जो सितंबर-2019² के अंत तक

* यह लेख वित्तीय बाजार विनियमन विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक के ऋतुराज, एम जगदीश, अभिषेक कुमार और अमित मीणा द्वारा तैयार किया गया है। बहुमूल्य मार्गदर्शन के लिए लेखक, सास्वत महापात्र के आभारी हैं। इस लेख में व्यक्त विचार लेखकों के हैं और वे भारतीय रिज़र्व बैंक के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह विश्लेषण अप्रैल 2020 के अंत तक के डेटा पर आधारित है।

¹ एमएसएमई मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट, 2018-19.

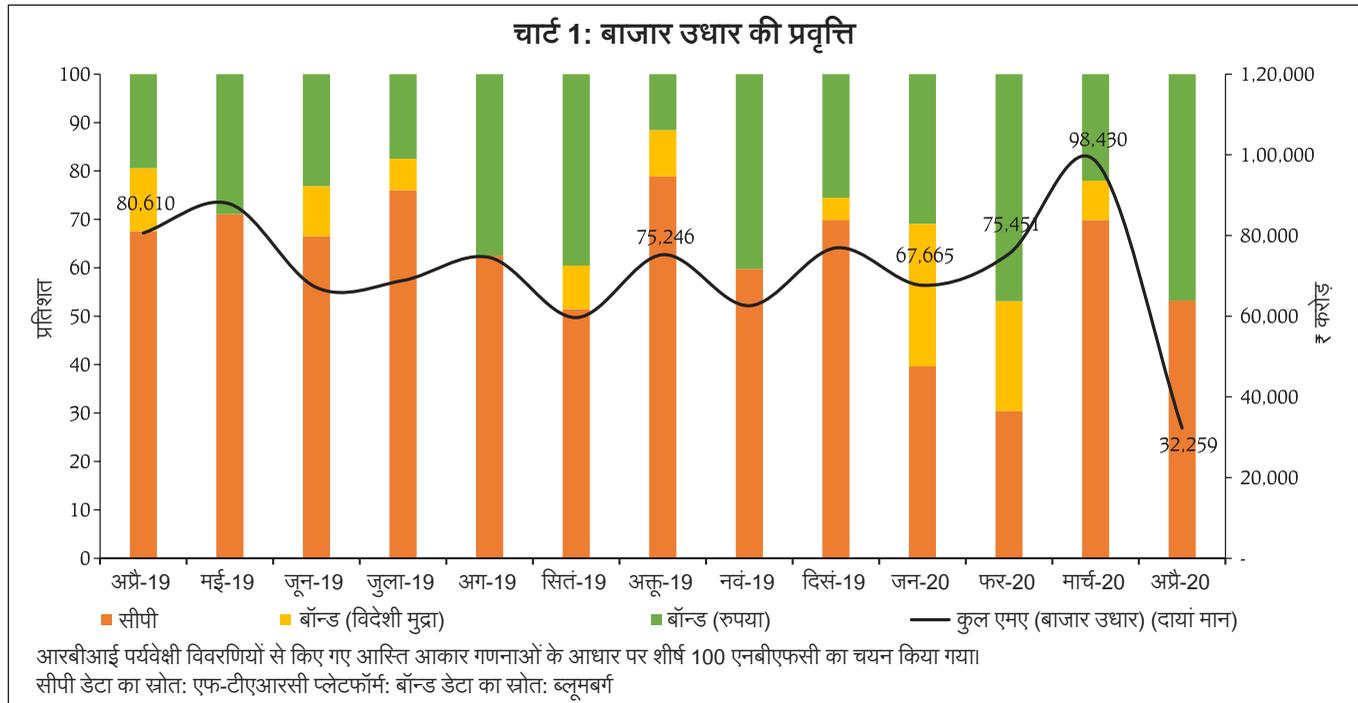
² भारत में बैंकिंग की प्रवृत्ति और प्रगति संबंधी रिपोर्ट के विभिन्न मुद्दे।

₹32 लाख करोड़ से अधिक हो गई है, हालांकि इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज (आईएल एण्ड एफएस) घटनाक्रम के बाद इसमें कुछ कमी आयी है। समय के साथ, एनबीएफसी का वित्तीय संस्थाओं की अन्य श्रेणियों के साथ गहरा संबंध बन गया है। एनबीएफसी के लिए बैंक ऋण एक प्रमुख स्रोत हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के विनियमों ने प्राथमिकता-प्राप्त क्षेत्र के रूप में वर्गीकृत कुछ विशिष्ट क्षेत्रों को ऋण देने के लिए एनबीएफसी को पात्र बनाने के कारण बैंकों से एनबीएफसी तक ऋण प्रवाह को प्रोत्साहन मिला है। अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड और वाणिज्यिक पत्र (सीपी) जैसे बाजार आधारित लिखतों पर एनबीएफसी की निर्भरता भी बढ़ी है जो दिसंबर 2019³ के अंत में उनकी कुल देनदारियों का लगभग 31 प्रतिशत होता है। म्यूचुअल फंड, विशेष रूप से डेट फंड, एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए बाजार लिखतों के प्रमुख निवेशकों में से एक हैं: एनबीएफसी द्वारा मार्च 2020⁴ के अंत तक जारी कुल बकाया वाणिज्यिक पत्रों में म्यूचुअल फंड की 61 प्रतिशत हिस्सेदारी है।

हालांकि, आईएल एंड एफएस के बाद एनबीएफसी के लिए बाजार वित्तपोषण की स्थिति चुनौतीपूर्ण हो गई है। जहां रेटिंग में गिरावट, गहन निवेशक जांच और संवर्धित विनियामक निरीक्षण के मामले में की गई कार्रवाई ने बाजार अनुशासन लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के साथ बेहतर रेटेड और बेहतर प्रदर्शन करने वाली कंपनियों के लिए बाजार वित्तपोषण के लिए अपेक्षाकृत आसान पहुंच जारी रही, वहीं उधार की लागत उच्च होने की वजह से आस्ति-देयता असंतुलन (एएलएम) के मुद्दे और/या आस्ति की गुणवत्ता को लेकर चिंता होना लाजमी था (वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट, आरबीआई, जून 2019)। इस अवधि में घरेलू रूप से धन जुटाने में कठिनाइयों के कारण ऑफशोर उधार में वृद्धि देखी गई। 2019 के दौरान एक बड़ी आवास वित्त कंपनी के पतन के परिणामस्वरूप इनकी वित्तपोषण की स्थिति और अधिक प्रभावित हुई। हाल के दिनों में, कोविड-19 के प्रकोप के कारण एनबीएफसी द्वारा अपनी आस्तियों को लेकर

³ आरबीआई की पर्यवेक्षी विवरणियों में दर्शाई गई शीर्ष 100 एनबीएफसी के संबंध में आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना। डेटा दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार है।

⁴ सेबी डेटा और आरबीआई स्टाफ द्वारा की गई गणना।



दी गई मोहलत, साथ-साथ बढ़े हुए जोखिम विमुखता के संपूर्ण माहौल को देखते हुए एनबीएफसी का क्रेडिट प्रोफाइल बिगड़ने की आशंका बनी हुई है। म्यूचुअल फंड उद्योग में हाल के घटनाक्रम, जो एनबीएफसी के लिए धन का एक प्रमुख स्रोत है, ने भी आशंकाएं व्यक्त की हैं कि एनबीएफसी को रोलओवर जोखिमों का सामना करना पड़ सकता है।

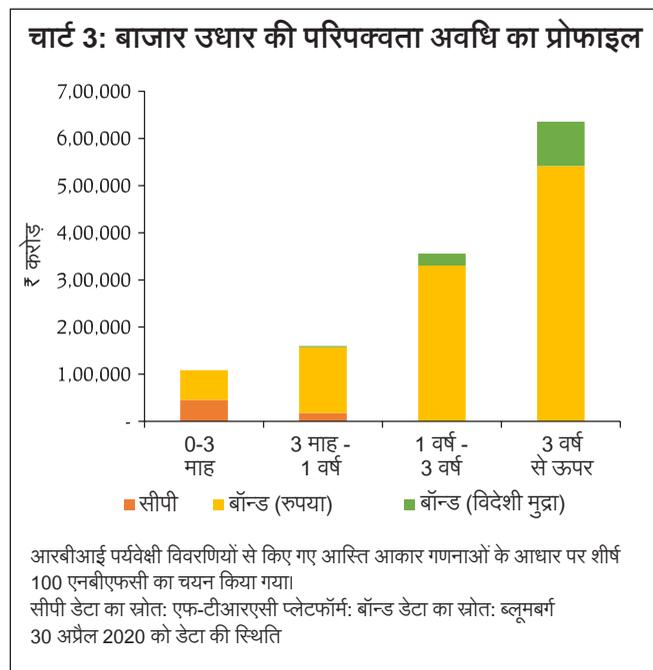
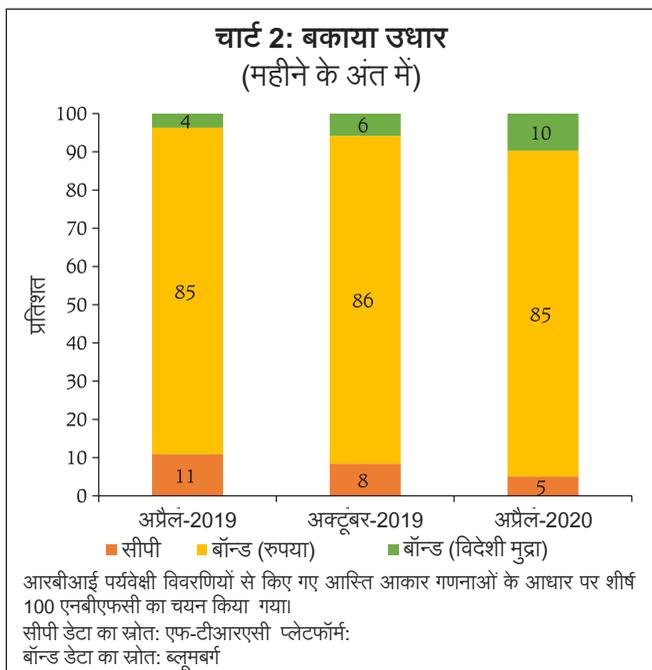
इस परिस्थिति में, यह लेख एनबीएफसी की वित्तपोषण स्थितियों पर हाल की घटनाओं के प्रभाव की जांच करता है। यह एनबीएफसी की क्षमता पर उनके प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करता है ताकि अपने चुकौती दायित्वों और धन संबंधी अन्य जरूरतों को पूरा करने के लिए बाजारों से धन जुटा सके। यह विश्लेषण एनबीएफसी की बाजार देनदारियों तक सीमित है और उनके बैंक उधारों के प्रभाव (सुधार या अन्यथा) में कारक नहीं है, यह देखते हुए कि 2018-19 के दौरान एनबीएफसी को दिए गए बैंक ऋण में 29 प्रतिशत की मजबूत वृद्धि हुई है और 2019-20⁵ में 26% की वृद्धि हुई है। खंड II में आर्स्टि आकार के संदर्भ में शीर्ष 100 एनबीएफसी द्वारा बाजार आधारित उधार के विकास पर चर्चा की गयी है। खंड III और IV में क्रमशः

कॉर्पोरेट बॉन्ड और सीपी बाजारों में वित्तपोषण की स्थिति में परिवर्तन की जांच की गयी है। इस क्षेत्र के लिए चलनिधि के संदर्भ में आरबीआई द्वारा हाल ही में किए गए उपायों के प्रभाव पर खंड V में चर्चा की गयी है। खंड VI में अध्ययन का निष्कर्ष निकाला गया है।

II. शीर्ष के 100 एनबीएफसी की बाजार उधारियों में आए बदलाव

30 अप्रैल 2020 तक सीपी और बॉन्ड (ऑनशोर और ऑफशोर दोनों) के माध्यम से शीर्ष 100 एनबीएफसी के लिए बकाया बाजार उधार लगभग ₹ 12.6 लाख करोड़ था, जो एक साल पहले के ₹ 12.5 लाख करोड़ से अधिक था। पिछले एक साल के दौरान मासिक बाजार उधार ₹ 60,000 करोड़ से ₹ 1,00,000 करोड़ के बीच में रहा। अप्रैल 2020 में हालांकि, इस तरह के उधार ₹ 33,000 करोड़ (चार्ट 1) से कम हो गए। विशेष रूप से वित्त वर्ष 2019-20 की अंतिम तिमाही में ऑफशोर उधार में वृद्धि हुई थी। नतीजतन, पिछले एक साल में, उनकी कुल बकाया बाजार देनदारियों में एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए विदेशी मुद्रा बॉन्ड की हिस्सेदारी भी बढ़ गई है क्योंकि सीपी की हिस्सेदारी कम हो गई है (चार्ट 2)। बकाया कॉर्पोरेट बॉन्ड की हिस्सेदारी काफी हद तक अपरिवर्तित रही।

⁵ भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किए गए बैंकों के सेक्टरल परिनियोजन के आंकड़ों के अनुसार।



एनबीएफसी की बकाया बाजार देनदारियों की परिपक्वता स्वरूप के विश्लेषण से पता चलता है कि 30 अप्रैल 2020 को ₹ 1.08 लाख करोड़ (या कुल बकाया बाजार उधार का 9 प्रतिशत के करीब) की अगले तीन महीनों के भीतर परिपक्वता है, जबकि और ₹ 1.6 लाख करोड़ (या कुल बकाया बाजार उधार का 13.4 प्रतिशत) निम्नलिखित नौ महीनों (चार्ट 3) में देय है। कुछ एनबीएफसी को प्रतियोगी दरों पर मोचन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने / वित्तपोषण करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जैसा कि खंड III और IV में सेक्टर के लिए वर्तमान वित्तीय स्थिति और समग्र आर्थिक वातावरण को देखते हुए दिया गया है। कुछ हद तक, रिज़र्व बैंक द्वारा विनियामक चलनिधि को लेकर किए गए उपायों की बदौलत बैंकों द्वारा वित्तपोषण में इजाफा हुआ है और एनबीएफसी द्वारा लिए गए उधार के संबंध में मोहलत बढ़ाने को लेकर कुछ बैंकों द्वारा हाल में किए गए निर्णयों से इन चुनौतियों को कम किया जा सकता है।

III. कॉर्पोरेट बॉन्ड और एनसीडी

कॉर्पोरेट बॉन्ड और गैर-परिवर्तनीय डिबेंचर (एनसीडी) एनबीएफसी की कुल देनदारियों के 29 प्रतिशत⁶ हैं, जो इस क्षेत्र

⁶ शीर्ष 100 एनबीएफसी के आस्तित्व आकार से संबंधित आरबीआई पर्यवेक्षी (अनंतिम) विवरणियों के डेटा पर आधारित। डेटा 31 दिसंबर 2019 की स्थिति के अनुसार है।

को वित्त प्रदान करने में इस बाजार की महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाता है। बॉन्ड बाजार के माध्यम से एनबीएफसी के लिए वित्तपोषण की स्थिति का विश्लेषण विभिन्न मेट्रिक्स, अर्थात्, समग्र निर्गम में क्षेत्र की हिस्सेदारी; एए और निम्न रेटेड एनबीएफसी के लिए सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) के क्रय-विक्रय के बीच के अंतर; और बॉन्ड रोलओवर अनुपात (सारणी 1 और 2) के माध्यम से किया गया है।

सारणी 1: एनबीएफसी (सरकारी और निजी) के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार स्थिति की गतिविधियां

एनबीएफसी	सितं-19	अक्तू-19	नव-19	विसं-19	जन-20	फर-20	मार्च-20	अप्रै-20
कुल जारी कॉर्पोरेट बॉन्ड में शेयर	35%	12%	43%	25%	24%	43%	31%	20%
बीपीएस में 3 साल का स्प्रेड (एए जी सेक)	129	154	129	119	95	110	156	198
बीपीएस में 3 साल का स्प्रेड (एए जी सेक)	210	228	212	190	174	185	226	274
बॉन्ड रोलओवर अनुपात (जारी/मोचन) #	1.51	1.32	1.68	1.44	2.45	3.53	1.01	1.01

स्रोत: प्राइम डेटाबेस, ब्लूमबर्ग
लाल रंग एक साल की सामान्य औसत गति की तुलना में महीने में बिगड़ते हालात की ओर इशारा करता है जबकि हरा रंग हालात में सुधार का संकेत देता है।
शीर्ष 100 एनबीएफसी द्वारा जारी किए गए बॉन्ड (आई एन आर और एफ सी वाइ बॉन्ड दोनों) शामिल हैं।

सारणी 2: एनबीएफसी-प्राइवेट के लिए कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार स्थितियों में आए बदलाव

(प्रतिशत में)

एनबीएफसी निजी	सितं-19	अक्तू-19	नव-19	दिसं-19	जन-20	फर-20	मार्च-20	अप्रै-20
कुल जारी में शेयर	13	4	19	13	10	26	11	5
सभी एनबीएफसी द्वारा जारी में शेयर	38	36	45	51	42	61	37	26
सभी एनबीएफसी द्वारा जारी में एए रेटेड बॉन्ड का शेयर	23	17	31	28	38	41	18	26
सभी एनबीएफसी द्वारा जारी में एए + उससे नीचे रेटेड बॉन्ड का शेयर	15	20	14	23	4	20	20	0

स्रोत: प्राईम डेटाबेस, ब्लूमबर्ग
लाल रंग एक साल की सामान्य औसत गति की तुलना में महीने में बिगड़ते हालात की ओर इशारा करता है जबकि हरा रंग हालत में सुधार का संकेत देता है।

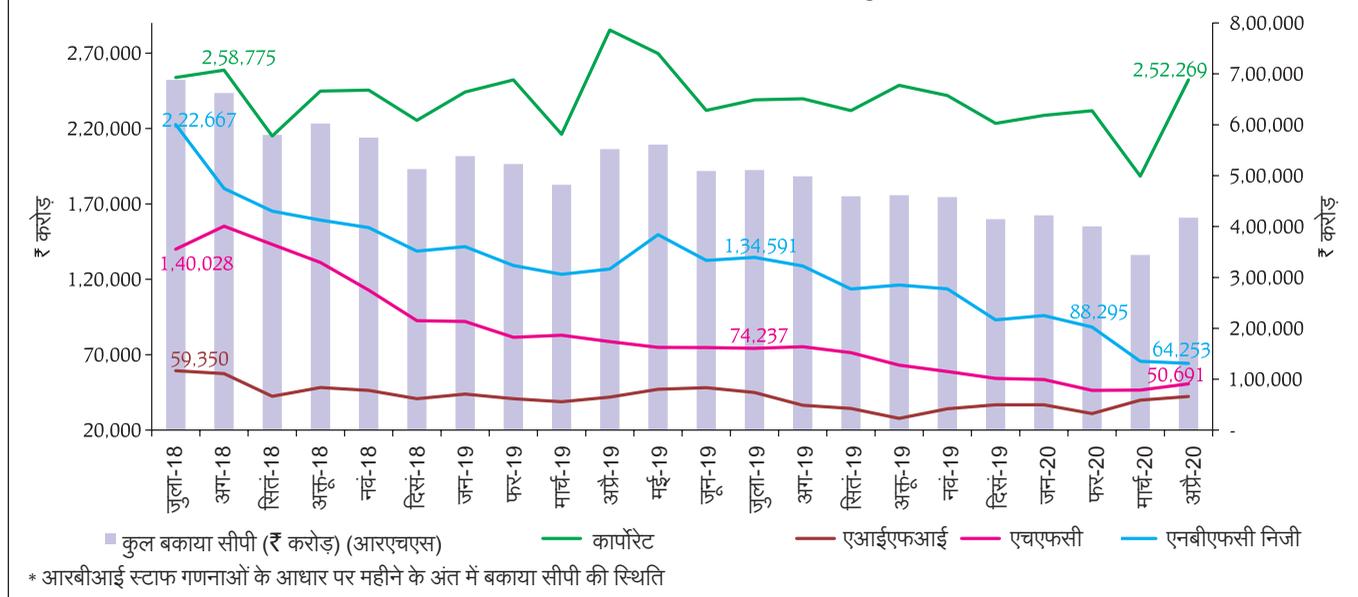
कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में वित्तपोषण की स्थिति, जो आईएल एंड एफएस घटनाक्रम के बाद से दबावग्रस्त बनी हुई है, धीरे-धीरे दिसंबर 2019 से फरवरी 2020 की अवधि में स्थिर हो गई और कम ब्याज दर, उच्च बैंकिंग प्रणाली चलनिधि और रिजर्व बैंक द्वारा लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (एलटीआरओ) जैसे चलनिधि समर्थन उपायों से उसे सहायता मिली है। इसे फरवरी 2020 के महीने के लिए हरे रंग से चित्रित किया गया है। आरबीआई द्वारा जनवरी 2019 में बाहरी वाणिज्यिक उधार

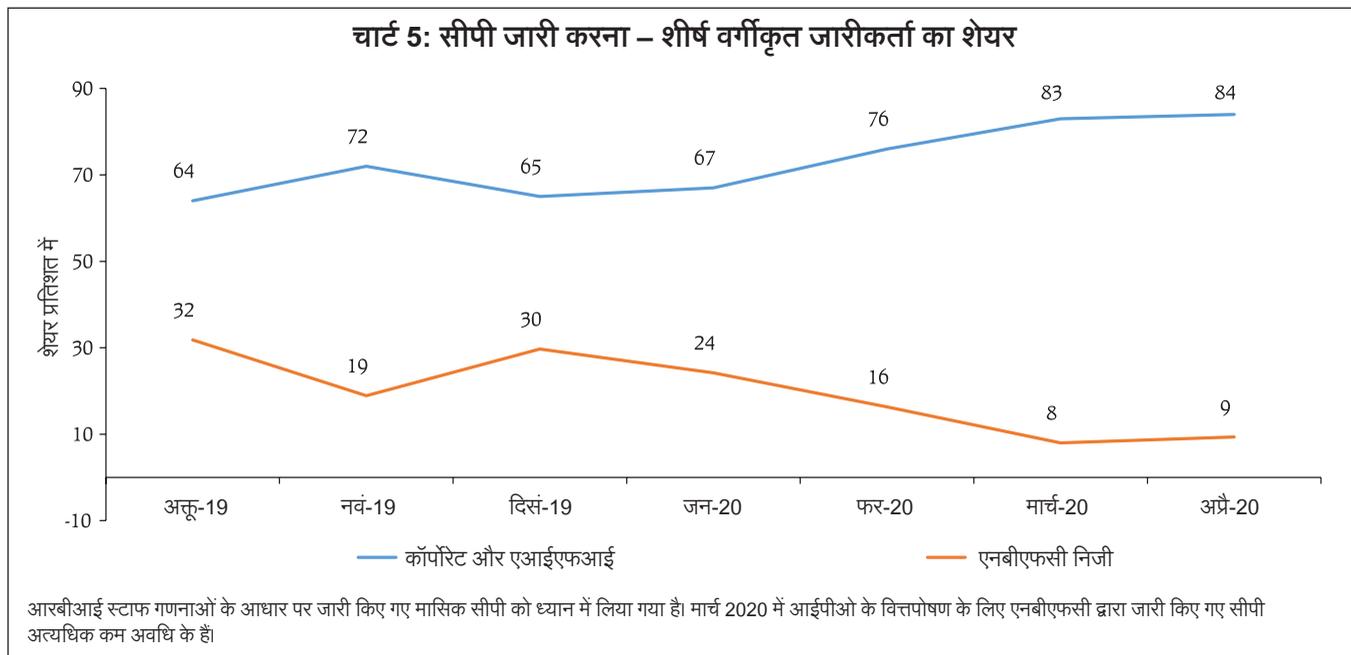
(ईसीबी) दिशा-निर्देशों को युक्तिसंगत करने से भी एनबीएफसी को विदेशी पूंजी पहुंच की सुविधा मिली और उनके वित्त पोषण के तरीकों में विविधता लाने में सहायक हुई। हालांकि, कोविड-19 के प्रकोप के बाद, एनबीएफसी के लिए बाजार की स्थितियों में गिरावट के संकेत मिले हैं, साथ ही एनबीएफसी-प्राइवेट के वित्तपोषण की स्थिति पर अपेक्षाकृत अधिक प्रभाव दिखाई दिया। कुल कॉर्पोरेट बॉन्ड निर्गमों में उनकी हिस्सेदारी फरवरी 2020 में 26 प्रतिशत से तेजी से गिरते हुए अप्रैल 2020 में 5 प्रतिशत रह गई।

IV . सीपी मार्केट

आईएल एण्ड एफएस से संबंधित घटनाक्रम के बाद, कुल बकाया सीपी, जो 31 जुलाई 2018 तक ₹ 6.88 लाख करोड़ थे, 30 अप्रैल, 2020 तक मुख्य रूप से एनबीएफसी-प्राइवेट और आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) के मामले में 39 प्रतिशत घटकर ₹4.17 लाख करोड़ रह गए। कॉरपोरेट्स और अखिल भारतीय वित्तीय संस्थाओं (एआईएफआई) के मुद्दे काफी हद तक अपरिवर्तित रहे। विशेष रूप से एनबीएफसी-प्राइवेट के बकाया सीपी 71 प्रतिशत से गिर गए (31 जुलाई 2018 के ₹ 2.22 लाख करोड़ से 30 अप्रैल, 2020 के ₹64,253 करोड़ तक) (चार्ट 4)।

चार्ट 4: बकाया सीपी- वर्गीकरण के अनुसार



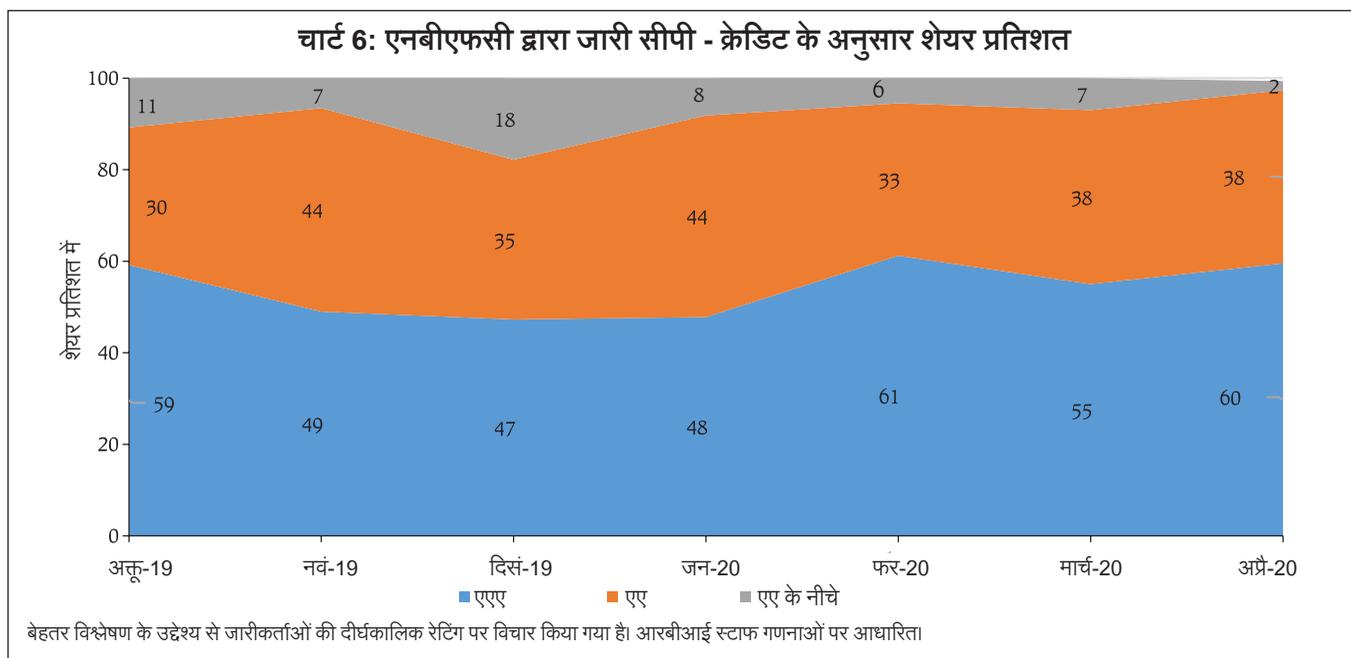


IV.1 एनबीएफसी द्वारा सीपी जारी करना

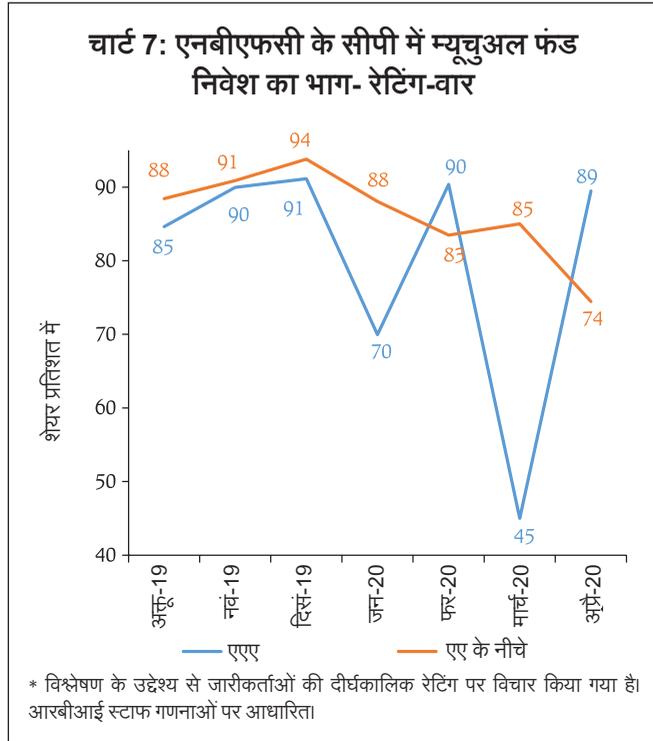
कॉर्पोरेट्स और एआईएफआई श्रेणी के जारीकर्ताओं के सीपी निर्गम, कुल निर्गम के प्रतिशत के रूप में, लगातार बढ़ रहे हैं (चार्ट 5)। हालांकि, कुल निर्गमों में विशेषतः फरवरी और मार्च 2020 के दौरान एनबीएफसी-प्राइवेट की हिस्सेदारी में तेजी से गिरावट आई है।

IV.2 निम्न रेटेड एनबीएफसी

भले ही एनबीएफसी द्वारा सीपी के समग्र निर्गमों में हाल के महीनों में गिरावट आई है, निम्न रेटेड एनबीएफसी द्वारा निर्गमों में तेजी से कमी आई है, संभवतः यह उनके द्वारा सामना की जा रही चुनौतीपूर्ण वित्तीय परिस्थितियों के कारण हो सकता है (चार्ट 6)।



सीपी बाजार के सबसे बड़े निवेशक म्यूचुअल फंड ने, जनवरी और मार्च 2020 के महीने को छोड़कर जब बैंक प्रमुख ग्राहक थे, एए और निम्न रेटेड एनबीएफसी में अपना हिस्सा दिसंबर 2019 के 94 प्रतिशत से अप्रैल 2020 में 74 प्रतिशत तक नीचे लाया। (चार्ट 7)

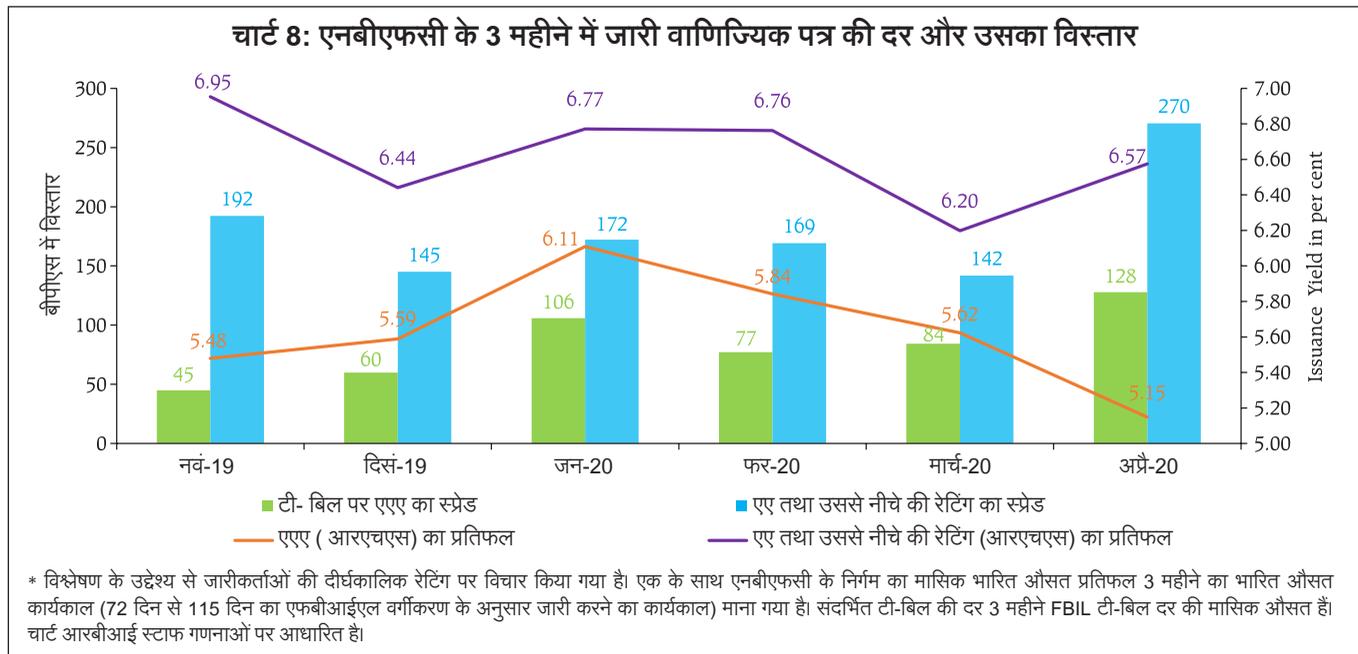


IV.3 सीपी निर्गमों का मूल्य निर्धारण

हाल की अवधि में, नीतिगत दरों में कटौती के अनुरूप एए रेटेड एनबीएफसी की निर्गम दरों में कमी आई है। निम्न रेटेड एनबीएफसी की आय भी घटी है लेकिन समानुपातिक रूप से नहीं। जनवरी और अप्रैल 2020 के बीच एए रेटेड कॉर्पोरेट्स के सीपी निर्गमों से हुई आय में औसतन 96 आधार अंकों की कमी आई जबकि इसी अवधि में निम्न रेटेड निर्गमों से हुई आय में मात्र 20 आधार अंकों की कमी आई। इसी समय अप्रैल 2020 के महीने में समान मीयाद के ट्रेजरी-बिलों को लेकर एए और निम्न रेटेड पेपर्स के क्रय-विक्रय अंतर में तेज वृद्धि भी हुई थी (चार्ट 8)।

V. आरबीआई द्वारा किए गए उपाय

मार्च 2020 से रिजर्व बैंक ने चलनिधि की कमी को दूर करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड और सीपी के लिए डी-स्ट्रेसिंग मार्केट देने के उद्देश्य से पॉलिसी रेपो दर से जुड़ी एक फ्लोटिंग दर पर ₹ 1 लाख करोड़ तक की कुल राशि के लिए तीन वर्ष के टारगेट लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस (टीएलटीआरओ) का लक्ष्य रखा। बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत प्राप्त चलनिधि का निवेश ग्रेड कॉर्पोरेट बॉन्ड, सीपी और एनसीडी में निवेश किया जाना था। इस सुविधा के अंतर्गत निवेश को भी परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, यहां तक कि कुल निवेश का 25 प्रतिशत से अधिक एचटीएम पोर्टफोलियो में



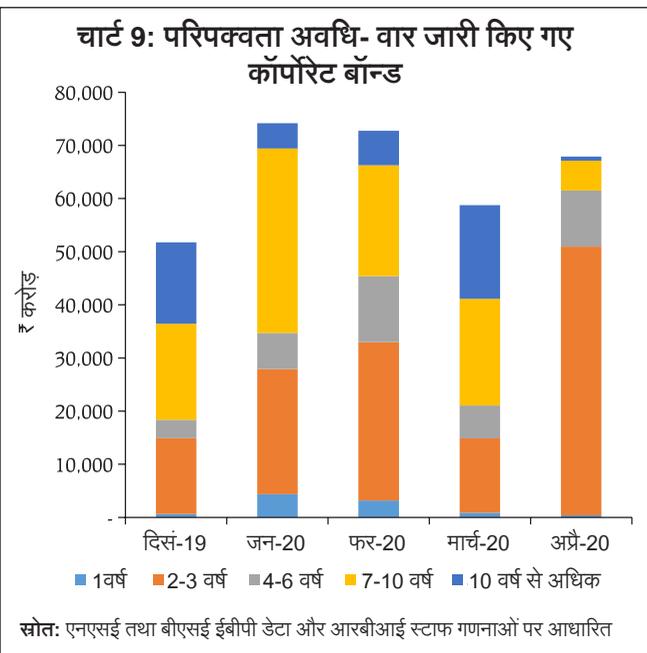
सारणी 3: कॉर्पोरेट बॉन्ड जारी करने की भारत औसत दर
(प्रतिशत में)

अवधि	दिसं-19	जन-20	फर-20	मार्च-20	अप्रै-20
1 वर्ष	7.24	7.38	8.43	7.59	6.90
2-3 वर्ष	8.16	7.48	7.54	8.52	7.05
4-6 वर्ष	7.93	7.39	7.35	7.39	7.38
7-10 वर्ष	7.96	7.72	7.53	7.37	7.99
10 वर्ष से अधिक	8.14	8.78	7.24	7.72	6.80

स्रोत : एनएसई और बीएसई ईबीपी डेटा पर आधारित

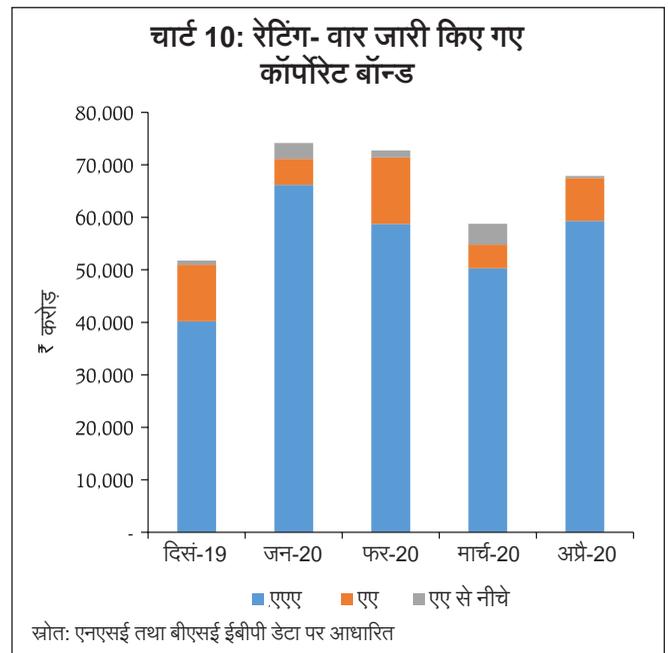
शामिल करने की अनुमति है। इसके अलावा, इस सुविधा के अंतर्गत उनके एक्सपोजर को बड़े एक्सपोजर फ्रेमवर्क के अंतर्गत नहीं माना जाएगा।

टीएलटीआरओ का बाजार पर एक स्वस्थ प्रभाव था। इन नीलामियों के परिणामस्वरूप कॉर्पोरेट बॉन्ड मार्केट में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और एनबीएफसी सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा सामना किए गए चलनिधि दबावों में सुधार हुआ। अप्रैल 2020 में 2-3 वर्षों के बकेट में निर्गम का भारत औसत दर भी लगभग 150 आधार अंकों से कम हुआ था (सारणी 3)। एनबीएफसी द्वारा निर्गम के संबंध में, बकेट का निर्गम भारत औसत दर लगभग 85 बीपीएस हो गया। अप्रैल 2020 में कुल निर्गम के लगभग 74 प्रतिशत 2-3 साल के बकेट में था, जबकि फरवरी और मार्च 2020 के दौरान 2-3 वर्षों के बकेट में निर्गम लगभग क्रमशः 41 प्रतिशत और 24 प्रतिशत था (चार्ट 9)।



मार्च और अप्रैल 2020 के दौरान एनबीएफसी और एचएफसी के बाद कॉर्पोरेट्स (बैंकों सहित) प्रमुख निर्गमकर्ता श्रेणियों में से एक थे। हालांकि, पिछले महीनों की तरह, मार्च-अप्रैल 2020 में अधिकांश निर्गम एए रेटेड संस्थाओं और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (चार्ट 10) द्वारा किए गए थे, जो यह दर्शाता है कि टीएलटीआरओ के लाभ का बड़ा हिस्सा उच्च श्रेणी की संस्थाओं को मिला है। अप्रैल में सीपी बाजार में, सभी श्रेणियों में निर्गम कम थे क्योंकि निर्गमकर्ता रोल-ओवर के जोखिमों से बचने के लिए लंबे मीयाद वाले बॉन्ड जारी करना और कम दरों को लंबे समय तक लॉक-इन करना पसंद कर रहे थे।

एनबीएफसी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं (एमएफआई) सहित छोटे और मध्यम आकार के कॉर्पोरेट्स को चलनिधि का प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए, रिजर्व बैंक ने ₹ 50,000 करोड़ की कुल राशि के लिए टीएलटीआरओ 2.0 का संचालन करने का निर्णय लिया। टीएलटीआरओ 2.0 के अंतर्गत बैंकों द्वारा लिए गए फंड को निवेश ग्रेड बॉन्ड, सीपी और एनबीएफसी के एनसीडी में निवेश किया जाना चाहिए, जिसमें कुल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत लाभ छोटे और मध्यम आकार के एनबीएफसी और एमएफआई में जाना चाहिए। हालांकि, इन नीलामियों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक नहीं रही और ₹ 25,000 करोड़ की अधिसूचित राशि के लिए टीएलटीआरओ 2.0 की पहली किश्त का बोली रक्षा अनुपात 0.5 रहा।



VI. निष्कर्ष

आगे बढ़ते हुए, एनबीएफसी द्वारा सीपी और कॉर्पोरेट बॉन्ड के माध्यम से लिए गए बाजार उधार के संबंध में निर्धारित पुनर्भुगतान की वजह से निकट समय में बड़े मोचन की स्थिति पैदा हो सकती हैं। अपनी आस्तियों पर एनबीएफसी/ एचएफसी द्वारा बढ़ाए गए अधिस्थगन, जोखिम से बचने के समग्र वातावरण के साथ मिलकर, इस क्षेत्र के लिए कैशफ्लो को प्रभावित कर सकते हैं। इनमें से कुछ एनबीएफसी के लिए चलनिधि दबाव बने रहने की संभावना, विशेष रूप से बाजार उधार पर उच्च निर्भरता वाले लोगों को खारिज नहीं किया जा सकता है। एक निश्चित सीमा तक, कुछ एनबीएफसी द्वारा बैंक के उधार और / या समूह समर्थन में वृद्धि के माध्यम से इस अंतर को कम किया जा सकता है। हालांकि, एनबीएफसी के प्रमुख उधारदाताओं में से एक - म्यूचुअल फंड उद्योग - अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण और कुछ डेट फंडों के बंद होने के प्रभाव के कारण भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। इस संदर्भ में, एनबीएफसी क्षेत्र, कुछ एनबीएफसी के लिए जो बाजार उधार के माध्यम से अपनी वित्तपोषण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए प्रतिकूल हालातों का सामना करना पड़ सकता है।

रिजर्व बैंक द्वारा किए गए उपायों ने बाजार की स्थितियों में दबाव को काफी कम कर दिया है; हालांकि, बाजार के कुछ क्षेत्रों में अभी भी दबाव दिखाई दे रहा है। यह प्रतीत होता है कि समस्या सिर्फ चलनिधि की नहीं है, बल्कि संभवतः, कोविड-19 संबंधित व्यवधानों के कारण ऋण गुणवत्ता में गिरावट संभावित है।

उभरते घटनाक्रम नीतिगत हस्तक्षेप की आवश्यकता की ओर निर्देश करते हैं, जो कि क्रेडिट संबंधित चलनिधि उपायों से हैं। एनबीएफसी को क्रेडिट / चलनिधि के प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए ठोस क्रेडिट बैकस्टॉप उपायों के साथ सिस्टम में जोखिम का पता लगाने, विश्वास में आई कमी को पाटने और विश्वास को बहाल करने की आवश्यकता है।

यह लेख प्रेस तक जाते जाते, भारत सरकार ने एक आर्थिक प्रोत्साहन पैकेज के हिस्से के रूप में, दो अलग-अलग योजनाओं के अंतर्गत एनबीएफसी द्वारा जारी ऋण प्रतिभूतियों में निवेश पर पूर्ण और आंशिक गारंटी की घोषणा की है। पहली योजना एनबीएफसी और एचएफसी के लिए ₹ 30,000 करोड़ की विशेष चलनिधि सुविधा है, जिसके अंतर्गत एक विशेष प्रयोजन वाहन

(एसपीवी) पात्र एनबीएफसी / एचएफसी की छोटी अवधि (3 महीने तक की अवशिष्ट परिपक्वता) के निवेश ग्रेड ऋण का अधिग्रहण करेगा। एक अन्य योजना के माध्यम से, जो पहले से मौजूद आंशिक क्रेडिट गारंटी योजना (पीसीजीएस) का विस्तार है, सरकार एनबीएफसी द्वारा, अन्य के साथ, जारी एए और नीचे की रेटिंग वाले बॉन्ड या सीपी की सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा खरीद के मामले में प्रथम बार होने वाले नुकसान के 20 प्रतिशत तक की गारंटी देगी (एक वर्ष तक की मूल/प्रारंभिक परिपक्वता वाले अनरेटेड कागज सहित)। इन उपायों से एनबीएफसी के सीपी और बॉन्ड के प्रतिफल में कमी आ सकती है, जो रिजर्व बैंक द्वारा पहले ही घोषित किए गए उपायों के पूरक हैं और एनबीएफसी के लिए बाजार से कर्ज उपलब्ध कराने/रोलिंग-ओवर में होने वाली चुनौतियों को कम करेगा। बाजार वित्तपोषण की स्थिति में सुधार और एनबीएफसी क्षेत्र को ठोस बैंक ऋण से इस क्षेत्र के लिए चलनिधि की स्थिति आसान होने की उम्मीद है।

मध्यम अवधि में, कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजारों को गहरा करने की आवश्यकता है। कॉर्पोरेट बॉन्ड के मूल्यांकन के मानकीकरण के परिणामस्वरूप निवेशकों के लिए पारदर्शी मूल्य निर्धारण किया जा सकेगा, जिससे उन्हें अपने जोखिम के संबंध में अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद मिलेगी। निवेशक आधार के विविधीकरण और दीर्घकालिक निवेशकों से बढ़ती भागीदारी की भी आवश्यकता होगी। इन सभी उपायों को एक सक्रिय क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप (सीडीएस) बाजार के माध्यम से कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार में क्रेडिट जोखिम हस्तांतरण तंत्र द्वारा समर्थित होने की आवश्यकता है। द्विपक्षीय तालमेल के जरिए कानून लागू करने से सीडीएस बाजार को बढ़ावा मिल सकता है।

संदर्भ

Shri P Vijaya Bhaskar (2014), "Non-Banking Finance Companies: Game Changers", Speech delivered at ASSOCHAM, Delhi

V. Acharya, H. Khandwala, T.S. Öncü (2013), "The growth of a shadow banking system in emerging markets: Evidence from India", *Journal of International Money and Finance*, 39 (2013), pp. 207-230

RBI (2019), *Financial Stability Report*, July, Reserve Bank of India, Mumbai.

केंद्र सरकार के वित्त 2019-20 का अंतिम लेखा: एक आकलन *

29 मई 2020 को लेखा महानियंत्रक कार्यालय (सीजीए) द्वारा जारी 2019-20 के लिए केंद्र सरकार के वित्त के अंतिम लेखा (पीए) के आंकड़े राजकोषीय संतुलन में गिरावट की ओर इशारा करते हैं जिसका मुख्य मुख्य कारण धीमी वृद्धि के परिणामस्वरूप राजस्व में कमी और वर्ष के दौरान इससे निपटने के लिए किए जा रहे संरचनात्मक उपाय हैं। दूसरी ओर, 2018-19 की दूसरी छमाही से गहराई आर्थिक मंदी के मद्देनजर खर्च में किसी भी तरह की कटौती से बचा गया है। यह देखते हुए कि 2020-21 के बजट अनुमानों को 2019-20 के संशोधित अनुमानों (आरई) के आधार पर अनुमानित किया गया था, 2019-20 (पीए) की तुलना में 2019-20 (आरई) में कर राजस्व संग्रह में कमी 2020-21 के राजकोषीय अंकगणित को बिगाड़ सकती है।

परिचय

कोविड-19 महामारी की पृष्ठभूमि के निमित्त, यह आलेख वर्ष 2019-20 में भारत सरकार (जीओआई) के अंतिम लेखा (पीएआई) का संक्षिप्त अवलोकन प्रस्तुत करता है। 1 फरवरी, 2020 को वर्ष 2020-21 के लिए केंद्रीय बजट के साथ जारी किए गए वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान (आरई) ने बजट अनुमानों (बीई) के सापेक्ष जीओआई वित्त में गिरावट के बारे में बताया था, जो राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन (एफआरबीएम) मोचन खंड के उपयोग को न्यायसंगत ठहराता है। अंतिम लेखा राजकोषीय संतुलन में एक और गिरावट को दर्शाता है, जिसका मुख्य कारण राजस्व में कमी है।

इस पृष्ठभूमि में, आलेख के बाकी हिस्सों को इस परिचयात्मक खंड सहित आठ खंडों में विभाजित किया गया है। तुरंत बाद वाले खंड में, सकल राजकोषीय घाटे और इसके अंतर्निहित राजकोषीय अंकगणित पर चर्चा की गई है। खंड III और IV में क्रमशः प्राप्ति और खर्चों की जांच की गयी है। खंड V सकल राजकोषीय घाटे

(जीएफडी) के वित्तपोषण पैटर्न से संबंधित है। खंड VI में भारत सरकार की बकाया देनदारियों के बारे में बताया गया है। खंड VII में भारत सरकार से राज्यों में संसाधन हस्तांतरण का विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। खंड VIII में समापन निष्कर्ष दिए गए हैं। आंकड़े परिशिष्ट 1 में दिए गए हैं।

II. अंतिम लेखा में अंतर्निहित राजकोषीय अंकगणित

किसी राजकोषीय वर्ष के लिए अंतिम लेखा लगभग दो महीने के अंतराल के साथ उपलब्ध रहते हैं, जबकि अंतिम लेखा लगभग आठ महीने¹ के अतिरिक्त अंतराल के साथ आते हैं। अंतिम लेखा बीई और आरई की तुलना में वास्तविक डेटा के करीब होते हैं (चार्ट 1)।

अंतिम लेखा में 2019-20 के लिए भारत सरकार के सकल राजकोषीय घाटे को जीडीपी के 4.6 प्रतिशत पर रखा गया है, जो आरई (जीडीपी के 3.8 प्रतिशत) के मुकाबले जीडीपी का 0.8 प्रतिशत और बीई (जीडीपी का 3.3 प्रतिशत) के मुकाबले लगभग 1.3 प्रतिशत अधिक चला गया है। बीई और आरई के बीच जीडीपी के 0.5 प्रतिशत के पार चले जाने से संशोधित एफआरबीएम अधिनियम² की धारा 4(3) के तहत प्रावधानों को लागू करने का अधिकार खुद ही मिल गया। वर्ष 2019-20 में जीएफडी में गिरावट मुख्य रूप से बीई से शुद्ध कर राजस्व में जीडीपी के 1.1 प्रतिशत की गिरावट के कारण हुई (सारणी 1)।

एफआरबीएम के बाद से प्रदर्शन

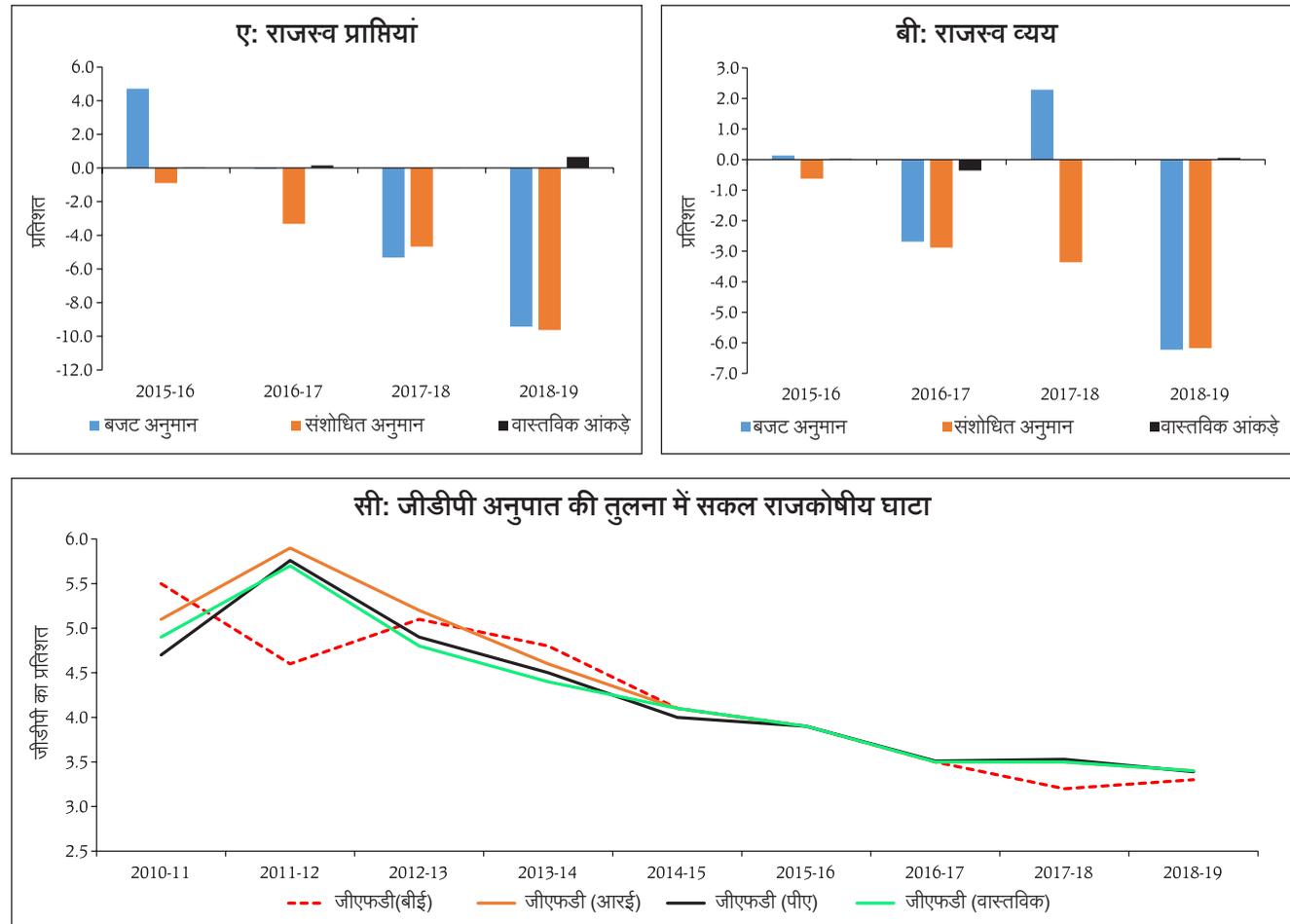
दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य में, 2003 में एफआरबीएम अधिनियम के अधिनियमित होने के बाद की अवधि को अलग-अलग चरणों में विभाजित किया जा सकता है (चार्ट 2)। एफआरबीएम के तत्काल बाद की अवधि में महत्वपूर्ण समेकन देखने को मिला, जिसमें 2003-04 में जीएफडी 4 प्रतिशत से अधिक घटकर 2007-08 में 2.7 प्रतिशत हो गया, जिसे उच्च जीडीपी वृद्धि और संबद्ध उच्च कर संग्रहण में उछाल से बल मिला। वर्ष 2008-09 के बाद से पांच साल की अवधि वैश्विक

* भारतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग की संगीता मिश्रा, समीर रंजन बेहरा, कौशिकी सिंह और सक्षम सूद द्वारा तैयार किया गया है। अंशुमान कामिला से डेटा सहयोग अभिस्वीकृत है। व्यक्त किए गए विचार लेखकों के हैं और संस्था से संबंधित नहीं हैं। सामान्य अस्वीकरण इस पर भी लागू होते हैं।

¹ उदाहरण के लिए, 2019-20 (पीए) को सीजीए द्वारा 29 मई 2020 को जारी किया गया, जबकि 2019-20 के लिए वास्तविक डेटा फरवरी 2021 में केंद्रीय बजट 2021-22 के हिस्से के तौर पर केंद्र द्वारा जारी किया जाएगा।

² भारतीय रिजर्व बैंक (2020)। केंद्रीय बजट 2020-21- एक आकलन, आरबीआई बुलेटिन, अप्रैल।

चार्ट 1: विभिन्न केंद्रीय सरकार के अनुमानों से अनंतिम लेखा का विचलन



स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

वित्तीय संकट (जीएफसी) के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए बड़े पैमाने पर राजकोषीय प्रोत्साहन से जुड़ी थी। हालांकि, व्यय

सारणी 1: मुख्य राजकोषीय संकेतक (जीडीपी का प्रतिशत)

	2018-19		2019-20			2020-21
	वास्तविक आंकड़े	बीई	आरई	पीए	बीई	
1	2	3	4	5	6	
1. राजकोषीय घाटा	3.4	3.3	3.8	4.6	3.5	
2. राजस्व घाटा	2.4	2.3	2.4	3.3	2.7	
3. प्राथमिक घाटा	0.4	0.2	0.7	1.6	0.4	
4. निवल कर राजस्व	6.9	7.8	7.4	6.7	7.3	
5. गैर-कर राजस्व	1.2	1.5	1.7	1.6	1.7	
6. राजस्व व्यय	10.6	11.6	11.5	11.6	11.7	
7. पूंजीगत व्यय	1.6	1.6	1.7	1.7	1.8	

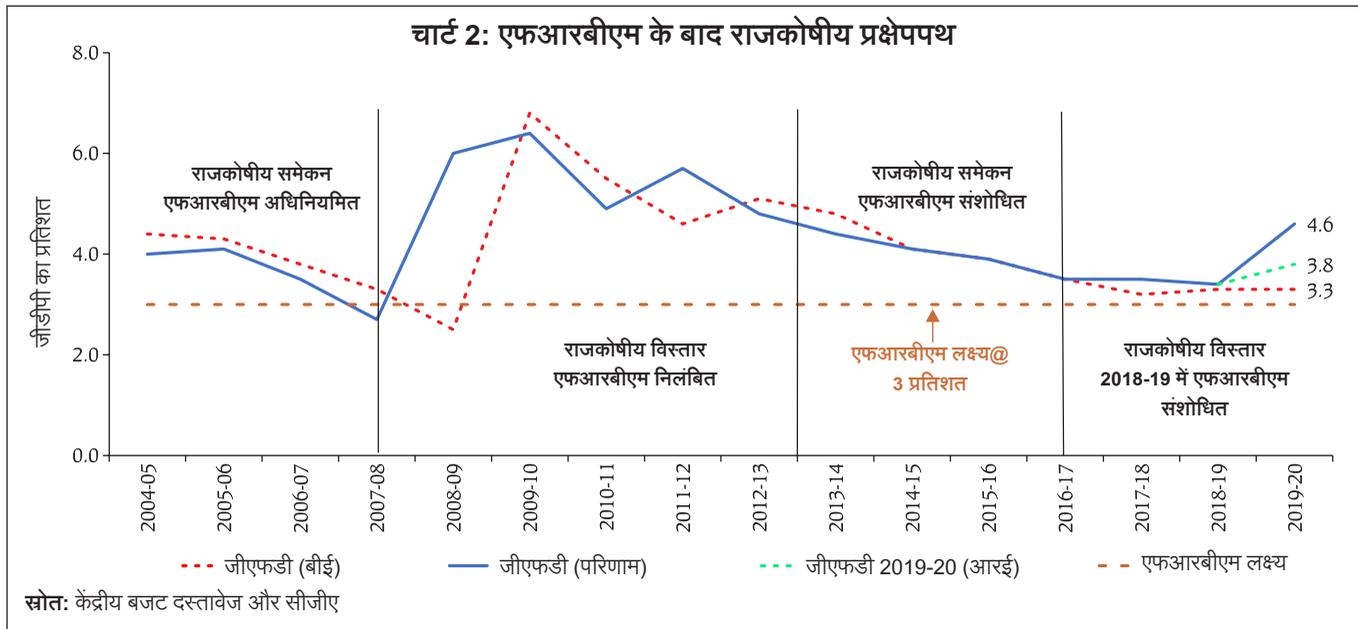
मेमो मद

सांकेतिक जीडीपी वृद्धि (प्रतिशत में)	11.0	12.0	7.8	7.2	10.0
--------------------------------------	------	------	-----	-----	------

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज, सीजीए और एनएसओ

में कटौती के माध्यम से लगभग 1 प्रतिशत अंक (2013-14 में 4.4 प्रतिशत से 2016-17 में 3.5 प्रतिशत) से कुल जीएफडी-जीडीपी अनुपात में गिरावट के साथ वर्ष 2013-14 से लेकर लगभग 2016-17 तक की अवधि में राजकोषीय अनुशासन देखने को मिला। वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि को राजकोषीय समेकन में एक ठहराव द्वारा चिह्नित किया गया है, जबकि 2019-20 में अच्छा-खासा लक्ष्य पार कर गया था (चार्ट 2)। जीएफसी से ठीक पहले की अवधि³ के विपरीत, भारत बाध्यकारी राजकोषीय गुंजाइश के साथ 2020-21 में कोविड-19 की महामारी में प्रवेश कर गया है।

³ संकट के समय राजकोषीय गुंजाइश की उपलब्धता ने जीएफडी-जीडीपी अनुपात को 2008-09 के बजटीय राजकोषीय घाटे से जीडीपी के 2.5 प्रतिशत के मुकाबले बढ़ाकर वास्तविक परिणामों में 6.0 प्रतिशत कर दिया।



अंतर्निहित गतिकी

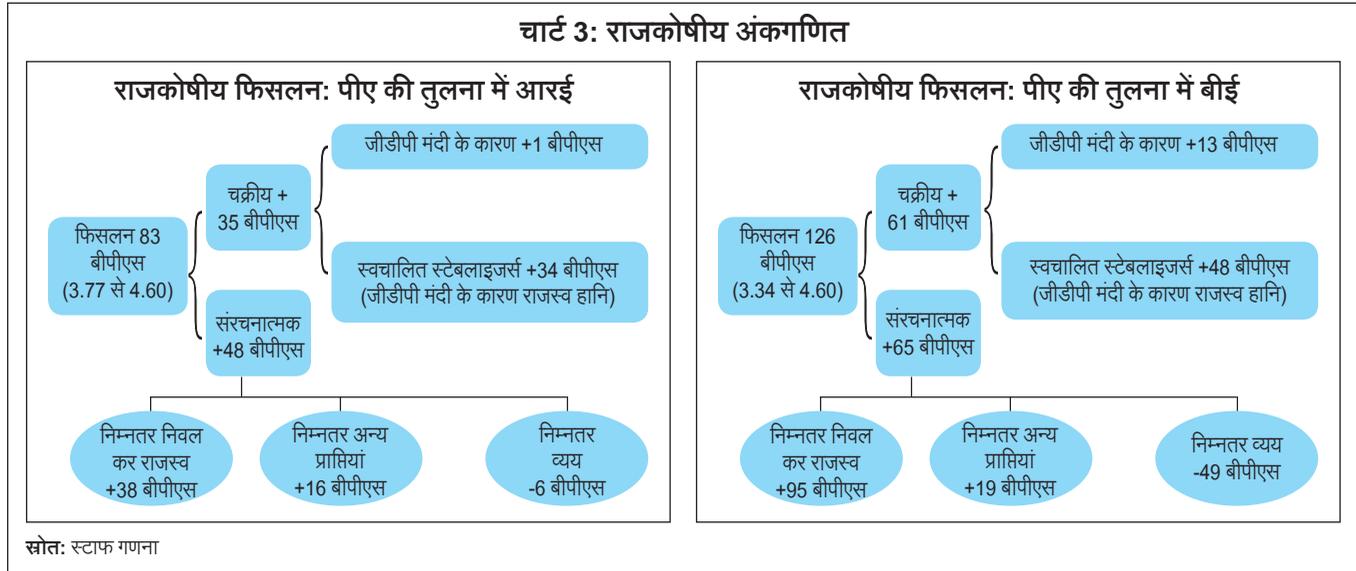
जहां 2019- 20 में राजकोषीय गिरावट का कुछ हिस्सा कॉर्पोरेट करों और वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में किए गए संरचनात्मक सुधारों की वजह से प्रत्याशित था, वहीं अप्रत्याशित घटक मामूली जीडीपी वृद्धि में तेज गिरावट से आया था (बीई में 12.0 प्रतिशत से आरई में 7.8 प्रतिशत और पीए में 7.2 प्रतिशत तक)। जीडीपी वृद्धि में मंदी का प्रभाव जीएफडी-जीडीपी अनुपात पर दो तरह से पड़ता है: (i) जीडीपी धीमी⁴ होने के कारण कर राजस्व में स्वाभाविक रूप से कमी होने पर स्वचालित स्टेबलाइजर्स चलन में आ जाते हैं, जिससे अंश बढ़ जाता है; और (ii) जीडीपी में अनुमानित मामूली वृद्धि कम होने के कारण हर बजट से कम है। इन दोनों को मिलाकर इसमें चक्रीय घटक, यानी राजकोषीय संतुलन पर व्यापार चक्रों का प्रभाव शामिल हैं। इस चक्रीय प्रभाव के लिए वास्तविक राजकोषीय संतुलन को समायोजित करने पर राजकोषीय संतुलन का संरचनात्मक घटक प्राप्त होता है जो अनिवार्य रूप से नीतिगत कार्रवाइयों के कारण विवेकाधीन परिवर्तनों को दर्शाता है।

⁴ सरकारी व्यय को, सामान्य रूप से, अपनी संपूर्णता में विवेकाधीन के रूप में देखा जाता है, और इस प्रकार यह कारोबार चक्र से स्वतंत्र है (बोर्नहोस्ट एवं अन्य, 2011)⁵। यह भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के लिए विशेष रूप से सत्य है जिनके पास व्यय नहीं है वह स्वाभाविक रूप से बेरोजगारी से संबंधित सामाजिक सुरक्षा लाभों की तरह धीमी गति से प्रतिक्रिया करते हैं जो कुछ उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में प्रचलित हो सकते हैं।
*: बॉर्नहोस्ट, एफ., गैब्रिएला, डी., फेडेलिनो, ए., गोस्चलक, जे., और नाकाटा, टी. (2011)। व्हेन एंड हाऊ टू एडजस्ट बियोन्ड द बिजनेस साइकिल? ए गाइड टू स्ट्रक्चरल फिस्कल बैलेंसेस। टेक्निकल नोट्स एंड मैनुअल्स 11/02, वाशिंगटन डीसी, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष।

वर्ष 2019-20 के दौरान, बीई से लेकर पीए तक, चक्रीय और संरचनात्मक कारक राजकोषीय फिसलन में समान रूप से साझा किए गए हैं (चार्ट 3)। चक्रीय प्रभावों के लिए समायोजित करने पर, जीएफडी जीडीपी⁶ का 4.0 निकलता है, जो अनंतिम अनुमानों की तुलना में 61 आधार अंक कम है, जिनमें से 13 आधार अंक हर पर निम्न जीडीपी वृद्धि के प्रत्यक्ष प्रभाव की वजह से है। यह ध्यान देने वाली बात है कि संरचनात्मक फिसलन का बड़ा हिस्सा (65 बीपीएस में से लगभग 50 बीपीएस) कॉर्पोरेट टैक्स दर और न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) दर में कटौती के साथ-साथ नई विनिर्माण कंपनियों के प्रोत्साहन के कारण था, जिसकी वजह से मोचन खंड⁶ के उपयोग की आवश्यकता पड़ गयी थी।

⁵ फेडेलिनो एनलिसा, मार्क हॉर्टन और अन्ना इवानोवा (2009) – का प्रयोग करके गणना। कम्प्यूटेशनल रूप से समायोजित बैलेंस और स्वचालित स्टेबलाइजर्स, टेक्निकल नोट्स और मैनुअल, फिस्कल अफेयर्स डिपार्टमेंट्स, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, दिसंबरा संभावित उत्पादन और कर लोच का अनुमान कर्मचारियों की गणना पर आधारित है।
⁶ यह ध्यान दिया जा सकता है कि सकल घरेलू उत्पाद में मंदी और उच्च मुद्रास्फीति में योगदान देने वाले क्षेत्रों में अंतर के कारण चक्रीय प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। जहां वास्तविक रूप में, विनिर्माण जैसे कर उत्पादन क्षेत्रों में जीडीपी अधिक धीमा हो गया है; वहीं अवास्तविक रूप में, जो वास्तव में राजकोषीय गणना में चला जाता है, मुद्रास्फीति बढ़ गई है, जो 2019-20 की दूसरी छमाही में खाद्य मुद्रास्फीति में बहुत अधिक है, जिस पर कर नहीं लगता है। इसके साथ ही, संरचनात्मक घटक में अप्रत्याशित बढ़ोतरी मार्च 2020 के अंत में घोषित कई नियामक उपायों से संबद्ध हो सकती है, जिसने ₹5 लाख तक आय अर्जित करने वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट और मानक कटौती में वृद्धि के साथ-साथ रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा को 31 मार्च, 2020 से बढ़ा कर 30 जून, 2020 तक कर दिया (पीआईबी, 07 जून, 2020)⁶। आयकर संग्रह में कमी के लिए इसे जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, जिसका हिस्सा संरचनात्मक घटक में जा रहा है (राजस्व खंड में विस्तार से दिया गया है)।
*: प्रेस सूचना ब्यूरो (पीआईबी). (2020)। प्रत्यक्ष कर संग्रह का वृद्धि दर और हाल के प्रत्यक्ष कर सुधार, वित्त मंत्रालय, 07 जून।

चार्ट 3: राजकोषीय अंकगणित



सारणी 2: जीएफडी का विश्लेषण

(प्रतिशत)

	2017-18		2018-19		2019-20		2020-21	
	बीई	वास्तविक	बीई	वास्तविक	बीई	आरई	पीए	बीई
1. राजस्व घाटा	58.8	75.1	66.6	70.0	68.9	65.1	71.3	76.5
2. पूंजीगत परिव्यय	49.4	41.5	44.6	43.0	44.2	41.9	33.1	47.8
3. निवल उधारी	5.1	0.4	1.5	1.6	1.8	1.4	0.9	2.1
4. निवेश (माइनस)	13.3	16.9	12.8	14.6	14.9	8.5	5.4	26.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

जीएफडी का विश्लेषण

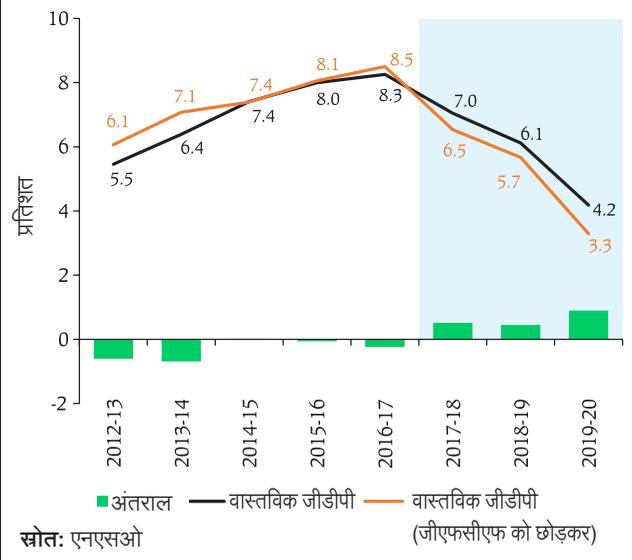
राजस्व घाटा वर्ष 2019-20 में जीएफडी के 70 प्रतिशत से अधिक हो गया। यह एक ऐसी घटना है जो 2017-18 से शुरू हुई है। हालांकि, 2017-18 और 2018-19 के विपरीत, 2019-20 पीए में विनिवेश से वित्त पोषण का समर्थन कम गया, जिससे पूंजीगत परिव्यय की हिस्सेदारी घट गयी (सारणी 2)।

राजकोषीय दबाव को उस सहायता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए जो उसने इन वर्षों में जीडीपी को प्रदान की है। जहां 29 मई, 2020 को जारी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) का नवीनतम जीडीपी प्रिंट 2019-20 में 4.2 प्रतिशत की वास्तविक वृद्धि दर को दर्शाता है; वहीं सरकारी खर्च को छोड़कर यह केवल 3.3 प्रतिशत ही रहा होगा (चार्ट 4)।

III. प्राप्ति

2019-20 (पीए) में, क्रमशः बीई के 9.9 प्रतिशत और आरई के 9.5 प्रतिशत के मुकाबले, कुल प्राप्ति जीडीपी के 8.6 प्रतिशत

चार्ट 4: वास्तविक जीडीपी वृद्धि: सरकारी खर्च के साथ और उसके बिना



पर रही। यह कमी निवल कर राजस्व के कारण थी जो जीडीपी के 6.7 प्रतिशत और विनिवेश प्राप्ति में से जीडीपी के 0.2 प्रतिशत के बराबर थी, जो कि क्रमशः बीई के 7.8 प्रतिशत और 0.5 प्रतिशत के मुकाबले थी। गैर-कर राजस्व अच्छी तरह से संभाला गया था और यहां तक कि बीई से भी मामूली रूप से अधिक हो गया था।

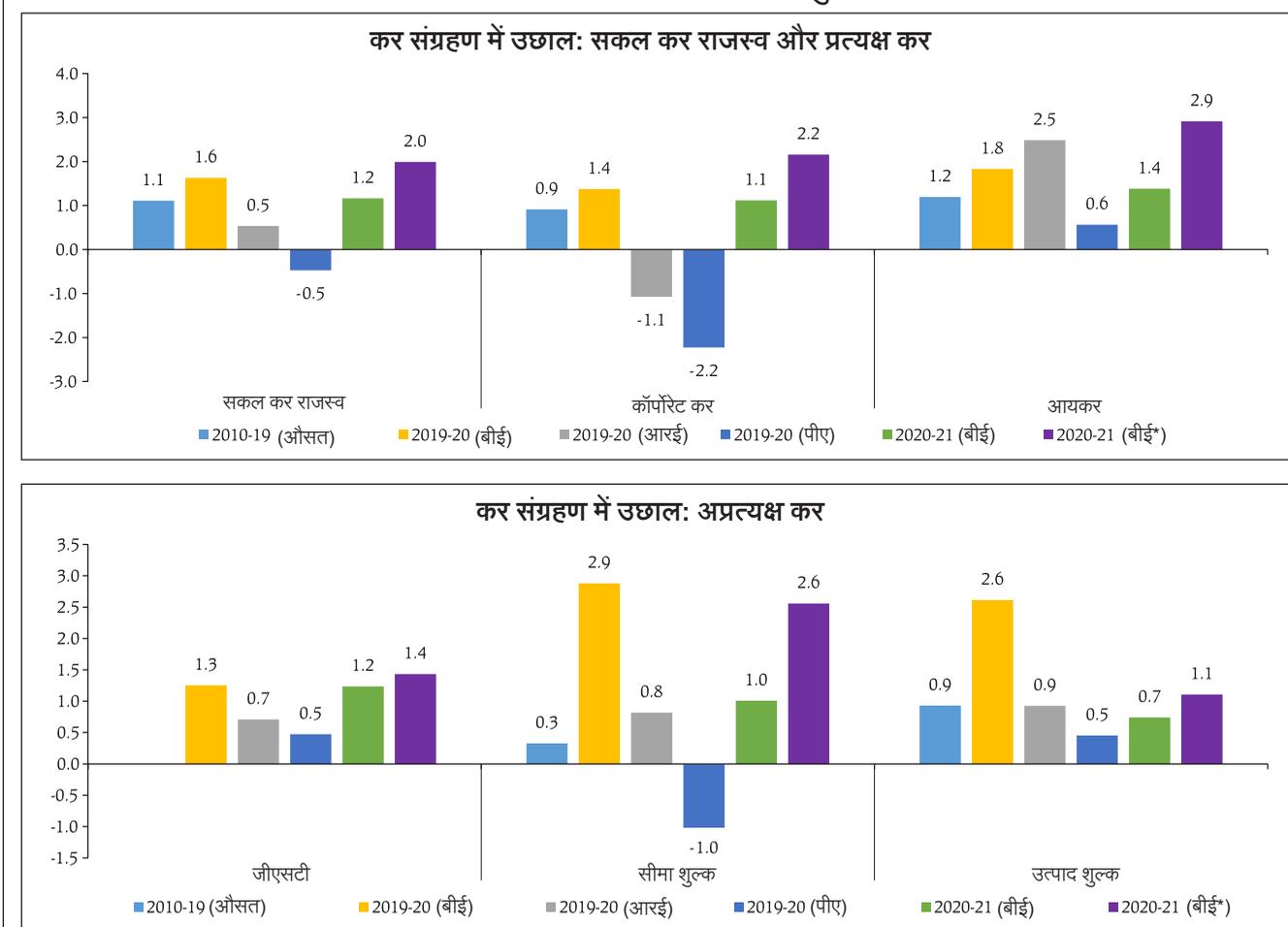
कर राजस्व

वर्ष 2010-11 से 2018-19 के दौरान प्राप्त 14.4 प्रतिशत के औसत के मुकाबले वर्ष 2019-20 में सकल कर राजस्व के लिए 18.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का बजट रखा गया था। संशोधित

अनुमानों में, इसे घटाकर 4.0 प्रतिशत किया गया था, लेकिन 2019-20 पीए के अनुसार वास्तविक वृद्धि दर (-) 3.4 प्रतिशत थी, जो कि गिरावट की तेजी में परिलक्षित हुई (चार्ट 5)। जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, 2019-20 के दौरान कर संग्रह में अभूतपूर्व कमी के लिए तीन व्यापक कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है: (1) वर्ष के दौरान वृद्धि में चक्रीय मंदी, (2) एमएटी दर में कटौती और नई विनिर्माण घरेलू कंपनियों के लिए प्रोत्साहन के

साथ कॉर्पोरेट कर की दर के मध्य-वर्ष के युक्तिकरण के संदर्भ में संरचनात्मक उपाय; और (3) कुछ अन्य उपाय अर्थात्, मानक कटौती में 5 लाख रुपये तक की आय वाले व्यक्तियों को आयकर से छूट, जैसा कि पहले बजट में घोषित किया गया था और 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाली समय-सीमा का विस्तार (विवाद से विश्वास योजना सहित) और वित्त वर्ष के अंत में घोषित कर भुगतान में विलंब के लिए राहत की स्थिति (पीआईबी, 2020)।

चार्ट 5: कर संग्रहण में उछाल के अनुमान



टिप्पणी: 2020-21 (बीई) का आशय 2019-20 (आरई) से 2020-21 (बीई) के लिए कर संग्रहण में उछाल से है जिसमें 10 प्रतिशत (बजट) की मामूली जीडीपी वृद्धि का अनुमान है; 2020-21 (बीई*) का आशय 2019-20 (पीए) से 2020-21 (बीई) के कर संग्रहण में उछाल से है जिसमें 10 प्रतिशत के बजटीय नाममात्र जीडीपी विकास का अनुमान है। कर संग्रहण में उछाल राष्ट्रीय आय में परिवर्तन और समय के साथ कर नीतियों में विवेकाधीन बदलाव दोनों कर राजस्व की कुल प्रतिक्रिया को मापता है, और आय में एक प्रतिशत परिवर्तन से जुड़े राजस्व में प्रतिशत परिवर्तन के रूप में माना जाता है (डुडिन और जलेस, 2018⁷)।

स्रोत: स्टाफ अनुमान

⁷ डुडाइन, पी., और जलेस, जे. टी. (2018)। हाउ बुओयंट इज द टैक्स सिस्टम? न्यू एविडेन्स फ्रॉम ए लार्ज हिट्रोजीनस. *इंटरनेशनल डेवलपमेंट जर्नल*, 30, 961-991।

सारणी 3: केंद्र सरकार का कर राजस्व

1	₹ हजार करोड़					जीडीपी का प्रतिशत			वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)
1. प्रत्यक्ष कर जिसमें से	1,137	1,335	1,170	1,050	1,319	6.3	5.7	5.2	17.5	2.9	-7.7
i. आयकर	461	556	547	480	625	2.6	2.7	2.4	20.5	18.5	4.1
ii. कॉर्पोरेट कर	664	766	611	557	681	3.6	3.0	2.7	15.4	-8.0	-16.1
2. अप्रत्यक्ष कर जिसमें से	944	1,126	993	960	1,104	5.3	4.9	4.7	19.3	5.3	1.7
i. जीएसटी	582	663	612	599	691	3.1	2.9	3.0	14.1	5.3	3.0
ii. सीमा शुल्क	118	156	125	109	138	0.7	0.6	0.5	32.3	6.1	-7.3
iii. उत्पाद शुल्क	232	300	248	240	267	1.4	1.2	1.2	29.3	6.9	3.3
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2,080	2,461	2,163	2,010	2,423	11.7	10.6	9.9	18.3	4.0	-3.4

टिप्पणी: 2019-20 (पीए) के लिए 'अन्य कर', जैसा कि सीजीए द्वारा रिपोर्ट किया गया है, को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में आनुपातिक रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

प्रत्यक्ष कर

प्रत्यक्ष करों के लिए, 1.6 की बजटीय उछाल के विपरीत, 2019-20 (पीए) में वास्तविक उछाल (-) 1.1 पर काफी कम हो गया, जिससे कॉर्पोरेट करों में वास्तविक संग्रह से पीए में 16 प्रतिशत की गिरावट देखने को मिला (सारणी 3)। इस तीव्र गिरावट का श्रेय, अन्य के बीच, कॉर्पोरेट कर दर के युक्तिकरण को दिया जा सकता है, जिसने घरेलू कंपनियों के लिए कर की प्रभावी दर को 25.17 प्रतिशत पर ला दिया। दूसरी ओर, आयकर संग्रहण, एक सकारात्मक उछाल के साथ अपेक्षाकृत बेहतर है।

अप्रत्यक्ष कर

अप्रत्यक्ष करों में 1.7 के बजटीय उछाल की तुलना में 0.2 की उछाल दर्ज किया गया। इस गिरावट का अधिकांश जीएसटी में कमी, इसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क में कमी के कारण हुआ था।

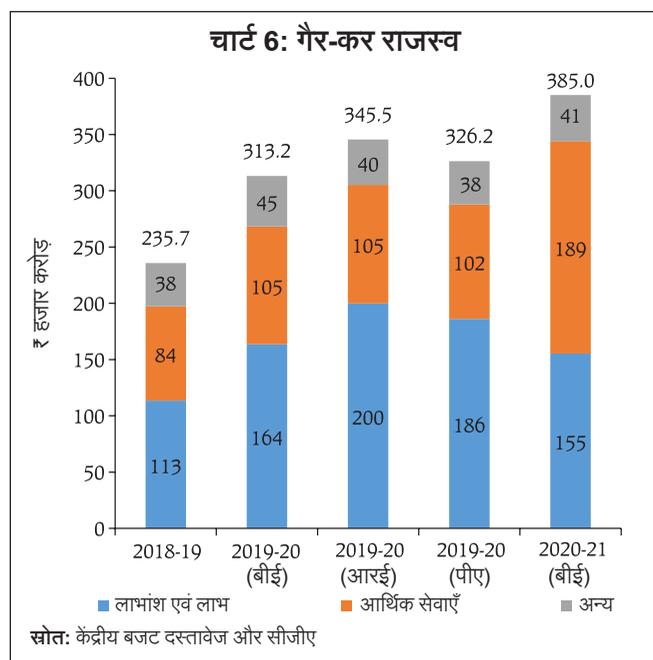
गैर-कर राजस्व

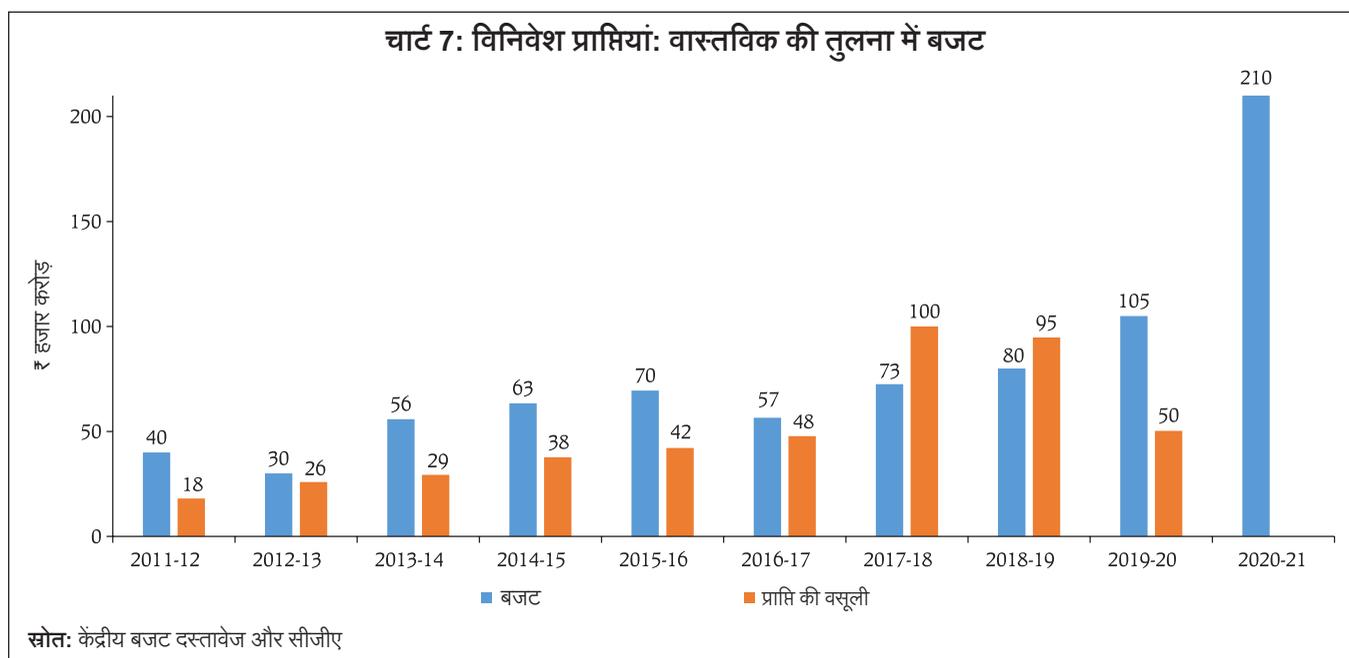
गैर-कर राजस्व ने 2019-20 में सरकारी वित्त को कुछ राहत प्रदान किया। रिज़र्व बैंक से उच्च अधिशेष स्थानान्तरण की वजह से 2019-20 (पीए) में गैर-कर राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में

38.4 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी, जो 2019-20 के बजट अनुमानों को पार कर गया (चार्ट 6)।

गैर-कर राजस्व प्राप्ति

2019-20 में विनिवेश प्राप्ति ₹1.05 लाख करोड़ के बजट में की गई थी। हालांकि, 2019-20 (पीए) के अनुसार, इस राशि के आधे से भी कम की वसूली हो सकी थी (चार्ट 7)।





IV. व्यय पैटर्न

यद्यपि, पीए के अनुसार कुल व्यय में 16 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जो कि बीई के 3.6 प्रतिशत से कम है, तथापि वृद्धि की मंदी की वजह से होने वाले दबाव के मद्देनजर पीए की तुलना में आरई से व्यय में किसी भी बड़ी कटौती से बचा गया है (सारणी 4)।

हालांकि, ब्याज भुगतान पिछले वित्त वर्ष की तुलना में लगभग 5 प्रतिशत अधिक है, फिर भी बीई और आरई से कम था।

बजट अनुमानों पर अंकुश लगाने के बावजूद प्रमुख सहायता अनुदानों पर व्यय में 13.4 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। हालांकि, यह पेट्रोलियम सब्सिडी आरई की तुलना में कुछ कटौती के साथ आरई के स्तरों पर लगभग बनाए रखा गया था। पेट्रोलियम सब्सिडी पिछले वित्त वर्ष से 30 प्रतिशत से अधिक बढ़ी है। दूसरी ओर, खाद्य सब्सिडी, जिसमें सभी सहायता अनुदानों से सबसे अधिक आबंटन है, को बजट राशि के मामले में 40 प्रतिशत (पीए) तक की कटौती की घटाया गया था, लेकिन इसे आरई पर बनाए रखा गया था।

सारणी 4: केंद्र सरकार का कर राजस्व

मद	₹ हजार करोड़					पीए की वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)	2018-19 के दौरान	बीई के दौरान	आरई के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. कुल व्यय	2,315	2,786	2,699	2,686	3,042	16.0	-3.6	-0.5
2. राजस्व व्यय (जिसमें से)	2,007	2,448	2,350	2,350	2,630	17.0	-4.0	0.0
(i) ब्याज भुगतान	583	660	625	611	708	4.9	-7.5	-2.3
(ii) प्रमुख सहायता अनुदान	197	302	227	223	228	13.4	-26.0	-1.8
खाद्य	101	184	109	109	116	7.3	-41.0	0.0
उर्वरक	71	80	80	81	71	14.9	1.4	1.4
पेट्रोलियम	25	37	39	33	41	34.5	-10.9	-13.4
3. पूंजीगत व्यय	308	339	349	337	412	9.4	-0.5	-3.5

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

सारणी 5: केंद्र सरकार का मंत्रालय-वार व्यय

मद	₹ हजार करोड़				पीए की वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2018-19 के दौरान	बीई के दौरान	आरई के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8
1. रक्षा	403	431	449	453	12.2	5.0	0.8
2. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	77	83	83	78	1.2	-5.7	-5.7
3. रेल	55	68	70	70	27.4	2.8	0.0
4. पेट्रोलियम और नैसर्गिक गैस	32	43	43	43	32.3	-0.2	-0.2
5. आवास एव शहरी कार्य	41	48	42	42	3.6	-12.4	-0.5

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

उच्च बजटीय खर्च वाले मंत्रालयों के बीच, रक्षा मंत्रालय द्वारा व्यय में लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो बजट राशि और आरई से अधिक है (सारणी 5)। इसी तरह, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा खर्च पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 1 प्रतिशत और 27 प्रतिशत अधिक है।

पूंजीगत व्यय में प्रमुख हिस्सेदारी रक्षा, सड़क परिवहन और राजमार्ग और रेल मंत्रालय की है, जो कुल बजटीय पूंजी परिव्यय का लगभग 70 प्रतिशत है। इनमें कुल पूंजीगत व्यय का लगभग 40 प्रतिशत रेल के साथ-साथ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय का है। हालांकि रक्षा और रेलवे ने वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि दर्ज की है, जो पीए के अनुसार खर्च रक्षा के लिए आरई से अधिक था, लेकिन रेलवे के लिए कम था (सारणी 6)। इसके विपरीत, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा पूंजीगत

व्यय पिछले वर्ष से संकुचित हो गया है और पीए आरई और बीई दोनों की तुलना में कम है।

V. जीएफडी वित्त पोषण

बजट के अनुरूप दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल बाजार उधारी ₹7.1 लाख करोड़ पर बरकरार रहा। जहां 2019-20 के लिए निवल बाजार उधारी के माध्यम से वित्तपोषण का हिस्सा लगभग 60 प्रतिशत बना हुआ है, वहीं राष्ट्रीय लघु बचत कोष (एनएसएसएफ) के माध्यम से वित्तपोषण की हिस्सेदारी में लगभग 26 प्रतिशत तक की वृद्धि देखी गई है (सारणी 7)।

VI. बकाया देनदारियां

केंद्र सरकार की कुल बकाया देनदारियां 2018-19 में अपने स्तर से 2019-20 (पीए) में तेजी से बढ़ीं (चार्ट 8)। केंद्रीय बजट 2020-21 के साथ जारी की गई मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी

सारणी 6 : केंद्र सरकार के मंत्रालयवार पूंजीगत व्यय

Item	₹ हजार करोड़				पीए की वृद्धि दर (प्रतिशत)		
	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2018-19 के दौरान	बीई के दौरान	आरई के दौरान
1	2	3	4	5	6	7	8
1. रक्षा	100	108	115	116	16.3	7.2	0.6
2. रेल	53	66	68	68	28.4	3.0	0.0
3. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग	68	72	72	67	-0.6	-6.6	-6.8
4. आवास एव शहरी कार्य	16	20	19	19	22.4	-1.2	0.6
5. ऊर्जा	2	2	2	2	-21.0	-32.7	-11.4

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

सारणी 7: जीएफडी वित्तपोषण

(राशि ₹ हजार करोड़ में)

मद	2018-19 (वास्तविक)	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)
1	2	3	4	5	6
सकल राजकोषीय घाटा	649 (100)	704 (100)	767 (100)	936 (100)	796 (100)
द्वारा वित्त पोषित					
निवल बाजार उधारियों	430 (66.3)	498 (70.7)	499 (65.1)	556* (59.4)	570 [990]** (71.6)
एनएसएसएफ	125 (19.3)	130 (18.5)	240 (31.3)	240 (25.7)	240 (30.2)
बाह्य सहायता	6 (0.9)	-3 (-0.4)	5 (0.7)	12 (1.2)	5 (0.6)
राजकीय भविष्य निधि	16 (2.5)	18 (2.6)	18 (2.3)	12 (1.2)	18 (2.3)
आरक्षित निधि	-18 (-2.8)	-1 (-0.1)	0 (0.0)	3 (0.3)	3 (0.4)
नगदी शेष की कमी	-1 (-0.2)	51 (7.2)	0 (0.0)	76 (8.1)	-53 (-6.7)
अन्य	91 (14.0)	11 (1.6)	5 (0.7)	37 (4.0)	13 (1.6)

मेमो मद

दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से सकल उधारियाँ	571	710	710	710	780 [1200]**
---	-----	-----	-----	-----	-----------------

टिप्पणियाँ: निवल बाजार उधारियों में 91-दिन, 182-दिन, 364-दिन और अन्य सभी ट्रेजरी बिलों के साथ दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियाँ शामिल हैं।

*: 2019-20 (पीए) के लिए बाजार उधारी सीएमबी सहित है

** - बजट के बाद भारत सरकार द्वारा ₹4.2 लाख करोड़ के अतिरिक्त बाजार उधारियों की घोषणा की गई है।

अन्य में जमा और अग्रिम, प्रतिभूतियों की वापसी-खरीद, प्रतिभूतियों को बंद करना, केश मैनेजमेंट बिल, अर्थोपाय अग्रिम, बचत बॉण्ड, राहत बॉण्ड्स आदि शामिल हैं।

कोष्ठक में आंकड़े जीएफडी के प्रतिशत को दर्शाते हैं।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए।

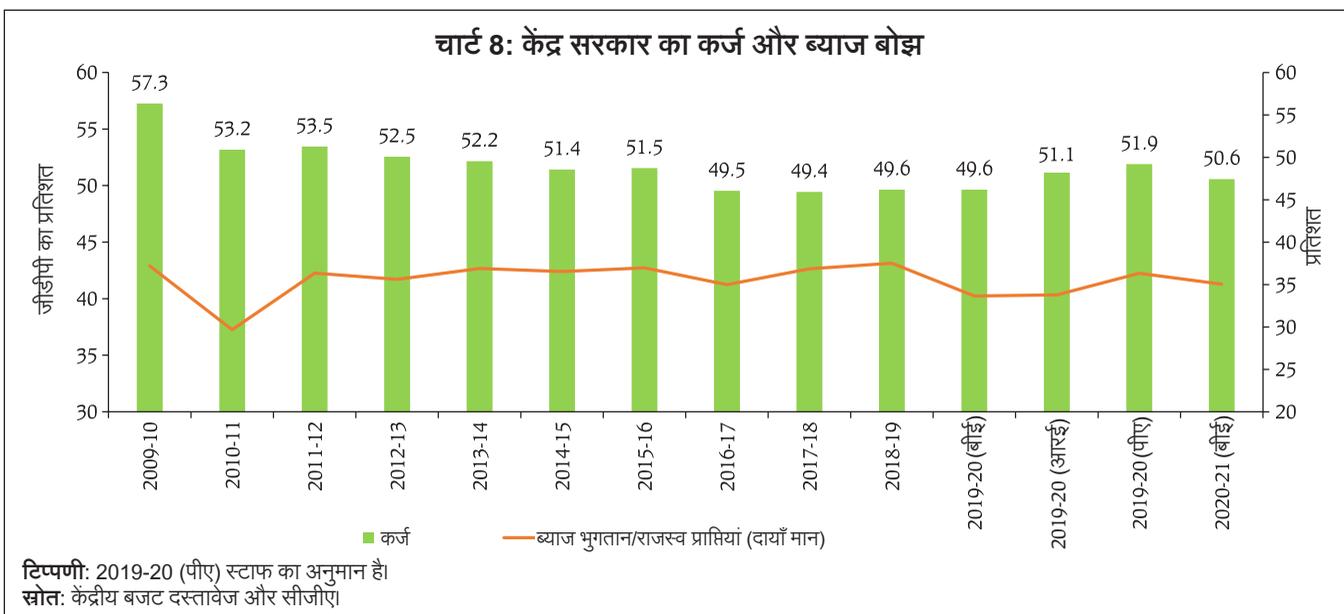
स्टेटमेंट में सरकार ने अनुमान लगाया था कि बकाया देनदारियां 2022-23 तक 45.5 प्रतिशत हो जाएंगी। हालांकि, बीई/आरई से 2019-20 (पीए) में वृद्धि और कोविड -19 संबंधित प्रोत्साहन उपायों के मद्देनजर 2020-21 के लिए अपेक्षित बढ़ोतरी की संभावना को देखते हुए, ऐसी उम्मीद नहीं दिखती है, अतः, राजकोषीय रोडमैप का खांका फिर से खींचने की जरूरत है। तथापि 2018-19 से कम, राजस्व प्राप्ति के लिए ब्याज भुगतान के अनुपात द्वारा दर्शायी गयी ऋण सेवा क्षमता, 2019-20 बीई और आरई से खराब हो गई है।

संशोधित घाटे और कर्ज के आंकड़ों के साथ, यह देखना उचित होगा कि जीएफडी के विपरीत, भारत ने अपने कुछ समकक्षों के अपेक्षाकृत कोविड-19 महामारी में कमजोर प्रारंभिक स्थिति में प्रवेश किया है (चार्ट 9)।

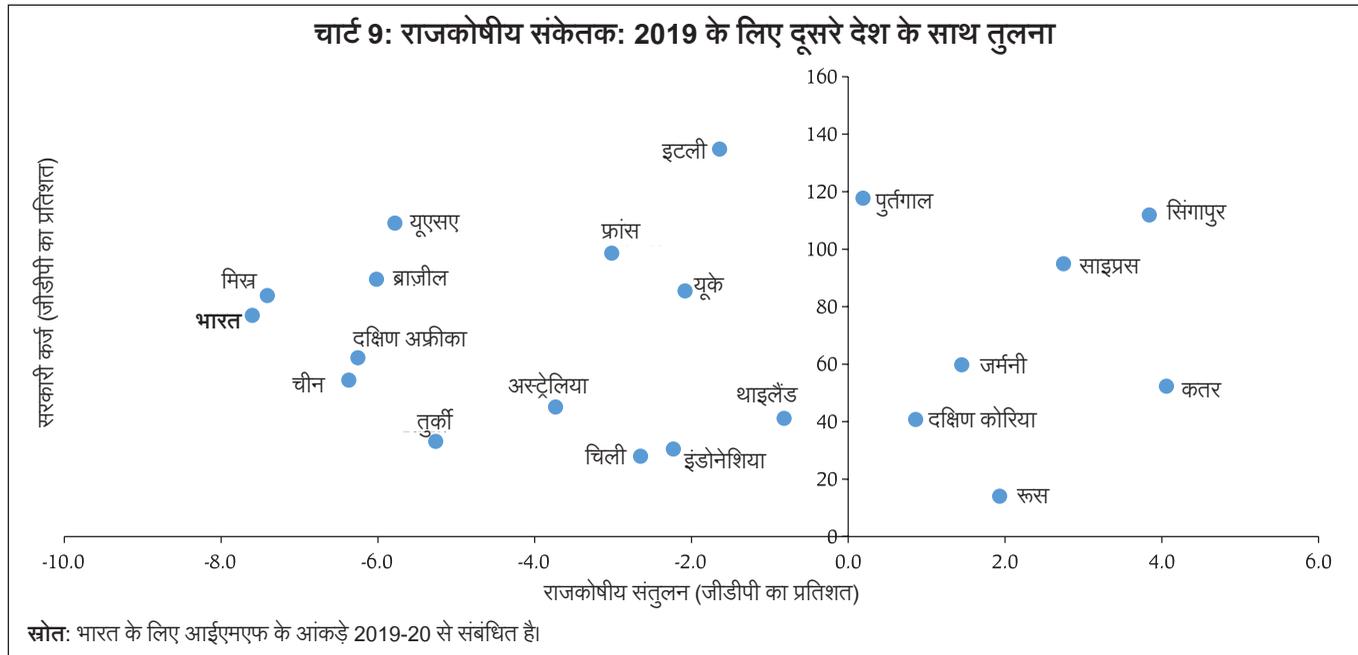
VII. केंद्र से राज्यों में कर न्यागमन

जहां 2019-20 (आरई) की तुलना में 2019-20 (पीए) में कर राजस्व में उल्लेखनीय कमी देखी गयी, वहीं केंद्र से राज्यों के कर न्यागमन में आनुपातिक गिरावट नहीं आई है। कर न्यागमन पीए में आरई से ₹5,369 करोड़ (जीडीपी का 0.03 प्रतिशत) तक और बीई से ₹1.6 लाख करोड़ (जीडीपी का 0.8 प्रतिशत) तक घट गया (सारणी 8)⁸। यह देखते हुए कि राज्यों को न्यागमन आरई के आधार पर किया जाता है, केंद्र से राज्यों को संसाधनों

चार्ट 8: केंद्र सरकार का कर्ज और ब्याज बोझ



⁸ यह ध्यान दिया जा सकता है कि 80 बीपीएस में से 30 बीपीएस वर्ष 2018-19 में अल्प वास्तविक कर संग्रह के 2019-20 (आरई) में समायोजन से आ रहा है। अधिक जानकारी के लिए, सरकारी वित्त पर आरबीआई अप्रैल 2020 बुलेटिन आलेख देखें।



का आधिक्य हस्तांतरण (लगभग ₹49,000 करोड़) को 2020-21 में राज्यों को कर न्यागमन में समायोजित करना होगा, जो इसे 2020-21 में संभावित मंदी के कारण कम निम्न न्यागमन के साथ नकारात्मक रूप से प्रभावित करने की संभावना है। इसके अलावा, राज्यों को मुआवजा उपकर के लिए संसाधनों को जुटाना इस मंदी वाले वर्ष में केंद्र के लिए एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा, यह ध्यान रखना उचित है कि केंद्र द्वारा बजट में किए गए कर न्यागमन का अनुमान उनके बजट लेखांकन में राज्यों द्वारा

बताए गए आंकड़ों से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। राज्य, आम तौर पर, केंद्र से अधिक बजट करते हैं।

VIII. निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 के लिए अनंतिम लेखा में गिरावट को चक्रीय और संरचनात्मक दोनों तरह के कर राजस्व की कमी के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। 2018-19 की दूसरी छमाही से आर्थिक मंदी के मद्देनजर खर्च में किसी भी तरह की कटौती से बचा गया है। यह देखते हुए कि 2020-21 के बजट अनुमानों को 2019-20 आरई के आधार पर अनुमानित किया गया था, 2019-20 (आरई) की तुलना में 2019-20 (पीए) में कर राजस्व संग्रह में कमी से 2020-21 का राजकोषीय अंकगणित बिगड़ सकता है। यह 2020-21 में कोविड-19 से संबंधित समष्टि आर्थिक प्रभावों से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो सकता है, विशेष रूप से पहली तिमाही। ऐसी पृष्ठभूमि में, 2020-21 में राजकोषीय प्रयास सुविचारित और विवेकपूर्ण होना चाहिए, जबकि साथ ही साथ मुश्किल भरे दौर खत्म होने के बाद राजकोषीय सूझ-बूझ के लिए एक बेहतर मार्ग भी तैयार करना चाहिए।

सारणी 8: राज्यों को कर का न्यागमन

(₹ लाख करोड़)

	2019-20 बीई	2019-20 आरई	2019-20 पीए	2020-21 बीई
1	2	3	4	5
केंद्र का सकल कर राजस्व	24.61	21.63	20.10	24.23
राज्यों को कर न्यागमन @	8.09*	6.56	6.51	7.84
पिछले वर्ष में निम्नतर अतिरिक्त कर न्यागमन				0.49
समायोजन के बाद वास्तविक कर न्यागमन				7.35

टिप्पणी: @ - राज्यों को कर न्यागमन को सकल कर राजस्व के 34.5 प्रतिशत के रूप में लिया गया है (2017-19 के लिए औसत अनुपात)।

* - राज्यों ने 2019-20 बीई में ₹8.5.52 लाख करोड़ रुपये का बजट रखा, जबकि केंद्र द्वारा ₹8.09 बजट किया गया था।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज़, सीजीए, राज्य बजट दस्तावेज़ और स्टाफ अनुमान

⁹ यह विसंगति वर्ष 2020-21 के लिए लगभग ₹50,000 करोड़ है।

परिशिष्ट 1: प्रमुख राजकोषीय संकेतक

	₹ हजार करोड़					जीडीपी का प्रतिशत		वृद्धि दर	
	2018-19	2019-20 (बीई)	2019-20 (आरई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)	2019-20 (पीए)	2020-21 (बीई)
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. प्रत्यक्ष कर	1,137	1,335	1,170	1,050	1,319	5.2	5.9	-7.7	25.7
(i) कॉर्पोरेशन	664	766	611	557	681	2.7	3.0	-16.1	22.3
(ii) आय	461	556	547	480	625	2.4	2.8	4.1	30.1
2. अप्रत्यक्ष कर	944	1,126	993	960	1,104	4.7	4.9	1.7	15.0
(i) जीएसटी	582	663	612	599	691	2.9	3.1	3.0	15.3
(ii) सीमा शुल्क	118	156	125	109	138	0.5	0.6	-7.3	26.4
(iii) उत्पाद शुल्क	232	300	248	240	267	1.2	1.2	3.3	11.4
3. सकल कर राजस्व (1+2)	2,080	2,461	2,163	2,010	2,423	9.9	10.8	-3.4	20.6
4. राज्यों को हक-अंतरण और एनसीसीडी अंतरण	763	812	659	654	787	3.2	3.5	-14.3	20.4
5. निवल कर राजस्व (3-4)	1,317	1,650	1,505	1,356	1,636	6.7	7.3	2.9	20.7
6. गैर-कर राजस्व	236	313	346	326	385	1.6	1.7	38.4	18.0
(i) लाभांश और लाभ	113	164	200	186	155	0.9	0.7	64.1	-16.5
(ii) ब्याज प्राप्ति	12	14	11	12	11	0.1	0.0	-4.3	-5.0
7. राजस्व प्राप्ति (5+6)	1,553	1,963	1,850	1,682	2,021	8.3	9.0	8.3	20.1
8. गैर कर्ज पूंजी प्राप्ति	113	120	82	69	225	0.3	1.0	-39.2	227.8
(i) विनिवेश प्राप्ति	95	105	65	50	210	0.2	0.9	-46.9	317.5
(ii) ऋणों की वसूली	18	15	17	18	15	0.1	0.1	1.5	-18.3
9. कुल प्राप्ति (उधार पूर्व) (7+8)	1,666	2,083	1,932	1,751	2,246	8.6	10.0	5.1	28.3
10. राजस्व व्यय	2,007	2,448	2,350	2,350	2,630	11.6	11.7	17.0	11.9
(i) ब्याज भुगतान	583	660	625	611	708	3.0	3.1	4.9	15.9
(ii) प्रमुख सहायता अनुदान	197	302	227	223	228	1.1	1.0	13.4	2.1
खाद्य	101	184	109	109	116	0.5	0.5	7.3	6.3
उर्वरक	71	80	80	81	71	0.4	0.3	14.9	-12.1
पेट्रोलियम	25	37	39	33	41	0.2	0.2	34.5	22.5
11. पूंजीगत व्यय (i + ii)	308	339	349	337	412	1.7	1.8	9.4	22.4
(i) पूंजीगत परिव्यय	279	311	322	310	380	1.5	1.7	10.8	22.8
(ii) ऋण और अग्रिम	28	28	27	27	32	0.1	0.1	-3.8	17.0
12. कुल व्यय (10+11)	2,315	2,786	2,699	2,686	3,042	13.2	13.5	16.0	13.2
13. राजकोषीय घाटा (12-9)	649	704	767	936	796	4.6	3.5	44.1	-14.9

टिप्पणी: 2019-20 (पीए) के लिए 'अन्य कर', जैसा कि सीजीए द्वारा रिपोर्ट किया गया है, को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों में आनुपातिक रूप से वर्गीकृत किया गया है।

स्रोत: केंद्रीय बजट दस्तावेज और सीजीए

वर्तमान सांख्यिकी

चुनिंदा आर्थिक संकेतक
भारतीय रिज़र्व बैंक
मुद्रा और बैंकिंग
मूल्य और उत्पादन
सरकारी खाते और खज़ाना बिल
वित्तीय बाजार
बाह्य क्षेत्र
भुगतान और निपटान प्रणालियाँ
अवसरिक श्रृंखला

विषयवस्तु

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
1	चुनिदा आर्थिक संकेतक	57
	भारतीय रिज़र्व बैंक	
2	भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां	58
3	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन	59
4	भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डॉलर का क्रय/विक्रय	60
4ए	भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार) परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	61
5	भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं	61
	मुद्रा और बैंकिंग	
6	मुद्रा स्टॉक मात्रा	62
7	मुद्रा स्टॉक (एम ₃) के स्रोत	63
8	मौद्रिक सर्वेक्षण	64
9	कुल चलनिधि राशियां	64
10	भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण	65
11	आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत	65
12	वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण	66
13	अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश	66
14	भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक	67
15	प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन	68
16	सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार विनियोजन	69
17	भारतीय रिज़र्व बैंक में खाते रखने वाले राज्य सहकारी बैंक	70
	मूल्य और उत्पादन	
18	उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)	71
19	अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	71
20	मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य	71
21	थोक मूल्य सूचकांक	72
22	औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)	76
	सरकारी खाते और खज़ाना बिल	
23	केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में	76
24	खज़ाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप	77
25	खज़ाना बिलों की नीलामी	77
	वित्तीय बाजार	
26	दैनिक मांग मुद्रा दरें	78
27	जमाराशि प्रमाण-पत्र	79
28	वाणिज्यिक पत्र	79
29	चुनिदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर	79
30	गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम	80

संख्या	शीर्षक	पृष्ठ
	बाह्य क्षेत्र	
31	विदेशी व्यापार	81
32	विदेशी मुद्रा भंडार	81
33	अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां	81
34	विदेशी निवेश अंतर्वाह	82
35	निवासी भारतीयों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना के अंतर्गत जावक विप्रेषण	82
36	भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर (आरईईआर) और सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर (एनईईआर) सूचकांक	83
37	बाह्य वाणिज्यिक उधार	83
38	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (मिलियन अमरिकी डॉलर)	84
39	भारत का समग्र भुगतान संतुलन (करोड़ ₹)	85
40	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (मिलियन अमरिकी डॉलर)	86
41	बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण (करोड़ ₹)	87
42	अंतरराष्ट्रीय निवेश स्थिति	88
	भुगतान और निपटान प्रणालियाँ	
43	भुगतान प्रणाली संकेतक	89
	अवसरिक श्रृंखला	
44	लघु बचत	91
45	केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप	92
46	केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण	93
47	विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता	94
48	राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश	95
49	राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां	96

टिप्पणियां : .. = उपलब्ध नहीं।

— = शून्य/नगण्य

प्रा/अ= प्रारंभिक/अनंतिम आंसं = आंशिक रूप से संशोधित

सं. 1 : चुनिंदा आर्थिक संकेतक

मद	2019-20	2018-19		2019-20	
		ति3	ति4	ति3	ति4
	1	2	3	4	5
1 वस्तु क्षेत्र (% परिवर्तन)					
1.1 आधार मूल्यों पर जीवीए	3.9	5.6	5.6	3.5	3.0
1.1.1 कृषि	4.0	2.0	1.6	3.6	5.9
1.1.2 उद्योग	0.8	4.4	1.4	-0.4	-0.01
1.1.3 सेवाएं	5.0	7.3	8.3	4.9	3.5
1.1क अंतिम खपत व्यय	6.3	7.0	7.3	7.6	4.2
1.1ख सकल नियत पूंजी निर्माण	-2.8	11.4	4.4	-5.2	-6.5
	2019-20	2019		2020	
	1	मार्च	अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5
1.2 औद्योगिक उत्पादन सूचकांक	-0.7	2.7	3.2	-16.7	-
2 मुद्रा और बैंकिंग (% परिवर्तन)					
2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक					
2.1.1 जमाराशियां	7.9	10.0	9.7	7.9	9.9
2.1.2 ऋण	6.1	13.3	13.0	6.1	6.8
2.1.2.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	6.1	13.4	13.1	6.1	6.7
2.1.3 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	9.1	1.9	2.8	9.1	14.9
2.2 मुद्रा स्टॉक मात्रा					
2.2.1 आरक्षित मुद्रा (एम0)	9.4	14.5	13.0	9.4	9.1
2.2.2 स्थूल मुद्रा (एम3)	8.9	10.5	10.0	8.9	10.8
3 अनुपात (%)					
3.1 आरक्षित नकदी निधि अनुपात	3.00	4.00	4.00	3.00	3.00
3.2 सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.25	19.25	19.00	18.25	18.00
3.3 नकदी-जमा अनुपात	4.6	5.1	4.8	4.6	3.7
3.4 ऋण-जमा अनुपात	76.4	77.7	77.1	76.4	74.9
3.5 वृद्धिशील ऋण-जमा अनुपात	60.3	99.9	#	60.3	-62.6
3.6 निवेश-जमा अनुपात	27.2	26.9	#	27.2	28.9
3.7 वृद्धिशील निवेश-जमा अनुपात	30.8	5.4	#	30.8	182.1
4 व्याज दरें (%)					
4.1 नीति रिपो दर	4.40	6.25	6.00	4.40	4.40
4.2 रिवर्स रिपो दर	4.00	6.00	5.75	4.00	3.75
4.3 सीमांत स्थायी सुविधा दर	4.65	6.50	6.25	4.65	4.65
4.4 बैंक दर	4.65	6.50	6.25	4.65	4.65
4.5 आधार दर	8.15/9.40	8.95/9.40	8.95/9.40	8.15/9.40	8.15/9.40
4.6 एमसीएलआर (एक दिन के लिए)	7.40/7.90	8.05/8.55	8.05/8.50	7.40/7.90	7.10/7.75
4.7 एक वर्ष से अधिक की मीयादी जमा दर	5.90/6.40	6.25/7.50	6.25/7.50	5.90/6.40	5.70/6.00
4.8 बचत जमा दर	3.00/3.50	3.50/4.00	3.50/4.00	3.00/3.50	2.75/3.50
4.9 मांग मुद्रा दर (भारित औसत)	5.05	6.35	6.16	5.05	4.09
4.10 91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.36	6.31	6.44	4.36	3.64
4.11 182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.97	6.35	6.50	4.97	3.66
4.12 364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	4.94	6.39	6.51	4.94	3.70
4.13 10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूतियों पर आय (एफबीआईएल)	6.71	7.34	7.44	6.71	6.55
5 आरबीआई संदर्भ दर और फारवर्ड प्रीमिया					
5.1 भा.रु.-अमरिकी डॉलर हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	74.84	69.17	70.14	74.84	76.42
5.2 भा.रु.-यूरो हाजिर दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	82.64	77.70	78.13	82.64	82.21
5.3 फारवर्ड प्रीमिया अमरिकी डॉलर					
1-माह (%)	8.98	6.07	4.83	8.98	3.93
3-माह (%)	5.93	4.80	4.51	5.93	3.85
6-माह (%)	5.05	4.16	4.28	5.05	3.93
6 मुद्रास्फीति (%)					
6.1 अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	4.76	2.9	3.0	5.8	-
6.2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	7.54	7.7	8.3	5.5	5.4
6.3 थोक मूल्य सूचकांक	1.74	3.1	3.2	1.0	-
6.3.1 प्राथमिक वस्तुएं	6.90	4.9	6.6	3.7	-0.8
6.3.2 ईंधन और पावर	-1.53	4.6	3.8	-1.8	-10.1
6.3.3 विनिर्मित उत्पाद	0.30	2.2	1.9	0.3	-
7 विदेशी व्यापार (% परिवर्तन)					
7.1 आयात	-9.12	2.1	3.6	-28.7	-58.6
7.2 निर्यात	-4.78	12.2	0.5	-34.6	-60.3

हर नकारात्मक है।

टिप्पणी : फाइनेंसियल बेंचमार्क इंडिया प्रा. लि. (एफबीआईएल) भारतीय रिजर्व बैंक के 31 अप्रैल 2018 के परिपत्र एफएमआरडी.डीआईआरडी.7/14.03.025/ 2017-18 के अनुसार जी सेक बेंचमार्क का प्रकाशन शुरू किया है। एफबीआईएल ने 10 जुलाई 2018 से संदर्भ दरों का प्रसार शुरू किया है।

भारतीय रिज़र्व बैंक

सं. 2 : भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(करोड़ ₹)

मद	अंतिम शुक्रवार/शुक्रवार की स्थिति						
	2019-20	2019		2020			
		मई	मई 1	मई 8	मई 15	मई 22	मई 29
	1	2	3	4	5	6	7
1 निर्गम विभाग							
1.1 देयताएं							
1.1.1 संचलन में नोट	2412993	2171370	2508819	2543244	2562603	2584761	2590153
1.1.2 बैंकिंग विभाग में रखे गए नोट	10	11	12	12	11	11	16
1.1/1.2 कुल देयताएं (जारी किए गए कुल नोट) या आस्तियां	2413003	2171381	2508831	2543256	2562614	2584772	2590169
1.2 आस्तियां							
1.2.1 सोने के सिक्के और बुलियन	103439	75782	108177	108892	110683	110805	109837
1.2.2 विदेशी प्रतिभूतियां	2308718	2094736	2399819	2433535	2451108	2473151	2479521
1.2.3 रुपया सिक्का	846	863	835	829	824	816	811
1.2.4 भारत सरकार की रुपया प्रतिभूतियां	—	—	—	—	—	—	—
2 बैंकिंग विभाग							
2.1 देयताएं							
2.1.1 जमाराशियां	1187409	680897	1299090	1302054	1294454	1250578	1170867
2.1.1.1 केंद्र सरकार	100	101	101	101	101	101	101
2.1.1.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	—	—	—	—	—	—	—
2.1.1.3 राज्य सरकारें	43	42	42	42	42	43	42
2.1.1.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	536186	536415	451948	423722	432978	433987	435222
2.1.1.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	7603	3910	5770	5565	5667	6059	5619
2.1.1.6 गैर-अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	3445	2584	2725	2690	2658	2574	2575
2.1.1.7 अन्य बैंक	32641	30172	25896	25613	26192	25594	25557
2.1.1.8 अन्य	605100	107673	812532	844321	825299	775382	694192
2.1.1.9 भारत के बाहर वित्तीय संस्थान	2291	—	76	—	1517	6838	7559
2.1.2 अन्य देयताएं	1350333	1143601	1421365	1441267	1442266	1466511	1468659
2.1/2.2 कुल देयताएं या आस्तियां	2537742	1824498	2720455	2743321	2736720	2717089	2639526
2.2 आस्तियां							
2.2.1 नोट और सिक्के	10	11	12	12	11	11	16
2.2.2 विदेश में रखे शेष	1006357	680328	956148	975153	966994	985129	990118
2.2.3 ऋण और अग्रिम	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.1 केंद्र सरकार	50477	—	165833	134970	128836	86080	—
2.2.3.2 राज्य सरकारें	1967	1322	3823	5582	5815	6752	7187
2.2.3.3 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	285623	44976	291382	290858	290842	292242	291023
2.2.3.4 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	—	35	—	—	—	—	—
2.2.3.5 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.6 नाबार्ड	—	—	—	10000	19000	19000	22000
2.2.3.7 एक्विजि बैंक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.3.8 अन्य	10064	7021	4510	5855	1372	3741	5402
2.2.3.9 भारत के बाहर की वित्तीय संस्थाएं	2300	—	7599	—	—	—	—
2.2.4 खरीदे और भुनाए गए बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.1 आंतरिक	—	—	—	—	—	—	—
2.2.4.2 सरकारी खजाना बिल	—	—	—	—	—	—	—
2.2.5 निवेश	1042951	962890	1145639	1174398	1174429	1174460	1174491
2.2.6 अन्य आस्तियां	137993	127915	145509	146493	149421	149674	149289
2.2.6.1 सोना	127644	84483	134183	135069	137998	138150	137294

*: डेटा अनंतिम है।

सं. 3 : भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा चलनिधि परिचालन

(करोड़ ₹)

दिनांक	रिपो	रिवर्स रिपो	परिवर्तन-शील रिपो दर	परिवर्तन-शील रिवर्स रिपो दर	एमएसएफ	स्थायी चलनिधि सुविधाएं	बाजार स्थिरीकरण योजना	विक्रय	क्रय	दीर्घावधि रिपो परिचालन	लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन#	म्यूचुअल फंड के लिए विशेष चलनिधि सुविधा	निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+6+9+10+11+12-2-4-7-8)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
अप्रैल 1, 2020	-	61250	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-61245
अप्रैल 2, 2020	-	74765	-	-	2549	-	-	-	-	-	-	-	-72216
अप्रैल 3, 2020	-	553978	-	-	5250	-644	-	-	-	-	25016	-	-524356
अप्रैल 4, 2020	-	46617	-	-	1764	-	-	-	-	-	-	-	-44853
अप्रैल 5, 2020	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-
अप्रैल 6, 2020	-	31863	-	-	13070	-	-	-	-	-	-	-	-18793
अप्रैल 7, 2020	-	620468	-	-	5925	330	-	-	960	-	-	-	-613253
अप्रैल 8, 2020	-	576741	-	-	7552	41	-	-	8750	-	-	-	-560398
अप्रैल 9, 2020	-	694403	-	-	5640	-	-	-	4950	-	25016	-	-658797
अप्रैल 10, 2020	-	6945	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-6945
अप्रैल 11, 2020	-	339	-	-	300	-	-	-	-	-	-	-	-39
अप्रैल 12, 2020	-	12	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-12
अप्रैल 13, 2020	-	689655	-	-	1576	-	-	-	840	-	-	-	-687239
अप्रैल 14, 2020	-	586	-	-	50	-	-	-	-	-	-	-	-536
अप्रैल 15, 2020	-	692305	-	-	0	-501	-	-	595	-	-	-	-692211
अप्रैल 16, 2020	-	699312	-	-	0	-44	-	-	14989	-	-	-	-684367
अप्रैल 17, 2020	-	709290	-	-	0	-	-	-	-	-	25009	-	-684281
अप्रैल 18, 2020	-	17534	-	-	75	-	-	-	-	-	-	-	-17459
अप्रैल 19, 2020	-	13	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-13
अप्रैल 20, 2020	-	712823	-	-	290	-	-	-	-	-	-	-	-712533
अप्रैल 21, 2020	-	706176	-	-	60	-469	-	-	-	-	-	-	-706585
अप्रैल 22, 2020	-	705394	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-705394
अप्रैल 23, 2020	-	721500	-	-	0	-471	-	-	29991	-	12850	-	-679130
अप्रैल 24, 2020	-	720716	-	-	45	-	-	-	-	-	-	-	-720671
अप्रैल 25, 2020	-	7421	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-7421
अप्रैल 26, 2020	-	0	-	-	0	-	-	-	-	-	-	-	0
अप्रैल 27, 2020	-	727043	-	-	0	-	-	-	-	-	-	2000	-725043
अप्रैल 28, 2020	-	756801	-	-	0	-215	-	10000	10000	-	-	-	-757016
अप्रैल 29, 2020	-	748828	-	-	0	1281	-	-	-	-	-	-	-747547
अप्रैल 30, 2020	-	735849	-	-	15	-718	-	-	29931	-	-	430	-706191

लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन (टीएलटीआरओ) और लक्षित दीर्घावधि रिपो परिचालन 2.0 (टीएलटीआरओ 2.0) शामिल है।

सं. 4: भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अमरिकी डॉलर का क्रय-विक्रय

i) ओटीसी सेगमेंट में ऑनशॉर / ऑफशॉर में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	45097	4901	-4054	-1142
1.1 क्रय (+)	72205	7724	3984	2450
1.2 विक्रय (-)	27108	2823	8038	3592
2 संविदा दर पर ₹ के बराबर (करोड़ ₹)	312005	33092	-30974	-8589
3 संचयी (मार्च के अंत से) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	45097	4901	45097	-1142
(करोड़ ₹)	312005	33092	312005	-8589
4 माह के अंत में बकाया निवल वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	-4939	-18512	-4939	-1739

ii) मुद्रा फ्यूचर्स सेगमेंट में परिचालन

मद	2019-20	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4
1 विदेशी मुद्रा का निवल क्रय/विक्रय (मिलियन अमरिकी डॉलर) (1.1-1.2)	0	0	0	0
1.1 क्रय (+)	7713	180	2808	500
1.2 विक्रय (-)	7713	180	2808	500
2 माह के अंत में बकाया निवल मुद्रा वायदा विक्रय (-)/क्रय (+) (मिलियन अमरिकी डॉलर)	-500	0	-500	0

**सं. 4ए भारतीय रिज़र्व बैंक में बकाया वायदे का (अवशिष्ट परिपक्वता के अनुसार)
परिपक्वता विश्लेषण (मिलियन अमरिकी डॉलर)**

मद	30 अप्रैल 2020 तक		
	दीर्घ (+)	अल्प (-)	निवल (1-2)
	1	2	3
1. 1 माह तक	519	300	219
2. 1 माह से अधिक और 3 माह तक	1866	140	1726
3. 3 माह से अधिक और 1 वर्ष तक	7901	1565	6336
4. 1 वर्ष से अधिक	0	10020	-10020
कुल (1+2+3+4)	10286	12025	-1739

सं. 5: भारतीय रिज़र्व बैंक की स्थायी सुविधाएं

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार की स्थिति							
	2019-20	2019		2020				
		मई 24	दिसंबर 20	जनवरी 31	फरवरी 28	मार्च 27	अप्रैल 24	मई 22
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 सीमांत स्थायी सुविधा	1262	1615	3856	2340	4130	1262	45	1400
2 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के लिए निर्यात ऋण पुर्नवित्त								
2.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	-	-
2.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	-
3 प्राथमिक व्यापारियों के लिए चलनिधि सुविधा								
3.1 सीमा	10000	2800	2800	2800	2800	10000	10000	4900
3.2 बकाया	4782	2762	1615	1872	1815	4782	4162	1372
4 अन्य								
4.1 सीमा	-	-	-	-	-	-	50000	50000
4.2 बकाया	-	-	-	-	-	-	-	21369
5 कुल बकाया (1+2.2+3.2+4.2)	6044	4377	5471	4212	5945	6044	4207	24141

टिप्पणी: 1. अन्य को विशेष पुर्नवित्त सुविधा अर्थात एक्जिम बैंक को 31 मार्च 2013 से बंद है।

2. अन्य को पुर्नवित्त सुविधा अर्थात नाबार्ड/सिडबी/एनएचबी यू/एस को भारिबैं अधिनियम, 1934 की 17(4एच) के अनुसार 17 अप्रैल 2020 से बंद है।

मुद्रा और बैंकिंग

सं. 6: मुद्रा स्टॉक मात्रा

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की बकाया स्थिति				
	2019-20	2019	2020		
			अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10
	1	2	3	4	5
1 जनता के पास मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 - 1.4)	2349715	2092067	2341744	2389526	2424621
1.1 संचलन में नोट	2420964	2154070	2412993	2460582	2496611
1.2 रुपये सिक्के का संचलन	25572	25167	25572	25572	25572
1.3 छोटे सिक्कों का संचलन	743	743	743	743	743
1.4 बैंकों के पास नकदी	97563	87913	97563	97371	98305
2 जनता की जमाराशियां	1776199	1494100	1775869	1635906	1621593
2.1 बैंकों के पास मांग जमाराशियां	1737692	1466439	1737692	1596480	1582022
2.2 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	27660	38177	39426	39570
3 एम₁ (1 + 2)	4125915	3586167	4117614	4025432	4046213
4 डाकघर बचत बैंक जमाराशियां	141786	142785	141786	141786	141786
5 एम₂ (3 + 4)	4267701	3728952	4259400	4167218	4187999
6 बैंकों के पास मीयादी जमाराशियां	12674016	11792438	12674016	12964111	12987875
7 एम₃ (3 + 6)	16799930	15378604	16791629	16989543	17034088
8 कुल डाकघर जमाराशियां	409246	372622	409246	409246	409246
9 एम₄ (7 + 8)	17209176	15751226	17200875	17398789	17443334

सं. 7: मुद्रा स्टॉक (एम₃) का स्रोत

(करोड़ ₹)

स्रोत	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5
1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4906583	4502970	5008525	5365413	5415971
1.1 आरबीआई का सरकार को निवल ऋण (1.1.1-1.1.2)	992192	842809	1094134	1171048	1214517
1.1.1 सरकार पर दावे	1047808	928547	1094277	1171191	1214660
1.1.1.1 केन्द्र सरकार	1045314	928481	1092310	1170829	1213597
1.1.1.2 राज्य सरकारें	2494	66	1967	362	1063
1.1.2 आरबीआई के पास सरकार की जमाशियां	55616	85738	143	143	143
1.1.2.1 केन्द्र सरकार	55573	85696	100	100	100
1.1.2.2 राज्य सरकारें	43	42	43	43	43
1.2 सरकार को अन्य बैंक ऋण	3914391	3660161	3914391	4194365	4201454
2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11038644	10226812	11037091	10991283	10923206
2.1 आरबीआई का वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	13166	8681	11613	7612	6126
2.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को अन्य बैंकों द्वारा दिया गया ऋण	11025478	10218131	11025478	10983671	10917080
2.2.1 वाणिज्य बैंकों द्वारा बैंक ऋण	10370861	9620945	10370861	10338598	10273416
2.2.2 सहकारी बैंकों द्वारा बैंक ऋण	637776	588367	637776	635535	633810
2.2.3 वाणिज्य और सहकारी बैंकों द्वारा अन्य प्रतिभूतियों में निवेश	16842	8818	16842	9538	9854
3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1 + 3.2)	3798902	3143334	3754433	3839237	3870102
3.1 आरबीआई की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (3.1.1-3.1.2)	3590402	2921080	3545933	3630737	3661602
3.1.1 सकल विदेशी आस्तियां	3590636	2921292	3546167	3630971	3661836
3.1.2 विदेशी देयताएं	234	212	234	234	234
3.2 अन्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	208500	222254	208500	208500	208500
4 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26315	25910	26315	26315	26315
5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	2970514	2520422	3034735	3232705	3201505
5.1 आरबीआई की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं	1378342	1093371	1344671	1428226	1456364
5.2 अन्य बैंकों की निवल गैर-मौद्रिक देयताएं (अवशिष्ट)	1592172	1427051	1690064	1804479	1745141
एम₃ (1+2+3+4-5)	16799930	15378604	16791629	16989543	17034088

सं. 8: मौद्रिक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
			अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10
	1	2	3	4	5
मौद्रिक समुच्चय					
एन एम1 (1.1 + 1.2.1+1.3)	4125915	3586167	4117614	4025432	4046213
एन एम2 (एन एम1 + 1.2.2.1)	9745743	8813622	9737442	9777023	9809686
एन एम3 (एन एम2 + 1.2.2.2 + 1.4 = 2.1 + 2.2 + 2.3 - 2.4- 2.5)	16923860	15572196	16915559	17105428	17155388
1 घटक					
1.1 जनता के पास मुद्रा	2349715	2092067	2341744	2389526	2424621
1.2. निवासियों की कुल जमाराशियां	14226198	13083007	14226198	14377792	14389739
1.2.1 मांग जमाराशियां	1737692	1466439	1737692	1596480	1582022
1.2.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	12488506	11616567	12488506	12781312	12807716
1.2.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5619828	5227455	5619828	5751590	5763472
1.2.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	278598	169419	178130	163845
1.2.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6868678	6389112	6868678	7029722	7044244
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	27660	38177	39426	39570
1.4 वित्तीय संस्थाओं से मांग /सावधि निधीयन	309439	369462	309439	298684	301459
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	16802627	15652304	16903016	17181134	17253140
2.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	4906583	4502970	5008525	5365413	5415971
2.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं. ऋण	992192	842809	1094134	1171048	1214517
2.1.1.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा सरकार को ऋण	3914391	3660161	3914391	4194365	4201454
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को बैंक ऋण	11896044	11149334	11894491	11815721	11837169
2.1.2.1 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैंक ऋण	13166	8681	11613	7612	6126
2.1.2.2 बैंकिंग प्रणाली द्वारा वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11882878	11140653	11882878	11808109	11831043
2.1.2.2.1 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियां)	846284	913592	846284	813447	902293
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26315	25910	26315	26315	26315
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3612303	2857066	3567834	3632818	3668867
2.3.1 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	2921080	3545933	3630737	3661602
2.3.2 बैंकिंग प्रणाली की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	21900	-64014	21900	2081	7264
2.4 पूंजी खाता	2670439	2399359	2645611	2745883	2789555
2.5 अन्य मदें (निवल)	846946	563725	935995	988956	1003377

सं. 9: चलनिधि समुच्चय

(करोड़ ₹)

समुच्चय	2019-20	2019		2020	
		अप्रैल	फरवरी	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5
1 एन एम₃	16923860	15572196	16589311	16923860	17155388
2 डाकघर जमाराशियां	409246	372620	409246	409246	409246
3 एल₁ (1 + 2)	17333106	15944816	16998557	17333106	17564634
4 वित्तीय संस्थाओं की देयताएं	57479	2932	57964	57479	56424
4.1 सावधि मुद्रा उधार	7928	2656	2851	7928	9928
4.2 जमा प्रमाण-पत्र	46249	31	51556	46249	43199
4.3 सावधि जमाराशियां	3302	245	3557	3302	3297
5 एल₂ (3 + 4)	17390584	15947748	17056522	17390584	17621058
6 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के पास जनता की जमाराशियां	31905	31905	..
7 एल₃ (5 + 6)	17422489	17422489	..

टिप्पणी: नवंबर 2019 के बाद से, वित्तीय संस्थानों की देनदारियों पर अद्यतन डेटा इस सारणी में शामिल किया गया है, और इसलिए, पिछले डेटा के साथ इसकी तुलना नहीं की जा सकती है।

सं. 10: भारतीय रिज़र्व बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 31 /माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/ नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019		2020	
		अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 संचलन में मुद्रा	2447279	2179980	2439308	2486897	2522926
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	560462	579875	435745	457178
1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	505131	522944	536186	401621	423731
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	27660	38177	39426	39570
आरक्षित मुद्रा (1.1+1.2+1.3=2.1+2.2+2.3-2.4-2.5)	3029674	2768103	3057360	2962068	3019674
2 स्रोत					
2.1 भा.रि.बैं.के देशी ऋण	791299	914483	829783	733242	788121
2.1.1 सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण	992192	842809	1094134	1171048	1214517
2.1.1.1 केन्द्र सरकार को निवल भा.रि.बैं.ऋण (2.1.1.1.1+2.1.1.1.2+2.1.1.1.3+2.1.1.1.4-2.1.1.1.5)	989741	842785	1092210	1170729	1213497
2.1.1.1.1 केन्द्र सरकार को ऋण और अग्रिम	-	-	50477	110942	111985
2.1.1.1.2 खज़ाना बिलों में निवेश	-	-	-	-	-
2.1.1.1.3 दिनांकित सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	1044468	927571	1040987	1059045	1100775
2.1.1.1.3.1 केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियां	1044468	927571	1040987	1059045	1100775
2.1.1.1.4 रुपया सिक्के	846	910	846	842	837
2.1.1.1.5 केन्द्र सरकार की जमाराशियां	55573	85696	100	100	100
2.1.1.2 राज्य सरकारों को निवल भा.रि.बैं. ऋण	2451	24	1924	319	1020
2.1.2 बैंकों पर भा.रि.बैं. के दावे	-214059	62993	-275964	-445418	-432522
2.1.2.1 अनुसूचित वाणिज्य बैंकों को ऋण और अग्रिम	-214059	62993	-275964	-445418	-432522
2.1.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को भा.रि.बैं. के ऋण	13166	8681	11613	7612	6126
2.1.3.1 प्राथमिक व्यापारियों को ऋण और अग्रिम	5920	2348	4782	5647	4162
2.1.3.2 नाबार्ड को ऋण और अग्रिम	-	-	-	-	-
2.2 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26315	25910	26315	26315	26315
2.3 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	2921080	3545933	3630737	3661602
2.3.1 सोना	230527	161192	231083	237531	251551
2.3.2 विदेशी मुद्रा आस्तियां	3359893	2759906	3314868	3393224	3410069
2.4 पूंजी खाता	1165066	1001770	1140238	1215928	1239451
2.5 अन्य मदें (निवल)	213276	91601	204433	212298	216913

सं. 11: आरक्षित मुद्रा - घटक और स्रोत

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	मार्च 31/माह के लिए नियत अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया					
		2019		2020			
		अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 3	अप्रैल 10	अप्रैल 17	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5	6	7
आरक्षित मुद्रा (1.1 + 1.2 + 1.3 = 2.1 + 2.2 + 2.3 + 2.4 + 2.5 - 2.6)	3029674	2768103	3057360	2972911	2962068	3016027	3019674
1 घटक							
1.1 संचलन में मुद्रा	2447279	2179980	2439308	2457025	2486897	2506266	2522926
1.2 भा.रि.बैं. के पास बैंकों की जमाराशियां	543888	560462	579875	477843	435745	470869	457178
1.3 भा.रि.बैं. के पास 'अन्य' जमाराशियां	38507	27660	38177	38043	39426	38892	39570
2 स्रोत							
2.1 सरकार को निवल रिज़र्व बैंक ऋण	992192	842809	1094134	1088018	1171048	1211995	1214517
2.2 बैंकों को रिज़र्व बैंक ऋण	-214059	62993	-275964	-357239	-445418	-433991	-432522
2.3 वाणिज्यिक क्षेत्र को रिज़र्व बैंक ऋण	13166	8681	11613	12513	7612	7066	6126
2.4 भा.रि.बैं. की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	3590402	2921080	3545933	3602983	3630737	3658405	3661602
2.5 जनता के प्रति सरकार की मुद्रा देयताएं	26315	25910	26315	26315	26315	26315	26315
2.6 भा.रि.बैं. की निवल गैर मौद्रिक देयताएं	1378342	1093371	1344671	1399679	1428226	1453763	1456364

सं. 12: वाणिज्य बैंक सर्वेक्षण

(करोड़ ₹)

मद	माह के नियत अंतिम शुक्रवार/ माह के नियत शुक्रवार की स्थिति के अनुसार बकाया				
	2019-20	2019	2020		
		अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5
1 घटक					
1.1 निवासियों की कुल जमाराशियां	13381983	12307999	13381983	13531819	13543024
1.1.1 मांग जमाराशियां	1617003	1351722	1617003	1476185	1461382
1.1.2 निवासियों की सावधि जमाराशियां	11764979	10956277	11764979	12055633	12081642
1.1.2.1 अल्पावधि सावधि जमाराशियां	5294241	4930324	5294241	5425035	5436739
1.1.2.1.1 जमा प्रमाण-पत्र	169419	278598	169419	178130	163845
1.1.2.2 दीर्घावधि सावधि जमाराशियां	6470739	6025952	6470739	6630598	6644903
1.2 वित्तीय संस्थाओं से मांग/सावधि निधायन	309439	369462	309439	298684	301459
2 स्रोत					
2.1 देशी ऋण	14913131	13990278	14913131	15113490	15148325
2.1.1 सरकार को ऋण	3684917	3454331	3684917	3957998	3968353
2.1.2 वाणिज्यिक क्षेत्र को ऋण	11228214	10535948	11228214	11155492	11179973
2.1.2.1 बैंक ऋण	10370861	9620945	10370861	10338598	10273416
2.1.2.1.1 गैर-खाद्यान्न ऋण	10319097	9577783	10319097	10284524	10220772
2.1.2.2 प्राथमिक व्यापारियों को निवल ऋण	11378	9193	11378	11254	11933
2.1.2.3 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में निवेश	8653	1180	8653	1156	1293
2.1.2.4 अन्य निवेश (गैर-एसएलआर प्रतिभूतियों में)	837321	904629	837321	804484	893331
2.2 वाणिज्य बैंकों की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां (2.2.1-2.2.2-2.2.3)	21900	-64014	21900	2081	7264
2.2.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	315641	251601	315641	285981	294196
2.2.2 अनिवासी विदेशी मुद्रा प्रत्यावर्तनीय मीयादी जमाराशियां	185510	175871	185510	182799	180159
2.2.3 समुद्रपार विदेशी मुद्रा उधार	108231	139745	108231	101102	106773
2.3 निवल बैंक रिज़र्व (2.3.1+2.3.2-2.3.3)	899410	538119	899410	933982	944027
2.3.1 भा.रि.बैं. के पास शेष	536186	522944	536186	401621	423731
2.3.2 उपलब्ध नकदी	87260	78168	87260	86943	87774
2.3.3 भा.रि.बैं. से ऋण और अग्रिम	-275964	62993	-275964	-445418	-432522
2.4 पूंजी खाता	1481202	1373418	1481202	1505784	1525934
2.5 अन्य मदें (निवल) (2.1+2.2+2.3-2.4-1.1-1.2)	661818	413504	661818	713266	729201
2.5.1 अन्य मांग और मीयादी देयताएं (2.2.3 का निवल)	495445	348151	495445	463376	414847
2.5.2 निवल अंतर-बैंक देयताएं (प्राथमिक व्यापारियों से इतर)	65654	-55907	65654	71083	68082

सं. 13: अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के निवेश

(करोड़ ₹)

मद	मार्च 27, 2020 की स्थिति	2019	2020		
		अप्रैल 26	मार्च 27	अप्रैल 10	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5
1 एसएलआर प्रतिभूतियां	3693570	3455511	3693570	3959154	3969646
2 वाणिज्यिक पत्र	104526	93223	104526	104021	110876
3 निम्नलिखित द्वारा जारी शेयर					
3.1 सरकारी उद्यम	14106	11721	14106	13578	13561
3.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	75415	69232	75415	70621	70543
3.3 अन्य	5734	6323	5734	5286	5250
4 निम्नलिखित द्वारा जारी बांड / डिबेंचर					
4.1 सरकारी उद्यम	125710	132729	125710	88879	128736
4.2 निजी कारपोरेट क्षेत्र	226559	259429	226559	230581	254953
4.3 अन्य	191690	167345	191690	155518	154872
5 निम्नलिखित द्वारा जारी लिखत					
5.1 म्यूचुअल फंड	35610	46128	35610	32672	45305
5.2 वित्तीय संस्थाएं	97665	95601	97665	103317	109222

सं. 14: भारत में कारोबार - सभी अनुसूचित बैंक और सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में) /नियत शुक्रवार की स्थिति							
	सभी अनुसूचित बैंक				सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक			
	2019-20	2019	2020		2019-20	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
1	2	3	4	5	6	7	8	
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	219	213	219	211	142	138	142	134
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं	320240	259760	320240	329365	314513	254808	314513	323746
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	239943	174593	239943	248981	234348	170026	234348	243507
1.2 बैंकों से उधार राशि	64001	74764	64001	64521	64001	74556	64001	64521
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	16295	10402	16295	15863	16163	10226	16163	15717
2 अन्य के प्रति देयताएं	14905949	13681911	14905949	14979130	14480607	13341227	14480607	14546260
2.1 कुल जमाराशियां	13975551	12811649	13975551	14139462	13567492	12483869	13567492	13723182
2.1.1 मांग	1653242	1381905	1653242	1497338	1617003	1351722	1617003	1461382
2.1.2 मीयादी	12322309	11429744	12322309	12642124	11950489	11132147	11950489	12261801
2.2 उधार	313908	373174	313908	305776	309439	369462	309439	301459
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	616491	497087	616491	533892	603676	487896	603676	521620
3 रिजर्व बैंक से उधार	285623	105478	285623	288194	285623	105478	285623	288194
3.1 मीयादी बिल / वचन पत्रों की जमानत पर	-	-	-	-	-	-	-	-
3.2 अन्य	285623	105478	285623	288194	285623	105478	285623	288194
4 उपलब्ध नकदी और रिजर्व बैंक के पास शेष	643038	616584	643038	526668	623446	601112	623446	511505
4.1 उपलब्ध नकदी	89671	79907	89671	90298	87260	78168	87260	87774
4.2 रिजर्व बैंक के पास शेष	553367	536677	553367	436370	536186	522944	536186	423731
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां	323680	360417	323680	333867	260238	319908	260238	267597
5.1 अन्य बैंकों के पास शेष	181460	242913	181460	195016	155401	222711	155401	161923
5.1.1 चालू खाते में	17204	13796	17204	20132	14457	11244	14457	17946
5.1.2 अन्य खातों में	164256	229117	164256	174884	140945	211467	140945	143977
5.2 मांग और अल्पसूचना पर मुद्रा	43335	40395	43335	44728	20273	27323	20273	19699
5.3 बैंकों को अग्रिम	38266	28291	38266	26670	30531	26461	30531	25331
5.4 अन्य आस्तियां	60619	48817	60619	67453	54032	43412	54032	60643
6 निवेश	3811765	3548355	3811765	4090673	3693570	3455511	3693570	3969646
6.1 सरकारी प्रतिभूतियां	3797040	3541477	3797040	4082760	3684917	3454331	3684917	3968353
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियां	14724	6878	14724	7914	8653	1180	8653	1293
7 बैंक ऋण	10705336	9906829	10705336	10604651	10370861	9620945	10370861	10273416
7क खाद्यान्न ऋण	82172	70197	82172	83051	51763	43161	51763	52643
7.1 ऋण नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	10480934	9667703	10480934	10404931	10149509	9386746	10149509	10076434
7.2 देशी बिल - खरीदे गए	26214	25783	26214	22933	25658	24435	25658	22511
7.3 देशी बिल - भुनाए गए	147209	148773	147209	135807	145683	146161	145683	134450
7.4 विदेशी बिल - खरीदे गए	20866	23924	20866	15344	20458	23522	20458	14956
7.5 विदेशी बिल - भुनाए गए	30114	40647	30114	25637	29554	40081	29554	25065

सं. 15: प्रमुख क्षेत्रों द्वारा सकल बैंक ऋण का अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

मद	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2019	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष
			अप्रैल 26	मार्च 27		
	1	2	3	4	5	6
1 सकल बैंक ऋण	9263134	8524065	9263134	9153122	-1.2	7.4
1.1 खाद्यान्न ऋण	51590	43033	51590	52474	1.7	21.9
1.2 गैर-खाद्यान्न ऋण	9211544	8481032	9211544	9100648	-1.2	7.3
1.2.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1157795	1107970	1157795	1151330	-0.6	3.9
1.2.2 उद्योग	2905151	2835204	2905151	2884372	-0.7	1.7
1.2.2.1 सूक्ष्म और लघु	381825	366577	381825	358340	-6.2	-2.2
1.2.2.2 मझौले	105598	106283	105598	99458	-5.8	-6.4
1.2.2.3 बड़े	2417728	2362344	2417728	2426574	0.4	2.7
1.2.3 सेवाएं	2594946	2315042	2594946	2574155	-0.8	11.2
1.2.3.1 परिवहन परिचालक	144466	140924	144466	148733	3.0	5.5
1.2.3.2 कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	20051	18625	20051	20157	0.5	8.2
1.2.3.3 पर्यटन, होटल और रेस्तरां	45977	39879	45977	45862	-0.3	15.0
1.2.3.4 नौवहन	6558	6482	6558	6491	-1.0	0.1
1.2.3.5 पेशेवर सेवाएं	177085	171279	177085	173346	-2.1	1.2
1.2.3.6 व्यापार	552392	507357	552392	545240	-1.3	7.5
1.2.3.6.1 थोक व्यापार	263397	226653	263397	249316	-5.3	10.0
1.2.3.6.2 खुदरा व्यापार	288995	280704	288995	295924	2.4	5.4
1.2.3.7 वाणिज्यिक स्थावर संपदा	229770	200296	229770	229926	0.1	14.8
1.2.3.8 गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियाँ	807383	623418	807383	812388	0.6	30.3
1.2.3.9 अन्य सेवाएं	611264	606782	611264	592012	-3.1	-2.4
1.2.4 व्यक्तिगत ऋण	2553652	2222816	2553652	2490791	-2.5	12.1
1.2.4.1 उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं	9298	6200	9298	8908	-4.2	43.7
1.2.4.2 आवास	1338964	1168623	1338964	1330709	-0.6	13.9
1.2.4.3 मीयादी जमाराशि की जमानत पर अग्रिम	79496	67389	79496	67905	-14.6	0.8
1.2.4.4 शेयरों और बांडों की जमानत पर व्यक्तियों को अग्रिम	5334	5692	5334	4818	-9.7	-15.4
1.2.4.5 क्रेडिट कार्ड बकाया	108094	92526	108094	96978	-10.3	4.8
1.2.4.6 शिक्षा	65745	67546	65745	65246	-0.8	-3.4
1.2.4.7 वाहन ऋण	220609	199817	220609	216968	-1.7	8.6
1.2.4.8 अन्य व्यक्तिगत ऋण	726112	615023	726112	699259	-3.7	13.7
1.2अ प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र	2897461	2729851	2897461	2811116	-3.0	3.0
1.2अ.1 कृषि और उससे जुड़ी गतिविधियां	1146624	1101235	1146624	1145120	-0.1	4.0
1.2अ.2 सूक्ष्म और लघु उद्यम	1149394	1065969	1149394	1100834	-4.2	3.3
1.2अ.2.1 विनिर्माण	381825	366577	381825	358340	-6.2	-2.2
1.2अ.2.2 सेवाएं	767568	699392	767568	742494	-3.3	6.2
1.2अ.3 आवास	449945	432122	449945	459911	2.2	6.4
1.2अ.4 माइक्रो क्रेडिट	38237	27331	38237	35154	-8.1	28.6
1.2अ.5 शिक्षा ऋण	51906	53814	51906	52003	0.2	-3.4
1.2अ.6 अजा/अजजा के लिए राज्य प्रायोजित संस्थाएं	388	392	388	395	1.8	0.8
1.2अ.7 कमजोर वर्ग	731409	677013	731409	743790	1.7	9.9
1.2अ.8 निर्यात ऋण	16114	15212	16114	16690	3.6	9.7

सं. 16: सकल बैंक ऋण का उद्योग-वार अभिनियोजन

(करोड़ ₹)

उद्योग	बकाया स्थिति				वृद्धि (%)	
	मार्च 27, 2020	2019	2020		वित्तीय वर्ष में अब तक	वर्ष-दर-वर्ष 2020
			अप्रैल 26	मार्च 27		
	1	2	3	4	5	6
1 उद्योग	2905151	2835204	2905151	2884372	-0.7	1.7
1.1 खनन और उत्खनन (कोयला सहित)	43927	41852	43927	43508	-1.0	4.0
1.2 खाद्य प्रसंस्करण	154146	153960	154146	152326	-1.2	-1.1
1.2.1 चीनी	27382	30532	27382	27362	-0.1	-10.4
1.2.2 खाद्य तेल और वनस्पति	19240	20946	19240	18044	-6.2	-13.9
1.2.3 चाय	5375	5102	5375	5193	-3.4	1.8
1.2.4 अन्य	102149	97380	102149	101727	-0.4	4.5
1.3 पेय पदार्थ और तंबाकू	16522	13034	16522	16458	-0.4	26.3
1.4 वस्त्र	192424	199280	192424	190040	-1.2	-4.6
1.4.1 सूती वस्त्र	89283	95458	89283	87254	-2.3	-8.6
1.4.2 जूट से बने वस्त्र	2116	2138	2116	1994	-5.8	-6.7
1.4.3 मानव-निर्मित वस्त्र	26074	26456	26074	26094	0.1	-1.4
1.4.4 अन्य वस्त्र	74951	75228	74951	74698	-0.3	-0.7
1.5 चमड़ा और चमड़े से बने उत्पाद	11098	11066	11098	10830	-2.4	-2.1
1.6 लकड़ी और लकड़ी से बने उत्पाद	12233	11644	12233	12343	0.9	6.0
1.7 कागज़ और कागज़ से बने उत्पाद	30965	30146	30965	31276	1.0	3.7
1.8 पेट्रोलियम, कोयला उत्पाद और आण्विक इंधन	75834	54874	75834	81636	7.7	48.8
1.9 रसायन और रासायनिक उत्पाद	202949	177611	202949	193201	-4.8	8.8
1.9.1 उर्वरक	49066	32750	49066	35981	-26.7	9.9
1.9.2 औषधि और दवाइयां	53427	49881	53427	53198	-0.4	6.6
1.9.3 पेट्रो केमिकल्स	42233	41242	42233	47383	12.2	14.9
1.9.4 अन्य	58223	53738	58223	56639	-2.7	5.4
1.10 रबड़, प्लास्टिक और उनके उत्पाद	50415	45410	50415	49763	-1.3	9.6
1.11 कांच और कांच के सामान	8777	9766	8777	8412	-4.2	-13.9
1.12 सीमेन्ट और सीमेन्ट से बने उत्पाद	58689	55348	58689	58916	0.4	6.4
1.13 मूल धातु और धातु उत्पाद	350325	355290	350325	354085	1.1	-0.3
1.13.1 लोहा और स्टील	262396	270001	262396	268125	2.2	-0.7
1.13.2 अन्य धातु और धातु से बने उत्पाद	87929	85289	87929	85960	-2.2	0.8
1.14 सभी अभियांत्रिकी	157259	166433	157259	154251	-1.9	-7.3
1.14.1 इलेक्ट्रॉनिक्स	30159	38118	30159	29968	-0.6	-21.4
1.14.2 अन्य	127100	128315	127100	124283	-2.2	-3.1
1.15 वाहन, वाहन के पुर्जे और परिवहन उपस्कर	82606	77769	82606	82565	0.0	6.2
1.16 रत्न और आभूषण	59515	66697	59515	58880	-1.1	-11.7
1.17 निर्माण	104288	98440	104288	98980	-5.1	0.5
1.18 इन्फ्रास्ट्रक्चर	1053913	1064713	1053913	1055204	0.1	-0.9
1.18.1 पावर	559774	569829	559774	566556	1.2	-0.6
1.18.2 दूरसंचार	143760	129704	143760	139040	-3.3	7.2
1.18.3 सड़क	190676	186154	190676	189441	-0.6	1.8
1.18.4 अन्य इन्फ्रास्ट्रक्चर	159703	179026	159703	160167	0.3	-10.5
1.19 अन्य उद्योग	239266	201871	239266	231698	-3.2	14.8

सं. 17: भारतीय रिज़र्व बैंक में राज्य सहकारी बैंकों के खाते

(करोड़ ₹)

मद	नियत अंतिम शुक्रवार (मार्च के संबंध में)/अंतिम शुक्रवार/नियत शुक्रवार की स्थिति								
	2018-19	2019		2020					
		मार्च 29	जनवरी 03	जनवरी 17	जनवरी 31	फरवरी 14	फरवरी 28	मार्च 13	मार्च 27
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
सूचना देने वाले बैंकों की संख्या	32	32	31	31	31	31	31	31	31
1 कुल जमाराशियां (2.1.1.2+2.2.1.2)	62003.4	62003.4	124366.8	124885.4	123075.2	119021.8	123327.0	123095.1	123812.9
2 मांग और मीयादी देयताएं									
2.1 मांग देयताएं	18241.3	18241.3	24731.1	24075.7	22487.2	23392.4	23551.9	24248.2	26007.5
2.1.1 जमाराशियां									
2.1.1.1 अंतर-बैंक	5842.3	5842.3	4708.8	4427.8	4195.9	4959.8	4673.7	5573.2	5295.0
2.1.1.2 अन्य	9,808.6	9808.6	13689.5	13123.8	11836.3	11897.2	12354.8	12161.4	14317.3
2.1.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	40.0	0.0	0.0	199.9	100.0
2.1.3 अन्य मांग देयताएं	2590.5	2590.5	6332.8	6524.0	6414.9	6535.3	6523.4	6313.7	6295.2
2.2 मीयादी देयताएं	98531.4	98531.4	165054.1	167344.8	166992.5	157744.2	166156.7	167444.2	167558.4
2.2.1 जमाराशियां									
2.2.1.1 अंतर-बैंक	45655.9	45655.9	52520.1	54056.6	54245.2	49117.1	53699.0	54997.7	56564.0
2.2.1.2 अन्य	52194.8	52194.8	110677.4	111761.5	111238.8	107124.6	110972.2	110933.7	109495.7
2.2.2 बैंकों से उधार	0.0	0.0	958.2	629.9	629.9	629.9	629.9	630.0	630.2
2.2.3 अन्य मीयादी देयताएं	680.7	680.7	898.5	896.7	878.6	872.5	855.6	882.7	868.6
3 रिज़र्व बैंक से उधार	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
4 अधिसूचित बैंक/राज्य सरकार से उधार	50375.4	50375.4	47721.8	46896.8	47300.4	42517.2	47242.3	49412.6	52538.8
4.1 मांग	16826.7	16826.7	14077.8	13830.6	13669.2	13469.1	12968.7	14027.1	13764.4
4.2 मीयादी	33548.7	33548.7	33644.0	33066.2	33631.2	29048.0	34273.6	35385.6	38774.4
5 उपलब्ध नकदी और रिज़र्व बैंक के पास शेष	5721.0	5721.0	9377.1	9283.9	9097.3	8975.0	8975.0	8860.3	9425.7
5.1 उपलब्ध नकदी	319.1	319.1	716.2	733.6	763.1	763.8	835.8	694.2	748.4
5.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष	5401.9	5401.9	8660.9	8550.3	8334.2	8211.2	8139.3	8166.1	8677.2
6 चालू खाते में अन्य बैंकों के पास शेष	1543.2	1543.2	904.8	1095.3	1072.3	1007.6	1390.0	1127.9	1489.1
7 सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश	30885.3	30885.3	50225.7	49531.9	49785.7	47885.8	47261.4	49381.9	50626.9
8 मांग और अल्प सूचना पर मुद्रा	16190.2	16190.2	22950.8	21965.6	19796.7	21632.0	19828.7	22642.7	25259.9
9 बैंक ऋण (10.1+11)	60089.8	60089.8	107825.9	102106.5	104819.2	105187.4	106797.1	108078.9	110575.6
10 अग्रिम									
10.1 ऋण, नकदी-ऋण और ओवरड्राफ्ट	60086.2	60086.2	107825.4	102105.9	104818.7	105186.7	106796.5	108078.4	110575.0
10.2 बैंकों से प्राप्य राशि	82610.9	82610.9	70604.2	78326.2	78091.6	78958.8	79645.0	80135.6	81300.1
11 खरीदे और भुनाए गए बिल	3.7	3.7	0.6	0.6	27.3	0.7	1.2	1.2	1.2

मूल्य और उत्पादन

सं. 18: उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (आधार: 2012=100)

समूह/उप समूह	2019-20			ग्रामीण			शहरी			मिश्रित		
	ग्रामीण	शहरी	मिश्रित	अप्रैल '19	मार्च '20	अप्रैल '20	अप्रैल '19	मार्च '20	अप्रैल '20	अप्रैल '19	मार्च '20	अप्रैल '20
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 खाद्य और पेय पदार्थ	146.3	149.6	147.5	138.0	148.2	150.1	141.7	150.1	153.5	139.4	148.9	151.4
1.1 अनाज और उत्पाद	140.7	143.2	141.4	137.1	144.4	147.2	140.0	146.5	151.8	138.0	145.1	148.7
1.2 मांस और मछली	163.3	161.4	162.6	156.2	166.8	--	153.7	167.5	--	155.3	167.0	--
1.3 अंडा	142.1	145.7	143.5	134.7	147.6	146.9	139.4	148.9	151.9	136.5	148.1	148.8
1.4 दूध और उत्पाद	146.5	146.0	146.3	142.4	151.7	155.6	141.9	151.1	155.5	142.2	151.5	155.6
1.5 तैल और चर्बी	127.1	121.8	125.1	124.0	133.3	137.1	118.4	127.5	131.6	121.9	131.2	135.1
1.6 फल	144.0	148.8	146.2	143.8	141.8	147.3	148.6	143.3	152.9	146.0	142.5	149.9
1.7 सब्जी	163.5	187.8	171.7	129.3	152.3	162.7	150.2	167.0	180.0	136.4	157.3	168.6
1.8 दाल और उत्पाद	133.7	132.0	133.1	122.9	141.8	150.2	121.7	139.7	150.8	122.5	141.1	150.4
1.9 चीनी और उत्पाद	112.0	113.4	112.5	108.4	112.6	119.8	110.4	114.4	121.2	109.1	113.2	120.3
1.10 मसाले	145.6	145.1	145.5	138.7	154.0	158.7	140.4	151.5	154.0	139.3	153.2	157.1
1.11 गैर नशीले पेय पदार्थ	138.8	130.2	135.2	137.5	140.1	139.2	128.7	131.9	133.5	133.8	136.7	136.8
1.12 तैयार भोजन, नाश्ता, मिठाई	157.6	156.7	157.2	156.3	160.0	--	154.2	159.1	--	155.3	159.6	--
2 पान, तंबाकू और मादक पदार्थ	166.3	169.0	167.0	162.9	170.5	--	165.7	173.3	--	163.6	171.2	--
3 कपड़ा और जूते	151.3	143.7	148.3	150.1	152.5	--	142.0	145.6	--	146.9	149.8	--
3.1 कपड़ा	152.0	145.7	149.5	150.8	153.4	--	143.9	147.7	--	148.1	151.2	--
3.2 जूते	146.9	132.4	140.9	146.3	147.6	--	131.3	133.8	--	140.1	141.9	--
4 आवास	--	152.2	152.2	--	--	--	149.7	154.5	155.6	149.7	154.5	155.6
5 ईंधन और लाइट	148.6	131.5	142.2	146.6	153.4	--	129.1	141.4	137.1	140.0	148.9	--
6 विविध	145.6	135.9	140.9	142.6	148.6	--	133.1	138.7	--	138.0	143.8	--
6.1 घरेलू सामान और सेवा	150.6	138.7	145.0	149.4	151.5	--	136.9	140.8	--	143.5	146.4	--
6.2 स्वास्थ्य	153.6	142.1	149.3	150.9	156.7	154.3	139.5	145.0	144.8	146.6	152.3	150.7
6.3 परिवहन और संचार	132.6	122.2	127.1	130.2	135.8	--	120.2	124.6	--	124.9	129.9	--
6.4 मनोरंजन	148.3	135.9	141.3	144.9	151.2	--	133.8	137.9	--	138.6	143.7	--
6.5 शिक्षा	159.8	150.9	154.5	156.3	161.2	--	147.7	152.5	--	151.3	156.1	--
6.6 व्यक्तिगत देखभाल और प्रभाव	139.2	138.4	138.9	133.7	145.1	--	132.4	145.3	--	133.2	145.2	--
सामान्य सूचकांक (सभी समूह)	147.3	145.1	146.3	141.7	149.8	--	140.6	147.3	--	141.2	148.6	--

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 19: अन्य उपभोक्ता मूल्य सूचकांक

मद	आधार वर्ष	योजक कारक	2019-20	2020		
				अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5	6
1 औद्योगिक कामगार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	2001	4.63	323	312	326	329
2 कृषि श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	5.89	980	932	1007	1014
3 ग्रामीण श्रमिक उपभोक्ता मूल्य सूचकांक	1986-87	--	986	939	1013	1019

स्रोत: श्रम ब्यूरो, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 20: मुंबई में सोने और चांदी का मासिक औसत मूल्य

मद	2019-20	2019		2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल	मार्च
	1	2	3	4	5
1 मानक स्वर्ण (₹ प्रति 10 ग्राम)	37018	31659	42285	45504	45504
2 चांदी (₹ प्रति किलोग्राम)	42514	37328	41382	42058	42058

स्रोत: मुंबई में सोने और चांदी के मूल्य के लिए भारत बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन लि., मुंबई।

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अप्रैल	फरवरी	मार्च (अ)	अप्रैल (अ)
	1	2	3	4	5	6
1 सभी पण्य	100.000	121.9	121.1	122.2	121.1	
1.1 प्राथमिक वस्तुएं	22.618	143.5	139.3	142.8	139.5	138.2
1.1.1 खाद्य वस्तुएं	15.256	155.8	148.8	154.7	151.6	152.6
1.1.1.1 खाद्यान्न (अनाज+ दाल)	3.462	159.6	153.5	163.4	159.8	160.1
1.1.1.2 फल और सब्जियाँ	3.475	174.8	158.5	157.2	150.7	159.3
1.1.1.3 दूध	4.440	146.7	143.2	149.6	150.9	151.6
1.1.1.4 अंडा, मांस और मछली	2.402	147.0	142.9	153.7	146.8	140.5
1.1.1.5 मसाले	0.529	144.0	127.4	150.0	149.4	146.8
1.1.1.6 अन्य खाद्य वस्तुएं	0.948	143.9	149.6	142.7	141.5	140.1
1.1.2 खाद्येतर वस्तुएं	4.119	128.9	127.7	131.7	126.1	126.2
1.1.2.1 फाइबर	0.839	128.3	133.4	124.4	124.0	123.8
1.1.2.2 तिलहन	1.115	151.4	147.8	153.7	149.9	150.0
1.1.2.3 अन्य खाद्येतर वस्तुएं	1.960	104.8	102.8	105.4	105.1	105.3
1.1.2.4 फूल	0.204	239.7	234.2	294.6	206.0	206.0
1.1.3 खनिज	0.833	154.2	158.0	157.4	153.8	157.4
1.1.3.1 धात्विक खनिज	0.648	147.1	153.7	148.0	144.4	148.0
1.1.3.2 अन्य खनिज	0.185	178.9	173.0	190.1	186.6	190.1
1.1.4 कच्चा तेल और नैसर्गिक गैस	2.410	86.7	92.7	81.3	81.3	61.2
1.2 ईंधन और बिजली	13.152	102.3	102.8	103.6	100.7	92.4
1.2.1 कोल	2.138	125.3	123.6	126.5	126.5	126.5
1.2.1.1 कुकिंग कोल	0.647	138.1	133.9	141.9	141.9	141.9
1.2.1.2 नॉन-कुकिंग कोल	1.401	119.0	119.0	119.0	119.0	119.0
1.2.1.3 लिग्नाइट	0.090	129.1	121.2	131.1	131.1	131.1
1.2.2 खनिज तेल	7.950	92.3	95.4	92.4	87.2	74.9
1.2.3 बिजली	3.064	112.1	107.3	116.6	117.9	113.9
1.3 विनिर्मित उत्पाद	64.231	118.3	118.5	118.8	118.7	
1.3.1 खाद्य उत्पादों का विनिर्माण	9.122	133.9	129.4	137.0	136.9	136.5
1.3.1.1 मांस का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.134	137.5	135.6	136.8	136.6	
1.3.1.2 मछली, क्रस्टेशियस, मोलस्क और उनके उत्पादों का प्रसंस्करण एवं परिरक्षण	0.204	136.1	133.6	136.0	137.2	139.2
1.3.1.3 फल और सब्जियों का परिरक्षण और प्रसंस्करण	0.138	114.3	112.2	114.9	114.5	114.7
1.3.1.4 सब्जियाँ और पशु तेल एवं चर्बी	2.643	119.4	113.9	129.3	128.4	127.6
1.3.1.5 डेयरी उत्पाद	1.165	145.0	135.1	151.0	151.9	151.4
1.3.1.6 अनाज मिल के उत्पाद	2.010	146.3	143.4	146.2	146.6	146.1
1.3.1.7 स्टार्च और स्टार्च के उत्पाद	0.110	135.5	133.3	133.4	132.5	129.5
1.3.1.8 बेकरी उत्पाद	0.215	133.5	131.3	136.4	136.2	136.4
1.3.1.9 चीनी, गुड़ और शहद	1.163	118.3	112.9	119.2	118.9	118.9
1.3.1.10 कोक, चॉकलेट और चीनी कन्फेक्शनरी	0.175	127.3	128.2	126.4	126.4	126.8
1.3.1.11 मैक्रोनी, नूडल्स, कूसकूस और उसके जैसे मैदे से बने उत्पाद	0.026	132.7	133.1	130.5	131.3	123.6
1.3.1.12 चाय और कॉफी उत्पाद	0.371	139.5	146.2	126.2	127.5	128.2
1.3.1.13 प्रसंस्कृत मसाले और नमक	0.163	132.4	125.3	140.4	140.6	139.5
1.3.1.14 प्रसंस्कृत तैयार खाद्य पदार्थ	0.024	128.7	128.3	130.3	129.4	
1.3.1.15 स्वास्थ्य पूरक	0.225	159.9	158.7	156.4	156.7	156.0
1.3.1.16 पशु के लिए तैयार खाद्य	0.356	173.7	165.3	170.0	167.2	166.9
1.3.2 पेय पदार्थों का विनिर्माण	0.909	123.6	122.7	123.9	124.1	124.4
1.3.2.1 शराब और स्पिरिट	0.408	117.7	115.6	119.1	119.1	119.2
1.3.2.2 माल्ट लिकर और माल्ट	0.225	125.7	122.6	126.5	126.7	127.1
1.3.2.3 शीतल पेय, मिनरल वॉटर और बोतलबन्द पानी के अन्य उत्पाद	0.275	130.5	133.3	129.1	129.3	129.8
1.3.3 विनिर्मित तंबाकू उत्पाद	0.514	153.5	153.2	155.0	154.8	
1.3.3.1 तंबाकू के उत्पाद	0.514	153.5	153.2	155.0	154.8	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अप्रैल	फरवरी	मार्च (अ)	अप्रैल (अ)
1.3.4 वस्त्र विनिर्माण	4.881	117.7	119.4	116.9	116.6	
1.3.4.1 धागों की कताई और वस्त्र तैयार करना	2.582	107.9	111.7	105.8	105.6	
1.3.4.2 बुनाई और तैयार वस्त्र	1.509	130.1	130.3	130.9	130.7	
1.3.4.3 बुने हुए और क्रॉचिडेट फेब्रिक्स	0.193	114.5	111.6	113.8	112.9	
1.3.4.4 कपड़ों को छोड़कर निर्मित वस्त्र सामग्री	0.299	134.5	132.2	133.5	133.5	
1.3.4.5 डोरियाँ, रस्सी, सुतली और नेटिंग	0.098	143.0	139.4	146.0	146.0	
1.3.4.6 अन्य वस्त्र	0.201	116.8	115.7	116.7	117.2	
1.3.5 विनिर्मित तैयार वस्त्र	0.814	138.3	139.0	138.1	138.0	
1.3.5.1 फर से बने वस्त्रों को छोड़कर वुलन के तैयार वस्त्र	0.593	139.2	140.2	138.8	138.9	
1.3.5.2 बुने हुए क्रॉचिडेट वस्त्र	0.221	135.8	135.5	136.2	135.7	
1.3.6 चमड़ा और उससे बने हुए उत्पाद का विनिर्माण	0.535	118.7	120.6	118.1	117.9	
1.3.6.1 चमड़े की टैनिंग और ड्रेसिंग; ड्रेसिंग और फर की रंगायी	0.142	105.5	108.4	103.6	103.5	
1.3.6.2 सामान, हैंडबैग, काठी और दोहन	0.075	136.3	135.3	137.6	137.4	
1.3.6.3 जूते-चप्पल	0.318	120.4	122.5	119.9	119.7	
1.3.7 लकड़ी के विनिर्माण और लकड़ी और कॉर्क के उत्पाद	0.772	133.7	133.6	132.7	133.0	
1.3.7.1 आरा मिलिंग और लकड़ी के उत्पाद	0.124	122.2	125.6	120.1	119.5	
1.3.7.2 विनियर शीट, प्लायवुड का विनिर्माण, लॅमिन बोर्ड, पार्टिकल बोर्ड और अन्य पॅनल और बोर्ड	0.493	135.5	135.3	135.4	135.3	
1.3.7.3 बिल्डरों की बढ़ईगीरी	0.036	176.2	173.9	178.0	178.0	
1.3.7.4 लकड़ी के डिब्बे	0.119	125.7	123.3	121.5	123.8	
1.3.8 कागज़ और कागज़ के उत्पाद का विनिर्माण	1.113	121.1	123.9	120.3	120.3	
1.3.8.1 लुगदी, कागज़ और कागज़ बोर्ड	0.493	125.0	129.5	123.6	123.7	
1.3.8.2 लहरदार कागज़ और पेपर बोर्ड और कागज़ के पात्र और पेपर बोर्ड	0.314	114.9	116.2	115.3	114.8	
1.3.8.3 कागज़ की अन्य सामग्री और पेपर बोर्ड	0.306	121.2	122.9	120.1	120.4	
1.3.9 मुद्रण और रिकार्डेड मीडिया का पुनरुत्पादन	0.676	150.6	150.1	152.3	153.3	
1.3.9.1 मुद्रण	0.676	150.6	150.1	152.3	153.3	
1.3.10 रसायन और रासायनिक उत्पाद का विनिर्माण	6.465	117.6	119.9	115.8	115.8	116.8
1.3.10.1 मूल रसायन	1.433	120.0	125.4	117.1	116.5	116.5
1.3.10.2 उर्वरक और नाइट्रोजन यौगिक	1.485	123.1	122.9	122.4	122.7	123.0
1.3.10.3 प्लास्टिक और सिंथेटिक रबड़ प्राथमिक रूप में	1.001	112.5	116.9	109.3	109.1	107.1
1.3.10.4 कीटनाशक और अन्य एग्रोकैमिकल उत्पाद	0.454	122.6	123.0	121.7	121.5	121.5
1.3.10.5 पेन्ट, वार्निश और समान कोटिंग, मुद्रण स्याही और मैस्टिक्स	0.491	114.7	116.2	113.2	113.3	
1.3.10.6 साबुन और डिटर्जेंट, सफाई और चमकाने की सामग्री, इत्र और शौचालय सफाई की सामग्री	0.612	118.8	120.0	117.7	119.0	117.1
1.3.10.7 अन्य रासायनिक उत्पाद	0.692	114.2	115.6	113.5	113.6	114.4
1.3.10.8 मानव निर्मित फाइबर	0.296	98.0	100.7	95.8	95.6	95.7
1.3.11 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद का विनिर्माण	1.993	127.4	125.1	131.7	130.6	130.4
1.3.11.1 फार्मास्यूटिकल्स, औषधीय रसायन और वनस्पति उत्पाद	1.993	127.4	125.1	131.7	130.6	130.4
1.3.12 रबड़ और प्लास्टिक उत्पाद का विनिर्माण	2.299	108.5	109.7	107.9	107.7	
1.3.12.1 रबड़ टायर और ट्यूब, रबड़ टायर की रीट्रीडिंग और पुनर्निर्माण	0.609	99.0	100.2	98.7	98.2	
1.3.12.2 रबड़ के अन्य उत्पाद	0.272	93.6	92.5	93.5	93.6	
1.3.12.3 प्लास्टिक उत्पाद	1.418	115.4	117.1	114.5	114.6	
1.3.13 अन्य अधात्विक खनिज उत्पादों का विनिर्माण	3.202	116.7	117.4	116.5	116.5	
1.3.13.1 कांच और कांच उत्पाद	0.295	124.7	125.4	125.5	125.9	
1.3.13.2 आग रोधक उत्पाद	0.223	108.7	108.0	108.6	107.9	
1.3.13.3 मिट्टी से बनी भवन निर्माण सामग्री	0.121	102.7	102.2	102.7	106.4	
1.3.13.4 चीनी मिट्टी के बर्तन और चीनी मिट्टी	0.222	113.9	114.5	114.7	112.3	
1.3.13.5 सीमेन्ट, चूना और प्लास्टर	1.645	119.5	119.9	119.4	119.4	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (जारी)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अप्रैल	फरवरी	मार्च (अ)	अप्रैल (अ)
1.3.13.6 कंक्रीट,सीमेन्ट और प्लास्टर से बनी वस्तुएं	0.292	121.7	121.8	122.9	122.8	
1.3.13.7 पत्थरों को काटना,आकार देना और संवारना	0.234	120.1	120.5	121.1	121.0	
1.3.13.8 अन्य अधात्विक खनिज उत्पाद	0.169	86.6	94.4	78.1	78.1	
1.3.14 मूल धातुओं का विनिर्माण	9.646	106.3	110.5	107.0	106.6	105.7
1.3.14.1 स्टील तैयार करने में प्रयुक्त सामग्री	1.411	100.7	106.2	104.3	104.2	115.6
1.3.14.2 मेटेलिक आयरन	0.653	107.8	115.5	109.7	108.0	111.1
1.3.14.3 नरम इस्पात-अर्ध निर्मित इस्पात	1.274	95.1	98.0	96.0	96.1	96.6
1.3.14.4 नरम इस्पात- लंबे उत्पाद	1.081	105.5	110.1	105.6	106.4	106.3
1.3.14.5 नरम इस्पात- चपटे उत्पाद	1.144	108.7	116.0	109.5	108.5	98.1
1.3.14.6 स्टेनलेस स्टील के अतिरिक्त एलॉय स्टील-आकार	0.067	102.8	110.6	101.5	101.5	102.9
1.3.14.7 स्टेनलेस स्टील अर्ध निर्मित	0.924	102.8	109.9	104.1	101.8	101.9
1.3.14.8 पाइप और ट्यूब	0.205	126.3	127.1	127.4	126.9	124.5
1.3.14.9 कीमती धातु सहित अलौह धातु	1.693	107.0	110.1	105.7	105.6	104.3
1.3.14.10 कास्टिंग	0.925	113.2	113.1	112.4	112.4	110.1
1.3.14.11 स्टील से गढ़ी वस्तुएं	0.271	146.5	140.5	146.6	145.2	
1.3.15 मशीनरी और उपकरणों को छोड़कर गढ़े हुए धातु उत्पादों का विनिर्माण	3.155	115.5	116.8	114.6	114.7	
1.3.15.1 इमारती धातु उत्पाद	1.031	113.8	115.6	112.8	112.5	
1.3.15.2 धातु से बने टैंक,जलाशय और डिब्बे	0.660	124.4	126.7	123.0	124.9	
1.3.15.3 बाष्प चालित जनरेटर, सेंट्रल हीटिंग हॉट वाटर बॉयलरर्स को छोड़कर	0.145	104.7	102.7	107.7	107.7	
1.3.15.4 धातु की फोर्जिंग, दबाना, स्टैपिंग और रोल फॉर्मिंग, पाउडर धातुकर्म	0.383	100.4	101.6	99.0	99.0	
1.3.15.5 कटलरी, हस्त चालित उपकरण और सामान्य हार्डवेयर	0.208	100.5	99.9	100.9	100.9	
1.3.15.6 अन्य गढ़े हुए धातु उत्पाद	0.728	124.0	125.3	122.9	122.3	
1.3.16 कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक और ऑप्टिकल उत्पादों का विनिर्माण	2.009	110.3	111.4	109.4	109.3	
1.3.16.1 इलेक्ट्रॉनिक पुरजे	0.402	98.1	98.0	98.1	97.9	
1.3.16.2 कंप्यूटर और संबंधित उपकरण	0.336	135.0	135.1	135.0	135.0	
1.3.16.3 संचार उपकरण	0.310	117.0	116.6	115.0	114.6	
1.3.16.4 उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स	0.641	98.6	101.9	96.5	96.5	
1.3.16.5 मापने, जांचने, नेविगेशन और नियंत्रण उपकरण	0.181	111.5	111.9	110.6	110.6	
1.3.16.6 हाथ घड़ी और दीवार घड़ी	0.076	139.1	139.7	140.9	141.1	
1.3.16.7 विभासन, विद्युत चिकित्सकीय एवं विद्युत उपचारात्मक उपकरण	0.055	103.9	105.3	108.3	108.0	
1.3.16.8 ऑप्टिकल उपकरण और फोटोग्राफिक उपकरण	0.008	110.2	109.2	112.0	112.0	
1.3.17 इलेक्ट्रिकल उपकरण का विनिर्माण	2.930	111.3	112.7	110.7	111.7	
1.3.17.1 विद्युतमोटर्स, जनरेटर, ट्रांसफार्मर और बिजली वितरण और नियंत्रण संबंधी उपकरण	1.298	109.0	111.0	108.6	111.1	
1.3.17.2 बैटरी और एक्युमुलेटर	0.236	117.0	117.6	115.9	115.9	
1.3.17.3 डेटा संचरण या छवियों के सजीव प्रसारण के लिए फाइबर ऑप्टिक केबल	0.133	109.9	119.0	105.9	104.7	
1.3.17.4 अन्य इलेक्ट्रॉनिक और बिजली के वायर और केबल	0.428	109.8	110.2	109.4	109.3	
1.3.17.5 वायरिंग संबंधी चीजें और बिजली के प्रकाश और सजावट के उपकरण	0.263	111.1	110.3	111.7	111.7	
1.3.17.6 घरेलू उपकरण	0.366	119.9	120.4	118.1	118.1	
1.3.17.7 अन्य इलेक्ट्रिकल उपकरण	0.206	108.6	108.9	109.5	109.1	
1.3.18 मशीनरी और उपकरणों का विनिर्माण	4.789	113.1	112.5	113.2	112.9	
1.3.18.1 इंजन और टर्बाइन, एयरक्राफ्ट, वाहन और दुपहिया वाहनों के इंजन को छोड़कर	0.638	104.8	105.0	105.3	105.3	
1.3.18.2 तरल बिजली उपकरण	0.162	119.9	119.5	119.6	119.6	
1.3.18.3 अन्य पंप, कंप्रेसर, नल और वाल्व	0.552	111.3	110.1	111.8	110.4	
1.3.18.4 बेयरिंग, गियर्स, गेयरिंग और ड्राइविंग उपकरण	0.340	109.8	110.1	107.9	108.6	
1.3.18.5 ओवन, फर्नेस और फर्नेस बर्नर	0.008	80.0	77.9	81.0	81.0	
1.3.18.6 माल उठाने एवं चढ़ाने-उतारने वाले उपकरण	0.285	111.5	111.8	111.2	110.9	

सं. 21: थोक मूल्य सूचकांक (समाप्त)
(आधार: 2011-12=100)

पण्य	भारांक	2019-20	2019	2020		
			अप्रैल	फरवरी	मार्च (अ)	अप्रैल (अ)
1.3.18.7 कार्यालय मशीनरी और उपकरण	0.006	130.2	130.2	130.2	130.2	
1.3.18.8 सामान्य प्रयोजन के अन्य उपकरण	0.437	130.9	128.4	128.5	128.5	
1.3.18.9 कृषि और वानिकी मशीनरी	0.833	120.6	119.3	121.4	121.5	
1.3.18.10 धातु निर्माण करनेवाली मशीनरी और मशीन टूल्स	0.224	108.1	104.9	109.7	109.7	
1.3.18.11 खनन, उत्खनन और निर्माण के लिए मशीनरी	0.371	75.1	76.9	75.0	74.8	
1.3.18.12 खाद्य, पेय और तंबाकू प्रसंस्करण के लिए मशीनरी	0.228	125.1	123.1	128.6	128.6	
1.3.18.13 कपड़ा, परिधान और चमड़े के उत्पादन से जुड़ी मशीनरी	0.192	119.6	122.1	117.9	117.8	
1.3.18.14 अन्य विशेष प्रयोजनों के लिए मशीनरी	0.468	126.3	125.6	126.9	125.8	
1.3.18.15 अक्षय ऊर्जा उत्पादन मशीनरी	0.046	66.1	66.6	65.4	65.4	
1.3.19 मोटर वाहन, ट्रेलरों और अर्ध-ट्रेलरों का विनिर्माण	4.969	114.5	113.2	115.6	115.4	
1.3.19.1 मोटर वाहन	2.600	115.1	113.6	116.3	116.1	
1.3.19.2 मोटर वाहन पुरजे और सहायक उपकरण	2.368	113.7	112.8	114.8	114.7	
1.3.20 अन्य परिवहन उपकरणों का विनिर्माण	1.648	118.0	114.2	120.5	120.5	
1.3.20.1 जहाजों और तैरने वाली -वस्तुओं का निर्माण	0.117	158.8	158.8	158.8	158.8	
1.3.20.2 रेलवे इंजन और रोलिंग स्टॉक	0.110	106.5	106.2	105.8	105.8	
1.3.20.3 मोटर साइकल	1.302	114.3	109.4	117.6	117.6	
1.3.20.4 साइकल और अवैध गाड़ी	0.117	128.9	130.5	128.3	128.2	
1.3.20.5 अन्य परिवहन उपकरण	0.002	126.1	124.7	127.5	127.5	
1.3.21 फर्नीचर का विनिर्माण	0.727	130.8	128.4	131.3	130.9	
1.3.21.1 फर्नीचर	0.727	130.8	128.4	131.3	130.9	
1.3.22 अन्य विनिर्माण	1.064	112.6	106.5	117.0	117.6	
1.3.22.1 आभूषण और संबंधित सामग्री	0.996	109.7	103.3	114.4	115.0	
1.3.22.2 संगीत उपकरण	0.001	174.0	170.4	175.1	174.5	
1.3.22.3 खेल के सामान	0.012	129.7	127.7	131.3	131.0	
1.3.22.4 खेल और खिलौने	0.005	136.7	138.9	135.5	135.5	
1.3.22.5 चिकित्सा और दंत चिकित्सा उपकरण और सामग्री	0.049	162.1	160.9	163.2	163.2	
2 खाद्य सूचकांक	24.378	147.6	141.5	148.1	146.1	146.6

स्रोत: आर्थिक सलाहकार का कार्यालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

सं. 22: औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आधार: 2011-12=100)

उद्योग	भारत	2018-19	2019-20	अप्रैल-मार्च		मार्च	
				2018-19	2019-20	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7
सामान्य सूचकांक	100.00	130.1	129.2	130.1	129.2	144.1	120.1
1 क्षेत्रवार वर्गीकरण							
1.1 खनन और उत्खनन	14.37	107.9	109.7	107.9	109.7	132.7	132.7
1.2 विनिर्माण	77.63	131.5	129.8	131.5	129.8	144.6	114.8
1.3 बिजली	7.99	156.9	158.6	156.9	158.6	160.1	149.2
2 उपयोग आधारित वर्गीकरण							
2.1 मूल वस्तुएं	34.05	126.1	127.1	126.1	127.1	140.0	135.6
2.2 पूंजीगत माल	8.22	108.4	93.6	108.4	93.6	118.6	76.4
2.3 मध्यवर्ती माल	17.22	126.2	137.3	126.2	137.3	154.4	125.8
2.4 बुनियादी/निर्माण वस्तुएं	12.34	141.7	136.1	141.7	136.1	155.4	118.4
2.5 उपभोक्ता टिकाऊ माल	12.84	130.4	119.4	130.4	119.4	131.7	88.1
2.6 उपभोक्ता गैर-टिकाऊ माल	15.33	145.5	146.3	145.5	146.3	156.6	131.2

स्रोत : राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार।

सरकारी खाते और खज़ाना बिल

सं. 23: केन्द्र सरकार के खाते - एक नज़र में

(राशि करोड़ ₹ में)

मद	2020-21			2019-20		
	बजट अनुमान	अप्रैल 2019		अनंतिम खाते	संशोधित अनुमान	संशोधित अनुमान की तुलना में अनंतिम खाते का प्रतिशत
		वास्तविक	बजट अनुमानों का प्रतिशत			
	1	2	3	4	5	6
1 राजस्व प्राप्ति	2020926	27183	1.3	1682107	1850101	90.9
1.1 कर राजस्व (निवल)	1635909	21412	1.3	1355886	1504587	90.1
1.2 करेतर राजस्व	385017	5771	1.5	326221	345514	94.4
2 पूंजीगत प्राप्ति	224967	365	0.2	68620	81605	84.1
2.1 ऋण की वसूली	14967	365	2.4	18316	16605	110.3
2.2 अन्य प्राप्ति	210000	0	0.0	50304	65000	77.4
3 कुल प्राप्ति (उधारियों को छोड़कर) (1+2)	2245893	27548	1.2	1750727	1931706	90.6
4 राजस्व व्यय	2630145	278754	10.6	2349618	2349645	100.0
जिसमें से:						
4.1 ब्याज भुगतान	708203	26696	3.8	611036	625105	97.7
5 पूंजी व्यय	412085	28306	6.9	336744	348907	96.5
6 कुल व्यय (4+5)	3042230	307060	10.1	2686362	2698552	99.5
7 राजस्व घाटा (4-1)	609219	251571	41.3	667511	499544	133.6
8 राजकोषीय घाटा (6-3)	796337	279512	35.1	935635	766846	122.0
9 सकल प्राथमिक घाटा (8-4.1)	88134	252816	286.9	324599	141741	229.0

स्रोत : महालेखानियंत्रक, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार।

सं. 24: खजाना बिल - स्वामित्व का स्वरूप

(करोड़ ₹)

मद	2018-19	2019		2020				
		अप्रैल 26	मार्च 20	मार्च 27	अप्रैल 3	अप्रैल 10	अप्रैल 17	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 91-दिवसीय								
1.1 बैंक	18521	22870	12826	10165	10444	12291	17513	19626
1.2 प्राथमिक व्यापारी	17878	16568	9116	9190	11003	13344	14404	23622
1.3 राज्य सरकारें	26999	29114	10746	8173	8173	8123	8218	8218
1.4 अन्य	27747	44885	50577	48004	47230	52692	52325	52995
2 182-दिवसीय								
2.1 बैंक	31953	40665	66070	66419	65008	68514	66368	67072
2.2 प्राथमिक व्यापारी	38738	45519	36917	43302	49074	48741	48233	45949
2.3 राज्य सरकारें	28036	20946	13386	13386	13382	13936	13934	13934
2.4 अन्य	18567	15078	24319	22465	29209	30310	36921	54270
3 364-दिवसीय								
3.1 बैंक	48811	52653	46954	49660	51148	51981	53188	53348
3.2 प्राथमिक व्यापारी	74170	78485	64818	70672	72936	74688	69990	66146
3.3 राज्य सरकारें	18892	20157	11945	11945	11145	13024	13133	12688
3.4 अन्य	62393	53565	72104	70576	75489	78389	84965	99950
4 14-दिवसीय मध्यवर्ती								
4.1 बैंक								
4.2 प्राथमिक व्यापारी								
4.3 राज्य सरकारें	165605	146432	154060	155112	130780	140053	123775	169253
4.4 अन्य	252	522	245	617	1093	976	1100	1112
कुल खजाना बिल								
(14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल को छोड़कर)#	412704	440506	419779	423957	444241	466034	479194	517816

14 दिवसीय मध्यवर्ती खजाना बिल बिक्री योग्य नहीं है, ये बिल 91 दिवसीय, 182 दिवसीय और 364 दिवसीय खजाना बिलों जैसे नहीं है। यह बिल स्वरूप के अनुसार मध्यवर्ती हैं क्योंकि राज्य सरकारों के दैनिक न्यूनतम नकदी शेष में कमी को पूरा करने के लिए परिसमाप्त किए जाते हैं।

सं. 25: खजाना बिलों की नीलामी

(राशि करोड़ ₹ में)

नीलामी की तारीख	अधिसूचित राशि	प्राप्त बोलियां				स्वीकृत बोलियां				कुल निर्गम (6+7)	कट-ऑफ मूल्य	कट-ऑफ मूल्य पर निहित प्रतिफल (प्रतिशत)
		संख्या	कुल अंकित मूल्य		संख्या	कुल अंकित मूल्य						
			प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी		प्रतियोगी	गैर-प्रतियोगी					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
91-दिवसीय खजाना बिल												
2019-20												
मार्च 30	5000	59	23312	470	12	5000	470	5470	98.92	4.3595		
2020-21												
अप्रैल 8	10000	99	38025	836	36	9999	836	10835	98.94	4.2972		
अप्रैल 15	10000	102	61457	1826	7	9994	1826	11820	98.98	4.1493		
अप्रैल 22	15000	133	92233	2051	14	14989	2051	17040	99.08	3.7297		
अप्रैल 29	15000	120	97283	689	35	14981	689	15670	99.10	3.6427		
182-दिवसीय खजाना बिल												
2019-20												
मार्च 30	10000	133	43927	0	35	10000	0	10000	97.58	4.9694		
2020-21												
अप्रैल 8	8000	171	55592	460	35	7990	460	8450	97.77	4.5799		
अप्रैल 15	8000	142	74684	15	5	7990	15	8005	97.89	4.3201		
अप्रैल 22	16000	187	136473	7	7	15993	7	16000	98.21	3.6553		
अप्रैल 29	16000	143	93303	3	9	15997	3	16000	98.21	3.6553		
364-दिवसीय खजाना बिल												
2019-20												
मार्च 30	10000	102	33465	0	23	10000	0	10000	95.31	4.9396		
2020-21												
अप्रैल 8	7000	117	32062	1931	43	6999	1931	8930	95.59	4.6261		
अप्रैल 15	7000	115	62228	1	4	6999	1	7000	95.82	4.3751		
अप्रैल 22	14000	146	114476	2	5	13998	2	14000	96.41	3.7393		
अप्रैल 29	14000	127	80287	2	10	13998	2	14000	96.44	3.7016		

वित्तीय बाजार

सं. 26: दैनिक मांग मुद्रा दरें

(वार्षिक प्रतिशत)

स्थिति के अनुसार	दरों का दायरा		भारित औसत दरें
	उधार लेना/उधार देना		उधार लेना/उधार देना
	1		2
अप्रैल	3, 2020	0.50-5.00	4.18
अप्रैल	4, 2020	3.05-4.40	3.69
अप्रैल	7, 2020	2.00-5.00	4.23
अप्रैल	8, 2020	2.40-5.25	4.24
अप्रैल	9, 2020	2.40-5.25	4.34
अप्रैल	13, 2020	2.40-5.00	4.25
अप्रैल	15, 2020	2.40-5.25	4.26
अप्रैल	16, 2020	2.40-5.00	4.24
अप्रैल	17, 2020	2.40-5.00	4.21
अप्रैल	18, 2020	2.60-3.90	3.12
अप्रैल	20, 2020	2.30-5.00	4.14
अप्रैल	21, 2020	2.30-5.00	4.10
अप्रैल	22, 2020	2.30-5.00	4.13
अप्रैल	23, 2020	2.30-4.55	4.13
अप्रैल	24, 2020	2.30-5.00	4.04
अप्रैल	27, 2020	2.00-4.50	4.03
अप्रैल	28, 2020	2.25-4.50	4.04
अप्रैल	29, 2020	2.30-4.50	4.07
अप्रैल	30, 2020	2.30-4.50	4.16
मई	2, 2020	2.80-4.25	3.19
मई	4, 2020	2.40-4.75	4.04
मई	5, 2020	2.30-4.50	3.96
मई	6, 2020	2.30-4.50	3.90
मई	8, 2020	2.30-4.75	3.98
मई	11, 2020	2.30-4.75	3.87
मई	12, 2020	2.30-4.30	3.79
मई	13, 2020	2.30-4.50	3.88
मई	14, 2020	2.30-4.50	3.92
मई	15, 2020	2.30-4.60	3.96

टिप्पणी: नोटिस मुद्रा सहित

सं. 27: जमा प्रमाण-पत्र

मद	2019	2020			
	अप्रैल 26	मार्च 13	मार्च 27	अप्रैल 10	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	225478.45	173941.00	172996.00	180116.00	180891.00
1.1 पखवाड़े के दौरान जारी (करोड़ ₹)	4582.87	19166.55	18290.30	12556.15	4539.49
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.65-7.33	4.95-6.50	4.96-8.80	4.70-7.94	4.70-7.84

सं. 28: वाणिज्यिक पत्र

मद	2019	2020			
	अप्रैल 30	मार्च 15	मार्च 31	अप्रैल 15	अप्रैल 30
	1	2	3	4	5
1 बकाया राशि (करोड़ ₹)	542885.80	401724.55	344526.95	381273.50	417227.05
1.1 पखवाड़े के दौरान रिपोर्ट किए गए (करोड़ ₹)	71210.80	148273.30	63166.10	54770.55	77889.20
2 ब्याज दर (प्रतिशत)	6.67-13.14	5.01-13.95	4.88-12.39	4.55-9.90	3.78-10.45

सं. 29: चुनिंदा वित्तीय बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(करोड़ ₹)

मद	2019-20	2019	2020					
		अप्रैल 26	मार्च 20	मार्च 27	अप्रैल 3	अप्रैल 10	अप्रैल 17	अप्रैल 24
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 मांग मुद्रा	26815	38125	30536	23920	11672	17680	19192	19171
2 नोटिस मुद्रा	3660	682	7169	1904	7996	1069	6162	622
3 मीयादी मुद्रा	790	900	1104	1239	1835	1347	1516	1083
4 सीबीएलओ / त्रिपक्षीय रिपो	300691	219772	411859	356209	355378	273677	384497	365866
5 बाजार रिपो	221719	158935	346213	203083	275424	230768	291022	239087
6 कापॉरेट बांड में रिपो	2468	4548	1137	3670	4333	4600	2630	1568
7 फोरेक्स (यूएस मिलियन डॉलर)	67793	76959	83800	64600	60818	38068	40305	39840
8 भारत सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां	93960	60217	119391	41929	60096	30921	34227	99925
9 राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां	5800	6178	4733	2699	2680	2991	3123	3927
10 खजाना बिल								
10.1 91-दिवसीय	3720	3877	4596	1848	4441	3165	2998	2783
10.2 182-दिवसीय	2380	2947	2161	1988	3205	2746	5900	9547
10.3 364-दिवसीय	2900	1648	1690	1543	4986	4530	6849	8753
10.4 नकदी प्रबंधन बिल	2310		4918		17100	14893	3193	3170
11 कुल सरकारी प्रतिभूतियां (8+9+10)	111070	74867	137490	50006	92508	59247	56290	128104
11.1 भारतीय रिजर्व बैंक	-	209	239	7873	133	4897	4134	6002

टिप्पणी : मुद्रा बाजार के संपार्श्विक उधार और ऋण दायित्व (सीबीएलओ) खंड को समाप्त किया गया तथा उसके स्थान पर 5 नवंबर 2018 से त्रिपक्षीय रिपो लाया गया।

सं. 30: गैर-सरकारी पब्लिक लिमिटेड कंपनियों के नए पूंजी निर्गम

(राशि करोड़ ₹ में)

प्रतिभूति और निर्गम का प्रकार	2019-20		2018-19 (अप्रै.-अप्रैल)		2019-20 (अप्रै.-अप्रैल)*		अप्रैल 2019		अप्रैल 2020*	
	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि	निर्गमों की संख्या	राशि
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 इक्विटी शेयर	72	64926	9	27756	3	14	9	27756	3	14
1ए प्रीमियम	70	43259	9	7709	3	7	9	7709	3	7
1.1 पब्लिक	57	9867	7	2744	3	14	7	2744	3	14
1.1.1 प्रीमियम	55	9434	7	2698	3	7	7	2698	3	7
1.2 राइट्स	15	55059	2	25012	—	—	2	25012	—	—
1.2.1 प्रीमियम	15	33825	2	5011	—	—	2	5011	—	—
2 अधिमान शेयर	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3 बांड और डिबेंचर	34	14984	5	2191	—	—	5	2191	—	—
3.1 परिवर्तनीय	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.1 पब्लिक	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.1.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3.2 अपरिवर्तनीय	34	14984	5	2191	—	—	5	2191	—	—
3.2.1 पब्लिक	34	14984	5	2191	—	—	5	2191	—	—
3.2.2 राइट्स	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4 कुल (1+2+3)	106	79910	14	29947	3	14	14	29947	3	14
4.1 पब्लिक	91	24851	12	4935	3	14	12	4935	3	14
4.2 राइट्स	15	55059	2	25012	—	—	2	25012	—	—

टिप्पणी : अप्रैल 2020 से मासिक डाटा का समेकन निर्गम की समाप्ति की तारीख के आधार पर की जाती है जबकि पूर्व में समेकन का कार्य निर्गम चालू होने की तारीख के आधार पर किया जाता था।

स्रोत : भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (सेबी)।

* : आंकड़े अनंतिम हैं।

बाह्य क्षेत्र

सं. 31: विदेशी व्यापार

मद	इकाई	2019-20	2019		2020			
			अप्रैल	दिसंबर	जनवरी	फरवरी	मार्च	अप्रैल
		1	2	3	4	5	6	7
1 निर्यात	करोड ₹	2226567	181021	194919	185219	197646	159158	78951
	मिलियन अमरिकी डॉलर	314314	26073	27379	25972	27647	21406	10356
1.1 तेल	करोड ₹	302858	25535	27711	23555	24265	18523	9473
	मिलियन अमरिकी डॉलर	42782	3678	3892	3303	3394	2491	1243
1.2 तेल से इतर	करोड ₹	1923709	155487	167208	161664	173382	140635	69479
	मिलियन अमरिकी डॉलर	271532	22396	23487	22669	24253	18915	9114
2 आयात	करोड ₹	3307977	287433	282124	293440	268064	231711	130525
	मिलियन अमरिकी डॉलर	467193	41401	39628	41148	37497	31165	17121
2.1 तेल	करोड ₹	917306	78989	76110	92503	76894	74462	35537
	मिलियन अमरिकी डॉलर	129431	11377	10691	12971	10756	10015	4661
2.2 तेल से इतर	करोड ₹	2390671	208443	206014	200938	191170	157249	94988
	मिलियन अमरिकी डॉलर	337762	30023	28938	28177	26741	21150	12460
3 व्यापार शेष	करोड ₹	-1081410	-106412	-87205	-108221	-70418	-72553	-51574
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-152879	-15327	-12249	-15175	-9850	-9758	-6765
3.1 तेल	करोड ₹	-614448	-53455	-48399	-68948	-52629	-55939	-26065
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-86648	-7699	-6798	-9668	-7362	-7524	-3419
3.2 तेल से इतर	करोड ₹	-466962	-52957	-38806	-39274	-17788	-16614	-25509
	मिलियन अमरिकी डॉलर	-66231	-7628	-5451	-5507	-2488	-2235	-3346

स्रोत: वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय तथा वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय।

सं. 32: विदेशी मुद्रा भंडार

मद	इकाई	2019	2020					
		मई 24	अप्रैल 17	अप्रैल 24	मई 1	मई 8	मई 15	मई 22
		1	2	3	4	5	6	7
1 कुल भंडार	करोड ₹	2924080	3662709	3665786	3612274	3666574	3680676	3721819
	मिलियन अमरिकी डॉलर	419992	479568	479455	481078	485313	487039	490044
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	करोड ₹	2730010	3374844	3376090	3328720	3381304	3390717	3430708
	मिलियन अमरिकी डॉलर	392189	441884	441564	443316	447548	448670	451706
1.2 स्वर्ण	करोड ₹	160780	249585	251551	242360	243961	248680	248955
	मिलियन अमरिकी डॉलर	23022	32679	32901	32277	32291	32906	32779
1.3 एसडीआर	एसडीआरएस मिलियन	1047	1045	1045	1045	1045	1048	1048
	करोड ₹	10060	10896	10865	10705	10748	10766	10876
	मिलियन अमरिकी डॉलर	1445	1427	1421	1426	1423	1425	1432
1.4 आईएमएफ में आरक्षित भाग की स्थिति	करोड ₹	23230	27384	27280	30489	30561	30513	31278
	मिलियन अमरिकी डॉलर	3337	3578	3570	4059	4051	4038	4127

* अंतर, यदि कोई हो, तो पूर्णांकन के वजह से है।

सं. 33: अनिवासी भारतीयों की जमाराशियां

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

योजना	बकाया				प्रवाह	
	2019-20	2019	2020		2019-20	2020-21
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल
	1	2	3	4	5	6
1 एनआरआई जमाराशियां	130581	130912	130581	129310	1983	924
1.1 एफसीएनआर (बी)	24244	24580	24244	23112	1410	-1132
1.2 एनआर (ई) आरए	90367	91282	90367	90456	548	1954
1.3 एनआरओ	15969	15050	15969	15742	26	102

सं. 34: विदेशी निवेश अंतर्वाह

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	2019-20	2019-20	2020-21	2019	2020	
		अप्रैल	अप्रैल	अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5	6
1.1 निवल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1-1.1.2)	42810	4649	1366	4649	2477	1366
1.1.1 भारत में प्रत्यक्ष निवेश (1.1.1.1-1.1.2)	55742	5540	2132	5540	4075	2132
1.1.1.1 सकल अंतर्वाह/सकल निवेश	74591	6866	4479	6866	6422	4479
1.1.1.1.1 ईक्विटी	51203	5364	2884	5364	4339	2884
1.1.1.1.1.1 सरकारी (एसआईए/एफआईपीबी)	3265	63	80	63	188	80
1.1.1.1.1.2 भारतीय रिज़र्व बैंक	39364	4584	2169	4584	3004	2169
1.1.1.1.1.3 शेयरों की अधिप्राप्ति	7348	604	524	604	1086	524
1.1.1.1.1.4 अनिगमित निकायों की ईक्विटी पूंजी	1226	112	112	112	61	112
1.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	14052	1116	1116	1116	1217	1116
1.1.1.1.3 अन्य पूंजी	9336	386	479	386	866	479
1.1.1.2 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	18849	1325	2346	1325	2346	2346
1.1.1.2.1 ईक्विटी	18677	1319	2345	1319	2345	2345
1.1.1.2.2 अन्य पूंजी	173	6	1	6	1	1
1.1.2 भारत द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (1.1.2.1+1.1.2.2+ 1.1.2.3-1.1.2.4)	12932	892	767	892	1598	767
1.1.2.1 ईक्विटी पूंजी	6528	378	442	378	611	442
1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	3121	263	263	263	253	263
1.1.2.3 अन्य पूंजी	5954	379	377	379	1050	377
1.1.2.4 प्रत्यावर्तन /विनिवेश	2672	128	315	128	315	315
1.2 निवल संविभागीय निवेश (1.2.1+1.2.2+1.2.3-1.2.4)	-138	1111	-1114	1111	-16165	-1114
1.2.1 जीडीआर/एडीआर	-	-	-	-	-	-
1.2.2 एफआईआई	247	1216	-1001	1216	-16053	-1001
1.2.3 अपतटीय निधियां और अन्य	-	-	-	-	-	-
1.2.4 भारत द्वारा संविभागीय निवेश	386	105	112	105	112	112
1 विदेशी निवेश अंतर्वाह	42672	5760	252	5760	-13688	252

सं. 35: वैयक्तिक निवासियों के लिए उदारीकृत विप्रेषण योजना (एलआरएस) के अंतर्गत जावक विप्रेषण

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	2019-20	2019	2020		
		अप्रैल	फरवरी	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5
1 एलआरएस के अंतर्गत जावक विप्रेषण	18760.69	1287.91	1686.70	1358.82	499.14
1.1 जमाराशियां	623.37	65.18	50.17	112.96	60.17
1.2 अचल संपत्ति की खरीद	86.43	8.47	7.59	8.99	3.21
1.3 इक्विटी / डेट में निवेश	431.41	35.38	29.68	49.22	24.80
1.4 उपहार	1907.71	166.59	196.77	190.91	55.15
1.5 दान	22.33	0.54	1.16	0.76	2.68
1.6 यात्रा	6955.98	429.75	539.74	307.24	121.13
1.7 निकट संबंधियों का रखरखाव	3439.74	296.14	342.58	346.31	148.25
1.8 चिकित्सा उपचार	33.90	2.49	4.02	3.21	1.35
1.9 विदेश में शिक्षा	4991.07	252.84	496.87	312.68	78.76
1.10 अन्य	268.75	30.53	18.10	26.55	3.66

**सं. 36: भारतीय रुपये का वास्तविक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (रीर) और
सांकेतिक प्रभावी विनिमय दर सूचकांक (नीर)**

मद	2018-19	2019-20	2019	2020	
			मई	अप्रैल	मई
	1	2	3	4	5
36-मुद्रा निर्यात और व्यापार आधारित भारांक (आधार: 2004-05=100)					
1 व्यापार आधारित भारांक					
1.1 नीर	72.64	73.28	74.40	70.37	70.63
1.2 रीर	114.01	116.75	116.04	113.86	114.28
2 निर्यात आधारित भारांक					
2.1 नीर	74.18	74.33	75.45	71.17	71.48
2.2 रीर	116.32	119.61	118.62	116.52	117.03
6-मुद्रा व्यापार आधारित भारांक					
1 आधार : 2004-05 (अप्रैल-मार्च) =100					
1.1 नीर	63.07	63.59	64.23	59.75	60.24
1.2 रीर	121.70	125.76	125.15	119.83	121.27
2 आधार : 2017-18 (अप्रैल-मार्च) =100					
2.1 नीर	92.88	93.63	94.58	87.99	88.71
2.2 रीर	94.20	97.32	96.87	92.76	93.87

सं. 37: बाह्य वाणिज्यिक उधार - पंजीकरण

(राशि अमरिकी मिलियन डॉलर में)

मद	2019-20	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4
1 स्वचालित मार्ग				
1.1 संख्या	1292	108	115	50
1.2 राशि	38011	2658	4959	696
2 अनुमोदन मार्ग				
2.1 संख्या	41	1	8	1
2.2 राशि	14921	500	2478	300
3 कुल (1+2)				
3.1 संख्या	1333	109	123	51
3.2 राशि	52932	3158	7437	996
4 भारत औसत परिपक्वता (वर्षों में)	6.00	4.70	5.58	7.00
5 ब्याज दर (प्रतिशत)				
5.1 6 महीने के लिबॉर पर भारत औसत मार्जिन या अस्थिर दर के ऋणों के लिए संदर्भ दर	1.34	1.31	1.07	1.70
5.2 सावधि दर के ऋणों के लिए ब्याज दर की सीमा	0.00-25.00	0.00-11.50	0.00-10.50	0.00-10.86

सं. 38: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	अक्टूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्टूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	285511	289806	-4296	314908	293307	21601
1 चालू खाता (1.1+1.2)	162792	180544	-17752	162579	163995	-1417
1.1 पण्य	83082	132363	-49281	81232	115856	-34625
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	79710	48181	31529	81347	48139	33208
1.2.1 सेवाएं	55075	33397	21678	55158	33278	21880
1.2.1.1 यात्रा	7372	4865	2508	8545	5569	2977
1.2.1.2 परिवहन	4807	5231	-424	5448	6411	-963
1.2.1.3 बीमा	689	419	271	617	549	67
1.2.1.4 जीएनआईई	144	289	-145	157	218	-62
1.2.1.5 विविध	42062	22594	19469	40391	20531	19860
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	21148	1254	19895	23760	2305	21455
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	9978	10135	-156	11889	12027	-138
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	1324	992	332	1183	550	633
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	673	284	390	757	308	449
1.2.2 अंतरण	18976	1552	17424	20627	1935	18693
1.2.2.1 आधिकारिक	102	237	-134	50	290	-240
1.2.2.2 निजी	18874	1316	17558	20577	1645	18932
1.2.3 आय	5658	13231	-7573	5562	12926	-7364
1.2.3.1 निवेश आय	4295	12639	-8344	4122	12232	-8110
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1363	592	771	1440	694	746
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	122719	108948	13770	151666	129312	22355
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	73237	68038	5199	94408	76606	17802
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	16130	8820	7309	19713	9740	9973
2.1.1.1 भारत में	15505	5139	10366	19085	5856	13229
2.1.1.1.1 इक्विटी	11002	5101	5901	11033	5747	5286
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	3450		3450	3590		3590
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	1052	38	1014	4462	109	4354
2.1.1.2 विदेश में	625	3681	-3056	628	3884	-3256
2.1.1.2.1 इक्विटी	625	1817	-1192	628	1804	-1176
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	758	-758	0	788	-788
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	1106	-1106	0	1293	-1293
2.1.2 संविभाग निवेश	57107	59218	-2111	74695	66866	7829
2.1.2.1 भारत में	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
2.1.2.1.1 एफआईआई	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	45530	47949	-2419	56356	50342	6014
2.1.2.1.1.2 ऋण	11203	10972	231	15405	13285	2119
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0		0	0		0
2.1.2.2 विदेश में	374	297	77	2934	3239	-304
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	20492	17554	2938	23041	19910	3131
2.2.1 बाह्य सहायता	2960	1278	1682	2511	1243	1268
2.2.1.1 भारत द्वारा	11	29	-18	2	28	-26
2.2.1.2 भारत को	2949	1249	1700	2509	1215	1294
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	10468	8466	2002	11007	7774	3233
2.2.2.1 भारत द्वारा	3337	3346	-9	2692	2687	5
2.2.2.2 भारत को	7131	5120	2011	8315	5087	3228
2.2.3 भारत को अल्पावधि	7064	7809	-745	9523	10893	-1370
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	4433	7809	-3377	9523	10129	-606
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	2631	0	2631	0	764	-764
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	21193	16279	4913	21012	23336	-2324
2.3.1 वाणिज्य बैंक	21193	16095	5098	21012	23279	-2266
2.3.1.1 आस्तियां	5964	1763	4202	5753	7260	-1507
2.3.1.2 देयताएं	15228	14332	896	15259	16019	-760
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	13298	13159	139	14407	13579	828
2.3.2 अन्य	0	185	-185	0	58	-58
2.4 रुपया ऋण चुकौती		0	0		0	0
2.5 अन्य पूंजी	7797	7077	720	13205	9460	3745
3 भूल-चूक		314	-314	663		663
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	4296	0	4296	0	21601	-21601
4.1 आईएमएफ	0	0	0			
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	4296	0	4296	0	21601	-21601

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आंशिकरूप से संशोधित

सं. 39: भारत का समग्र भुगतान संतुलन

(करोड़ ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
समग्र भुगतान शेष (1+2+3)	2057747	2088707	-30960	2243026	2089165	153861
1 चालू खाता (1.1+1.2)	1173282	1301224	-127943	1158014	1168105	-10091
1.1 पण्य	598791	953970	-355179	578595	825220	-246625
1.2 अदृश्य मर्दे (1.2.1+1.2.2+1.2.3)	574491	347254	227236	579419	342885	236534
1.2.1 सेवाएं	396941	240704	156237	392878	237033	155845
1.2.1.1 यात्रा	53135	35060	18075	60866	39664	21202
1.2.1.2 परिवहन	34647	37704	-3057	38802	45662	-6860
1.2.1.3 बीमा	4967	3016	1950	4395	3914	481
1.2.1.4 जीएनआईई	1039	2086	-1047	1116	1555	-438
1.2.1.5 विविध	303153	162837	140316	287699	146238	141461
1.2.1.5.1 सॉफ्टवेयर सेवाएं	152422	9037	143385	169238	16420	152819
1.2.1.5.2 कारोबार सेवाएं	71917	73043	-1126	84680	85666	-986
1.2.1.5.3 वित्तीय सेवाएं	9541	7149	2392	8427	3917	4510
1.2.1.5.4 संचार सेवाएं	4854	2046	2808	5390	2194	3196
1.2.2 अंतरण	136768	11188	125580	146924	13780	133143
1.2.2.1 आधिकारिक	738	1705	-967	358	2066	-1708
1.2.2.2 निजी	136030	9483	126547	146566	11714	134852
1.2.3 आय	40781	95362	-54581	39617	92072	-52455
1.2.3.1 निवेश आय	30957	91096	-60139	29362	87129	-57766
1.2.3.2 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9824	4266	5558	10255	4943	5312
2 पूंजी खाता (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5)	884465	785218	99247	1080286	921060	159227
2.1 विदेशी निवेश (2.1.1+2.1.2)	527835	490368	37468	672447	545645	126802
2.1.1 विदेशी प्रत्यक्ष निवेश	116250	63571	52680	140410	69373	71037
2.1.1.1 भारत में	111745	37038	74707	135938	41710	94229
2.1.1.1.1 इक्विटी	79294	36764	42530	78585	40936	37649
2.1.1.1.2 पुनर्निवेशित आय	24868	0	24868	25569		25569
2.1.1.1.3 अन्य पूंजी	7583	274	7309	31784	774	31011
2.1.1.2 विदेश में	4505	26532	-22027	4472	27664	-23192
2.1.1.2.1 इक्विटी	4505	13097	-8592	4472	12846	-8375
2.1.1.2.2 पुनर्निवेशित आय	0	5464	-5464		5611	-5611
2.1.1.2.3 अन्य पूंजी	0	7971	-7971	0	9207	-9207
2.1.2 संविभाग निवेश	411585	426797	-15212	532037	476272	55765
2.1.2.1 भारत में	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
2.1.2.1.1 एफआईआई	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
2.1.2.1.1.1 इक्विटी	328145	345579	-17434	401412	358574	42838
2.1.2.1.1.2 ऋण	80746	79080	1666	109725	94630	15095
2.1.2.1.2 एडीआर /जीडीआर	0	0	0	0	0	0
2.1.2.2 विदेश में	2695	2139	556	20901	23068	-2168
2.2 ऋण (2.2.1+2.2.2+2.2.3)	147693	126518	21175	164114	141812	22303
2.2.1 बाह्य सहायता	21334	9213	12121	17887	8856	9031
2.2.1.1 भारत द्वारा	81	209	-128	14	201	-187
2.2.1.2 भारत को	21253	9004	12249	17873	8655	9218
2.2.2 वाणिज्यिक उधार	75446	61020	14425	78398	55370	23028
2.2.2.1 भारत द्वारा	24052	24119	-67	19175	19136	39
2.2.2.2 भारत को	51394	36901	14493	59224	36234	22990
2.2.3 भारत को अल्पावधि	50913	56284	-5372	67829	77586	-9757
2.2.3.1 आपूर्तिकर्ता का ऋण >180 दिन तथा खरीदार का ऋण	31949	56284	-24335	67829	72147	-4318
2.2.3.2 आपूर्तिकर्ता का 180 दिन तक का ऋण	18964	0	18964	0	5439	-5439
2.3 बैंकिंग पूंजी (2.3.1+2.3.2)	152740	117328	35412	149666	166220	-16553
2.3.1 वाणिज्य बैंक	152740	115997	36743	149666	165808	-16142
2.3.1.1 अस्तित्वां	42987	12706	30281	40978	51709	-10731
2.3.1.2 देयताएं	109753	103292	6461	108688	114099	-5411
2.3.1.2.1 अनिवासी जमाराशियां	95839	94838	1001	102621	96723	5898
2.3.2 अन्य	0	1331	-1331	0	411	-411
2.4 रुपया ऋण चुकौती	0	0	0	0	0	0
2.5 अन्य पूंजी	56197	51005	5192	94059	67383	26675
3 भूल-चूक	0	2264	-2264	4725	0	4725
4 मौद्रिक गतिविधियां (4.1+4.2)	30960	0	30960	0	153861	-153861
4.1 आईएमएफ	0	0	0	0		
4.2 विदेशी मुद्रा भंडार (वृद्धि -/ कमी +)	30960	0	30960	0	153861	-153861

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आशिकरूप से संशोधित

सं. 40: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नामे	निवल	जमा	नामे	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	162786	180523	-17738	162576	163968	-1391
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क. + 1.अ.ख.)	138157	165760	-27603	136389	149134	-12745
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	83082	132363	-49281	81232	115856	-34625
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	82438	125275	-42837	80294	108605	-28311
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	643	0	643	938		938
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण		7087	-7087		7252	-7252
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	55075	33397	21678	55158	33278	21880
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	99	13	87	76	9	67
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	64	376	-313	64	207	-143
1.अ.ख.3 परिवहन	4807	5231	-424	5448	6411	-963
1.अ.ख.4 यात्रा	7372	4865	2508	8545	5569	2977
1.अ.ख.5 निर्माण	865	618	247	734	570	164
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	689	419	271	617	549	67
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	1324	992	332	1183	550	633
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	182	2173	-1990	184	2197	-2013
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	21907	1629	20278	24592	2712	21880
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	9978	10135	-156	11889	12027	-138
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	459	583	-124	535	757	-222
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	144	289	-145	157	218	-62
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	7183	6075	1108	1134	1502	-367
1.आप्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	5658	13231	-7573	5562	12926	-7364
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	1363	592	771	1440	694	746
1.आ.2 निवेश आय	3438	12472	-9035	3312	12078	-8767
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	1668	6495	-4827	1369	5760	-4391
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	35	2311	-2277	28	2435	-2408
1.आ.2.3 अन्य निवेश	204	3653	-3449	138	3871	-3733
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	1531	14	1517	1777	12	1764
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	857	167	690	811	154	657
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	18970	1532	17438	20625	1907	18718
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	18874	1316	17558	20577	1645	18932
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और / अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	18200	987	17213	19862	1189	18673
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	674	329	345	715	455	260
1.इ.2 सामान्य सरकार	96	216	-120	48	262	-214
2. पूंजी खाता (2.1+2.2)	71	147	-76	108	258	-150
2.1 अनुत्पादित वित्तर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	5	42	-36	19	108	-89
2.2 पूंजी अंतरण	66	106	-40	89	150	-61
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	126950	108822	18128	151560	150683	878
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1अ+3.1आ)	16130	8820	7309	19713	9740	9973
3.1अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	15505	5139	10366	19085	5856	13229
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	14452	5101	9351	14623	5747	8875
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	11002	5101	5901	11033	5747	5286
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	3450		3450	3590		3590
3.1.अ.2 ऋण लिखत	1052	38	1014	4462	109	4354
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	1052	38	1014	4462	109	4354
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	625	3681	-3056	628	3884	-3256
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	625	2575	-1950	628	2591	-1963
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	625	1817	-1192	628	1804	-1176
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश		758	-758		788	-788
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	1106	-1106	0	1293	-1293
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक		1106	-1106		1293	-1293
3.2 संविभाग निवेश	57107	59218	-2111	74695	66866	7829
3.2अ भारत में संविभाग निवेश	56733	58921	-2188	71761	63627	8133
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	45530	47949	-2419	56356	50342	6014
3.2.2 ऋण प्रतिभितियां	11203	10972	231	15405	13285	2119
3.2आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	374	297	77	2934	3239	-304
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	5859	5362	497	7328	7194	134
3.4 अन्य निवेश	43559	35422	8137	49825	45282	4542
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशियां	13298	13343	-46	14407	13637	770
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रुपी डेट मूवमेंट; एनआरजी)	0	185	-185	0	58	-58
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	13298	13159	139	14407	13579	828
3.4.2.3 सामान्य सरकार						
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र						
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईसीबी और बैंकिंग पूंजी)	21323	12681	8642	20123	18716	1407
3.4.3अ भारत को ऋण	17975	9305	8670	17429	16001	1428
3.4.3आ भारत द्वारा ऋण	3348	3376	-27	2694	2715	-21
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	29	207	-179	190	660	-469
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	7064	7809	-745	9523	10893	-1370
3.4.6 अन्य खाते प्राप्य/देय-अन्य	1845	1381	464	5581	1377	4205
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार						0
3.5 आरक्षित आस्तियां	4296	0	4296	0	21601	-21601
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण						0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए.						0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए.						0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	4296	0	4296	0	21601	-21601
4. कुल आस्तियां / देयताएं	126950	108822	18128	151560	150683	878
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	66869	61491	5378	82059	69772	12287
4.2 ऋण लिखत	53940	45950	7991	63920	57933	5988
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	6141	1381	4759	5581	22978	-17396
5. निवल भूल-चूक		314	-314	663		663

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आंशिक रूप से संशोधित

सं. 41: बीपीएम 6 के अनुसार भारत में भुगतान संतुलन का मानक प्रस्तुतीकरण

(कोड़ ₹)

मद	अक्तूबर-दिसंबर 2018 (पीआर)			अक्तूबर-दिसंबर 2019 (प्रा.)		
	जमा	नाम	निवल	जमा	नाम	निवल
	1	2	3	4	5	6
1 चालू खाता (1.अ+1आ+1.इ)	1173236	1301076	-127839	1157998	1167908	-9910
1.अ माल और सेवाएं (1.अ.क.+ 1.अ.ख.)	995732	1194674	-198942	971473	1062253	-90780
1.अ.क. माल (1.अ.क.1 से 1.अ.क.3)	598791	953970	-355179	578595	825220	-246625
1.अ.क.1 बीओपी आधार पर सामान्य वाणिज्यिक वस्तुएं	594154	902892	-308738	571916	773569	-201652
1.अ.क.2 वाणिज्य के अंतर्गत माल का निवल निर्यात	4637	0	4637	6679	0	6679
1.अ.क.3 गैर-मौद्रिक स्वर्ण	0	51078	-51078	0	51652	-51652
1.अ.ख सेवाएं (1.अ.ख.1 से 1.अ.ख.13)	396941	240704	156237	392878	237033	155845
1.अ.ख.1 अन्य के स्वामित्व वाले भौतिक इनपुट पर विनिर्माण सेवाएं	716	91	626	543	63	480
1.अ.ख.2 अन्यत्र शामिल न की गई रखरखाव व मरम्मत सेवाएं	460	2713	-2254	456	1477	-1021
1.अ.ख.3 परिवहन	34647	37704	-3057	38802	45662	-6860
1.अ.ख.4 यात्रा	53135	35060	18075	60866	39664	21202
1.अ.ख.5 निर्माण	6235	4455	1781	5227	4057	1170
1.अ.ख.6 बीमा और पेंशन सेवाएं	4967	3016	1950	4395	3914	481
1.अ.ख.7 वित्तीय सेवाएं	9541	7149	2392	8427	3917	4510
1.अ.ख.8 अन्यत्र शामिल न किए गए बौद्धिक संपत्ति के उपयोग के लिए प्रभार	1314	15658	-14344	1312	15650	-14338
1.अ.ख.9 दूरसंचार, कंप्यूटर और सूचना सेवाएं	157892	11741	146151	175162	19318	155844
1.अ.ख.10 अन्य कारोबारी सेवाएं	71917	73043	-1126	84680	85666	-986
1.अ.ख.11 वैयक्तिक, सांस्कृतिक और मनोरंजन संबंधी सेवाएं	3311	4203	-892	3813	5395	-1582
1.अ.ख.12 अन्यत्र शामिल न की गई सरकारी माल और सेवाएं	1039	2086	-1047	1116	1555	-438
1.अ.ख.13 अन्य जो अन्यत्र शामिल नहीं हैं	51768	43785	7982	8079	10696	-2617
1.आ प्राथमिक आय (1.आ.1 से 1.आ.3)	40781	95362	-54581	39617	92072	-52455
1.आ.1 कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति	9824	4266	5558	10255	4943	5312
1.आ.2 निवेश आय	24777	89892	-65115	23588	86031	-62443
1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश	12022	46809	-34787	9753	41027	-31274
1.आ.2.2 संविभाग निवेश	250	16658	-16408	199	17347	-17148
1.आ.2.3 अन्य निवेश	1471	26327	-24857	982	27570	-26588
1.आ.2.4 रिजर्व आस्तियां	11034	97	10936	12655	88	12567
1.आ.3 अन्य प्राथमिक आय	6180	1204	4976	5774	1097	4677
1.इ द्वितीयक आय (1.इ.1+1.इ.2)	136723	11039	125684	146908	13584	133324
1.इ.1 वित्तीय निगम, वित्तेतर निगम, परिवार और एनपीआईएसएच	136030	9483	126547	146566	11714	134852
1.इ.1.1 वैयक्तिक अंतरण (निवासी और/अनिवासी परिवारों के बीच चालू अंतरण)	131173	7113	124060	141473	8471	133002
1.इ.1.2 अन्य चालू अंतरण	4857	2370	2487	5093	3243	1850
1.इ.2 सामान्य सरकार	693	1556	-864	342	1869	-1527
2. पूँजी खाता (2.1+2.2)	512	1063	-550	770	1837	-1068
2.1 अनुत्पादित वित्तेतर आस्तियों का सकल अधिग्रहण (नामे) / निस्तारण (जमा)	39	299	-260	132	768	-636
2.2 पूँजी अंतरण	473	763	-290	637	1069	-432
3. वित्तीय खाता (3.1 से 3.5)	914958	784305	130653	1079533	1073281	6253
3.1 प्रत्यक्ष निवेश (3.1.अ+3.1.आ)	116250	63571	52680	140410	69373	71037
3.1.अ भारत में प्रत्यक्ष निवेश	111745	37038	74707	135938	41710	94229
3.1.अ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	104162	36764	67398	104154	40936	63218
3.1.अ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश से इतर इक्विटी	79294	36764	42530	78585	40936	37649
3.1.अ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	24868	0	24868	25569	0	25569
3.1.अ.2 ऋण लिखत	7583	274	7309	31784	774	31011
3.1.अ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	7583	274	7309	31784	774	31011
3.1.आ. भारत द्वारा प्रत्यक्ष निवेश	4505	26532	-22027	4472	27664	-23192
3.1.आ.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	4505	18561	-14056	4472	18457	-13985
3.1.आ.1.1 अर्जनों के पुनर्निवेश को छोड़कर इक्विटी	4505	13097	-8592	4472	12846	-8375
3.1.आ.1.2 अर्जनों का पुनर्निवेश	0	5464	-5464	0	5611	-5611
3.1.आ.2 ऋण लिखत	0	7971	-7971	0	9207	-9207
3.1.आ.2.1 प्रत्यक्ष निवेश उद्यमों में प्रत्यक्ष निवेशक	0	7971	-7971	0	9207	-9207
3.2 संविभाग निवेश	411585	426797	-15212	532037	476272	55765
3.2.अ भारत में संविभाग निवेश	408890	424658	-15768	511136	453204	57933
3.2.1 इक्विटी और निवेश निधि शेयर	328145	345579	-17434	401412	358574	42838
3.2.2 ऋण प्रतिभूतियां	80746	79080	1666	109725	94630	15095
3.2.आ. भारत द्वारा संविभाग निवेश	2695	2139	556	20901	23068	-2168
3.3 वित्तीय डेरिवेटिव (रिजर्व निधियों को छोड़कर) और कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन	42225	38642	3583	52196	51239	957
3.4 अन्य निवेश	313938	255295	58642	354890	322535	32355
3.4.1 अन्य इक्विटी (एडीआर/जीडीआर)	0	0	0	0	0	0
3.4.2 मुद्रा और जमाराशिया	95839	96169	-330	102621	97135	5486
3.4.2.1 केंद्रीय बैंक (रूपी डेट मूवमेंट, एनआरजी)	0	1331	-1331	0	411	-411
3.4.2.2 केंद्रीय बैंक को छोड़कर जमाराशियां लेने वाले निगम (अनिवासी भारतीय जमाराशियां)	95839	94838	1001	102621	96723	5898
3.4.2.3 सामान्य सरकार	0	0	0	0	0	0
3.4.2.4 अन्य क्षेत्र	0	0	0	0	0	0
3.4.3 ऋण (बाह्य सहायता, ईपीबी और बैंकिंग पूँजी)	153680	91392	62288	143331	133310	10020
3.4.3.अ भारत को ऋण	129547	67064	62483	124142	113973	10168
3.4.3.आ भारत द्वारा ऋण	24133	24328	-195	19189	19337	-148
3.4.4 बीमा, पेंशन, और मानकीकृत गारंटी योजनाएं	207	1494	-1287	1355	4699	-3344
3.4.5 व्यापार ऋण और अग्रिम	50913	56284	-5372	67829	77586	-9757
3.4.6 अन्य खाते प्राच्य/देय-अन्य	13298	9955	3343	39755	9805	29949
3.4.7 विशेष आहरण अधिकार	0	0	0	0	0	0
3.5 आरक्षित आस्तियां	30960	0	30960	0	153861	-153861
3.5.1 मौद्रिक स्वर्ण	0	0	0	0	0	0
3.5.2 विशेष आहरण अधिकार एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.3 आईएमएफ में रिजर्व निधियों की स्थिति एन.ए	0	0	0	0	0	0
3.5.4 अन्य रिजर्व आस्तियां (विदेशी मुद्रा आस्तियां)	30960	0	30960	0	153861	-153861
4. कुल आस्तियां / देयताएं	914958	784305	130653	1079533	1073281	6253
4.1 इक्विटी तथा निवेश निधि शेयर	481939	443179	38761	584489	496972	87516
4.2 ऋण लिखत	388761	331171	57590	455289	412642	42648
4.3 अन्य वित्तीय आस्तियां और देयताएं	44258	9955	34302	39755	163666	-123912
5. निवल भूल-चूक	0	2264	-2264	4725	0	4725

टिप्पणी: पी: प्रारंभिक पीआर: आशिकरूप से संशोधित

सं. 42: अंतरराष्ट्रीय निवेश की स्थिति

(मिलियन अमरिकी डॉलर)

मद	वित्तीय वर्ष/समाप्त तिमाही की स्थिति							
	2018-19		2018		2019			
			दिसंबर		सितंबर		दिसंबर	
	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं	आस्तियां	देयताएं
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 विदेश/भारत में प्रत्यक्ष निवेश	169964	399229	166594	386172	175438	417137	178694	426928
1.1 इक्विटी पूंजी और पुनर्निवेशित अर्जन	111122	382105	109875	369544	114340	398819	116303	404393
1.2 अन्य पूंजी	58841	17124	56719	16628	61099	18318	62392	22536
2 संविभाग निवेश	4699	260313	2666	245842	4541	260001	4845	266707
2.1 इक्विटी	590	147479	1386	138091	2344	144039	2619	148859
2.2 ऋण	4109	112834	1280	107752	2197	115962	2226	117848
3 अन्य निवेश	54538	419092	41550	401165	55406	428901	54006	430301
3.1 व्यापार ऋण	924	105192	252	103657	1707	106581	2286	105214
3.2 ऋण	9884	167924	6553	160322	7895	174838	6183	177286
3.3 मुद्रा और जमाराशियां	25158	130644	17211	125997	27563	133105	27099	133331
3.4 अन्य आस्तियां/देयताएं	18574	15332	17534	11190	18240	14378	18438	14469
4 रिज़र्व्स	412871		395591		433707		459863	
5 कुल आस्तियां/देयताएं	642072	1078634	606401	1033179	669092	1106039	697409	1123937
6 आईआईपी (आस्तियां - देयताएं)		-436563		-426779		-436947		-426528

भुगतान और निपटान प्रणाली

सं. 43: भुगतान प्रणाली संकेतक भाग I - भुगतान प्रणाली संकेतक - भुगतान तथा निपटान प्रणाली सांख्यिकी

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	विव 2018-19	2019	2020		विव 2018-19	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
	1	2	3	4	5	6	7	8
ए. निपटान प्रणाली								
वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 सीसीआईएल प्रचालित प्रणाली (1.1 से 1.3)			3.14	1.34			13808922	9808581
1.1 सरकारी प्रतिभूति समाशोधन (1.1.1 से 1.1.3)			1.27	0.70			8427404	6644724
1.1.1 आउटराइट			0.86	0.38			1306083	779511
1.1.2 रेपो			0.23	0.17			3096901	2517435
1.1.3 त्रि-पक्षीय रिपो			0.19	0.16			4024420	3347778
1.2 विदेशी मुद्रा समाशोधन			1.82	0.63			5034489	3030887
1.3 रुपये के डेरिवेटिव @			0.04	0.01			347030	132970
बी. भुगतान प्रणाली								
I वित्तीय बाजार अवसंरचना (एफएमआई)								
1 ऋण अंतरण - आरटीजीएस (1.1 से 1.2)			118.95	54.35			12047221	6443653
1.1 ग्राहक लेनदेन			117.06	53.35			10368946	5612493
1.2 इंटरबैंक लेनदेन			1.89	1.00			1678274	831161
II खुदरा								
2 ऋण अंतरण - खुदरा (2.1 से 2.7)			19743.26	17950.56			2831185	1687713
2.1 एईपीएस (निधि अंतरण) @			0.66	0.69			36	29
2.2 एपीबीएस \$			1247.79	2312.36			7951	18996
2.3 ईसीएस जमा			0.00	0.00			0	0
2.4 आईएमपीएस			2168.23	1224.75			201962	121141
2.5 एनएसीएच जमा \$			1234.43	2657.23			131109	89999
2.6 एनईएफटी			2623.70	1759.79			2283665	1306406
2.7 यूपीआई @			12468.45	9995.74			206462	151141
2.7.1 जिसमें से यूएसएसडी@			0.68	0.70			12	11
3 डेबिट ट्रांसफर और डायरेक्ट डेबिट (3.1 से 3.4)			818.06	691.42			76126	56029
3.1 भीम आधार पे @			8.88	20.66			141	217
3.2 ईसीएस नामे			0.00	0.00			0	0
3.3 एनएसीएच नामे \$			791.30	667.06			75952	55805
3.4 एनईटीसी (बैंक खाते से जुड़ा) @			17.88	3.70			33	7
4 कार्ड भुगतान (4.1 से 4.2)			5354.85	2863.83			115877	49807
4.1 क्रेडिट कार्ड (4.1.1 से 4.1.2)			1638.57	768.53			50574	20765
4.1.1 पीओएस आधारित \$			900.64	283.26			26656	8052
4.1.2 अन्य \$			737.93	485.27			23918	12713
4.2 डेबिट कार्ड (4.2.1 से 4.2.1)			3716.28	2095.30			65303	29043
4.2.1 पीओएस आधारित \$			1925.25	676.32			27238	9005
4.2.2 अन्य \$			1791.03	1418.98			38065	20037
5 प्रीपेड भुगतान लिखत (5.1 से 5.2)			3982.85	2086.01			15341	9648
5.1 वालेट			3178.60	1841.26			13111	8693
5.2 कार्ड (5.2.1 से 5.2.2)			804.25	244.75			2229	956
5.2.1 पीओएस आधारित \$			81.02	38.21			1021	313
5.2.2 अन्य \$			723.23	206.54			1209	642
6 पेपर-आधारित लिखत (6.1 से 6.2)			710.34	176.82			565315	163685
6.1 सीटीएस (एनपीसीआई प्रबंधित)			710.01	176.57			565046	163487
6.2 अन्य			0.33	0.25			269	197
कुल - खुदरा भुगतान (2 + 3 + 4 + 5 + 6)			30609.36	23768.64			3603844	1966882
कुल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)			30728.31	23822.99			15651064	8410535
कुल डिजिटल भुगतान (1 + 2 + 3 + 4 + 5)			30017.97	23646.17			15085750	8246850

भाग II - भुगतान के प्रकार तथा चैनल

प्रणाली	मात्रा (लाख)				मूल्य (₹ करोड़)			
	1	2019	2020		5	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
ए. अन्य भुगतान चैनल								
1 मोबाइल भुगतान (मोबाइल ऐप आधारित) (1.1 से 1.2)			13830.33	11276.04			520199	364031
1.1 इंटर-बैंक \$			1287.27	1064.77			109624	73418
1.2 इंटर-बैंक \$			12543.06	10211.27			410575	290613
2 इंटरनेट भुगतान (नेटबैंकिंग / इंटरनेट ब्राउज़र आधारित) @ (2.1 से 2.2)			2530.83	1597.63			3421077	2246296
2.1 इंटर-बैंक @			584.09	390.07			1595574	1203819
2.2 इंटर-बैंक @			1946.74	1207.57			1825503	1042477
बी. एटीएम								
3 एटीएम से नकद निकासी (3.1 से 3.3)			5471.63	2866.32			251075	127660
3.1 क्रेडिट कार्ड का उपयोग करना \$			7.54	3.68			360	159
3.2 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$			5441.22	2851.68			249930	127121
3.3 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$			22.87	10.97			785	379
4 पीओएस पर नकद निकासी \$ (4.1 से 4.2)			33.69	40.87			110	111
4.1 डेबिट कार्ड का उपयोग करना \$			30.55	35.67			105	105
4.2 प्री-पेड कार्ड का उपयोग करना \$			3.14	5.21			5	5
5 माइक्रो एटीएम में नकद निकासी @			344.98	875.54			9993	14462
5.1 एईपीएस @			344.98	875.54			9993	14462

भाग III - भुगतान अवसंरचना (लाख)

प्रणाली	1	2019	2020	
		अप्रैल	मार्च	अप्रैल
		2	3	4
भुगतान प्रणाली अवसंरचना				
1 कार्ड की संख्या (1.1 से 1.2)			8863.07	8868.07
1.1 क्रेडिट कार्ड			577.45	573.60
1.2 डेबिट कार्ड			8285.62	8294.47
2 पीपीआई की संख्या @ (2.1 से 2.2)			18251.64	18342.76
2.1 वॉलेट @			17032.85	17150.44
2.2 कार्ड @			1218.79	1192.32
3 एटीएम की संख्या (3.1 से 3.2)			2.34	2.34
3.1 बैंक के स्वामित्व वाले एटीएम \$			2.11	2.10
3.2 व्हाइट लेबल एटीएम \$			0.24	0.24
4 माइक्रो एटीएम की संख्या @			2.71	2.76
5 पीओएस टर्मिनलों की संख्या			51.39	50.85
6 भारत क्यूआर @			20.27	20.18

@: नवंबर 2019 से नया समावेश

\$: नवंबर 2019 से अलग से शुरू किया गया समावेश - अभी तक अन्य मदों का हिस्सा रहा होगा

नोट: 1. डेटा अनंतिम है।

- कार्ड पेमेंट्स (डेबिट / क्रेडिट कार्ड्स) और प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट (पीपीआई) के लिए नवंबर 2019 के डेटा की पहले के महीनों / अवधि के साथ तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि डेटा के परिभाषाओं में संशोधन के साथ अधिक ग्रेन्युलर डेटा प्रकाशित किया जा रहा है।
- केवल घरेलू वित्तीय लेनदेन पर विचार किया गया है। नए प्रारूप में ई-कॉमर्स लेनदेन लिया जाता है; फास्ट टैग लेनदेन; डिजिटल बिल भुगतान और एटीएम आदि के माध्यम से कार्ड-टू-कार्ड ट्रांसफर आदि इसके अलावा, असफल लेनदेन, चार्जबैक, रिवर्सल, एक्सपायर्ड कार्ड / वॉलेट को शामिल नहीं किया गया है।

अवसरिक श्रृंखला

सं. 44: लघु बचत

(करोड़ ₹)

योजना		2018-19	2019		2020	
			फरवरी	दिसंबर	जनवरी	फरवरी
		1	2	3	4	5
1. लघु बचत	प्राप्तियां	115714	9839	15814	15184	16911
	बकाया	918459	899191	1015010	1030037	1046766
1.1 कुल जमाराशियां	प्राप्तियां	91108	7130	12117	11091	11460
	बकाया	618418	606920	693812	704903	716363
1.1.1 डाक घर बचत बैंक जमाराशियां	प्राप्तियां	31037	2360	3455	3106	2690
	बकाया	140247	134863	150462	153568	156258
1.1.2 एमजीएनआरईजी	प्राप्तियां					
	बकाया					
1.1.3 राष्ट्रीय बचत योजना, 1987	प्राप्तियां	-31	-19	-31	-25	-20
	बकाया	3107	2877	2984	2959	2939
1.1.4 राष्ट्रीय बचत योजना, 1992	प्राप्तियां	53	0	-827	-2	-3
	बकाया	10	-8	-18	-20	-23
1.1.5 मासिक आय योजना	प्राप्तियां	10967	928	1753	1712	1887
	बकाया	192658	191653	203460	205172	207059
1.1.6 वरिष्ठ नागरिक योजना, 2004	प्राप्तियां	13990	1184	2070	2133	2131
	बकाया	55708	54446	69464	71597	73728
1.1.7 डाक घर मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	25000	2451	4296	3999	4494
	बकाया	124292	121687	152622	156621	161115
1.1.7.1 1 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	71534	70179	86344	88247	90327
1.1.7.2 2 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	5910	5824	6749	6854	6970
1.1.7.3 3 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	6901	6910	7328	7397	7464
1.1.7.4 5 वर्ष की मीयादी जमाराशियां	बकाया	39947	38774	52201	54123	56354
1.1.8 डाक घर आवर्ती जमाराशियां	प्राप्तियां	10081	215	1401	168	281
	बकाया	102401	101407	114842	115010	115291
1.1.9 डाक घर सावधि मीयादी जमाराशियां	प्राप्तियां	11	11	0	0	0
	बकाया	-26	-26	-25	-25	-25
1.1.10 अन्य जमाराशियां	प्राप्तियां	0	0	0	0	0
	बकाया	21	21	21	21	21
1.2 बचत प्रमाणपत्र	प्राप्तियां	16067	1732	3326	3524	3937
	बकाया	221517	219257	240900	244267	248022
1.2.1 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VIII निर्गम	प्राप्तियां	11318	1262	2272	2458	2619
	बकाया	98492	94795	110050	112508	115127
1.2.2 इंदिरा विकास पत्र	प्राप्तियां	334	3	0	0	1
	बकाया	263	300	-289	-289	-288
1.2.3 किसान विकास पत्र	प्राप्तियां	-18678	-1609	-971	-1713	-1120
	बकाया	19303	21232	6782	5069	3949
1.2.4 किसान विकास पत्र-2014	प्राप्तियां	23018	2065	2025	2782	2452
	बकाया	93630	91314	113273	116055	118507
1.2.5 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VI निर्गम	प्राप्तियां	93	12	0	-1	0
	बकाया	2	-47	-179	-180	-180
1.2.6 राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र VII निर्गम	प्राप्तियां	-18	-1	0	-2	-15
	बकाया	-80	-82	-82	-84	-99
1.2.7 अन्य प्रमाणपत्र	बकाया	9907	11745	11345	11188	11006
1.3 लोक भविष्य निधि	प्राप्तियां	8539	977	371	569	1514
	बकाया	78524	73014	80298	80867	82381

स्रोत : महालेखाकार, पोस्ट और टेलीग्राफ।

टिप्पणी: अप्रैल 2017 से प्राप्तियों का डेटा निवल रसीदें हैं, अर्थात् सकल रसीद माइनस सकल भुगतान

सं. 45: केंद्र और राज्य सरकारों की प्रतिभूतियों के स्वामित्व का स्वरूप

(प्रतिशत)

केंद्र सरकार की दिनांकित प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2019				2020
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(क) कुल (₹ करोड़ में)	5921026	6072243	6314426	6512659	6486585
1. वाणिज्य बैंक	40.28	39.05	39.66	39.05	40.41
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.31	0.36	0.42	0.39	0.39
3. बीमाकृत कंपनियां	24.34	24.88	24.86	24.90	25.09
4. म्यूच्युअल फंड	0.35	0.64	0.77	1.53	1.43
5. सहकारी बैंक	2.29	2.17	2.01	1.97	1.90
6. वित्तीय संस्थाएं	1.05	1.05	1.15	1.14	0.53
7. कॉरपोरेट	0.97	0.99	0.92	0.84	0.81
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	3.22	3.27	3.31	3.33	2.44
9. भविष्य निधियां	5.47	5.35	4.87	4.93	4.72
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	15.27	15.67	14.99	14.72	15.13
11. अन्य	6.46	6.57	7.05	7.23	7.17
11.1 राज्य सरकार	2.00	2.02	1.99	1.97	2.05

राज्य सरकारों की प्रतिभूतियां					
श्रेणी	2019				2020
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ख) कुल (₹ करोड़ में)	2777229	2826935	2905169	3047353	3265990
1. वाणिज्य बैंक	33.87	32.57	32.53	32.46	34.99
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	0.58	0.81	0.72	0.64	0.76
3. बीमाकृत कंपनियां	33.04	33.94	33.39	32.50	31.63
4. म्यूच्युअल फंड	1.20	1.24	1.12	1.20	1.14
5. सहकारी बैंक	4.55	4.65	4.24	4.16	4.12
6. वित्तीय संस्थाएं	0.42	0.44	0.33	0.31	0.11
7. कॉरपोरेट	0.29	0.32	0.28	0.31	0.30
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.09	0.08	0.05	0.04	0.02
9. भविष्य निधियां	22.15	21.88	22.36	23.66	22.22
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	3.81	4.08	4.98	4.73	4.71
11.1 राज्य सरकार	0.11	0.14	0.16	0.17	0.18

खजाना बिल					
श्रेणी	2019				2020
	मार्च	जून	सितंबर	दिसंबर	मार्च
	1	2	3	4	5
(ग) कुल (₹ करोड़ में)	412704	524618	538041	514588	538409
1. वाणिज्य बैंक	57.56	53.60	50.81	45.19	61.06
2. गैर-बैंक प्राथमिक डीलर्स	2.68	1.85	1.92	2.07	2.26
3. बीमाकृत कंपनियां	6.61	5.13	5.55	5.76	7.45
4. म्यूच्युअल फंड	2.78	13.00	14.08	20.42	13.24
5. सहकारी बैंक	2.48	2.54	2.55	2.07	2.55
6. वित्तीय संस्थाएं	2.49	2.14	1.82	2.12	0.58
7. कॉरपोरेट	2.23	1.67	1.57	1.66	1.89
8. विदेशी संस्थागत निवेशक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9. भविष्य निधियां	0.08	0.07	0.01	0.01	0.02
10. भारतीय रिज़र्व बैंक	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11. अन्य	23.10	19.99	21.70	20.70	10.95
11.1 राज्य सरकार	17.91	15.59	17.91	16.36	6.22

सं. 46: केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त प्राप्तियां और संवितरण

(करोड़ ₹)

मद	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
	1	2	3	4	(सं.अ.) 5	(ब.अ.) 6
1. कुल वितरण	3285210	3760611	4265969	4515946	5516932	6071777
1.1 गतिविधियां	1872062	2201287	2537905	2635110	3344948	3660857
1.1.1 राजस्व	1483018	1668250	1878417	2029044	2543965	2830634
1.1.2 पूंजी	332262	412069	501213	519356	694352	732102
1.1.3 ऋण	56782	120968	158275	86710	106630	98121
1.2 गैर गतिविधियां	1366769	1510810	1672646	1812455	2089516	2315637
1.2.1 राजस्व	1269520	1379727	1555239	1741432	2002766	2204742
1.2.1.1 ब्याज भुगतान	584542	648091	724448	814757	901783	1009776
1.2.2 पूंजी	94687	127306	115775	69370	85375	109030
1.2.3 ऋण	2563	3777	1632	1654	1375	1865
1.3 अन्य	46379	48514	55417	68381	82469	95284
2. कुल प्राप्तियां	3189737	3778049	4288432	4528422	5364245	6003162
2.1 राजस्व प्राप्तियां	2387693	2748374	3132201	3376416	4205473	4653758
2.1.1 कर प्राप्तियां	2020728	2297101	2622145	2978134	3512454	3910428
2.1.1.1 पण्य और सेवाओं पर कर	1212348	1440952	1652377	1853859	2186529	2399337
2.1.1.2 आय और संपत्ति पर कर	805176	852271	965622	1121189	1323113	1506912
2.1.1.3 संघशासित क्षेत्र (बिना विधान मंडल के) के कर	3204	3878	4146	3086	2812	4179
2.1.2 गैर-कर प्राप्तियां	366965	451272	510056	398282	693019	743330
2.1.2.1 ब्याज प्राप्तियां	39622	35779	33220	34224	36739	33619
2.2 गैर-ऋण पूंजी प्राप्तियां	60955	59827	69063	142433	136636	170056
2.2.1 ऋण और अग्रिम की वसूली	22072	16561	20942	42213	56398	63131
2.2.2 विनिवेश से प्राप्त राशि	38883	43266	48122	100219	80238	106926
3. सकल वित्तीय घाटा [1-(2.1+2.2)]	836563	952410	1064704	997097	1174823	1247962
3 क वित्तपोषण के स्रोत : संस्था-वार						
3क.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3क.1.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	-37476	231090	617123	144792	386389	...
3क.1.1.1 सरकार को निवल भा.रि. बैंक का ऋण	-334185	60472	195816	-144847	325987	...
3क.1.2 सरकार को गैर-बैंक ऋण	861106	708572	429585	844375	793327	----
3क.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
3ख. वित्तपोषण के स्रोत : लिखत-वार						
3ख.1 घरेलू वित्तपोषण	823630	939662	1046708	989167	1179716	1250914
3ख.1.1 बाजार उधार (निवल)	664058	673298	689821	794856	831554	959294
3ख.1.2 लघु बचत (निवल)	-56580	-78515	-105038	-163222	-217165	-208528
3ख.1.3 राज्य भविष्य निधियां (निवल)	34339	35261	45688	42351	42703	42482
3ख.1.4 आरक्षित निधियां	5109	-3322	-6436	18423	-14577	-871
3ख.1.5 जमाराशियां और अग्रिम	27545	13470	17792	25138	16011	13706
3ख.1.6 नकद शेष	95474	-17438	-22463	-12476	152688	68615
3ख.1.7 अन्य	53684	316908	427343	284095	368504	376216
3ख.2 बाह्य वित्तपोषण	12933	12748	17997	7931	-4893	-2952
4. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल वितरण	26.3	27.3	27.8	26.4	29.0	28.8
5. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कुल प्राप्तियां	25.6	27.4	27.9	26.5	28.2	28.5
6. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर राजस्व प्राप्तियां	19.2	20.0	20.4	19.8	22.1	22.1
7. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर कर प्राप्तियां	16.2	16.7	17.1	17.4	18.5	18.5
8. सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत पर सकल वित्तीय घाटा	6.7	6.9	6.9	5.8	6.2	5.9

...: उपलब्ध नहीं। सं.अ.: संशोधित अनुमान, ब.अ.: बजट अनुमान

स्रोत : केन्द्रीय और राज्य सरकारों का बजट दस्तावेज

सं.47: विभिन्न सुविधाओं के अंतर्गत राज्य सरकारों द्वारा ली गई वित्तीय सहायता

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2020 के दौरान					
		विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ)		अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए)		ओवरड्राफ्ट (ओडी)	
		प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या	प्राप्त औसत राशि	सुविधा प्राप्त करने के दिनों की संख्या
1	2	3	4	5	6	7	
1	आंध्र प्रदेश	-	-	-	-	-	-
2	अरुणाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
3	असम	-	-	-	-	-	-
4	बिहार	-	-	-	-	-	-
5	छत्तीसगढ़	-	-	-	-	-	-
6	गोवा	-	-	-	-	-	-
7	गुजरात	-	-	-	-	-	-
8	हरियाणा	-	-	-	-	-	-
9	हिमाचल प्रदेश	-	-	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	-	-	640	19	4	2
11	झारखंड	-	-	-	-	-	-
12	कर्नाटक	-	-	-	-	-	-
13	केरल	354	15	566	13	-	-
14	मध्य प्रदेश	-	-	-	-	-	-
15	महाराष्ट्र	-	-	-	-	-	-
16	मणिपुर	83	7	18	2	-	-
17	मेघालय	-	-	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	-	-	-	-	-	-
19	नगालैंड	351	20	-	-	-	-
20	उड़ीसा	-	-	-	-	-	-
21	पुदुचेरी	-	-	-	-	-	-
22	पंजाब	-	-	-	-	-	-
23	राजस्थान	-	-	-	-	-	-
24	तमिलनाडु	-	-	-	-	-	-
25	तेलंगाना	-	-	-	-	-	-
26	त्रिपुरा	-	-	-	-	-	-
27	उत्तराखंड	-	-	-	-	-	-
28	उत्तरप्रदेश	-	-	-	-	-	-
29	पश्चिम बंगाल	-	-	-	-	-	-

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

सं.48: राज्य सरकारों द्वारा किए गए निवेश

(करोड़ ₹)

क्र.सं.	राज्य /संघ शासित प्रदेश	अप्रैल 2020 के अंत तक			
		समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ)	गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ)	सरकारी प्रतिभूतियाँ	निलामी खजाना बिल (एटीबी)
	1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	8062	792	--	-
2	अरुणाचल प्रदेश	1346	2	--	-
3	असम	4306	53	--	-
4	बिहार	6774	--	--	-
5	छत्तीसगढ़	4302	--	1	5000
6	गोवा	578	291	--	-
7	गुजरात	13282	467	--	-
8	हरियाणा	2022	1166	--	-
9	हिमाचल प्रदेश	--	--	--	-
10	जम्मू और कश्मीर	--	--	--	-
11	झारखंड	--	--	--	-
12	कर्नाटक	4110	--	--	-
13	केरल	2092	--	--	-
14	मध्य प्रदेश	--	892	--	-
15	महाराष्ट्र	39969	417	--	-
16	मणिपुर	367	97	--	-
17	मेघालय	644	35	9	-
18	मिज़ोरम	536	38	--	-
19	नगालैंड	1596	32	--	-
20	उड़ीसा	13016	1413	82	18505
21	पुदुचेरी	286	--	--	902
22	पंजाब	236	--	8	-
23	राजस्थान	--	--	129	1800
24	तमिलनाडु	6440	--	40	8634
25	तेलंगाना	5502	1199	--	-
26	त्रिपुरा	319	5	--	-
27	उत्तराखंड	--	--	180	-
28	उत्तरप्रदेश	3070	77	--	-
29	पश्चिम बंगाल	10737	519	214	-
	कुल	129593	7494	662	34840

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं

सं. 49: राज्य सरकारों की बाज़ार उधारियां

(करोड़ ₹)

क्र. सं.	राज्य	2018-19		2019-20		2020-21						2020-21 में अब तक कुल राशि उठाई गई है	
		सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	फरवरी		मार्च		अप्रैल		सकल	निवल
						सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई	सकल राशि उठाई	निवल राशि उठाई		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	आंध्र प्रदेश	30200	23824	42915	33944	3928	3345	5020	4213	5000	3834	5000	3834
2	अरुणाचल प्रदेश	719	693	1366	1287	87	87	807	807	428	428	428	428
3	असम	10595	8089	12406	10496	1000	-910	2306	2306	500	500	500	500
4	बिहार	14300	10903	25601	22601	1959	1959	5000	5000	-	-1000	-	-1000
5	छत्तीसगढ़	12900	12900	11680	10980	-	-	5680	5680	-	-	-	-
6	गोवा	2350	1850	2600	2000	175	175	344	244	200	200	200	200
7	गुजरात	36971	27457	38900	28600	2500	1700	5500	5500	2080	2080	2080	2080
8	हरियाणा	21265	17970	24677	20677	1500	1100	4176	3476	5000	4000	5000	4000
9	हिमाचल प्रदेश	4210	2108	6580	4460	1500	1500	1580	660	-	-	-	-
10	जम्मू और कश्मीर	6684	4927	7869	6760	600	57	1677	1650	800	300	800	300
11	झारखंड	5509	4023	7500	5656	1000	1000	4500	4500	-	-	-	-
12	कर्नाटक	39600	31383	48500	42500	6000	6000	6400	5150	2000	2000	2000	2000
13	केरल	19500	14784	18073	12617	1000	-480	1471	1471	5930	5930	5930	5930
14	मध्य प्रदेश	20496	14971	22371	16550	3000	3000	7371	6223	2000	2000	2000	2000
15	महाराष्ट्र	20869	3117	48498	32998	11998	9498	5000	3000	7000	7000	7000	7000
16	मणिपुर	970	667	1757	1254	400	86	554	554	200	200	200	200
17	मेघालय	1122	863	1344	1070	150	150	449	449	-	-	-	-
18	मिज़ोरम	0	-123	900	745	90	90	360	306	100	-	100	-
19	नगालैंड	822	355	1000	423	150	22	200	200	200	200	200	200
20	उड़ीसा	5500	4500	7500	6500	1000	1000	2000	1000	3000	3000	3000	3000
21	पुदुचेरी	825	475	970	470	100	100	170	170	-	-	-	-
22	पंजाब	22115	17053	27355	18470	1300	1300	3400	3400	1600	800	1600	800
23	राजस्थान	33178	20186	39092	24686	2500	2326	6511	2361	2750	2750	2750	2750
24	सिक्किम	1088	795	809	481	-	-188	216	76	467	467	467	467
25	तमिलनाडु	43125	32278	62425	49826	5500	5500	3535	2136	8000	8000	8000	8000
26	तेलंगाना	26740	22183	37109	30697	2000	1583	8985	8409	4000	3166	4000	3166
27	त्रिपुरा	1543	1387	2928	2578	470	370	378	378	-	-	-	-
28	उत्तराखंड	46000	33307	67453	50494	7750	4679	17703	15675	5000	3000	5000	3000
29	उत्तरप्रदेश	6300	5289	5100	4500	750	750	2000	2000	1000	500	1000	500
30	पश्चिम बंगाल	42828	30431	59242	43132	7250	6450	12982	12982	2000	-500	2000	-500
	कुल	478323	348643	634521	487454	65657	52250	116275	99976	59255	48855	59255	48855

- : शून्य

टिप्पणी : 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू और कश्मीर राज्य संवैधानिक रूप से मौजूद नहीं है और उस राज्य की देनदारियाँ जम्मू और कश्मीर के नए केंद्र शासित प्रदेश की देनदारियों के रूप में बनी हुई हैं।

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक।

वर्तमान सांख्यिकी की व्याख्यात्मक टिप्पणियां

सारणी सं. 1

- 1.2 और 6: वार्षिक आंकड़े महीनों के औसत हैं।
- 3.5 और 3.7: वित्त वर्ष में अब तक वृद्धि के अनुपात से संबंधित है।
- 4.1 से 4.4, 4.8, 4.9 और 5 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार से संबंधित है।
- 4.5, 4.6 और 4.7 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम शुक्रवार को पांच प्रमुख बैंकों से संबंधित है।
- 4.10 से 4.12 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम निलामी दिन से संबंधित है।
- 4.13 : माह/वित्त वर्ष के अंतिम दिन से संबंधित है।
- 7.1 और 7.2: विदेशी व्यापार यूएस डॉलर से संबंधित है।

सारणी सं. 2

- 2.1.2 : चुकता पूंजी, आरक्षित निधि और दीर्घावधि परिचालनगत निधि शामिल है।
- 2.2.2 : नकदी, सावधि जमाराशियों और अल्पावधि प्रतिभूतियों/बांडों सहित जैसे - आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी।

सारणी सं. 4

<http://nsdp.rbi.org.in> के 'रिज़र्व टेम्पलेट' के अंतर्गत परिपक्वतावार बकाया फॉर्बर्ड संविदा की स्थिति दर्शायी गयी है।

सारणी सं. 5

अन्य को विशेष पुनर्वित्त सुविधा, अर्थात् एक्विजम बैंक को 31 अप्रैल 2013 से बंद है।

सारणी सं. 6

- अनुसूचित बैंकों के लिए, मार्च की समाप्ति के आंकड़े सूचना देने के लिए नियत अंतिम शुक्रवार से संबंधित हैं।
- 2.2 : आईएमएफ खाता सं.1 की शेष राशि, आरबीआई कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन निधि, उपदान और अधिवर्षिता निधि शामिल नहीं हैं।

सारणी सं. 7 और 11

सारणी 7 में 3.1 और सारणी 11 में 2.4: आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांड शामिल हैं।

सारणी सं. 8

- एनएम्₂ और एनएम्₃ में एफसीएनआर (बी) जमाराशियां शामिल नहीं हैं।
- 2.4: चुकता पूंजी और आरक्षित राशि शामिल हैं।
- 2.5 : बैंकिंग प्रणाली की अन्य मांग और मीयादी देयताएं शामिल हैं।

सारणी सं. 9

वित्तीय सस्थाओं में एक्विजम बैंक, सिडबी, नाबार्ड और एनएचबी शामिल हैं।
एल₁ और एल₂ मासिक आधार पर और एल₃ तिमाही आधार पर संकलित किए जाते हैं।
जहां आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं वहां अंतिम उपलब्ध आंकड़े पुनः दिए गए हैं।

सारणी सं. 13

कालम सं. (1) (2) और (3) में दर्शाए गए आंकड़ें अंतिम (आरआरबीसहित) और कालम सं. (4) और (5) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम (आरआरबी को छोड़कर) हैं।

सारणी सं. 14

कालम सं. (4) और (8) में दर्शाए गए आंकड़ें अनंतिम हैं।

सारणी सं. 15 और 16

डाटा अनंतिम है और चुनिंदा 41 अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संबंधित है जिसमें सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (आईएनजी वैश्य को छोड़कर जिसे अप्रैल 2015 को कोटक महिंद्रा के साथ विलय किया गया है) द्वारा कुल दिये गये कुल खाद्येतर ऋण के 90 प्रतिशत शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अंतर्गत निर्यात ऋण केवल विदेशी बैंक से संबंधित है।

मद 2.1 के अंतर्गत माइक्रो और लघु में विनिर्माण क्षेत्र में माइक्रो और लघु उद्योग को ऋण शामिल है।

मद 5.2 के अंतर्गत माइक्रो और लघु उद्यमों में विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में माइक्रो तथा लघु उद्यमों को ऋण शामिल है।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र पुरानी परिभाषा के अनुसार है और दि. 23 अप्रैल 2015 के एफआईडीडी परिपत्र एफआईडीडी.केका.प्लान. बीसी.54/ 04.09.01/2014-15 के अनुरूप नहीं है।

सारणी सं. 17

2.1.1: राज्य सहकारी बैंकों में सहकारी सोसाइटियों द्वारा अनुरक्षित आरक्षित निधि शामिल नहीं है।

2.1.2 : आरबीआई, एसबीआई, आईडीबीआई, नाबार्ड, अधिसूचित बैंकों और राज्य सरकारों से लिए गए ऋण शामिल नहीं है।

4. : आईडीबीआई और नाबार्ड से लिए गए ऋण शामिल हैं।

सारणी सं. 24

प्राथमिक व्यापारियों में, प्राथमिक व्यापारी का कारोबार करने वाले बैंक शामिल हैं।

सारणी सं. 30

प्राइवेट प्लेसमेंट और बिक्री के प्रस्ताव शामिल नहीं हैं।

1: बोनस शेयर शामिल नहीं हैं।

2: संचयी परिवर्तनीय अधिमान शेयर और इक्वी - अधिमान शेयर शामिल हैं।

सारणी सं. 32

आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी विदेशी मुद्रा में निर्दिष्ट बांडों में निवेश तथा सार्क स्वेप व्यवस्था के अंतर्गत प्राप्त विदेशी मुद्रा और भारत सरकार द्वारा रिजर्व बैंक को अंतरित एसडीआर शामिल नहीं हैं। अमेरिकी डॉलर में दिखाई गई विदेशी मुद्रा आस्तियों में रिजर्व में रखी गैर यूएस मुद्राओं (जैसे यूरो, स्टर्लिंग, येन और ऑस्ट्रेलिया डॉलर) के मूल्यवृद्धि/मूल्यहास को शामिल किया गया है। विदेशी मुद्रा धारिता को रूपी-अमेरिकी डॉलर आरबीआई धारिता दरों में परिवर्तित किया गया है।

सारणी सं. 34

1.1.1.1.2 और 1.1.1.1.4 : अनुमान

1.1.1.2 : नवीनतम माह के लिए अनुमान

'अन्य पूंजी' एफडीआई उद्यम की मूल और अनुषंगी सस्थांओ/शाखाओं के बीच के ऋण संबंधी लेनदेन से संबंधित है।

हो सकता है कि सूचना देने में हुए समय-अंतराल के कारण ये आँकड़े भुगतान-संतुलन के आंकड़ों से मेल न खाएं।

सारणी सं. 35

1.10 : जर्नलों के लिए अभिदान, विदेश में किए गए निवेशों का अनुरक्षण, छात्र ऋण चुकौती और क्रेडिट कार्ड भुगतान जैसी मदें शामिल हैं।

सारणी सं. 36

सूचकांकों में वृद्धि रुपये की मूल्यवृद्धि या मूल्यहास का संकेतक। 6-मुद्राओंवाले सूचकांक के लिए, आधार वर्ष 2016-17 अस्थिर है जिसे प्रत्येक वर्ष अद्यतन किया जाता है। रीर के आंकड़े उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (संयुक्त) पर आधारित है। इससे संबंधित कार्यपद्धति का विवरण बुलेटिन के दिसंबर 2005 और अप्रैल 2014 अंक में दिया गया है।

सारणी सं. 37

ईसीबी/विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बांडों के लिए आवेदनों पर आधारित जिन्हें उस अवधि के दौरान ऋण पंजीकरण संख्या दी गई है।

सारणी सं. 38, 39, 40 और 41

इन सारणियों के संबंध में व्याख्यात्मक टिप्पणियां आरबीआई बुलेटिन 2012 के दिसंबर अंक में उपलब्ध हैं।

सारणी सं. 43

भाग I- ए. भुगतान प्रणाली

1.1.3: प्रतिभूति खंड के अंतर्गत त्रिपक्षीय रेपो का परिचालन 05 नवंबर, 2018 से किया गया है।

भाग I-बी भुगतान प्रणाली

4.1.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

4.2.2: अन्य 'में ई-कॉमर्स लेनदेन, कार्ड से कार्ड अंतरण और एटीएम के माध्यम से डिजिटल बिल भुगतान आदि शामिल हैं।

5: दिसंबर 2010 से उपलब्ध है।

5.1: माल और सेवाओं की खरीद और वॉलेट के माध्यम से निधि अंतरण शामिल है।

5.2.2: ऑनलाइन लेनदेन और अन्य लेनदेन के लिए पीपीआई कार्ड का उपयोग शामिल है।

6.1: तीन ग्रेडों से संबंधित - मुंबई, नई दिल्ली और चेन्नई।

6.2: अन्य 'में गैर-एमआईसीआर लेनदेन शामिल है जो 21 बैंकों द्वारा प्रबंधित समाशोधन केंद्र से संबंधित है।

भाग II- ए अन्य भुगतान चैनल

1: मोबाइल भुगतान -

○ बैंकों और यूपीआई ऐप के मोबाइल ऐप के माध्यम से किए गए लेनदेन शामिल है।

○ जुलाई 2017 के डेटा में केवल व्यक्तिगत भुगतान और मोबाइल के माध्यम से पहल किए गए, संसाधित और अधिकृत किए गए कॉर्पोरेट भुगतान शामिल हैं। अन्य कॉर्पोरेट भुगतान जो मोबाइल के माध्यम से शुरू नहीं किए गए हैं, संसाधित और अधिकृत नहीं हैं, को शामिल नहीं किया गया है।

2: इंटरनेट भुगतान --नेटबैंकिंग 'के माध्यम से केवल ई-कॉमर्स लेनदेन और बैंक की इंटरनेट बैंकिंग वेबसाइट से किया गया वित्तीय लेनदेन शामिल है।

भाग II-बी एटीएम

3.3 और 4.2: केवल बैंक द्वारा जारी पीपीआई से किए गए लेनदेन से संबंधित है।

भाग III. भुगतान प्रणाली अवसंरचना

3: अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) और व्हाइट लेबल एटीएम ऑपरेटर्स (डब्ल्यूएलएओ) के एटीएम शामिल हैं। डब्ल्यूएलएओ को अप्रैल 2014 से शामिल किया गया है।

सारणी सं. 45

(-): नगण्य को दर्शाता है।

जून 2016 से टेबल फार्मेट संशोधित किया है, जिसमें केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों सहित राज्य सरकारों की स्वामित्ववाली प्रतिभूतियाँ और खजाना बिलों सहित शामिल है।

राज्य सरकार की प्रतिभूतियों में उज्ज्वल डिस्कॉ म एश्योरेंस योजना (यूडीएवाई) के अंतर्गत जारी विशेष बान्ड शामिल हैं।

वाणिज्यिक बैंकों के अंतर्गत बैंक के प्राथमिक डीलरों को शामिल किया गया है। तथापि, कुल बकाया प्रतिभूतियों में इसका हिस्सा बहुत कम है।

"अन्य" श्रेणी में राज्य सरकारों, पेंशन निधियां न्यास, संस्थाएं, हिंदू अविभक्त परिवार / वैयक्तिक आदि. शामिल है।

सारणी सं. 46

वर्ष 2011-12 के आधार पर जीडीपी डेटा है। वर्ष 2018-19 का जीडीपी डेटा केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा 31 मई 2019 को जारी राष्ट्रीय आय के अनंतिम अनुमान से संबंधित है। वर्ष 2019-20 का जीडीपी डेटा केंद्रीय बजट 2019-20 से लिया गया है। वर्ष 2017-18 से एनसीटी दिल्ली और पदुचेरी के आंकड़े भी शामिल किए गए हैं।

राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि व्यय को छोड़कर कुल प्राप्तियां और कुल व्यय।

1 और 2: आंकड़े केंद्र सरकार (एनएसएसएफ की पुनःचुकोती सहित) और राज्य सरकार के निवल चुकोती से संबंधित है।

1.3: राज्य द्वारा स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थानों को दिये गये मुआवजे और कार्य से संबंधित है।

2: यह डाटा केंद्र और राज्य सरकारों को दिये गये उधार प्राप्तियों सहित केंद्र और राज्य सरकारों के नकदी शेष में हुए घटबढ़ से संबंधित निवल को दर्शाते हैं।

3ए.1.1: आंकड़े भारतीय रिज़र्व बैंक के अभिलेख के अनुसार है।

3बी.1.1: दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से उधारियां शामिल हैं।

3बी.1.2: राष्ट्रीय लघु बचत निधि (एनएसएसएफ) द्वारा केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा विशेष प्रतिभूतियों में किये गये निवल निवेश को दर्शाते है।

3बी.1.6: केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को दिये गये अर्थोपाय अग्रिमों सहित।

3बी.1.7: वित्तीय संस्थानों, बीमा और पेंशन निधि, प्रेषण, नकदी शेष निवेश लेखा से लिये गये ऋण, खजाना बिलों (364-दिन के खजाना बिलों को छोड़कर) सहित।

सारणी सं. 47

राज्य सरकारों द्वारा समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) और निलामी खजाना बिल (एटीबी) के शेषों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में किए गए अन्य निवेशों को संपादिक के तौर पर रखते हुए विशेष आहरण सुविधा (एसडीएफ) प्राप्त की जाती है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा राज्य सरकारों को उनके अल्प कालिक नकदी असंतुलन से निपटने के लिए अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यू एमए) दिया जाता है।

राज्य सरकारों को उनकी अर्थोपाय अग्रिम (डब्ल्यूएमए) सीमा से अधिक की आवश्यकता को पूरा करने के लिए आग्रिम के तौर पर ओवरड्राफ्ट दिया जाता है।

प्राप्त कुल सहायता (एसडीएफ/डब्ल्यूएमए/ओडी) को उन दिनों की संख्या से भाग देने पर, जिनके लिए माह के दौरान सहायता प्राप्त हुई, औसत राशि प्राप्त होती है।

-: नगण्य

सारणी सं. 48

समेकित ऋण शोधन निधि (सीएसएफ), गारंटी उन्मोचन निधि (जीआरएफ) वे आरक्षित निधियाँ हैं जो कुछ राज्य सरकारों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के पास रखी जाती हैं।

नीलामी खजाना बिलों (एटीबी) में राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिक बाज़ारों में निवेश किए गए 91 दिवसीय, 182 दिवसीय तथा 364 दिनों की खजाना बिल शामिल हैं।

--: लागू नहीं (इस योजना का सदस्य नहीं है)।

वर्तमान सांख्यिकी संबंधी अवधारणाएं एवं कार्यप्रणालियां भारतीय रिज़र्व बैंक मासिक बुलेटिन के वर्तमान सांख्यिकी संबंधी व्यापक मार्गदर्शिका (<https://rbi.org.in/Scripts/PublicationsView.aspx?id=17618>) में उपलब्ध हैं।

‘वर्तमान सांख्यिकी’ का टाइम सीरिज डाटा <https://dbie.rbi.org.in> पर उपलब्ध है।

विस्तृत टिप्पणियां भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी संबंधित प्रेस विज्ञप्तियों और बैंक के अन्य प्रकाशनों (जैसे **भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंडबुक**) में उपलब्ध हैं।

भारतीय रिज़र्व बैंक के हाल के प्रकाशन

प्रकाशन का नाम	मूल्य	
	भारत में	विदेश में
1. भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन 2020	₹300 एक प्रति (काउंटर पर) ₹350 एक प्रति (डाक प्रभार सहित) ₹4,200 (डाक प्रभार सहित एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) ₹3,150 (एक वर्ष का रियायती दर*) ₹3,360 (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क - डाक प्रभार सहित [@]) ₹2,520 (एक वर्ष का रियायती दर [@])	15 अमरीकी डॉलर एक प्रति (डाक प्रभार सहित) 180 अमरीकी डॉलर (एक वर्ष का सदस्यता शुल्क) (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
2. भारतीय राज्यों से संबंधित सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹650 (सामान्य) ₹700 (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था पर सांख्यिकीय हैंड बुक 2018-19	₹600 (सामान्य) ₹650 (डाक प्रभार सहित) ₹450 (रियायती) ₹500 (रियायती डाक प्रभार सहित)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
4. राज्य वित्त: 2019-20 के बजटों का अध्ययन	₹600 एक प्रति (काउंटर पर) ₹650 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	24 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
5. रिपोर्ट ऑफ दि कमिटी ऑन फुलर कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी (तारापोर समिति की रिपोर्ट II)	₹140 एक प्रति (काउंटर पर) ₹170 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	25 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
6. बैंकिंग शब्दावली (2012)	₹80 एक प्रति (काउंटर पर) ₹120 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
7. अनुवाद के विविध आयाम (हिंदी)	₹165 एक प्रति (काउंटर पर) ₹205 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
8. बैंक में राजभाषा नीति का कार्यान्वयन: दशा और दिशा (हिंदी)	₹150 एक प्रति (काउंटर पर) ₹200 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	
9. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 38, 2017	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
10. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 39, 2018	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
11. भारतीय रिज़र्व बैंक सामयिक पेपर खंड 40, सं. 1, 2019	₹200 एक प्रति (काउंटर पर) ₹250 एक प्रति (डाक प्रभार सहित)	18 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)
12. पर्सपेक्टिव्स ऑन सेंट्रल बैंकिंग गवर्नंस; स्पीक (1935-2010) प्लैटिनम जुबिली	₹1400 एक प्रति (काउंटर पर)	50 अमरीकी डॉलर एक प्रति (हवाई डाक कुरियर प्रभार सहित)

टिप्पणियां:

- उपर्युक्त प्रकाशनों में से कई प्रकाशन आरबीआई की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर उपलब्ध हैं।
- टाइम सीरीज डेटा भारतीय अर्थव्यवस्था के डेटाबेस में उपलब्ध हैं (<http://dbie.rbi.org.in>)।
- भारतीय रिज़र्व बैंक का इतिहास 1935-1997 (4 खंड), वित्तीय संकट के संदर्भ में केन्द्रीय बैंकिंग की चुनौतियां और भारत की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था: वृद्धि और वित्त भारत के प्रमुख पुस्तक भंडारों में उपलब्ध हैं।
- * भारत में छात्रों, अध्यापकों / व्याख्याताओं, अकादमिक और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत रियायत दी जाएगी बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।
- @ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान को बढ़ावा देने हेतु, घरेलू ग्राहक जो एनईएफटी के माध्यम से भुगतान करना चाहते हैं, उन्हें 20 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है।

सामान्य अनुदेश:

1. बिक्री हुई प्रतियां वापस नहीं ली जाएंगी।
2. प्रकाशन कन्साइनमेंट वीपीपी आधार पर नहीं भेजा जाएगा।
3. जहां कहीं रियायती मूल्य का उल्लेख नहीं है, वहां भारत में छात्रों, अध्यापकों/व्याख्याताओं, अकादमि क और शैक्षिक संस्थाओं, सार्वजनिक पुस्तकालयों और पुस्तक विक्रेताओं को 25 प्रतिशत की रियायत दी जाएगी, बशर्ते उन्हें संबंधित संस्था से पात्रता प्रमाण प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रकाशन के पिछले अंक उपलब्ध नहीं है।
4. प्रकाशनों की बिक्री तथा वितरण (सोमवार से शुक्रवार) तक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001 पर उपलब्ध हैं। बिक्री अनुभाग का संपर्क नं. 022-2260 3000, विस्तार 4002, ई-मेल: spsdcs@rbi.org.in है।
5. सदस्यता शुल्क मुख्यतः एनईएफटी द्वारा किया जाना चाहिए और अग्रेषणपत्र, जिसके साथ एनईएफटी विवरण संलग्न हो, निदेशक, रिपोर्ट और ज्ञान प्रसार प्रभाग, आर्थिक और नीति अनुसंधान विभाग, भारिबैं, अमर बिल्डिंग, तल मंजिल, सर पी.एम. रोड, फोर्ट, पोस्ट बॉक्स संख्या 1036, मुंबई - 400 001।

एनईएफटी फार्म में निम्नलिखित जानकारी भरना अपेक्षित है :

लाभार्थी का नाम	कॉर्पोरेट सेवा विभाग, भारिबैं
बैंक का नाम	भारतीय रिज़र्व बैंक
शाखा तथा पता	फोर्ट, मुंबई
बैंक शाखा का आईएफएससी	RBISOMBPA04
खाते का प्रकार	चालू खाता
खाता संख्या	41-8024129-19
प्रेषक से प्राप्तकर्ता की जानकारी	अभिदाता का नाम..... अभिदाता सं.....

6. प्रकाशनों को शीघ्रताशीघ्र भेजने का हर संभव प्रयास किया जाएगा। तथापि मांग अधिक होने पर 'पहले आओ, पहले पाओ' आधार पर प्रकाशनों की आपूर्ति की जाएगी। औपचारिकताएं पूरा करने और उसके बाद उपलब्ध प्रकाशनों को भेजने में न्यूनतम एक महीने का समय लगेगा। 'प्रकाशन प्राप्त न होने की शि कायत' 2 महीने के अंदर भेजी जाए।
7. कृपया अपनी अंशदान संख्या, नाम, पता तथा ई-मेल आईडी spsdcs@rbi.org.in पर मेल करें ताकि हम आपसे संपर्क कर सकें।